

**पांचवीं
पंचवर्षीय
जिला योजना**

1974-75 से 1978-79

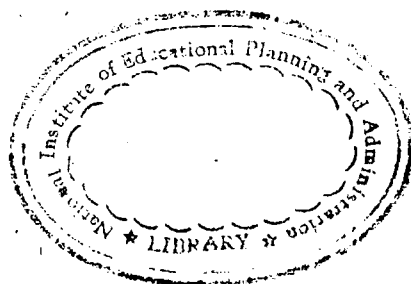
चमोली

*पंचम पंच वषीय योजना जमपद- हंगोलो *

- विषय सूची :-

संख्या	पृष्ठ संख्या
1:- शैक्षिक लक्ष्य	1-5
2:- जनसंख्या एवं व्यवसाय	6-11
3:- प्राथमिक शिक्षा	12-23
4:- उद्देश्य एवं रणनीति	24-28
5:- विभागीय कार्यक्रम :-	
(1) कृषि उत्पादन	29-40
(2) शिक्षा	41-47
(3) धूमि संरक्षण	48-51
(4) उद्यान एवं फलोपयोग	52-59
(5) पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन	60-69
(6) रस्ते	70
(7) वन	71-75
(8) नृशोष कृषि	76
(9) सहकारिता	77-83
(10) पंचायतराज	84-91
(11) बा. नियंत्रण	92
(12) बेधुत श्रम	93-97
(13) उद्योग (प्राथमिक लघु उद्योग)	98-108
(14) रकनित्त विभाग	109
(15) मंदार व्यवस्था	110-114
(16) पर्यटन	115-121
(17) सामान्य शिक्षा	122-126
(18) स्वास्थ्य एवं परिवार	127-129
(19) पुष्ठाहार	130-132
(20) जल उत्पादन	133-137
(21) आवासीय एवं नगरीय विकास	138
(22) पि.ओ.के. समुदाय का विकास [संस्थापन]	139-146
(23) सामान्य कल्याण	147-148
(24) ग्राम कल्याण	149
(25) अर्थिक सेवाएँ	150

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Shaheed Marg, New Delhi
Doc. No.
Date



अनुसूची :-

पृष्ठ संख्या :-

6:- वितीय वृद्धि कोण रूप रण संख्याओं का सेवकान	151-153
7:- सामग्री की आवश्यकता	154-156
8:- सेवा की योजना कार्यक्रम	157-159
9:- न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	160-164
10:- प्रवाज के लक्ष्योर् कार्य के लिये कार्यक्रम	165-167
11:- अनुसूचित विभाग	168-169
12:- न्यूनतम क्षेत्र का विभाग	170-172

विवरण पत्र :-

=====

1:- रूप पत्र 1- परिचय, प्रारंभिक	173-181
2:- रूप पत्र 2- धैर्य लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ	182-203
3:- विवरण पत्र 1 - आधारभूत आंकड़े	204-210

=====

5:- माने लों में भी कलता ल, देवरियाता ल, बेनो ताल, उपकुण्ड, वा सुतको ताल, होम कुण्ड और सतोपैय के नाम उल्लेखानोय है।

6:- धुन्तरव के आ इतर पर जनपद को जोशोमठ तहसील के पूरे क्षेत्र और चपोलो तहसील के उदतर भाग को लौवरमपोलोकोइक, चपोलो तहसील के इ शोभा भाग, जोशोमठ तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र और कर्णप्रयाग तहसील के शोभा इभाग को घेनाइदस लेहईजाा वो जा सकती है।

7:- जनपद में जलबृष्टि का विभाजन समा नवातय निम्न प्रकार रर ले

1:- चण्डौत-मई (मानसून से पूर्व)	92- चपोलो मीटर
2:- चण्डौत-सतंबर (मानसून)	1063-0 ,,
3:- जहदूबर-नवंबर (मानसून के पश्चात्)	46-5 ,,
4:- चण्डौत-मार्च (शांति काल)	231-9 ,,
वाणिज्यिक क्षेत्र -	1433-4 चपोलो मीटर
गासिक अंतर्गत -	119-1 चपोलो मीटर

8:- जोशोमठ तहसील और उसके पार्श्व क्षेत्रों चपोलो तहसील के क्षेत्र में वर्षा के क्षेत्र 800 से 1000 चपोलो मीटर तक वर्षा होती है। अन्य क्षेत्रों में वर्षा जोशोमठ और कर्णप्रयाग तहसील के पश्चिमी भाग में 1200 से 1600 चपोलो मीटर तक वर्षा होती है। अन्य क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 1000 से 1200 चपोलो मीटर के बीच है। इस प्रकार पूरे जिले के लिये वर्षा का कोई एक औसत स्वीकार करना युक्तिगत न होगा।

9:- यह यह उल्लेखानोय है कि स्थानों को ऊंचाई के अनुसार वर्षा का मात्रा और विश्वसनीयता बदल जातो है। वायु को दिशा में पडने वाले प्रक्रय पार्श्व क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है।

10:- जनवायु की दृष्टि से जनपद के निम्नांकित छाण्डों में विषय वस्तु किया जा सकता है।

(1)-उष्ण मंडल -

(2) शीतोष्ण मू-भाग :-

१,२०० मीटर से २,००० मीटर तक उंचे स्थान सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद होते हैं। यहाँ यकृतदाहिमपात होता है।

(3) शीतल मू-भाग :-

२,००० से ३,००० मीटर की उंचाई तक के क्षेत्रों में कड़ी सर्दी पड़ती है। पहाड़ों के उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणों के कम समय तक रहने के कारण घाटी में नदी बहती होती है।

(4) कुव्याल :-

३००० से ४००० मीटर की उंचाई पर घास से ढके ढलान मिलते हैं। इस क्षेत्र में घास से बर्फ निकलने लगती है और घास का फसल बिक जाता है जो वनस्पति में रोग-विहीन पुष्पकाल में परिणत हो जाता है।

(5) ध्रुव कक्षीय मू-भाग :-

४२०० से ५००० मीटर की उंचाई पर जाड़े की अवधि लम्बी और गर्मी की कृत अल्पकालीन होती है। वनस्पति का अभाव रहता है।

(6) हिमालय :-

हिमालयों एवं हिम शिखरों के समीप की घाटी लगभग ८ मास तक बर्फ से ढकी रहती है।

११- इस आपद में सनातन हिमरेखा ५,००० मीटर पर है जो सर्दियों में २५०० मीटर तक उत्तर आती है।

१२- ग्रीष्मकाल १३ फरवरी से १२ जून तक, वर्षाकाल १३ जून से १२ अक्तूबर तक और शीतकाल १३ अक्तूबर से १२ फरवरी तक माना जाता है। माणा और नीति आपद की उच्चतम उन्नतियों की मानव वस्तियाँ हैं। यहाँ पर वसन्त कृत सभी अल्पकालिक होती है।

१३- उच्च माणा-नीति जो अतिशीतल स्थानों पर वाष्पिक तापमान सेन्टीग्रेड पाया जाता है। यहाँ प्रति १०० मीटर की उंचाई पर तापमान एक डिग्री सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है।

१४ मुख्य सतत वाहिनियाँ एवं मौसमी धाराओं के नाम निम्न प्रकार दिये जा रहे हैं :-

१- अलकनन्दा, २- सरस्वती, ३- झेलमगंगा, ४- राप्तीगंगा, ५- गण्डकगंगा, ६- पातलीगंगा, ७- विन्ध्य, ८- नन्दाकिनी, ९- पिण्डर, १०- मन्दाकिनी, ११- सोनगंगा, १२- काशीगंगा, १३- जीरगंगा, १४- बालकिला, १५- निगाल, १६- झुंजाड़, १७- सूर्यगढ़, १८- भाविका, १९- गण्डक, २०- व्युण्ण, २१- रोणा, २२- अरमा, २३- लस्तर, २४- भाईगंगा, २५- जेलगंगा, २६- गुप्तारगंगा, २७- तीर्थगढ़, २८- प्राणानती, २९- आटागढ़, ३०- राभांगंगा ।

नोट:- २ से १५ तक अलकनन्दा में, १६-२३ तक मन्दाकिनी में तथा २४ से २९ तक पिण्डर में मिलती हैं ।

१५- नदियों की लम्बाई तथा उनके श्राव (discharges) की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होसकी है । नदियाँ गहरी घाटियाँ से होकर बहती हैं । अतएव उनके मार्गों में परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं है । हाँ जल के घनीकरण से वे अपनी लम्बाई में उच्चरी तर निचला जाती जा रही है ।

१६- जनपद की भौगोलिक विषयताओं से दृष्टि में रखते हुये दो उपसम्भाग बनाये गये हैं । प्रथम उपसम्भाग में विकास खण्ड केदारनाथ (उत्तरीखण्ड), दशोली (चण्डीखण्ड) भैरवखण्ड (जोशीखण्ड) तथा धौली हैं । दूसरे उपसम्भाग में विकास खण्ड मन्दाकिनी (अगस्तुमि) नागपुर (पीरगढ़), कपीप्रग, नारायणवाड़ एवं गोरसेणा हैं ।

१७- प्रथम उपसम्भाग हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के समीप है और समुद्रतल से २,००० मीटर से अधिक ऊँचाई का भू-भाग है । इस क्षेत्र में शीतल वायु एवं बृहत्तरल पाये जाते हैं । सर्दियों के दिनों में अधिकतर भू-भाग हिमाच्छादित रहता है और तेजज हवाएँ चलती हैं । सीमा क्षेत्र में नाणा और नीली घाटियों के ग्रामों में निवास करने वाले लोग सर्दियों के दिनों में अपने मूल ग्रामों को छोड़कर नीचे के स्थानों में चले आते हैं ।

१८- इस भू-भाग में वर्षा में ८०० से १,००० मिलीमीटर तक वर्षा होती है । जनपद की सभी सतत वाहिनियाँ नदियाँ इसी भू-भाग से निकलती हैं । यह उपसम्भाग जनपद के ३-३ भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है । यहाँ की जलसंधि विकरित हुई है और इसका घनत्व कम है । इस उपसम्भाग में उद्यान के विकास की विशेष सम्भावनाएँ हैं तथा भेड़ पालन के लिये उपयुक्त हैं । यह उपसम्भाग राष्ट्रीय दृष्टि से भी

महाराष्ट्र में है। केदारनाथ तथा बद्रीनाथ घाट भी इसी उपसमूह में हैं जहाँ प्रति वर्षीय राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र से लाखों यात्री आते हैं।

३ - द्वितीय उपसमूह समुद्र तल से २,००० मीटर से नीचे का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण है। घाटियाँ मैदानी और सदीय दोनों प्रकार की जलवायु रहती हैं। इस भू-भाग में कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है। वर्षा १२०० से १६०० मिलीमीटर तक होती है। इस उपसमूह में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँतक खनिज पदार्थों का प्रश्न है, अधिकतर खनिज पदार्थ इसी उपसमूह में पाये जाते हैं।

४ - प्रायः २,००० मीटर तक अच्छे ढंग से खेती की जासक्ती है। यहाँ तलाबों, उपरान, इज्जान तथा कटौले प्रकार की कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। स्थिति रूप से सुव्यवस्थित क्षेत्रों को तलाबों से सिंचित किया जाता है। जिस भूमि में सीढ़ी नुमा खेत का-रू शुष्क कृषि की जाती है, उसे उपरान कहते हैं। इज्जान भूमि में तीसरे या चौथे वर्ष खेती की जाती है। कटौले वह भूमि है जहाँपर सीढ़ीदार खेत नहीं काये जाते क्योंकि उर्वरता निम्न सी होती है जिसे पशुओं के मलमूत्र एवं गोशालाओं में बिछाई गई पत्तियों का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। वैसे अब कटौली की प्रथा प्रायः समाप्त होगई है।

भूमि के सफल न होने के कारण जल धरती के उपर और नीचे दोनों स्थानों में शीघ्र बह जाता है। जलपद में पानी की कमी नहीं है। उपत्यकाओं में अनेक सदा नीरवा नदियाँ एवं उनकी शाखाएँ बहती हैं, परन्तु सिंचाई के लिये उनके जल का सुव्यवस्थित-उपयोग नहीं होसका है।



2-जन संख्या एवं व्यवसाय

1971 की जनगणना के अनुसार चपौली जनपद की जनसंख्या 2,92,571 थी जिसमें 1,41,962 पुरुष तथा 1,50,609 महिलाएँ थी। जिले का क्षेत्रफल 9,1228 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ जनपद प्रदेश के पाँच सबसे बड़े जिलों में से एक है, वहीं आबादी की दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद की छोड़कर सबसे छोटा भी है। यद्यपि गत दशक में यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि राज्य की औसत दर से न्यून रही परन्तु गढ़वाल प्रखण्ड के चारों जिलों में यह सबसे अधिक पायी गई। 1971 की जनगणना से पूर्व यहाँ 1657 ग्राम थी जिसमें से 18 ग्रामों को मिलाकर 3 नोटीपाइड एरिया बना दी गई है और अब कुल ग्रामों की संख्या 1639 है और इसमें से 146 गैर आबाद एवं 16 विहा-व्यवहित ग्राम हैं।

2- गत दशक में जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुमान नीचे देदी गई तारिका से हो सकता है।

* भारत एवं उत्तर प्रदेश में जनपद-चपौली *

क्रम	संदर्भ वर्ष	इकाई	जनसंख्या	उत्तर प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5	6
1:- क्षेत्रफल	1971	वर्ग किलोमीटर	9,1228	10-29	3-277
2:- जनसंख्या	1971	वर्ग किलोमीटर	2,92,571	88-4	547-44
3:- जनसंख्या वृद्धि दर	1961-71	प्रतिशत	15-6	19-8	24-7
4:- जनसंख्या का घनत्व	1971	प्रति वर्ग किलोमीटर	32	300	182
5:- नगरों की संख्या	1971	संख्या	3	293	2921
6:- गाँवों की संख्या	1961	संख्या	1529	1, 12, 624	5, 666, -8
7:- नगरीय जनसंख्या	1971	प्रतिशत	4-60	14-00	19-887

3- 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद की नगरीय जनसंख्या 12,206 थी इसमें 7624 पुरुष एवं 4,582 महिलाएँ थी। जनसंख्या का एकमात्र घनत्व नगरीय प्रखण्ड की वस्ती के आसपास था। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 2,80,365 थी जिसमें से 1,344,338

पुरुष तथा 1,46,027 महिलायें थीं। इस जनपद में घोर अतीत से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही। यद्यपि प्रत्येक दशक में यौन अनुपात में कमी आती रही है परन्तु आज भी जिले की जनसंख्या में नारी बाहुल्य है। महिलाओं के अत्यधिक होने का प्रमुख कारण, पुरुषों का भारी संख्या में रोजगार की तलाश में जिले से बाहर जाना है। जैसे जैसे रोजगार की सुविधाएँ स्थानीय रूप से सुलभ होती जा रही हैं, यत अस्तित्व भी कम होता जा रहा है।

4:- 1961 की जनगणना के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों के पछि 1108 स्त्रियाँ थीं परन्तु 1971 में यह संख्या घटकर 1061 रह गई है फिर भी यह राज्य के औसत 883 से कहीं अधिक है। लैंगिक अनुपात की इस विषमता का कारण यह नहीं है कि चणोली जनपद में बालक कम और बालिकाएँ अधिक संख्या में जन्म लेती हैं अथवा बालिकाओं का लात्म पालन बालकों की अपेक्षा अधिक सावधानी से होता है। वास्तविकता यह है कि बालक और बालिकाएँ लगभग समान अनुपात में जन्म लेती हैं और उनकी देखभाल भी एक ही होती है। इस तथ्य की पुष्टि 1961 की जनगणना के समय 0-14 आयु वर्ग के बालकों की संख्या 48,866 और बालिकाओं की संख्या 48,297 से होती है। चणोली जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी कुछ प्रमुख आँकड़े निम्न तालिका में दिये हुए हैं।

वर्ष	क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाख में)	स्त्री पुरुष अनुपात	दशमिक प्रतिशत वृद्धि	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग की०मी०)	साक्षरता का प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1961	चणोली	2-53	1108	16-67	28	21-80	-
	गौड़ी गढ़वाल	4-82	1164	14-12	89	23-33	5-70
	टिहरी गढ़वाल	3-48	1202	13-53	79	15-99	2-20
	उत्तरकाशी	1-23	964	15-82	15	15-58	2-20
	पिठौरा गढ़	2-64	1055	18-54	37	23-35	-
	देहरादून	4-29	766	18-61	139	38-75	46-1
	अल्मोड़ा	6-33	1080	15-05	90	21-38	4-30
	नैनीताल	5-74	719	73-10	85	27-37	19-5
	उत्तर प्रदेश	737-00	909	16-66	251	17-65	12-90
	भारत	4391-00	941	21-60	134	24-60	18-00

1	2	3	4	5	6	7	8
1971	चमोली	2-93	1061	15-58	32	28-13	4-60
	पौड़ी गढ़वाल	5-39	1180	11-87	99	31-53	6-40
	टिहरी गढ़वाल	3-97	1198	14-13	90	19-09	2-66
	उत्तरकाशी	1-50	896	22-06	19	22-00	4-60
	देहरादून	5-83	772	35-80	189	45-04	46-00
	पिथौरागढ़	3-08	1073	16-89	43	31-43	3-90
	अल्मोड़ा	7-42	1103	17-20	106	28-73	5-10
	नैनीताल	7-90	802	37-57	116	32-49	22-20
	उत्तर प्रदेश	884-00	883	19-80	300	21-64	14-00
	भारत	5470-00	932	24-66	182	29-34	19-87

जिला	कार्यकर्ताओं का प्रतिशत		कार्य करने वालों में प्रतिशत		अन्य	
	1961	1971	1961	1971	1961	1971
चमोली	65-3	58-2	88-8	86-9	11-2	13-1
पौड़ी गढ़वाल	58-9	45-2	85-8	81-2	13-8	17-2
टिहरी गढ़वाल	64-5	51-6	92-7	91-5	7-0	8-0
उत्तरकाशी	69-0	63-7	86-6	85-3	12-5	13-8
देहरादून	40-2	35-2	35-0	28-2	60-2	63-7
पिथौरागढ़	59-9	41-7	87-3	79-9	11-9	18-9
अल्मोड़ा	59-3	39-6	89-5	83-9	9-9	14-5
नैनीताल	48-4	34-4	49-7	45-3	38-8	36-6

	1961	1971
1:- जनसंख्या में कार्य रत व्यक्तियों का प्रतिशत	65-3	58-2
2:- कार्य रत जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत	60-8	54-5
3:- कार्य रत जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत	69-0	61-0
4:- कार्य रत जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत	88-8	86-9
5:- कार्यरत कृषकों में पुरुषों का प्रतिशत	80-4	74-3
6:- कार्य रत कृषकों में स्त्रियों का प्रतिशत	95-4	97-4
7:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत जनसंख्या का प्रतिशत	4-5	1-9
8:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत पुरुषों का प्रतिशत	5-1	2-8
9:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत स्त्रियों का प्रतिशत	4-1	1-3
10:- अन्य कार्यों में रत जनसंख्या का प्रतिशत	6-7	11-2
11:- अन्य कार्यों में रत पुरुषों का प्रतिशत	14-5	22-9
12:- अन्य कार्यों में रत स्त्रियों का प्रतिशत	0-5	1-3

5:- 1961 में कार्य रत जनसंख्या का प्रतिशत 65-3 था जो 1971 में ~~58-2~~ घटकर 58-2 हो गया। 1961 में उक्त जनसंख्या का 88-8 प्रतिशत कृषि एवं सहायकीय धंधों में, 4-5 प्रतिशत खान, विनिर्माण लघु उद्योग एवं निर्माण तथा 6-7 प्रतिशत वाणिज्य, परिवहन संचार एवं अन्य सेवाओं में लगा हुआ था। 1971 में कृषि 86-9, 1-9 व 11-2 हो गया। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जिले में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक संख्या में कार्य रत हैं एवं वे परिश्रम भी अधिक करती हैं। यहाँ का आर्थिक ढाँचा उनके सहयोग पर बिका हुआ है जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है।

6:- इन सबके बावजूद स्त्रियाँ उपेक्षित अवस्था में हैं। उनमें शिक्षा का अभाव है तथा सार्वजनिक जीवन में उन्हें कोई विशेष भूमिका निभाने की नहीं दी जाती है, 1971 में जहाँ पढ़ने वाली आयु के 99 प्रतिशत बालक आधारिक विद्यालयों में जाते थे वहाँ केवल 44 प्रतिशत बालिकाएँ ही पाठशालाओं में भाती थीं। पूर्व आध्यात्मिक कतर पर यह प्रतिशत क्रमशः 44 और 6 रहा है।

7:- पिछड़े हुए समुदाय में प्रायः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को गिना जाता है। 1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को सदस्य संख्या क्रमशः 48,957 व 8151 थी जो जिले की जनसंख्या का क्रमशः 12-8 प्रतिशत होती है। यह दशक में जहाँ जिले की सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर 15 रही वहाँ अनुसूचित जातियों में इस वृद्धि का प्रतिशत 13-9 देखाने को मिला। अनुसूचित जन जातियों को स्थिति के विषय में टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्योंकि 1961 की जनगणना के समय उनकी पृथक से गिनती नहीं की गई थी।

8:- 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों की कुल संख्या 42,998 थी जिसमें से 42,825 व्यक्तियों ने अपने को शिल्पकार की संज्ञा दी थी। शेष 173 ने अपनी जाति वाल्मीकी तथा चमार आदि बतलाई थी। चमेली में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की विद्यमानता के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न कर्मचारियों की काफी संख्या में नियुक्ति करता आ रहा है एवं तीर्थ यात्राएँ में लोगों को भी पर्याप्त काम मिल जाता है। प्रमुख ये कर्मचारी प्रायः पर्व वृत्त मैदानी जिलों से आते हैं और अधिकतर में इस जिले में निवास ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से 1173 व्यक्तियों जिले के मूल निवासी न हो कर मैदानी इलाकों से आकर बसने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

9:- योजनाओं के निर्माण एवं आर्थिक अध्ययनों के लिये राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा वर्ष 1978 तथा उसके बाद के बहुत व के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के जनसंख्या के प्रति अनुमान बनाये गये हैं। पाँचवी योजना के लिये जनशक्ति से सम्बन्धित कार्यकारी दल के जनसंख्या एवं श्रमशक्ति पर गठित उप कार्यकारी दल ने इस पृष्ठ भूमि में कि अभी तक जनसंख्या की वृद्धि दर में के बराबर वृद्धि होती रही है, परिवार नियोजन कार्य क्रम के प्रभाव को ध्यान में रखाते हुये यह संतुष्टि दी कि 1971-79 के बीच प्रतिशत जनसंख्या तैयार करने के लिये वार्षिक वृद्धि दर वही ली जाय जो 1961 व 1971 की जनगणनाओं के बीच रही थी विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 1979, 1981 व 1986 की अनुमानित प्रक्षेपित जन संख्या यदि 1979-81 और 1979-86 के बीच वार्षिक वृद्धि दर देखी जाय तो यह क्रमशः 1-7 और 1-4 प्रतिशत आती है। इसी दृष्टिकोण से कि जनसंख्या के अनुमान कम से कम नहीं

वर्ष 1979 से 1984 के बीच वार्षिक वृद्धि दर 1-8। तथा 1984 के बाद यह विशेषज्ञ समिति के अनुसार 1-4 प्रतिशत घटकर प्रक्षोभण किया गया है।

जनसंख्या चार्टों की 1971 से 1989 तक प्रक्षिप्त जनसंख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

ग्रामीण जनसंख्या की प्रक्षिप्त जनसंख्या (हजार में)

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल
1971	280	12	292
1972	284	13	297
1973	286	15	301
1974	289	16	305
1975	291	18	309
1976	295	19	314
1977	297	21	318
1978	300	23	323
1979	304	24	328
1984	320	35	355
1989	327	44	371

10:- जनसंख्या में प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर 32 व्यक्ति रहते हैं। यह विवरण यह कि कठिन परिस्थितियों के कारण है। जैसा कि आराखों (अनुच्छेद-4) का वास्तविक है कि जनसंख्या वृद्धि की गति इस जनसंख्या में कम नहीं है और परिष्कार योजनाओं के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु जनसंख्या के घटने का अर्थ अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास में बाधा पड़ेगी और जनसंख्या अत्यंत कम रहेगी।

11:- जनसंख्या में घनी आबादी वाले क्षेत्रों को नियंत्रित है जैसा कि 1971 की जनगणना के समय पाया गया कि निम्नलिखित स्थिति में स्पष्ट होती है।

1:- गैर आबादी वाले क्षेत्र	146
2:- 200 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र	961
3:- 200 से 499 जनसंख्या वाले क्षेत्र	437
4:- 500 से 999 जनसंख्या वाले क्षेत्र	72
5:- 1000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र	

इसके अतिरिक्त जोखिम में रहने वाले 16 ग्राम विभाजित हैं। जहाँ ग्रामपाल में लोग आकर बस जाते हैं और जहाँ में नौचे चले आते हैं।

३- प्राकृतिक साधन

जपद के दोनों उपस म्भागों के प्राकृतिक साधनों में मृत्ति, जल, खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ और पशुवन मुख्य हैं। दोनों सम्भागों में हिमालय के निकटता तथा समुद्रतल से उँचाई आदि का वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

जपद के दोनों उपसम्भागों की मृत्ति पथरीली और ढाल वाली है। कृषि कार्य के लिये बहुत कम मृत्ति उपलब्ध है जैसा कि मृत्ति उपयोगिता के निम्न लक्ष्यों से स्पष्ट होता है :-

जपद में मृत्ति उपयोगिता की स्थिति (१९७१-७२)

वर्ग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
१- भौगोलिक क्षेत्रफल	६, १२, ८००	-
२- वन	४, ६६, ०००	५४-४२
३- उसर और कृषि के अयोग्य मृत्ति	३, ०६, ०००	३३-८०
४- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गयी मृत्ति	८, ५००	०-६०
५- कृषि योग्य क्षेत्र	१३, ६४३	१-५६
६- चारागाह	२५, ८००	२-८०
७- उद्यान के अन्तर्गत क्षेत्र	३, ७५७	०-४०
८- बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल	५५, ८००	६-१०
९- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	२७, ७००	३-२७
१०- सींचित क्षेत्रफल	२, ०३६	३-६०

(कृषि क्षेत्र का प्रतिशत)

२- कृषि के अन्तर्गत मृत्ति को दोनों उपसम्भागों में दो भागों में वितरित किया जा सकता है :

(अ) वह मृत्ति जो नदी के किनारे घाटियों में है जहाँ मृत्ति की गहराई (सायल डेप्थ) खेती के अनुकूल है और मिट्टी की बरकी से बरकी दोमट तक वर्गीकृत किया जा सकता है। ये स्थिति दोनों उपसम्भागों में न्यूनतम समान है।

(क) वह मृत्तिका जो उर्चाई के दोत्रों की है। प्रायः वड़े-वड़े बोल्लसों के ओर मिट्टी (डेली-पीकेट्स) में है। मिट्टी की रक्ता की बालू से क्वकी दोमट्ट के फूमर ख-जासकता है। उगपरि भागों में कहीं-कहीं ल भाग के मिट्टी के लाल डेली मिलते हैं।

३- स्वामित्व के आधार पर ज्यों वितरण का प्रश्न है प्रायः पूर्ण की पूर्ण लगभग ५५,००० हेक्टेयर कृषि मृत्तिका छोटी-मोटी जनयिक जीतों में वितरि हैं। जीतों के आधार पर जीतों की संख्या निम्न प्रकार है।

जीतों का आकार	प्रथम सम्भाग	द्वितीय सम्भाग	कुल योग	प्रतिशत
१- हेक्टेयर तक की जीते	३०, ३२६	३०, ०६३	६०, ४८९	८४-९९
२- हेक्टेयर से अधिक और ३ हेक्टेयर तक की जीते	३, ८८६	७, ६१४	१०, ५०२	१५-०२६
३- हेक्टेयर से अधिक और ५ हेक्टेयर तक की जीते	२६३	३१६	५७९	०-८९
४- हेक्टेयर से अधिक की जीते	२४	४	२८	०-०४
योग-	३३, ८०२	३८, ०९७	७१, ८९९	१००-००

जिसे में कुल कृषि परिवारों की संख्या ५२,०४६ है। एक परिवार की एक ही ग्राम में एक से अधिक जीत होने के कारण एवं अन्य ग्रामों में भी जीत होने के कारण जीतों की संख्या परिवारों की संख्या से अधिक है।

४- जनपद के दोनो उप-सम्भागों में मृत्तिका की उत्पादकता में अन्तर असिंचित और असिंचित दशाओं पर ही आधारित है। दोनो उप-सम्भागों में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ व गेहूँ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज २० से २५ कुन्तल है। यहाँ मात्रा निकली घाटियों के असिंचित दोत्रों में १० से १२ कुन्तल प्रति हेक्टेयर है और उगपरि दोत्रों में ७-८ कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है। वर्षा अधिक होने तथा मृत्तिका ढाल होने के कारण जल द्वारा मृत्तिका धारण अधिक होता है और लीचिंग के कारण दोनो उप-सम्भागों में सोयल का ट्रेण्ड रेसेडिक है।

५- जनपद में समतल मृत्तिका का अभाव होने के कारण खेतों को अंत गात्र पर सिंचियों के रूप में बना जाता है। चट्टानों पर मिट्टी की तह पतली होती है। फलतः खेतों को मिट्टी से ढाना आवश्यक हो जाता है। खेतों की निकली और पत्थरों की दीवार सड़ी करके ४-५ हाथ उगपर से मिट्टी काट कर दीवार की जड़

से जमा लिया जाता है। वर्षा काल में ये दीवारें पगन हो जाती हैं और उनकी समय-समय पर मरम्मत करनी होती है।

६- प्रायः २००० मीटर तक अच्छे ढंग से खेती की जा सकती है। यों तो ३००० मीटर की ऊँचाई पर भी गेहूँ उगा लेते हैं। यदि खेत पर्वत के छायादार पार्श्व पर होता है और उसके पास क्ल भी रहता है तो अधिक नमी के कारण वह मिट्टी की तह मोटी और उर्वरा होती है।

७- कृषि भूमि के मुख्यतः चार प्रकार हैं :

१- तलछट, २- उपतल, ३- हज्रान तथा ४- कटौल

स्थायी रूप से सिंचित क्षेत्रों को तलछट कहते हैं। उपतल भूमि में सिंचित नुसार काश्त शुष्क कृषि की जाती है। हज्रान भूमि में तीसरी या चौथी वाष्प से होती है तथा कटौल वह भूमि है जहाँ सीढ़ीदार खेत नहीं बनाये जाते हैं क्योंकि मृदा निम्नकोटि की होती है। कटौल की प्रथा पुरानी थी जो अब प्रायः समाप्त हो गई है। भूमि के समतल न होने के कारण जल धरती के उभार और नीचे दोनों स्थानों पर बहुत जल्दी बह जाता है। वैसे जनपद में पानी की कमी नहीं है। खेत को एक बार जोत कर उसमें मण्डुवा, भंगौरा, कांण्णि जैसे जनाज बोये जाते हैं। गेहूँ और धान की फसल के लिये खेत को कई बार जोतने, उसके पत्थरों को चुनने और ढ़ालों को तोड़ने की आवश्यकता होती है।

८- खरिफ की फसल में मण्डुवा, भंगौरा, सिंवा, कांण्णि, तिल, मक्का, चीन उदुद, मिर्च, हल्दी एवं अदरक आदि बोने का रिवाज है। रबी में मुख्यतः गेहूँ और सब्जियों की खेती की जाती है।

९- जनपद में ६००० फीट की ऊँचाई जो मुख्यतः उपसम्राज-१ में पड़ती है प आलू का अच्छा उत्पादन होता है। इन स्थानों पर आलू का उत्पादन प्रति हेक्टर ८० क्विन्टल तक आका गया है।

१०- २००० मीटर की ऊँचाई पर रबी की फसल नहीं से फल नहीं पकती। इसी प्रकार २३०० मीटर पर जूज, २६०० मीटर पर जुलह तथा ३००० मीटर पर अगस्त में फटह का समय होता है। इससे अधिक ऊँचाई पर जूज के महीने में बर्फ गिरने पर खेत बोये जाते हैं और फिलहाल इस उतक मण्डुवा बोयी जाती है। १९३०० मीटर की ऊँचाई पर जूज के बिलो पार्श्वों में मण्डुवा बोयी जाती है। पर्वतों की चोटी पर मण्डुवा बोया जाता है और मण्डुवा की बोनी २००० से ३००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है और मण्डुवा की बोनी ३००० से ४००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ४००० से ५००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ५००० से ६००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ६००० से ७००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ७००० से ८००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ८००० से ९००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है। ९००० से १०००० मीटर की ऊँचाई पर मण्डुवा बोयी जाती है।

मीटर से २६०० मीटर ऊँची घाटियाँ के निचले भागों में धान की खेती होती है। धान अप्रैल में बोकर सितम्बर में काटा जाता है और अक्टूबर में उसी खेत में गेहूँ की खेती है। तदुपरान्त आली अप्रैल में धान न बोकर मण्डुवा बोते हैं जिसे काटने के बाद आगामी अप्रैल तक खेती को खाली छोड़ देते हैं। मण्डुवा और धान क्रम-क्रम आये खेत में बोने का ही रिवाज है। ५२,८०० हैक्टियर भूमि अर्थात् भौगोलिक क्षेत्रफल का ६ प्रतिशत में खेती की जाती है परन्तु खेती की प्रणाली प्राच्यप्रगत ढंग से ही खान-पान उगाने की रही है। प्रति कृषक परिवार जीत का औसत आकार १ हैक्टियर आता है।

११- प्रायः गाँव वाले एक समय में अपने एक ओर के सारे खेत परती छोड़कर पशुओं की चरने की सुविधा प्रदान करते हैं। धान की कटाई उपर से नीचे की ओर जाती है परन्तु गेहूँ की नीचे से उपर की जाती है। अधिक ऊँचे स्थानों पर एक ही फसल हो पाती है।

जल

जल संसाधनों की दृष्टि से हिमालय के समीप का यह क्षेत्र सम्पन्न माना जा सकता है। सतत जाहिनी सदा नीरवाँ में जलमन्दा, नन्दाकिनी, पिण्डर और मन्दाकिनी चार प्रमुख हैं और इनके अतिरिक्त ही अनेक छोटी-बड़ी स्थानीय नदियाँ हैं जिनमें अधीप्त जल रहता है किन्तु न तो सिंचाई के लिये और न ही पेयजल के लिये इन संसाधनों का उपयोग किया गया है। भूमिगत जल का न तो अभी कोई सर्वेक्षण हुआ है और न उसकी कोई आवश्यकता ही है क्योंकि भूमि सतह पर ही इतना जल उपलब्ध है जिसका सम्भवतया आने वाले अनेक वर्षों में भी पूरा-पूरा उपयोग न हो पाये। जलपदों के दीर्घी उपसमागों में अतिरिक्त नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर जहाँ नदियाँ चौड़ी घाटियाँ काती हैं, लिफ्ट हरिनेश से सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अन्ततः लक्ष्मीनारायण सिंचाई के साथ स्थानीय फरनी और गधरी से ही गुल कामर उपलब्ध कराये गये हैं।

२- वतमान सिंचाई प्रणाली में पानी का ह्रास कुत होता है। निजी क्षेत्र में भी जो गल्लें हैं उनके लम्बे हैं अधिक होम से जल का ह्रास स्वाभाविक है। पक्की नहरों की कमी ^{संख्या कम} है और उनके रख-रखाव पर व्यय अधिक होता है। सृजित सिंचाई कामता का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि कृषक सभी कृषकों

में जलपत्र के दोनो उपसम्भर्गों में वर्षा प्राप्त होती रहती है। सुजित सिंचाई दामता के अनुसूचित क्षेत्रों को समस्त जलाने का कार्य कृषक की साधन हीनता के कारण कर में ही पाता है। मुख्यतया करों में धान की पोष के लिये और रबी में लम्बी अवधि तक सुखा की स्थिति रहने पर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

३- जल की सुविधायी की मरनी और विभिन्न जल श्रोतों से पाहल लहन विद्या र उफला रह गई है। इन्ही श्रोतों में उल्लव जल को दोनो उपसम्भर्गों में रार दाल र सिंचाई के छोटे-छोटे हवर्जी का निर्माण किया गया है। नदियों में कने वाले जल को विद्युत शक्ति द्वारा उगार उठाकर सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल में काफी वृद्धि की जासकी है परन्तु ऐसी परियोजनाओं में जो लागत जाती है, उसका उनके कायन्वियन के फल:स्वरूप प्राप्त होने वाले राजस्व के धनराशि से कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं रहता। कदाचित यही कारण है कि इस ओर बड़े पैमाने पर कार्य नहीं किया जासका है।

खनिज पदार्थ

जल में ताँबा, शीशा, लोहा आदि अनेक धातुय उल्लव हैं किन्तु इनके विषय में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिसके आधार पर कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जासके। मैग्नेसइट और सेलखड़ी भी कई स्थानों पर उल्लव हैं। जल की खनिज सम्पत्ति का कुछ परिचय निम्न प्रकार है :-

१-ताँबा:- गोरखा शासन में ताँबे की खानों से रार कर की लगभग ५०,००० ररर प्रतिवर्षी की आय होती थी। यहाँ के धन मुख्यतः पाहराइट व धुकर (विद्युत) तानु की हैं। लाल आषाधि तथा हरा क्विन्ट भी वहीं-वहीं मिलता है। अतीत की प्रमुख खानों के नाम ये हैं :-

- (अ) आगर-सेरा-लालगंगा के दाहिनी तरफ लोहवा पट्टी में।
- (ब) ताल-गुला-डंडा से १ मील उत्तर पूर्व।
- (स) डंडा - पोखरि से २-२ मील थाला स्थान से १५०० फीट ऊपर।
- (द) ताँबा - पोखरि से २-२ मील उत्तर-पश्चिम।
- (य) थाला-नीता से १ मील उत्तर-पश्चिम (पोखरि)

दशोला : - यहाँ के बस-मिलानग ७० प्रतिशत रुद्ध लीहो होता है। पुन काली वन-जा
 वन-विहारी है न। मुख्य खाने-निम्न स्थानों पर स्थित है :-

- (अ) सुश-मिखण्डा के नीचे चांदपुर के पास।
- (ब) राजहवा-सेती चांदपुर के पास।
- (स) गिलेश-तला कालिकाट में।
- (द) मोत-मला दशोली में।
- (य) चोर परगना-मला दशोली में।
- (र) जासतोखी - विचला नागपुर में।
- (व) बूखण्डा-विचला नागपुर में।
- (श) लोखना-
- (ष) हाट-मला नागपुर में अलमन्दा के तट पर।
- (ह) तला चांदपुर।

३- शीशा :- भी लगभग उन्ही स्थानों पर पाया जाता है जहाँ ताँबा उल्लब्ध है।
 मग्नेसाइट तथा सेलसिडी पीकलोटो व घूर्ण में उल्लब्ध है।

४- रश्मिद्वय :- मन्दाकिनी घाटी में लगभग इसकी १५ मील लम्बी पट्टी का पता चल
 है। कण्डारा, जूह तथा माली गुना के निकट इसकी अच्छी किस्म का पता चल है।

५- यूरेनियम, माइका आदि के विषय में जनपद के पोखरी विभास खण्ड में भूमि
 शास्त्रियों का कल संवेदना कर रहा है। संवेदना की कोई ठोस उपलब्धि अभी
 प्रकार में नहीं आई है। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है जिसके अभाव में सनिज पदार्थों
 के विषय में योजना में कोई निश्चित रूप से प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

वनस्पति

हिमालय क्षेत्र में जिसमें यह जनपद भी आता है, इसके प्रथम उपसम्भाग
 (जोशीमठ, थारली, उगसीमठ एवं दशोली विभास खण्ड) में मुख्यतया शुष्कार्णिक वन हैं
 जिसमें चीड़, केल, देवदार, रई, मुरिण्डा तथा सुरई के जंगल हैं। इसी उपसम्भाग में
 बुग्याल भी हैं जो चारागाह के अच्छे क्षेत्र होते हैं। उगवाह के अनुसार जनपद में
 विन्न-भिन्न वृक्षों के क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :-

१- १००० मीटर तक :- साल की सीमा-हल्दु, तोणा, साई, थार और सादणा की
 उल्लब्धि।

- २- १९०० मीटर तक :- चीड़ का बाहुल्य ।
- ३- २००० मीटर से :- केवदार का बाहुल्य और बॉय और कुसुम की उफल विप ।
- ४- २३०० मीटर तक :- चीड़ का अन्त । बाँज बुराँश मूल (साहस्रा) का बाहुल्य ।
- ५- २६०० मीटर तक :- बाँज का अन्त । तिलज, पदम और रंपा की उफल विप ।
- ६- ३००० मीटर तक :- तिलज और शिसू की विद्यमानता ।
- ७- ३३०० मीटर से :- उदमकर, बुराँश, पाँगर आदि । भोजपत्र व घास ढलान का आरम्भ ।
- ८- ३६०० मीटर से :- घास ढलान अधिक । पदम रंपा की उफल विप ।
- ९- ४००० मीटर पर :- पदम, धुँवर, साँसला औ मूँज की विद्यमानता ।
- १०- ४३०० मीटर से :- कल्पति का अभाव ।

जमपद का २४-४२ प्रतिशत क्षेत्र काल्कादित है । राष्ट्रीय कानून के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के मूलभूत के ६६ प्रतिशत में कानून का होना आवश्यक है । अतएव कृषि एवं वागवानी के लिये इन क्षेत्रों के अतिक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं है अपितु बेकार पड़ी भूमि के नियोजित कल्पना की आवश्यकता है ।

कानून में और उन्नतताओं पर स्थित क्षेत्रों में निम्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं जिनका स्वामित्व इन विभाग में होता है किन्तु इनके संग्रह एवं विभाजन का कार्य इन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि इन्हें ठेके पर उठा दिया जाता है या निर्धारित रायल्टी लेकर किसी को भी अधिकार दे दिया जाता है कि वह इन जड़ी-बूटियों का संग्रह करे । इस प्रवृत्ति की दो हानियाँ हैं । सबसे बड़ी हानि यह है कि विशेषाधिकार के प्रजातियों को नष्ट होने की है जो कि संग्रह कार्य प्रायः अनु-शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और अधिक लाभ की दृष्टि से पूरा पूरा पैड़ समूह ही उखाड़ लेते हैं । दूसरी हानि यह होती है कि ठेकेदार को मजदूरी पर स्थानीय मजदूरों को रखता है और जड़ी-बूटियों से होने वाला लाभ स्थानीय कर्मियों को नहीं मिल पाता है । इसके नियम की आवश्यकता है ।

जड़ी-बूटियाँ

<u>हिन्दी नाम</u>	<u>स्थानीय नाम</u>	<u>बोटैनिक्ल नाम</u>
रसी	घुघुकी	<i>Abies Precatorius</i> Linn
लेंटजीरा अभायारी	सजी	<i>Achrynthes- aspera</i> Linn

मीठा	वत्सनान	Aconitum tonic Supp.
अतीस	अतीस-मतीस	Aconitum Hetrophyllum Linn.
वच	वच	Acorus . Calamus. Linn.
हंस राज	हंस राज	Adiantum- Venstum. Gen.
वासक	वेसिंग	Adbotoda-Vasaca-Ness.
नील कण्ठी	रत पत्तिया	Ajuga- Bracteoser Wall
स्याह मूसली	हाली मूसली	Aneilime. scapiflorum-Wight
मन्द्रावण	चोरा	Angalic- glauca-Edgw
अफ सन तीन	हारा	Artimissia- Supp.
सतापरि सतमूली	फिणफिणया	Asparagus- Supp.
नुनैता	पुनूप	Boehovia- deffusa linn
खनार	खेरल	Bsuhimia- tomentosa
दाह हहृति	स्निगोड	Barbaris-aristats
,,	,,	Barbaris- Crustata
,,	,,	Barbaris- Vulguries
भोजपत्र	भोजपत्र	Betula-Bhejpatra-Val.
भंग	भंग	Canvis- Supp.
दालचीनी	दालचीनी	Cinnomorium Species
शंखपुष्पी	शंखी कुल	Cansocora- Ccestata
चक्रवर्त	पदी	Cassia Oxidentatora-Linn
ककभई	कनाड	Cassia Oxidentalis-Linn.
तुन	तुन	Cidrela- Toona
देवदह	दयार	Cedrus- deodara
धतूरा	धतूरा	Datura Supp.
गृष्टिका जाति	गेठी जाति	Dioscoria Supp- Linn.
निर विसी	निर विसी	Delphinium- denudatium
दहनीज अरु रसि	गुगुल	Donicum- roylie
मृगराज	मृगराज	Elipta-alba

आवला	आला	Embelic- Officinatas
सोमजाति	सोमजाति	Ephedra Supp.
पित पोखडा जाति	केरवा जाति	Eumaria Supp.
कपूर क्वरि	का हल्दी	Hedycium Spicatum
द्राक्षी	कमी	Herpastris- momiera
अखरोट	अखरोट	Juglans- Supp.
द्रोणामुष्णी	द्रोणामुष्णी	Leucas- cephalotes
पुदिना जाति	पुदिना जाति	Meutha Supp.
शहतूत जाति	किन्ना जाति	Aorus Supp.
वालछट	जवामासी, मासी	Nardus- stacchys Jatama
सालम पैजा	हस्त जडी	Orchis- latifolia.
सिलम किन्ना	गठा किन्ना	Orchis- mascular
छडीला	मूला	Permelia amstchandates
कुटकी	कडवी, केदार कडवी	Picramnia Kurroria.
चीड जाति	सल्ला	Pinus- Supp.
का कडवी	रिखलीकी	Podophyllum- emodi
वाँज	वाँज वान	Quercus- incana
सेन्द चीनी	डोलू आरवा	Rheum- emodi
काकडा कृष्णि	कासड	Rhus- succedana
मजिस्टा	मजिस्टा	Rubia- cordifolia
रीठा	रीठा	Sapindus- detergens
फुट	फुट	Sausria- lappa
ब्रह्ममूळ	ब्रह्ममूळ	Sausria- ohyallata
सेमल	सेमल	Salamatia- malabricum
अतिक्ला	मुह्या	Sida- cordifolia
चिरामता	चिरात	Surtia- chirata
लोष	लोष	Symptococ- paniculats
वामीस फत्र	धुरे	Taxus- baccate
कसक	कसक	Terminalis- chebula
मामिक्री	मामिक्री	

हरद	हरद	Terminalis- chebula
ममीरी	त्रिलि जडी	Thalictrum- foliolosum
गडेची	गुजे	Tinsphora- cordifolia
वत्सल जाति	वत्सल जाति	Valariana- Supp.)
निरगुण्डी	सिवाही	Veila- ccorate
तेजल जाति	तिमुर जाति	Vitex- nagundo
		Zanthoxylum- spp.

फलदार वृक्षों में नासपाती, खुबानी, बाहु अखरोट, सेव, तिनली, काकल, किरबोड़, बेरिज, कपारी तथा नींबू प्रजाति के पेड़ मिलते हैं। यद्यपि बागवानी अधिक लाभकारी सिद्ध होसकती है परन्तु अन्न की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अन्य साधन न होने के कारण लोग कृषि क्षेत्र में पेड़ लगाने को तैयार नहीं होते।

भांग के पौधे का पित्त मात्रा में उपलब्ध है। जलित की गतिविधि के आधार पर इसके रेशे के प्रयोग की सम्भावना विद्यमान है। वृष से मिलता-जुलता गिराल मिलता है। ग्वालदम, तलवाड़ी, बेरिताल, सिलकोट में चाय की खेती ब्रिटिस काल में होती थी जो देखरेख के अभाव में क्षयित स्थिति में है। अवस्थापना के सुदृढ़ ढाँचे के अभाव में यहाँ का औद्योगिक एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ नहीं पाया है।

पशुपालन

राज्य के मुख्य-मुख्य पालतू पशुओं एवं पक्षियों की संख्या पशु गणना के आधार पर निम्न प्रकार थी :-

	१९६६	१९७१
१- गोरक्षीय	२, १६, ४५०	२, ४०, २१३
२- महिष वैशीय	५३, १०६	६५, ६६०
३- भेड़-बकरी	२, २१, ६४६	२, २६, ४०७
४- मुर्गीयाँ	६, ७०५	१५, ०००
५- अन्य	२, ०४०	२, ६७४
योग-	५, ००, २५०	२, ५०, २५४

इस जपद में एक लाख १,२९,००० भैंसे हैं जो अधिकांश उप-सभाग १ में पायी जाती हैं। क्योंकि चार की उफ़लवता के साथ-साथ जलवायु भी अनुकूल है और वृत्त में इसी उप-सभाग में होता है जहाँ गर्मियाँ एवं बरसात (मई से सितम्बर तक) में चरहों का कार्य होता है। चार की समस्या भी मह विकास में बाधक है क्योंकि जाड़े में नीली की भैंसे देहरादून तक चरने जाती हैं। लगभग १५,००० भैंसे प्रतिवर्षी मांस के लिये प्रयोग की जाती हैं जिससे लगभग ३,००० क्विन्टल मांस प्रतिवर्षी प्राप्त होता है। उफ़लव आँकड़ों के अनुसार अनुमानतः प्रतिवर्षी ७६२ क्विन्टल उत्पन्न उत्पादन होता है। बकरियों के सम्बन्ध में जो आँकड़े उफ़लव्य हैं उनसे जपद के दोनों उप-सभागों में इनकी संख्या ६६ हजार है और इनका उपयोग बोफा ढोने तथा मुख्यतः मांस के लिये किया जाता है। जपद में १ लाख गायें और ५० हजार भैंसे इस समय हैं जिनमें लगभग ४० हजार

गायें व २० हजार भैंसे दूध देने वाली हैं। प्रति दिन लगभग ५२,००० लीटर दूध देने वाली हैं। प्रतिदिन लगभग ५२,००० लीटर दूध प्राप्त होता है। कल मुख्यतः खेती के काम में लाये जाते हैं। गायोंसे अधिकांश रूप में उप-सभाग-२ में जिसमें घाटि का क्षेत्र अधिक है, पाली जाती हैं। ये सभी पशु स्थानिय प्रजाति के हैं। और इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिये इनके बैश सम्बन्धन की आवश्यकता है। खेती और हड्डियों के संग्रह का रिवाज नहीं है क्योंकि पारिषद एवं लावादी के हित होने के कारण वहाँ मरे जानवरों की खली एवं हड्डियों को लोग नहीं उठाते हैं।

मुर्गियों की संख्या लगभग १५,००० आँकी गयी है जिनका अधिकांश भाग उप-सभाग-१ में है। इनसे औसतन २०,५०,००० अण्डे प्रतिवर्षी प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग मांस के लिये भी होता है।

मत्स्य पालन के लिये अब तक कोई कार्य क्रम नहीं चलाया गया है। अल्प पिण्डर, मन्दाकिनी और नन्दाकिनी तथा रामगंगा नदियों जिले में महलियों के लिये विद्यमान हैं।

विशाल क्षेत्र विकास सण्ड थाली में लवा, नामक स्थान पर एक हेक्टेर की स्थापना भी पहले की गयी थी किन्तु यह हेक्टेर भी लुप्तावस्था में है और कोई भी कार्य इसमें किया गया हो, ऐसा कोई भी लक्षण इसमें नहीं है। किन्तु नहरियाँ विभिन्न नदियों से पकड़ी जाती है इसके कोई भी आड़े उफ़लव्य नहीं है। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन नदियों से नहरियाँ पकड़ते हैं।

जपद में निम्न प्रजाति की नहरियाँ भई जाती हैं

LOCAL NAME	ZOOLOGICAL NAME
1. Trout	Salmo - trutta fromb. fessie (Baran Trout)
2. Mirror Carp	Cypricus Carpid var. specularis
3. Asela	Oriacus
4. Tarrā	Barileas bandelesis
5. Fucta	Barbus cholanoic
6. Gadiyal	Nemachailus
7. Cadara	Casa, Goby
8. Naved	Pseudochenis
9. Sumpu	Glyptosternum

जपद में भेड़ों के प्रजनन के लिये जो सुविधायें इस समय उपलब्ध हैं, वेवल 25,000 भेड़ों के लिये प्राप्ति है जबकि इनकी संख्या 52,000 आंकी गयी है। गाय-भेड़ों के प्रजनन के लिये भी जपद में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है किन्तु साँडों की संख्या यहाँ के प्रजनन के अनुसार नहीं है।

पशुओं के चमड़े और हड्डियों का वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं किया जाता है और न इनके संकलन की कोई व्यवस्था ही उपलब्ध है। जिले के अन्तराल में जो पशु आये दिन मरते रहते हैं उन्हें उनके मालिक अपनी सुविधानुसार कस्ती से दूर फेंक देते हैं और उनके चमड़े और हड्डियों का वे कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी हकड़ियों के जिले में स्थापना हो जाने पर मोटा भाग के आस के ग्रामों के मरने वाले पशुओं की हड्डियाँ और चमड़े का उपयोग किया जासकेगा किन्तु अन्तराल के दोत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ किया जासकेगा, ये सम्भव नहीं देखता। वर्तमान समय में परम्परा के अनुसार पशुओं के मरने के बाद कोई कीमत नहीं आंकी जाती है अतः चमड़े और हड्डियों के उपयोग का मुल्यांकन करना भी सम्भव नहीं है।

पाँचवी योजना के उद्देश्य एवं रणनीति

पाँचवी योजना के NATIONAL APPROACH PAPER के अनुसार : गरीबी हटाओ : उद्देश्य को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य यह कि १५ वर्षों (सातवी योजना के अन्त तक) की पूरी निर्धारित अवधि में गरीबी का अन्त करके अत्यधिक असमानता को समाप्त करना है।

गरीबी समस्या के दो फल हैं : -

(१) ₹६६-७० के भावों पर कम से कम ६१ प्रतिशत जनसंख्या को ३६ रुपये का न्यूनतम उभोग स्तर प्राप्त करना।

(२) आयिक दृष्टि से गति का स्तर उस सीमा तक बढ़ाना जिससे कि साधारण मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को सुगमता एवं शैघ्रता से प्राप्त कर सके।

प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये १९८३-८४ तक ब्रह्म शक्ति (Labour-Force) में आने वालों को आयिक दृष्टि से लाभकारी रोजगार दिलाना ताकि वे कम से कम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आय की असमानता को दूर करना आयिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिये आवश्यक है।

इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ५ वीं योजना के उद्देश्यों का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है :-

(१) रोजगार एवं अर्द्ध रोजगार व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार, विद्युत् तथा छोटे कृषक एवं ग्राहीणा मशीनों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ताकि वे उभोग का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सकें।

(२) आधारभूत अवस्थानार्थ, जो (अ) विद्युत् शक्ति, सिंचाई, ज्ञान एवं सड़कों की उन्नति करना, (ब) कृषि उत्पादन को ६ प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना, और (स) औद्योगिक विकास को ८-१० प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाकर आयिक विकास को तीव्र करना।

- (3) जनपद स्तर पर न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।
- (4) संतुल्य क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना।
- (5) जनशक्ति को रक्षित करना।
- (6) भाषाई स्थिरता लाना।
- (7) विकास केन्द्रों का स्थापन एवं नागरिक विकास को बढ़ाना।
- (8) जन सहयोग प्राप्त करना।

सामान्यतः जनपद के लिये भी यही उद्देश्य रखे जा सकते हैं। परन्तु प्रत्येक जनपद की अपनी कुछ विशेषताएँ एवं समस्याएँ होती हैं। अतः जनपद के लिये उद्देश्य एवं रणनीति निम्नलिखित करते समय उनकी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राकृतिक दृष्टि से चम्पौर जनपद राज्य के मध्य हिमालय श्रृंखला जिसमें उत्तरकाशी, टिकरि-गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपद, नैनीताल जनपद की तहसील नैनीताल तथा जनपद देहरादून की चरखता तहसीलों के क्षेत्र आते हैं, कालविहित है। जनपद की भौगोलिक विषमताओं को दृष्टि में रखते हुये इसे दो उपसमूहों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपसमूह में विकास खण्ड देवद्वारा (उत्तरीमठ) दशोली, फसखण्डा (जीसीमठ) एवं धराली आते हैं, दूसरे उपसमूह में विकास खण्ड मन्दाकिनी (अण्डास्तुमि), नागपुर (पोखरी), नारायणवाड़ा, काशीमग एवं गोरसेण हैं।

प्रथम उपसमूह हिमालय पर्वत शिखरों के समीप है और समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊँचाई का भू-भाग है। जनपद का 2/3 भौगोलिक क्षेत्रफल इसी उपसमूह में आता है। इस उपसमूह में उद्योग विकास विशेषतः सेव के क्षेत्रों की विशेष सम्भावनाएँ हैं और मछ पालन के लिये उपयुक्त है।

द्वितीय उपसमूह समुद्र तल से 2000 मीटर से नीचे का क्षेत्र है। इस भू-भाग में कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है तथा सिंचन कर्तव्य लिये भी उपयुक्त है।

जनपद में सतलुवा नदी एवं मोरादी नदियों का बाहुल्य है और उनकी किनारे जनपद के सिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग स्थित है। परन्तु अधिकांश क्षेत्र में सिंचनी सुविधाओं का अभाव है। यह एक अभावग्रस्त क्षेत्र है और शुष्क कृषि होती है। औद्योगिकी कार्यक्रम जनपद के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में जनपद की पाँचवीं योजना के निम्न लिखित उद्देश्य निम्नलिखित किये गये हैं :

(१) कृषि उत्पादन में जलपद की वास्तु निर्धार करना। इसके लिये सर्वोच्च प्राथमिकता सिद्ध कामता को बढ़ाने की है। तथा कृषि विकास, उन्नत प्रकार की प्रजातियों का वितरण एवं रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। लगभग ८५ प्रतिशत जोती का आकार १-२० हेक्टर से कम है। अतः जोती का हीटा एवं हित होना भी कृषि के विकास में वापक है। कृषि विकास कार्यक्रम द्वितीय तब सम्भाग में कलने का प्रयास किया जायेगा।

जलपद की दृष्टि से प्रथम तब सम्भाग में जो वास्तु व जल विकास योजनाओं पर कल दिया जायेगा।

राजधानी की कमी को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी फसलों के उत्पादन पर कल दिया जाय जिसका वाणिज्यिक दृष्टि में महत्व हो। प्रथम तब सम्भाग में फलों, जल, रसदार तथा राजा के उत्पादन की सम्भावना अधिक है। इसके साथ साथ सब्जी उत्पादन क्षेत्रों का भी बढ़ाने की सम्भावना है अतः फलों एवं सब्जी उत्पादन पर विशेष कल दिया जायेगा। किसानों की सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु नकदी फसलों के उत्पादन पर कल दिया जायेगा।

परिष्कार योजना में वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों के विकास का विशेष कल दिया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य को लागू करके जायेगा एवं उद्योग परिवर्तन को इस जलपद में नहीं रुकावट स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु संस्थागत कल को भी इस जलपद की ओर आकर्षित करना का उद्देश्य है।

कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों की स्थाना एवं पैतृक धर्मों के विकास के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण एवं सहायता की सुविधा के प्रदान किये जाने पर कल दिया जायेगा। इनमें उन्नत व अच्छे के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि वे देश के लिये अलग से बाजार लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सामान की स्थानीय सपता है।

जलपद में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं जिसके कारण लोग बहर प्रयास कर जाते हैं। अतः नये रोजगार सृजन के अवसरों पर परिष्कार योजना में कुछ कल दिया जायेगा। ये अवसर कृषि, औद्योगिक, उद्योग कौशल कार्यक्रम बादि में सुनिश्चित होंगे

सही है। इस प्रकार सोजाना के जलसुर बढ़ाना भी बची बची जा जा मुख्य उद्देश्य होगा।
ग्रामी में पीने के पानी की मुख्य समस्या है। कई-कई तो एक कुँडल से अधिक की दूरी से पानी लाया जाता है। अतः आवागमन क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी।

इस जनपद में अर्ध-कृषि ग्राम पिछरे हुये और ५०० से कम जनसंख्या वाले हैं ५०० से अधिक वासादी वाले ग्रामी को मोटर नाली से जोड़ा जाना मात्र उत्पादन एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभ दायक नहीं होगा। अतः पंचवती योजना में जो नई सड़कें ली जा रही हैं उनका आगार औद्योगिकी तथा पर्यटन का विकास और अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों को यथासंभव ही सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत् संचयन के माध्यम से उच्च प्राथमिकता उन ग्रामी तथा क्षेत्रों को दी जायेगी जो उद्देश्य है जहाँ पर स्थानीय उद्योगों की स्थापना के लिये अच्छा माल उपलब्ध है तथा औद्योगिकी के विकास की सम्भावना है। इस लिये ही पिछले उत्पादन की बहुत कामता है अतः पिछले हल्ले-डोलले निरुक्त योजनाएँ भी प्रस्तावित हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में ६-११ वर्षी के आयु वाले समस्त बालक-बालिकाओं की वाषारिक शिक्षा देने की व्यवस्था भी करने का उद्देश्य है। यह भी व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक ६ वर्षी आयु के बालक-बालिका को शिक्षा क्षेत्र की सुविधा सही प प्राप्त हो सके।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति एवं सहायता प्रदान करने जानी की भी व्यवस्था की जायेगी।

आरूपाक्ष एवं चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से योजना में प्रत्येक ५ कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाने का उद्देश्य है। मातृशिशु कल्याण केन्द्र भी प्रत्येक ५ कि०मीटर के भीतर उपलब्ध कराये जागे का उद्देश्य है। अबतक यह सुविधा जनसंख्या के आगार पर दी जाती थी। किन्तु भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये दूरस्थ क्षेत्रों की प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

पिछड़े हुये समुदाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि इन जातियों के परिवारों को योजना काल में अधिकाधिक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाय।

जामदनी बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न सनिज पदार्थों के होने का अनुमान है। इसके विकास की ओर भी कुछ दिखे जाने की आशंका है किन्तु वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में कोई निश्चित योजना बनाना सम्भव नहीं है।

शासन के निर्देशानुसार काई गढ़ी पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का विवरण जिला परामर्श दायी समिति की बैठक दिनांक १२-७-७२ में समस्त सदस्यों को वितरित किया गया था और सदस्यों से विचार विमर्श के उपरान्त पूर्णतया नियंत्रित की गई थी। तत्पश्चात् सप्ताह-सप्ताह पर प्रगति से प्राप्त निर्देशों और वित्तीय परिव्यय के संकेतों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों में संशोधन करते हुए पाँचवीं योजना का यहाँ प्रारूप प्रस्तुत है।

विभागीय
कार्यक्रम

अधिकांश उपज देने वाले फसलों का कार्य, म इस जनपद में वर्ष 1968-69 से से बलाया गया जो प्रायः ही विलुप्त क्षेत्रफल में ही सिमटा हुआ है। लारवों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी तथा तक केवल 20.56 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिये ही निम्न क्षमता सृजित की गयी है। जो सभी ही क्षेत्रों में क्षेत्र पर एक हाईड्रम सिस्तेम की योजना भी चल रही है।

राज्याधिकार क्षेत्रों के प्रयोग को गति भी अभी तक विलुप्त भन्द रही है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इस राज्य देने वाले फसलों केवल ही सृजित क्षेत्र तक ही सीमित है और सम्भवतः उर्वरकों का प्रयोग भी इस क्षेत्र में ही रहा है।

आजु एवं लोपायोन की योजनाओं के वक्तुय योजनाकाल में बसाई गई थी, ततोषूर्ण ढंग से बल्ले विकास विलुप्त क्षेत्रों के अभाव में कृषकों को कोई विशेष लाभ अभी तक नहीं पहुँचा। वक्तुय योजनाकाल में बसाई गई कृषि व विशेष योजनाओं को कुछ वर्षों को प्रगति इस प्रकार रही है :-

योजना का नाम	69-70	70-71	71-72	73-74	74-75
1:- राज्याधिकार क्षेत्रों का वितरण (तल्लो के रूप में)					
1:- नेत्रजानक (मैटन)	45	61	52	36	37
2:- काल्मेटक (,,)	27	44	38	78	47
3:- पोटेते तक (,,)	18	23	17	15	13
2:- लोपायोन के लक्षण विकास की योजना:-					
1:- ईक्कल का अक्कलान (हेक्टेयर में)	-	160	165	138	300
2:- लोपायोन इक्कल लीव्या	-	32	32	36	40

3:- अधिकांश उपज देने वाले क्षेत्रों की योजना:-

गत कुछ वर्षों में अधिकांश उपज देने वाले क्षेत्रों से अक्कलान को प्रगति निम्न प्रकार रही:-

क्रम सं०	कृषक	69-70	70-71	73-74	74-75
1:-	गेहूँ	398	323	2173	2464
2:-	धान	459	959	1670	1557
3:-	मूँग	133	53	63	129
4:-	फिसलियों का प्रविशरण लीव्या	500	500	720	750

4:- कृषि क्षेत्र वितरण :-

क्षेत्र का नाम	69-70	70-71	73-74	74-75	
1:- गार्डन रोक	112	214	133	115	119
2:- हेक्क हो	32	94	41	43	9
3:- अक्कल हल्लो का वितरण	-	-	26	3	13

41- चुकन्दर की रवेती :- चुकन्दर के बीज के उत्पादन के लिये

5000 फीट की ऊँचाई वाले क्षेत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुये है और आगे प्रदेश के मैदानी भागों में चुकन्दर की रवेती बड़े पैमाने पर होने जा रही है । इसी बात को ध्यान में रखते हुये जिले में पंचम पंचवर्षीय योजना काल में चुकन्दर की रवेती के विषय में किसानों का परिचित कराये जाने का प्रस्ताव है । इस विधान के अन्तर्गत प्रति वर्ग 90 प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे । अब तक इस जनपद में चुकन्दर की रवेती नहीं के बराबर रही है और पाँचवी योजना काल में लगभग 50 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में चुकन्दर की रवेती किये जाने का प्रस्ताव है ।

5- चाय की रवेती :- ग्वालदम तलवाड़ी तथा गैरहै के कुछ क्षेत्रों में अब भी चाय के पुराने उखड़े हुये भागों का निर्यात के रूप में देरदे जा रहे है । चाय की फरेलू रकपत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और भय है कि कहीं इसी चाय के निर्यात द्वारा अर्जित किये जाने वाली मुद्रा से वंचित न रहना पड़े । इसी को दृष्टि में रखते हुये जनपद में उखड़े पुराने चाय बाग बानों के जीर्णोद्धार तथा नये उपयुक्त क्षेत्रों की चाय के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई गई है । पंचम पंच वर्षीय योजना काल में लगभग 500 हे० क्षेत्रफल में चाय की रवेती करने का प्रस्ताव रखा गया है । चाय की रवेती के लिये नया क्षेत्र वन विभाग से प्राप्त किया जायेगा ।

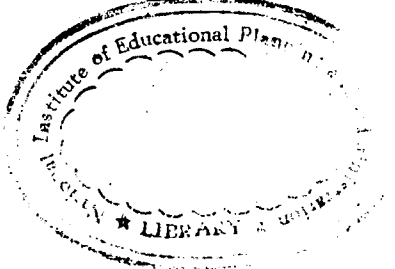
6- तम्बाकू विकास योजना :- जिले में तम्बाकू का वर्तमान क्षेत्रफल 260 हेक्टेयर है । इस क्षेत्रफल से तम्बाकू की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों से अङ्कुरित किया जायेगा । यद्यपि तम्बाकू की रवेती जिले में जादा पैमाने पर नहीं की जाती रही परन्तु दोनों उप सम्भागों में तम्बाकू उत्पादन की प्राप्ति क्षमता है । इस उद्देश्य से पाँचवी योजना काल में तम्बाकू विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है ।

7- जड़ी बूटी उत्पादन कार्यक्रम :- जनोपयोगियों के उत्पादन की दृष्टि से हिमालय का यह बवंडर पीहिते से ही प्रतिष्ठित रहा है । जड़ी बूटी उत्पादन कार्यक्रम को कृषकों के लिये आर्थिक स्वयं आर्षित बनाने के लिये जड़ी बूटी उत्पादन की एक योजना बनाई गई है जिसमें कृषकों को अपनी आय का एक श्रोत प्राप्त किया जायेगा । इसमें तम्बाकू विकास क्षेत्र में दो से पाँच एकड़ जड़ी बूटी उत्पादन के क्षेत्र स्थापित कराये जाने का प्रावधान है । जहाँ विभिन्न जड़ी बूटियों के पैड, पौधे पैदा किये जायेंगे और इन्हे किसानों में वितरित किया जावेगा ऐसी बहुत सी भूमि उन क्षेत्रों में उपलब्ध है जहाँ कोई खेत नहीं ली जाती इसका ही उपयोग इस योजना में जड़ी बूटी उत्पादन के साथ किया जायेगा । सहकारी समितियों द्वारा इन जड़ी बूटियों के संग्रहण एवं विपणन किये जाने का प्रावधान है । जिससे कि किसान के लिये उत्पादन के बाद विपणन और इस प्रकार की दूसरी कठिनाईयें आसक न बनें । ऐसा अनुमान है कि पंचम पंच वर्षीय योजना में लगभग 100 हेक्टेयरनेसुद्ध तथा से जड़ी बूटी उत्पादन चलाया जायेगा ।

8- मोन पालन योजना :- किसानों के अधिक विकास को ध्यान में रखते हुये
 को कार्यालय को चलाये जाने जाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमे किसानों को आर्थिक
 लाभ प्राप्त हो सके और प्राथमिक जल जीवन का स्तर उंचा हो सके । मधुमक्खी पाल कर
 शहद तैयार करने की योजना से प्रत्येक औषधि/पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध होगा अपितु
 उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । इसके अतिरिक्त ऐसा भी अनुमान है कि यदि
 शहद से मोन पालन को 1990 तक चलाया जाता है तो उस क्षेत्र की अन्य फसलों को जिसमे
 मोन पालन किया जाता है, से इनकार के 1990 रुपये के बाजार में बहोतरी हो जाती है ।
 प्रत्येक विकास क्षेत्र में पंचम पंच योजना वर्षों योजना काल के दौरान मधु मक्खी पालने की
 एक एक इकाईयों स्थापित की जावेगी जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर अन्य छोटी छोटी इकाईयां
 भी शहद उत्पादन के लिये स्थापित की जावेगी । मोन पालन योजना के अंतर्गत पंचवी
 योजना काल में अनुदान रकम अन्तः राज्य परिवहन के लिये 50000 रुपये का प्रावधान किया
 गया है ।

9- फल सर्वेक्षण योजना :- प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल
 तथा उसके उत्पादन का अध्ययन एवं फलों उत्पादन के अनुमान हेतु सर्वेक्षण की योजना पंचम
 पंचवर्षीय योजना के चलाये जाने का प्रावधान किया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों का विकास
 कृषि के त्वरित विकास पर आधारित है । त्वरित विकास के विषय जानकारी सार्वजनिक
 आँकड़ों से उपलब्ध हो सकती है परन्तु ये सार्वजनिक आँकड़े अभी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं
 है । अतएव योजना आयोग ने इस समस्या पर गम्भीर रूपा से विचार किया और यह निश्चय
 किया कि प्रदेश के पहाड़ी भागों में जिन फसलों पर कृषि विभाग द्वारा ड्रॉप कर्टिंग प्रयोग
 किये जा रहे है, उनके अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी ड्रॉप कर्टिंग प्रयोग किये जाय । जहाँ ही
 साथ पर्वतीय-क्षेत्रों में फलों की खेती का विस्तार का अध्ययन करने तथा उत्पादन का अनुमान
 लगाने हेतु सर्वेक्षण किये जाय । इस परियोजना के अंतर्गत पंचम योजना काल में 3 लाख
 रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

10:- कृषि सार्वजनिक सुधार की योजना :- प्रदेश की पर्वतीय जिलों में
 मैदानी भागों के विपरीत भूमि उपयोगिता तथा सुरक्ष फसलों के क्षेत्रफल के विभागीय आँकड़े
 अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पर नियमित पड़ताल की अब तक कोई व्यवस्था नहीं
 थी । अतः इन क्षेत्रों के लिये अनुमानित आँकड़े ही प्रयोग किये जा रहे हैं । पर्वतीय क्षेत्रों के
 समुचित विकास के लिये इन आँकड़ों की आवश्यकता निरन्तर महसूस किये जा रही है ।
 जमींदारी उन्मूलन के पश्चात इन क्षेत्रों के भी जमीनी भागों की तरह पड़ताल किया जाने का
 प्रयास किया गया परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थिति के कारण यह कार्य सुचारु रूप से
 सम्पादित नहीं कराया जा सका । पड़ताल कार्य के महत्व को देखते हुए वर्ष 1973-74 के प्रत्येक गाँव में
 पड़ताल न करवा कर प्रत्येक पट्टा की गट्टों के रोडव विधि से चुने सके । 1/5 गाँव में पड़ताल करा
 कराई जाय ताकि पाँचों वर्षों की अवधि में प्रत्येक गट्टों को सम्पूर्ण गतिमें पड़ताल समाप्त हो
 जाय । यह पड़ताल प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक की गयी है होगी जिसके



अन्तर्गत रवी एवं जामद की फसलों की पड़ताल मोटे पर वास्तविक रूप में की जावेगी ^{प्रत्येक} फसलों की किसानों से पूछ ताछ करके खरीफ तथा रवी की मुख्य फसलों के बीजफसल के अग्रिम अनुमानों के लिये प्रति वर्षा के रोस्टर में से प्रत्येक पटवारी के एक गाँव की पड़ताल सबसे पहिले कराई जावेगी तथा इन गाँवों में वास्तविक पड़ताल खरीफ ऋतु में ही होगी । इस कार्य को पुचार रूप से चला ने के लिये सम्बन्धित प्रत्येक जिले में नैनीताल तथा देहरादून को छोड़कर एक ही सार्वभौमिक विदेशिक जिला अधिकारियों के अधीन रह कर पड़ताल कार्य को निर्धारित समय पर सही कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगे जिसके परिणाम मुख्यालय को समय समय पर उपलब्ध हो सके । सार्वभौमिक निरीक्षणों के कार्य को समन्वित करने के लिये एक सार्वभौमिक अधिकारी का ही इस योजना में प्राविधान किया गया है । इस कार्यक्रम के लिये पाँचवी योजना में 30000 रुपये का परिव्यय निर्धारित है ।

11:- वृद्धि उत्पादन के अन्तर्गत न्यून के अन्तर्गत न्यून करने की योजना :- यह जनपद कृषि के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है और ताप जो पैदावार होती है उचित अन्तर्गत के अभाव में क्षतिग्रस्त होती रहती है । इस अर्थ को रोक्नेके लिये जनपद में अन्तर्गत सम्बन्धी इकाई स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है जिसके अन्तर्गत इस पाँच वर्षीय योजना में 60 कृषकों को अन्तर्गत (स्टोरजिडस) ऋण पर वितरित करने का प्रस्ताव है इसमें लगभग 120 00 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

12:- सिंचाई साधनों में वृद्धि करण :- पाँचवी पाँच वर्षीय योजना में राजकीय साधनों के से 620 हेक्टेयर तथा अन्य सिंचाई कार्यों से 847 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जावेगी जिसका विस्तृत विवरण सिंचाई परिच्छेद में दिया गया है ।

13:- अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की बोआई :-

क्र० सं०	फसल का नाम	75-76 का लक्ष्य	पाँचवी योजना का लक्ष्य
1:-	संतुलित घान (हजार हेक्टेयर में)	1-94	2-10
2:-	मैक्सिमम गेहूँ , , ,	3-4-39	4-95
3:-	रवी एवं जामोजिट मक्का , , ,	0-25	0-30

उपरोक्त फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की बोआई कर भरपूर सिंचाई, समुचित मात्रा में उर्वरक, कीट एवं व्याधि उपचार वृषि बीजों का उपयोग आदि समस्त समस्त वृषि विधियाँ अपना कर उपज में वृद्धि करने का प्राविधान किया गया है ।

14:- उन्नत बीज प्रयोग :- पाँचवी पाँच वर्षीय योजनाकाल में घान और गेहूँ के पूरे क्षेत्र को उन्नत जाति के बीजों के आध्वारित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे भूमि में सिंचाई की सुविधाये उपलब्ध होगी उतने सहज कृषि परजातियाँ अपनाये जाने ^{उपयुक्त} प्रस्ताव है । उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा रोग व्याधियों से बचाव हेतु कृषि रसायनों को अपनाया जावेगा उन्नत बीजों की समय से पूर्ति विदेशी फसलों के संशुद्ध बीजों से की जावेगी । उन्नत बीजों के अधिक माँग की पूर्ति के लिये बीज योजना तैयार की गई है और उसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र में उन्नत एवं सम्बन्धित बीज उत्पादन एवं वितरण की योजना

बनाई जावेगी। पाँचवी योजना काल के अन्त तक सम्पूर्ण क्षेत्र उन्नतशील एवं आच्छादित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पाँचवी योजना में वर्ष 75-76 में 202 क्वींटल रेकॉर्डेटिक किस्मों के बीज का वितरण किया जावेगा और योजना के अन्तिम वर्ष तक 700 क्वींटल करने का प्रस्ताव है।

151- रासायनिक उर्वरक वितरण :- जितनी भूमिमें सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध होती होंगी उनमें सबसे अधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित प्रयोग, तथा रोग वृद्धि से बचाव हेतु दूध रक्षा उपाय अपनाने ज वैसे और अतिरिक्त भूमि में रासायनिक उर्वरकों का आर्थिक उपयोग (इकोनॉमिक यूज आफ फर्टिलाइजर) किया जावेगा। चौथी पाँच वषीय योजना काल में रासायनिक उर्वरकों के दुलान पर बीज गण्डार से विद्री केन्द्रों तक शत प्रतिशत प्रतिशत राजकीय सहायता का प्राविधान किया गया है। पाँचवी योजना में भी यह सहायता जारी रखने का प्राविधान है। उर्वरकों के परिवहन के लिए पर राज सहायता हेतु पाँचवी योजना में। तारबन्ध तथा परिवहन निर्धारित है।

अभी तक उर्वरकों के संग्रहण की व्यवस्था किराये के भवनों में की गई है। यदुधीय ग्राम सेवक मुख्यालय तक दुलान व्यय पर शत प्रतिशत राजकीय सहायता है किन्तु यहाँ पर उर्वरकों के संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है। पाँच वषीय योजना में ग्राम सेवक मुख्यालय पर या उनके क्षेत्रान्तर्गत विद्री केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव है।

तार गोदाम तथा जो बीज गण्डार किराये के भवनों पर स्थित है, एक टिक विकास क्षेत्र में इन गण्डारों पर भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जहाँ उर्वरकों का संग्रहण किया जा सके, जिसका विवरण निम्न प्रकार तारपी बद्ध है :-

विवरण	स्थान	क्षमता :-
1:- तार गोदाम - 1	गोचर	100 मैट्रिक टन
2:- बीज गण्डार - 9	प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर	100 ,, ,,
3:- विद्री केन्द्र - 90	प्रत्येक ग्राम सेवक मुख्यालय पर	10 मैट्रिक टन

वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 में 286 मैट्रिक टन नेत्रजन, 220 मैट्रिक टन पोस्पोटिक तथा 140 मैट्रिक टन प्रोटेसिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

ये क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं वहाँ बुक रवेती का कार्यक्रम अपनाया जावेगा, जिसमें भूमि की व्यवस्था एवं फसल व्यवस्था की विधियाँ अपनाई जावेगी।

16:- द्विवर्षीय कार्यक्रम :- रबीफसल में जनपद की कुल बुंभित भूमि में फ फसल ली जाती है। प्रथम उप-समूह के अत्यधिक ऊँचे स्थानों पर रबीफसल में रबी फसल के अनाज जैसे गेहूँ, जौ आदि की रवेती होती है और रबी में ये स्थान हिमाच्छादित रहते हैं। वर्ष 1973-74 व 1974-75 में क्रमशः 35-3 व 37-1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र, द्विवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 75-76 में 39-3 और पाँचवी योजना में 44-1 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में एकवार से अधिक आच्छादन करने का लक्ष्य है।

17-कृषि उपकरण:- कृषि यंत्र वितरण करने के लक्ष्य निम्न प्रकार से रखे गये हैं:-

यंत्र का नाम	75-76 का लक्ष्य	पाँचवी योजना का लक्ष्य
1:- उन्नत हल	25	150
2:- हँड हो	200	1000
3:- कर्टीवेटर	15	50
4:- सीड ड्रिल	5	40
5:- प्रेसर	5	50

18:- पौष्टीकरण:- पंचम पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 75-76 के लिये पुरक्षा का लक्ष्य 45 हजार हेक्टेयर नियमित किया गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये वर्तमान समय में कार्यरत कृषि रक्षा इकाई का सुदृढीकरण किया जाना है जिसमें सभी विकास क्षेत्रों में कम से कम एक कनिष्ठ कृषि रक्षा सहायक, दो कृषि रक्षा पर्यवेक्षक तथा 10-10 क्षेत्रप्रचारक रखे जाने हैं। कृषि रक्षा औषधियों के मिलने पर 50% अनुदान तथा महाभारी निक्षेप पर 100% राजसहायता प्रस्तावित की गई है।

19:- कृषि अनुशीलन केंद्रों की स्थापना:- जिले की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु के अनुसार विभिन्न फसलों में किसी के अनुसंधान उबरकों की माँग बुझाई का समय आदिनिर्धारित करने के लिये आधार भूत आँकड़े एकत्रित करने और नियमित सन्तुति देने की दृष्टि से एक अनुशीलन केंद्र की स्थापना की जावेगी। इस केंद्र पर प्रत्येक उप-समूह की मिट्टी का प्र-परिक्षण कार्य भी किया जावेगा।

20:- जीवाणु एवं कम्पोस्ट रवाद का कार्यक्रम:- क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की कमी को देखते हुए भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में जीवाणु एवं कम्पोस्ट रवाद बनाने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1975-76 में 587 हजार मेट्रिक टन कम्पोस्ट रवाद बनाने का लक्ष्य है जिसे पाँचवी योजना के अंत तक बढ़ा कर 621 हजार मेट्रिक टन तक पहुंचाने का प्रयास किया जावेगा।

21:- बीज संवर्धन प्रकेंद्रों की स्थापना:- इस जनपद की जलवायु मैदानी क्षेत्रों की जलवायु से भिन्न हानि के कारण जो बीज मैदानी क्षेत्रों से आता है वह उत्पादन में पूर्ण योगदान नहीं दे पाता है। साथ ही साथ मैदानों से आने पर समय और धन का बहुत अपव्यय होता है। इसे दृष्टिगत करते हुए जनपद में 4 कृषि प्रकेंद्रों की स्थापना इस पंचम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में प्रस्तावित की गई है जिसके लिये 10 लाख रुपये परिव्यय नियमित किया गया है।

22:- बीज विद्यालय संयंत्र लगाने की योजना:- जनपद में बृहत्तम अथवा बीज उगलव्द कराने हेतु बीज विद्यालय संयंत्र लगाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिये पाँचवी योजना में 1 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित है।

23:- फलों की विपणन प्रणाली एवं उत्पादन लागत की आगाही परियोजना:-

इस परियोजना के लिये पाँचवी योजना में 1-50 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित है।

24:- गोवर गैस प्लांट योजना :- पाँच पाँच वर्षीय योजना काल में गोवर गैस को प्लांटों की सहायता से जल से अलग करने की योजना का चयन किया गया है। यह योजना जनपद के 5 विकास क्षेत्रों में चलाई जायेगी जो निम्न प्रकार प्रस्तावित की गई है।

- 1:- विकास क्षेत्र दशोली:- पाट, पीपलकोटी एवं गाड़ी।
- 2:- विकास क्षेत्र गेरुषेण:- लखौरी, कालीगाड़ी एवं सेरा।
- 3:- विकास क्षेत्र नारायणपुर:- नारायणपुर, कुलसारी एवं नौली।
- 4:- विकास क्षेत्र मोर्चागाँव:- पारसी, टीपरी, लंगरी, गुलावकोटी एवं हैरीग।
- 5:- विकास क्षेत्र ऊरवीमठ:- देहा।

खाद्यान्नों का उत्पादन :- वर्ष 1974-75 में कृषि की दृष्टि से अच्छे मौसम को देखते हुए आशा की जाती है कि खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 78 हजार मेट्रिक टन रहा है। वर्ष 1975-76 में 82 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन का लक्ष्य है जिसे पाँचवी योजना के अंत तक 90 हजार मेट्रिक टन तक बढ़ाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को सम्पन्न करने हेतु वर्ष 1975-76 में 283 हजार और पाँचवी योजना में 3568 हजार रुपया राष्ट्रीय आयोजनागत क्षेत्रों में जनपदीय योजना से वसुत से कार्यक्रम चलाये जायेंगे इस हेतु वर्ष 75-76 में 70 हजार रुपया अस्थागत तर्ज 2622 हजार रुपया जनपदीय क्षेत्र से प्रस्तावित किया गया है। पाँचवी योजना में यह परिव्यय क्रमशः 350 हजार और 2960 हजार रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 में राष्ट्रीय आयोजनागत क्षेत्र से 35000 तथा जनपदीय क्षेत्र से 340 हजार रुपया व्यय किया गया है।

पाँचवी योजना की सफलता के लिये जनपद में निम्न तिरिचत योजना का संचालन किया जाना नितान्त आवश्यक होगा, क्योंकि आगतक जनपद में इन योजनाओं का संचालन नहीं हो सका है। अतः राज्य सरकार के विचारार्थ निम्न तिरिचत सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-

- 1:- जनपद के लिये कृषि अनुसंधान संस्थान का होना नितान्त आवश्यक है जिसमें मिट्टी परिक्षण का कार्य कर कृषि क्षेत्र में अग्रसर हो सके।
- 2:- जनपद में एक प्रसार प्रशिक्षण केंद्र का होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें तकनीकी जानकारी, नदीय कृषि प्रणालियों की जानकारी, प्रसार कार्यकर्ताओं को कराई जा सके।
- 3:- जनपद के लिये क्षेत्रीय विकास योजना अद्वितीय कार्यक्रमित होनी आवश्यक है। इससे अधिक उत्पादन देने वाली फसलों से सम्पूर्ण क्षेत्र को अर्थवित्त किया जायेगा, जिससे पाँचवी पाँच वषीय योजना काल के अंत तक जनपद खाद्यान्नों में आत्म निर्भर हो सके।
- 4:- जनपद के लिये उर्वरक, बीज, उपकरण आदि के भुलान हेतु एक सरकारी गाड़ी का होना नितान्त आवश्यक है। आज तक विभाग के पास भुलान व्यवस्था हेतु वाहन उपलब्ध नहीं है।
- 5:- अभी तक साप्ताहिक उर्वरकों के भुलान पर बीज भंडार से विभिन्न केंद्र (ग्राम सेवक मुख्यालय) तक शत्रुतिरिचत राज सहायता दी जा रही है किंतु जनपद में कितने ही गाँव ऐसे हैं जो ग्राम सेवक मुख्यालय से 10 किलोमीटर के भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। आसपास के ग्रामीण सड़क उपलब्ध न होने के कारण उर्वरकों के गाँव तक भुलान पर किसान को काफी धन लगाना पड़ता है जिससे वह उर्वरक के उपयोग से ही हिचकता है।

अतः यह जान शक है कि राम सहायता कृषक के गाँव तक के दुलान पर मिलना चाहिये ।
इस प्रकार की सहायता फल पौधों, बीजों (विशेषकर आलू के बीज) आदि के दुलान पर भी
उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

(2) सिंचाई
=====

जनपद के उपसभाग स्व में केवल 3-9% भूमि तथा उपसभाग दो में 8-1% भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त है। इस प्रकार अब तक जनपद के 6-4% क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान सिंचाई प्रणाली में पानी का ह्रास बहुत होता है क्योंकि कि वर्तमान नहरों के बहुत से भाग कच्चे हैं। वर्षा ऋतु में मूसलन एवं भूमि के पलाय के कारण नहरों की क्षति पहुंचती है और उनके रख रखाव पर व्यय भी अधिक होता है। सुजित सिंचाई क्षमता का अभी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। वर्ष 1973-74 में राजकीय सिंचाई नहरों द्वारा कुल सिंचाई 614 हेक्टर हुई है जो प्रस्तावित सिंचित क्षमता का 85% है। प्रस्तावित सिंचित क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने के मुख्य कारण खेतों का समतल न होना तथा आवश्यकता अनुसार फिन्ड गूलों की कमी है। गत वर्षों में कुछ फील्ड मुलियां बनाई गईं जिनसे सिंचन क्षमता के द उपयोग में वृद्धि हुई है। नहरों से सिंचित क्षेत्र में पानी का इकठ्ठा होने की कोई समस्या नहीं है।

मुख्यतः खरीफ में धान की पाय के लिये और रबी में लगनी अवधि तक सूख की स्थिति रहने पर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जनपद के दोनो उपसभागों में सिंचाई क्षमता की दृष्टि से अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रसार होने की सम्भावनायेके मुख्यतः घाटी के क्षेत्रों में हैं। नहरों के सभादेश क्षेत्र में निजी सिंचाई कार्यों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

जनपद का समस्त क्षेत्र पर्वतीय है और भू विगत जल श्रोत उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे कृषि क्षेत्रों में जिनके सरीप वर्तमान नालों में जल उपलब्ध है और अभी तक वहाँ पर राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर परकीय नहरें प्रस्तावित की गई है।

जनपद में अलकनन्दा, पिण्डर, रामगंगा एवं मन्दाकिनी नदियों के किनारे कुछ ऐसे भूमि खण्ड है जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई करने की सम्भावनाये अच नहीं है तथा जहाँ पर नहरों के लायक जल श्रोत उपलब्ध नहीं हैं ऐसे स्थलों में प मीग सेट लगाने का ही योजना प्रस्तावित की जा सकती है। पंचम पंच वरिय योजनाओं में जनपद में दो डाल सिंचाई योजनाये (लिफ्ट सिंचाई योजनाये) बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1973-74 तक जनपद में निजी क्षेत्र में सात पियिंग सेट कार्यरत हैं। विकास अ नदेशणालय लखनऊ द्वारा गहौरा नामक स्थान पर एक हाई डूम योजना कार्यान्वित की गई है जिससे 15 हेक्टर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है जो इस ईकाई पर दो हाइड्रम रशीनों को समानान्तर रूप में जोड़कर एक साथ संचालित करके पानी उठाने तथा उसकी सिंचित क्षमता का अध्ययन करने हेतु पांचवीं योजना के परीक्षण लिये जाने का प्रस्ताव है।

जनपद में भूमिगत जल संसाधन नहीं हैं और न ही उनके संरक्षण का प्रश्न है। कुछ स्थानों में अवरुध बांध बनाकर वर्षा के पानी को रोकने से सब उसे सिंचाई हेतु उपयोग करने की सम्भावनाये हैं।

जनपद में सिंचाई के लिये वर्ष 1973-74 तक 98 किलोमीटर लम्बी 43 राजकीय नहरों बनाई गई हैं। इन नहरों तथा अन्य साधनों के माध्यम से केवल 2-04 हजार हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्रफल में सिंचाई सम्भव हो सकती है। यह क्षेत्र युक्त भूमि का 3-6% है। जनपद में उपलब्ध जल के उपयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त उपलब्धि नहीं हुई है। जबतक कृषि योग्य भूमि में अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक पैदावार में अधिक वृद्धि सम्भव नहीं हो पायेगी।

विगत पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित की गई राजकीय सिंचाई परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	पंचवर्षीय योजना	नहरों की लम्बाई (कि०मी०)	सी०सी०ए० (हेक्टर में)	सिंचाई के लिये (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (रबी)	सिंचाई के लिये कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
1-	प्रथम	27-800	512	77	154	231
2-	द्वितीय	50-535	734	110	221	331
3-	तृतीय	13-115	23	37	73	110
4-	चतुर्थ	5-700	85	19	33	52
योग :-		97-850	1575	243	481	724

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निजी सिंचाई साधनों द्वारा जनपद में 745 हे० तथा 304 कि०मी० लम्बी नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ जिससे जनपद के 1978 हे० क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्राप्त हुई।

इस क्षेत्र में वर्षा एवं वर्षा के कारण योजनाओं के कार्य को पूर्ण करने में काफी रुकावट आती है। निर्माण सामग्री भूखंड एवं अधिष्ठान की कमी के कारण योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में व्यवधान होता है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक जनपद के 1575 हेक्टर क्षेत्र को राजकीय सिंचाई साधनों एवं 1978 हे० क्षेत्र को अन्य निजी सिंचाई साधनों द्वारा सिंचाई सुविधायें प्राप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार कुल 3553 हे० क्षेत्र सिंचाई सुविधायों से लाभान्वित हो चुका है जो कि कृषि युक्त क्षेत्र का 6-4% है। वर्ष 1974-75 में राजकीय सिंचाई साधनों द्वारा 80 हे० सिंचन क्षमता का पूजन 1-25 कि०मी० लम्बी पर्वतीय नहर बनाकर किया गया। निजी साधनों से 38 हे० सिंचन क्षमता एक पम्पिंग सेट लगाकर और 6 कि०मी० नहर तथा 43 हे० जोड़ बनाकर सृजित की गई। इस प्रकार 118 हे० अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्रदान की गईं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद राज्य स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि उपलब्ध सिंचन क्षमता में लगभग 5% हास प्रति वर्ष हो

जाता है। इस दृष्टि से 1974-75 के अन्त में जनपद में 3-50 हजार 80 क्षेत्रफल के लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध रह गई हैं।

जनपद को अधिक सिंचाई सुविधायें प्रदान करने हेतु पंचम पंच वर्षीय योजना में

राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 35-5 कि०मी० लम्बी नहरें, दो डाल सिंचाई योजनायें तथा 2 9-6 कि०मी० लम्बी वर्तमान नहरों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है जिससे 0-42 हजार हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। इस के अतिरिक्त अन्य लघु सिंचाई साधनों द्वारा 847 हे० क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्रदान की जायेगी जिसे निजी सिंचाई साधनों के अन्तर्गत जनपद में 30 एम्पंगमेंट लगाकर और 155 कि०मी० भूत तथा 690 होज बनाकर प्राप्त किया जायेगा।

वर्ष 1975-75 में राजकीय सिंचाई योजना के अन्तर्गत 11-75 कि०मी० पर्यन्त

नहरें निर्मित करने का लक्ष्य है जिससे 60 हे० सिंचन क्षमता क्षीयत की जा सकेगी।

इस के अतिरिक्त निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा इस वर्ष 195 हे० सिंचन क्षमता 8 एम्पंगमेंट लगाकर 25 कि०मी० भूत और 150 होज बनाकर क्षीयत करने का लक्ष्य है।

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित राजकीय सिंचाई नहरों का विवरण

निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	नहर का नाम	नहर की लम्बाई (कि०मी०)	री० मी० (हे०)	सिंचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	री०	सिंचाई के लिये प्रस्तावित कुल क्षेत्र (हे०)
1-	2	3	4	5	6	7
1-	रोकोट	2-2	53-0	33-0	33-0	66-0
2-	अगठला	1-6	42-0	24-0	24-0	48-0
3-	नाला	7-0	150-0	64-0	64-0	128-0
4-	क्यैजा	2-4	30-0	20-0	20-0	40-0
5-	गिरसा	6-0	73-0	45-0	45-0	90-0
-	झीरी	0-9	18-0	5-0	8-0	13-0
7-	बहुवावाण	3-2	35-0	18-0	18-0	36-0
8-	घाँस गढ़	2-2	22-0	11-0	11-0	22-0
9-	हाट	2-0	16-0	11-0	11-0	22-0
10-	सीमान	2-1	27-0	12-0	12-0	24-0
11-	रासी	6-0	40-0	24-0	24-0	49-0
योग:-		35-6	517-00	247-6	270-6	538-0

आवक सिंचाई योजनाएं :-

1	2	3	4	5	6	7
1-	कोरगी	1-1	43	21-5	21-5	43
2-	तिलवाड़ा	1-6	36	18	18	36
योग :-		2-7	79	39-5	39-5	79

वर्तमान नहरों का आधुनिकरण :-

क्र० सं०	नहर का नाम	नहर की लम्बाई (कि०मी०)	वर्तमान सी०मी० ए० (हे० में)	आधुनिकीकरण के पश्चात् प्रस्तावित अतिरिक्त सिंचाई के लिये		आधुनिकीकरण पश्चात् प्रस्तावित कुल अतिरिक्त सिंचाई (हे० में)
				रबी	खरीफ	
1	2	3	4	5	6	7
1-	अमस्तदुनी	4-6	53	3	2	5
2-	जौरासी	1-6	13	2	2	4
3-	कोट	3-2	32	1	1	2
4-	भट्टनागर	3-4	43	4	4	8
5-	सिमली	7-2	93	2	2	4
6-	लांली	4-2	100	2	4	6
7-	दीग	5-4	89	2	2	4
योग :-		29-6	423	16	17	33

उपरोक्त ता. लिखा दशरत योजनाओं में गृह सर्वेक्षण के पश्चात् यदि कोई योजना तर्कनी दृष्टि से उचित नहीं पाई जाती है तब निम्नलिखित ता. लिखा में दशरत योजनाओं में से प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना की पूर्ति की दी जायेगी ।

क्र० सं०	नहर का नाम	नहर की लम्बाई (कि०मी०)	सी०मी० ए० (हे० में)	सिंचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्र		सिंचाई के लिये प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल
				रबी	खरीफ	
1	2	3	4	5	6	7
1-	देवपुरा की नहर	2-0	22	11	11	22
2-	इम्री	1-9	33	12-0	12-0	24-0
3-	गालकोट	1-5	13	6-0	6-0	12
4-	क्योर	2-5	20	12	12	24

1	2	3	4	5	6	7
5-	था मदेव	2-1	16	10-0	10-0	20-0
6-	पलासी	2-0	10	6	6	12
7-	खरीदाई विस्तार	1-2	40	20	20	40
8-	उरुकु	4-0	50	18	18	36
9-	पलदुवाडी	8-0	110	41	41	82
10-	असेर	4-5	60	30	30	60
11-	तेलो र	5-0	80	40	40	80
12-	ढाफ	3-0	40	15	15	30
13-	फलदिया	4-0	60	30	30	60
14-	त्रिकोट	1-0	16	8-0	8-0	16-0
15-	नलगॉव	1-5	20	10	10	20
16-	राजवटी	3-0	14	7	7	14
17-	ठैठाना	3-5	40	20	20	40
18-	मण्डल विस्तार	4-0	50	25	25	50
19-	सरिंगवाड	5-0	20	10	10	20
20-	थराली	2-0	20	10	10	20
21-	काण्डई	3-0	20	10	10	20
22-	वजकोट	2-4	20	10	10	20
23-	गवाड	3-0	30	15	15	30
24-	सीड	3-0	24	12	12	24
25-	कंडारी गवाड	2-6	32	16	16	32
26-	गसोली	1-0	12	6	6	12
27-	सलना	1-0	14	7	7	14
28-	रडूवा	1-2	40	20	20	40
योग :-		78-9	926	437-0	437-0	874-0

हाल लिफ्ट सिचाई योजनायें

1-	सुनाऊ	1-5	31	15-5	15-5	31
2-	शोनला	1-25	23	11-5	11-5	23
3-	सिकणी	0-90	20	10	10	20
4-	ठैठाना	1-20	18	9	9	18
5-	रियांसू	1-20	17	8-5	8-5	17
6-	हिनका	1-20	16	8-0	8-0	16
7-	हिसर बागडी	1-0	15	7-5	7-5	15

1	2	3	4	5	6	7
8-	जिला सू	1-0	14	7	7	14
9-	हरनी	0-30	12	6	6	12
योग :-		9-55	166	83-0	83-0	166

वर्तमान नहरों का आधुनिकीकरण
 कुल नहरों का नाम नहरों की वर्तमान आधुनिकीकरण के पश्चात आधुनिकीकरण के
 सं० लंबाई (कि०मी०) सी०मी० ए० वर्तमान के अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र (हे०मी०) पश्चात प्रस्तावित कुल अतिरिक्त क्षेत्र हे०मी०

1	2	3	4	5	6	7
1-	डमार	4-2	42	6	5	11
2-	पनई	1-8	81	4		4
3-	सारी दाई	4-6	22	4	2	6

योग:- 10-6 145 14 7 21

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि यहाँ पर सिंचाई विभाग का एक बृहद निरन्तर कार्य करता रहेगा ।

योजनाये जिनका लाभ एवं लागत का अनुपात एक से अधिक हो वे श्रोत्र से पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने की सम्भावना है ही तथा कास्तकार सिंचाई हेतु भी उत्सुक ही ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ।

प्रस्तावित राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं के लिये आठवीं योजना में 112 लाख रुपये और वर्ष 1975-76 में 11-40 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित है । वर्ष 1974-75 में 9-20 लाख रुपये परिव्यय के विपरित 2-02 लाख रुपये व्यय किया गया है । निजी लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना में 12-10 लाख रुपये और वर्ष 1975-76 में 2-0 लाख रुपये परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 1974-75 में 3-90 लाख रुपये निर्धारित परिव्यय के विपरित 3-41 लाख रुपये व्यय किया गया है । जिले के कुचवाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सिंचाई साधनों का निर्माण राजकीय श्रोत्रों पर ही आधारित है । विकास अनवशेषणालय लखनऊ द्वारा लगाये गये हाइड्रम के संचालन हेतु पांचवीं योजना में 87 हजार रुपये और वर्ष 1975-76 में 17 हजार रुपये परिव्यय प्रस्तावित है ।

राजकीय सिचाई योजनाओं की कार्यान्वयन सिचाई विभाग के मानकों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा कराया जायेगा। पश्चिमी योजना में प्रस्तावित कार्यों का पूर्ण करने हेतु लगभग 6 हजार टन सीमेंट एवं 55 टन लोहे की आवश्यकता होगी।

पंचम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने हेतु 70 हजार व्यक्ति दिन कुश्तु एवं 3 लाख व्यक्ति दिन अन्य श्रमकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार स्थानीय व्यक्तियों को जिविका कमाने का एक साधन उपलब्ध हो सकेगा।

भवनों की कमी, आवागमन की कठिनाई, आवश्यक वस्तुओं का अभाव रेलमार्ग से दूरी तथा यहाँ की जलवायु के कारण कार्य सम्पदान विशेषतः क्षेत्रीय कार्य में अत्यधिक कठिनाई होती है। जिसके कारण क्षेत्रीय कर्मचारी यहाँ आने से कतराते हैं। इस ^{कारण} में सहायक अभियन्ताओं को तथा अवर अभियन्ताओं की बहुत कमी है। कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये भवनों का निर्माण तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिये विशेष धन अथवा पुरस्कार देने का सुझाव है।

==== 0000 =====

* (3) भूमि संरक्षण *

=====

देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि खेतों में उन्नति को जाय, खेतों को दशा सुधारी जावे, पानी का प्रबन्ध ही तथा उन्नत विद्या के बोजों का प्रयोग किया जाये। मिट्टी के लुप्तकर वह जाने से भूमि को उर्वरा शक्ति दिन प्रति दिन कम होती रहती है, इसलिये अधिक अन्न पैदा करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि भूमि को उर्वरा शक्ति का ह्रास बचाया जाय। इसी उद्देश्य के अन्तर्गत मे भूमि एवं जल संरक्षण योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि को लुटाव को रोकना, जल का संरक्षण करना एवं भूमि को उर्वरा शक्ति को बनाने रखना है।

2 - इस जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9, 12, 800 हेक्टर है जिसमें से 55, 800 हेक्टर क्षेत्र में कृषि को जाय है। जल के प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति अन्तर्गत क्षेत्रों में भिन्न है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से नदियाँ हैं जिनमें से मुख्य नदियाँ अर्थात् अलकनन्दा, गन्दाकिनी, पिण्डर, राणगंगा, नन्दाकिनी आदि हैं। इन नदियों के कारण यहाँ पर बहुत गहरी छ गहरी घाटियाँ बन गई हैं, जिससे पहाड़ों को श्रृंखला अधिक दालू होने के कारण भू-लुटाव एवं भूमि के संरक्षण अधिक होता है। चौरस क्षेत्र बहुत ही कम है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव यहाँ पर उल्लेख है परन्तु उष्ण प्रचुरित जल प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जिसका मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक (टोपोग्राफी) स्थिति है। इस कारण यहाँ पर भूमि एवं जल संरक्षण को निम्नान्त आवश्यकता है।

3- जिले की कुल कृषि योग्य भूमि 55, 800 हेक्टर में से मात्र 3, 553 हे० भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध है। साधन सम्पन्न होने से यह क्षेत्र कृषकों द्वारा पहले से ही भूमि क्षति स्थिति का सामना कर रहे गये हैं जिसके कारण इस क्षेत्र पर भूमि संरक्षण प्रकृया अपनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इस जिले में भूमि संरक्षण के कोई साधन प्राप्त आसनें तो उपलब्ध नहीं हैं, फिलहाल अनुमानतः करीब 11, 175 हे० भूमि खोती है जिसमें भूमि संरक्षण विधियाँ अपनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, या अपनाने में कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसे भूमि यार्तों विलम्बित साधन है या बोज-बोज में पत्थर के बड़े-बड़े चट्टान निकल आते हैं। इस प्रकार 14, 723 हे० भूमि को छोड़कर जिले में कुल 41, 072 हे० भूमि वर्तमान में भू-संरक्षण कार्य के लिये उपलब्ध है जिसमें से चतुर्ष पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भूमि संरक्षण विभाग को वर्तमान एक इकाई द्वारा 1, 040 हे० एवं उक्त के डेट गुना क्षेत्र 14560 हे० सास्तिकारों द्वारा संरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में चतुर्ष पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 2, 600 हे० क्षेत्र उपलब्धित कर लिया गया है। अतः अगली पंचवर्षीय योजना में 38, 472 हे० क्षेत्र में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पादन की आवश्यकता होगी।

4- पंचवर्षीय योजना के अर्धे अर्धे में कृषि विभाग (भूमि संरक्षण अनुभाग) को एक इकाई द्वारा 1, 500 हे० क्षेत्र संरक्षित किया जायेगा। तथा अनुमानतः इसके डेट गुना क्षेत्र 2, 250 हे० में सास्तिकारों द्वारा इसमें भूमि संरक्षण का कार्य किया जायेगा। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में कुल 3, 750 हे० क्षेत्र संरक्षित किया जायेगा।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत् कुल 6,350 हे० क्षेत्र संरक्षित हो जायेगा ।

5- इस प्रकार पानी योजना के उपरान्त श्री जगज्जल का लक्ष्य 34,722 हे० क्षेत्र भूमि संरक्षण कार्य विधि अपनाने के लिये आरंभ रह जायेगा, जिसका संरक्षण अमली योजनाओं में कृषि विभाग तथा सामान्यारों के अपने प्रयास से किया जायेगा । इस प्रकार जिले की कृषिनीय भूमि को भूमि संरक्षण कार्य विधियों से संरक्षित कर अधिक उपज देने योग्य बनाया जा सकेगा । एक भूमि एवं जल संरक्षण इकाई द्वारा 300 हे० भूमि में प्रतिवर्ष भूमि संरक्षण को विधिगत अपनवाई जाती है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्न कार्य कराये जाते हैं ।

- (1) - फसलें पुस्तों का निर्माण ।
- (2) - जल नलोकन ।
- (3) - उद्गानोकरण ।
- (4) - बनोकरण ।
- (5) - चरागाह विकास ।
- (6) - बिछाई हेतु डीजे-जेटो जलियों का निर्माण ।

6- चतुर्ष पंचवर्षीय योजना :-

इस जिले में पारसुरत इकाई को स्थापना वर्ष 1968-69 में हुई थी और मार्च वर्ष 1969-70 में प्रारम्भ हुआ । स्टाफ कम होने के कारण प्रारम्भ में कार्य को प्रगति मन्द रही । चतुर्ष योजना काल को वर्ष वार प्रगति निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	इकाई	वर्षवार भौतिक प्रगति का वितरण	कुल योग			
1	2	3	4			
1969-70	1970-71	1971-72	1972-73			
1	2	3	4			
संरक्षित हेक्टर क्षेत्र	42	121-63	217-71	313-27	346-14	1,040-75

उपरोक्त पाँचों वर्षों में वर्तमान इकाई के द्वारा 1,040 हे० क्षेत्र संरक्षित किया गया और अनुमानतः इकाई हेतु गुना 1,560 हे० क्षेत्र सामान्यारों द्वारा संरक्षित कर लिया गया ।

सुर्ज पंच वर्षीय योजना में पाँच वर्षों में हुये व्यय का विवरण (विभाग द्वारा)
व्यय लाभ रूपों में

सं. क्र. योजना	वर्षवार व्यय का विवरण					योग
	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	
1- स्वयं	1-241	2-954	2-803	3-096	3-562	12-756

7- जनपद को सत्याग्रह दृष्टिकोण भूमि को देखने हुये जिले में हर विभाग क्षेत्र स्तर पर एक भूमि संरक्षण इकाई को स्थापना का विचार या लेखन घनाभाव के कारण वर्तमान एक भूमि संरक्षण इकाई से ओ पूरे पंच वर्षीय योजना काल में भूमि संरक्षण कार्य कराने का प्रभाव है । यह भी निश्चय किया गया है कि मार्ग अलखनन्दा एवं गन्दाकिनो के जल सफेट क्षेत्र में हो किया जावे । एम अगली योजना में अन्य नदियों के जल सफेट को लिया जावेगा ।

8- ~~अनुसूचित~~ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 1,500 है निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 के 300 है लक्ष्य के विपरित उपलब्ध 304 है रहो । वर्ष 1975-76 का भी लक्ष्य 300 हैक्टर है । पाँचवर्षीय योजना का विभागीय श्रोतों से वित्तिय लक्ष्य 1,223 हजार रुपया निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 का परिव्यय 391 हजार रुपया था और व्यय 567 हजार रुपया रहा । वर्ष 1975-76 के लिये वित्तिय लक्ष्य 2-42 लाख रुपया प्रस्तावित है । भूमि संरक्षण कार्य को औसत लागत 2,500 रुपया प्रति हैक्टर मानने हुये पाँचवर्षीय योजना में सम्पन्न किये जाने वाले कार्य को लागत मात्र 1,375 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 375 हजार रुपया व्ययों को वहन करना होगा ।

9- जनपद के नृशर्तों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ने अब तक भूमि संरक्षण के कार्य पर विभिन्न वर्षों में विभिन्न दरों से नृशर्तों को अनुदान के तौर पर सहायता दिया है । वर्तमान में यह अनुदान कार्य को लागत का आधा या एक हजार रुपया (1,000 रुपया) प्रत्येक एकड़ को कम ही की दर से देते हैं । वर्षों में कराने गये कार्य को लागत के अनुसूच शासन के घन उपलब्ध न हो जाने के कारण संपूर्ण कार्य पर अनुदान दे पाना सम्भव नहीं हो पाता है । भूमि संरक्षण कार्य कराने के लिये आसक्तियों को तत्कालीन तानोको ज्ञान देने के लिये विभागीय कार्यकर्ता जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं । जहाँ तक श्र को बात है उसे क्षेत्रीय जन समूह द्वारा नृशर्तों द्वारा पूर्ण कराने का प्रविधान किया गया है ।

10- जिले को सत्याग्रह क्षेत्रस्त को देखने हुये कार्य रत ~~इकाई~~ एक इकाई विभागा वार्षिक लक्ष्य 300 हैक्टर है , के द्वारा भूमि संरक्षण कार्य कराने में लगभग 150 वर्ष लग जायेगे । बिना तानोको देख रेख के क्या भूमि संरक्षण कार्य अधिन लोग तान नृशर्तों सिद्ध नहीं होगा ।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एन.डी.डी. का जमाकट में प्रत्येक विभाग
 क्षेत्र में एक संयुक्त रिजर्व फंड (सीएफ) को तैयार करके रखे जाये, जिस पर शासन
 द्वारा अनुसूचित जातों को आरक्षण करे जाये।

***** 0 0 *****

उहा परिशिष्टमें भी स्थान में रहने की शक्ति का समर्थन में लीज किना
संघ में का दृष्टि परिलक्ष्य करता है कि किने को लगे रहने की विषय पर शासन
द्वारा अनुसूचित जाति को अलग हो जाने है ।

***** 0 0 *****

यह विधिवत कार्य के अन्तर्गत क्षेत्र में कृषि की प्रकृति को ध्यान में रखकर कहीं अधिकतर क्षेत्रों में लागू करने के हैं। यहाँ की भूमि व जलसु विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। कहीं-कहीं पर पत्तियों में बाध का उत्पादन होता है, दूसरी ओर किन्हीं क्षेत्रों में उष्णता के कारण ही बाध रचना भी सब का उत्पादन सफलता पूर्वक किया जा सकता है। धाती के क्षेत्र में जून, १९०० से १९०० तक की उम्मीदें के क्षेत्र में ही प्रजातीय फलों व गुठलियाँ फलों के व १९०० से १९०० तक की उम्मीदें वाली क्षेत्र में उम्मीदें हेतु उपयुक्त हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यहाँ की अभाव सभी प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु सहाय है। इसी प्रकार यह क्षेत्र में भी सभी प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु ही सहाय है, अपितु यहाँ पर सबसे विशेषता अभाव में उम्मीदें जाने वाली कृषि की तथा सब की ही का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अन्त में यहाँ का उत्पादन सभी फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है, किन्तु प्रकृति उपयुक्तता में प्राथमिकता फलों के उत्पादन की अपेक्षा सहायता है।

विदेशी आकाश में पर्यटन क्षेत्रों में विशेष रूप से यहाँ पर उच्च फल में निरक्षरता द्वारा इस दिशा में कौटुम्बिक रीति-रिवाज क्षेत्रों में जा रहा विचार प्रणाली स्वतन्त्रता के उत्पादन में यादायात की अनुभवों के कारण हम क्षेत्र में भी व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाने जाते। अन्त में निरक्षरता के उत्पादन सहाय रूप में फल उपयुक्त कार्यक्रमों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। अन्त में यहाँ की क्षेत्रों के अन्त तक जिल में लगभग ४६०० हे० भूमि में फलोत्पादन तथा १२५० हे० भूमि में सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है। यह क्षेत्रों में जा रहे क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय योजना के अन्त तक फल में अन्त उत्पादन के फल का उत्पादन करके ५००० हे० तथा सब्जी ३७००-४०५५ में सब्जी है। अन्त में क्षेत्रों में १६०० हे० अन्त में उत्पादन का अनुमान है, जो पर्यटन योजना के अन्त तक क्षेत्रों में १३३०० व २५०० में टन हो पायेगा।

पर्यटन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में तथा उत्पादन वस्तु के समुचित विकास

... किन्तु ... निर्माण की पूर्ण उपलब्ध न होने से लक्ष्य को पूर्ण नहीं करे जासके। इस कमी को पूरा करने के लिए ... में ... निर्माण का कार्यक्रम अपनाया गया है। फल: स्वरूप वर्षी १९७४-७५ ३६ है। ... में ५ औद्योगिक स्तर का निर्माण किया गया। परीक्षा योजना फल में २०० है। ... की स्थापना का उद्देश्य है। उक्त कार्य हेतु तथा व्यापकता उद्योगों की स्थापना हेतु ... २२-२०० लाख रुपये के उद्योग कृपा का प्राविधान रखा गया है। वर्षी १९७४-७५ में १०० १-७० लाख तक की कृपा स्वरूप में कांटा गया। इस योजना के फल: स्वरूप सघन क्षेत्रों में फलोत्पादन को बढ़ावा देना तथा उत्पादन के विकास में क्षेत्र के उद्योगियों की सहजता मिलेगी।

२- फल उत्पादकों तथा शिक्षित क्षेत्रों के व्यक्तियों को उद्योग प्रोत्साहन :-

... औद्योगिक कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान संगठन एवं उत्तम फलों के उत्पादन के लिए आवश्यक है, अतः हुए औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन सेवा का होना आवश्यक है। ताकि उद्योगियों को आधुनिकतम सीधी से सहायता दी जाये। हमारे शिक्षित शिक्षित क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोजगार के अन्तर्गत सुलभ श्रम के उद्देश्य से भी औद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम की आवश्यकता समझी जा रही है। प्रोत्साहन की अवधि में फल उत्पादकों को एवं शिक्षित क्षेत्रों के व्यक्तियों को आवश्यक सेवा प्रदान रखा गया है। योजना फल में अल्प में २५०० व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। वर्षी १९७४-७५ में ४०२ व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। इस परियोजना पर ५८-७५ हजार रुपये व्यय हुआ।

३- फल परीप, सब्जों की बजारों, बाजारों तथा पौधे बजारों की एवं औद्योगिक लौहरी के वितरण पर राश सहजता :-

फल परीप, सब्जों की बजार, सब्जों की बजार तथा लौहरी बजार उपकरणों की उचित मूल्य में उत्पादकों को सुलभ कराने हेतु उक्त योजनाएँ रही हैं। कृषि जगत में यातायात की कठिनाई है व उत्पादकों को उक्त कार्य हेतु व्यवहार स्वयं भूषण करने में लक्ष्मी के स्थान पर हाथि होने की सम्भावना रहती है। उद्योग विकास के विस्तृत आधार को देखते हुए इस परियोजना का हीनकालीन परिष्कार में महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्षी १९७४-७५ में १०-१५ लाख रुपये

६०- पौधों का प्रसारण :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधों की योजना साल में २२०० है। अतिरिक्त कोव को उद्यान के अन्तर्गत लाया जायेगा। इसी तरह २०० है। सब्जी के अन्तर्गत २२०० है। पौधों का प्रसारण के अन्तर्गत लाया जायेगा। वर्षी १९७४-७५ में २०४ है। इस योजना में उद्यान लाये गये और ६० है। अतिरिक्त कोव में सब्जी उद्यान का और ३०४ है। भी कीट रक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। वर्षी १९७५-७६ में ४५० है। भी उद्यान लाये ३५ है। अतिरिक्त कोव में सब्जी उत्पादन तथा १२०० है। उद्यानों में, सिटापुञ्जी के रोन्धान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीमारियों के रोकथाम करने के उद्देश्य से विनाश लवट धरती, जोशीमत एवं अण्डरमती में फसल रक्षा के उपाय, उपाय तथा विपत्तियों के एक एक लवट वल उपायों की रचना का प्रस्ताव है। वर्षी १९७५-७६ में केवल में इसी योजना की जायगी है। इसके अतिरिक्त ४ पुर में सब्जियों में एक एक अतिरिक्त परियोजना की योजना शुरू करनी गयी है। योजना साल में २१ परियोजना शुरू की जायेगी प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्षी १९७५-७६ में २४ हजार रु. का व्यय हुआ।

६१- पौधों की उद्यान प्रसारण :- इस कार्यक्रम में उद्यान शुरू से निर्धारित योजना के अन्तर्गत वर्षी उद्यान उपायों की रचना का नाम रखा गया है।

६२- कल संरक्षण, फसल एवं टिकवा पत्तों तथा पुष्पों का रक्षण का विस्तार :- पौधों के अतिरिक्त कोव में उद्यानों के विकास का प्रस्ताव है, जिसमें कुल रु. १००००० का व्यय करीब का अनुमान है।

६३- विपत्तियों के रक्षण के लिये उपायों का कार्यक्रम :- उद्यान विकास को उपाय उपाय का उचित प्रचार किया जाये है। मुख्य मुख्य उपायों के अन्तर्गत मात्र दो है। यह योजना अतिरिक्त कोव में प्रस्तावित है।

६४- पौधों की उद्यानों में अतिरिक्त उपायों को उपाय विस्तार करने हेतु पौधों का विकास :- उद्यान के अतिरिक्त कोव में उपाय विस्तार हेतु पौधों के विकास की योजना है। पौधों के अतिरिक्त कोव में १०० उपायों को उपाय विस्तार किया जायगा। इस कार्य हेतु पौधों की योजना में रु. १००००० का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

20 - भारतीय क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्यिक कारीगरों का समन्वय :- विनास क्षेत्र
सर्व विनास क्षेत्र में पहले हुए उद्योग कारीगों मजदूर रहते हुए अब यह क्षेत्र
अनुभव की जा रही है कि अतिरिक्त कारीगरों तकल का रूप जैसा ताकि जिता स्तर
सर्व विनास क्षेत्र स्तर से गुणस्तर का व्यापक व सश्रित ढंग से योजाई जाय विनास
की आसके। इसी उद्देश के पूर्ण हेतु परिवर्तित योजना काल में उक्त योजना प्रस्तुत
वित है।

20 - सप्त उपाय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की स्थापना :- सप्त क्षेत्रों में कृषि की
सहायता की पूर्ण रूप उत्पादित वस्तु के समुचित विनास एवं स्तर पर लभ्यते
उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश से नई इकाईयों स्थापित की
जायगी।

21 - भारतीय क्षेत्रों में उत्पादित पदार्थों के संग्रह हेतु शीत गृहों का विनियोग :- गत
योजनाओं में अल्पोपलब्धताओं के फलत में अनेक गांवों में शीत गृहों के संग्रह की
समस्या उत्पन्न होती चली आ रही है। अतः शीत गृहों का विनियोग व फल
के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश से मुख्य मुख्य फल उत्पादन वाले क्षेत्रों में
शीत गृहों के निर्माण की योजना रखी जाती है ताकि उत्पन्न हुए फल तंतु संग्रह
कर उसका मूल्य प्राप्त होसके। जिस हेतु अल्पोपलब्धता का प्राविधान परिवर्तित
योजना काल में रखा गया है।

22 - भारतीय कृषि शोध परिषद के सहयोग में चलने वाली परियोजनाओं के व्यय
का 25 प्रतिशत व्यय :- भारतीय कृषि शोध परिषद, भोपाल तथा भारतीय
श्री फलों के व्यापक उत्पादन एवं संरक्षण हेतु इत्यादि हेतु उक्त योजनाओं को कारुण्य
दान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कुल मिलाकर 1954 प्रतिशत स्तर पर
कर शेष 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार से अर्जित करता है। इस उद्देश की पूर्ति
हेतु अल्पोपलब्धता का प्राविधान परिवर्तित योजना काल में रखा गया है।

संसाधनों का प्रयोग :- परिवर्तित योजना में 1954-55 तक 100 करोड़ रुपए का
परिव्यय विभागीय संसाधनों से उक्त व्यय होता है। वास्तविक तथा कालोपायी कार्य
कर्मा के लिए वर्ष 1954-55 में 22.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार से तथा 22-3
हजार रुपए केन्द्र द्वारा पुरोन्मोदित प्रकल्प के अन्तर्गत विधिवित परीक्षण के

25) पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन

जनाद चण्डी हिमालय के पर्वतवर्ती क्षेत्र में है और अधिक शीत क्षेत्र विकट पर्वतो एवं घाटियों से भरा हुआ है। जनाद में प्राकृतिक वन, सर्पण की अधिकता है, जिसका क्षेत्रफल 4,96,000 हैक्टर है तथा पानी के पर्याप्त अभाव उपलब्ध है।। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक चारागाह उपलब्ध है जिसका क्षेत्र अनुमानतः 25,800 हैक्टर है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जनाद में पशुपालन कार्य स्थापित करना अधिक है, जिसमें भेड़, बकरी, कुकुर एवं कुत्तर पशु उल्लेखनीय है।

जनाद के पशुपालन सम्बन्धी अद्यतन आँकड़े निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	भेड़		बकरी		कुत्तर
	कुल	प्रजननयोग्य	कुल	प्रजननयोग्य	
1961	1,78,000	58,000	43,000	15000	87,000
1966	2,16,000	80,000	57,000	40,000	1,25,000
1971	2,40,000	1,00,000	65,000	50,000	1,27,000

2- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनाद में निम्नलिखित संस्थाएँ कार्यरत रही हैं:-

- 1:- विज्ञानिक अभियान केंद्र 37
- 2:- भेड़ प्रक्षेत्र 1
- 3:- भेड़ केंद्र 15
- 4:- बकरी प्रक्षेत्र 1
- 5:- कुकुर प्रक्षेत्र 1
- 6:- कुकुर प्रजनन इकाई 1
- 7:- चारा प्रयोगशाला 9
- 8:- पशु चिकित्सालय 9
- 9:- सचल पशु चिकित्सालय 1
- 10:- पशु सेवा केंद्र 17
- 11:- रोग निरीक्षण केंद्र 1

38- उक्त संस्थाओं के कार्यरत होने से ही की कार्यरत समय में जनाद में निम्न कार्यवाही करी हुई है:-

अ- पशु प्रजनन क्षेत्र में जहाँ तक सम्भव है उसे समस्त प्राथमिक पशुओं के प्रजनन की सुविधा उपर्युक्त है।

ब- वृत्तीय प्रजनन द्वारा प्रजनन सुविधा पर कार्य है।

ग- कुकुर क्षेत्र में कुत्तों को प्रजनन करने के लिये जनाद में कोई बड़ा प्रक्षेत्र नहीं है।

द- पौष्टिक रीव उन्नत किसिम के चारे का अभाव है।

घ- बुगियालों के विकास की ओर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

चुं किन्तु पशु उन्नति के निमित्त रीव बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये जो

सुविचारों जनपद में उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अतः कार्यरत स्थितियों के जनपद में लक्ष्य चलाये रखने की आवश्यकता है।

अब तक के प्रयासों के बावजूद भी जनपद में पशुधन के लिये पर्याप्त प्रजनन सुविचारों उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान जनसंख्या को देखते हुये मांस, अण्डा रीव दुग्ध उत्पादन प्रति वर्ग प्रति न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नहीं है। जिले की औद्योगिक आवश्यकता को देखते हुये ऊन का उत्पादन भी कम है, क्योंकि प्रति वर्ष अन्य जिलों से ऊन का आयात करना पड़ता है। कारणों को देखते हुये उपरोक्त स्थितियों में वृद्धि का होना नितान्त आवश्यक है।

4:- दीर्घकालीन योजनाएँ

जनपद में जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुये 1978-79 में 3-28 तथा 1988-89 में 3-71 लाख जनसंख्या हो जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार से पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। अतस्व जिले में मांस, अण्डा तथा दुग्ध की मांग भी साथ साथ बढ़ती जावेगी। स्थानीय जनता की वार्षिक उन्नति के लिये ऊन पर अधिक आधारित औद्योगिक इकाई खूलीगी। इसके लिये कच्चे माल की स्थानीय पूर्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन पशुपालन कार्यकर्ताओं की स्पर्धा संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

अ- दुग्ध पालन तथा पशु प्रजनन के क्षेत्र में दो विदेशी उन्नत नस्ल के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किये जावेंगे जिन पर 164-360 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रति प्रक्षेत्र पर 400 गाये तथा 6 सड़ि रखे जावेंगे, जिनसे प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल के सड़ि रीव दुग्ध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध की जा सकेगी।

ब- जनपद के पशुपालकों में उन्नत नस्ल के कुशल पशुपालन हेतु 3-00 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जावेगा।

स- जनपद में 8 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 8 उप केन्द्र स्थापित किये जावेंगे, जिससे प्रजननात्मक कार्य में सुविधा हो सके। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अगस्त्यानि में स्थापित किया जावेगा, जिस पर 0-318 लाख का व्यय अनुमानित है। उप केन्द्र ऊर्जापट, लटा, रामपुर, गुप्तकासी, चन्द्रपुरी, भीरी, लहौरा में स्थापित किये जावेंगे, जिन पर मान्यतः 0-360 लाख खर्चा व्यय होगा।

द- दो बैल प्रक्षेत्र सिरसी (पट्टा)) रीव उर्गम नगर स्थानों पर स्थापित किये जावेंगे, जिन पर 60-00 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

घ- उपरोक्त बैल प्रक्षेत्रों की स्थापना हो जाने पर उन्नत नस्ल के बैलें उपलब्ध होंगी, जिनसे प्रसार कार्य को सुचारु रूप में कार्यान्वित करने हेतु 9 बैल केन्द्रों की स्थापना की जावेगी। इन केन्द्रों की स्थापना हेतु 3-60 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

रक वृद्धियों से जनन वृद्धि हेतु 20 करोड़ की अंशदान पर वितरित किया जायेगा, जिन पर 0-0.50 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

ल- कुक्षुण संरक्षण विधायक के अधीन निर्माता हेतु 2 वड़े कुक्षुण प्रवेश स्थापित किये जायेंगे, जिन पर 7-902 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। उक्त प्रवेशों की स्थापना हो जाने पर राष्ट्रीय स्तर से चुकी का उत्पादन, बाकी का उत्पादन रीव छाने के उद्देश्य हेतु कागलस विज्ञानों की दृष्टि से होये। उक्त उद्देश्य स्थापन निपतकियों रीव नवीकरण में स्थापित किये जायेंगे।

व- पशु चिकित्सा रीव उद्योग की दृष्टि से जनपद में एक सचल पशु - चिकित्सालय, एक पशु चिकित्सालय तथा 15 पशु सेवा केंद्र स्थापित किये जायेंगे, जिन पर क्रमशः 0-260, 2-595 तथा 1-680 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। सचल पशु चिकित्सालय, गोरेखर में, पशु चिकित्सालय, प्रोबलकोटी में तथा पशु सेवा केंद्र निम्न स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे -

पासी, छिन्का, कैकोट, नैग, कौरी, कैली, डुरा, शिसतोली, तने, कान, बौ, जहूरी, शिवपुर, कोटगा, देहा, सूरप्रयाग, वगैरह।

घ- सूअर विनाश की दृष्टि से वर्तमान समय में जनपद में कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं है। अतः 50 सूअरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पिछड़े वर्गों के लोग सूअर पालन व्यवसाय में उन्नीत कर अधीनस्थ हो सकें। इस योजना पर 0-200 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

5- उद्योग रीव रणनीति

अधिक अच्छे पोषण तकनीकी सुविधाओं की प्राप्ति के लिये खाद्यों की उपलब्धि करना।

अ- खेती के कार्यों के लिये उचित बल उपलब्ध करना (संसाधन व श्रमिकों के लिये) की उपलब्धि करना।

ब- व्यापारिक उत्पादन जैसे ऊन, चाड़ा तथा गन्ना इत्यादि के लिये अधिक प्रयास करना व- कुषुणों के लिये सहायक व्यवसाय और पुरक आय की व्यवस्था करना।

घ- प्रजनन, रोग निरोधक और जनपद में उत्पादन क्षमता में सुधार लाना।

6. पंचम पंचवर्षीय योजना

पंचम योजना काल में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न योजनायें विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं और आज की जाती हैं कि इतने पशु जनित पदार्थों के उत्पादन, पशुपालकों की आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और राष्ट्रीय जनता के रहन सहन का स्तर ऊँचा हो सके।

13- पशु प्रजनन रीव उद्योग

1966 की पशु प्रजनन के अंशदान पर जनपद में 80,000 गाये रीव 40,000 भैंस प्रजननालय के अंतर्गत हैं, जिनमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में 37 वैज्ञानिक अभियान केंद्र जनपद में हैं। प्रजनन रीव उद्योग रीव पंचम योजना में यह प्रयास है कि जनपद में प्रजनन रीव माताओं के 40% रीव रीव गैरित किया जाये। इसके लिये निम्न

योजनाय विभाग द्वारा अनुमोदित है:-

63

(अ) नैसर्गिक अभयारण्य क्षेत्रों की स्थापना:- पंचम योजनाकाल में एक 1-991 लाख रुपये के व्यय से तीन क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। उक्त क्षेत्र मयकोटी, देवाल रैंड नलपूरा स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में एक क्षेत्र मयकोटी में स्थापित किया जा चुका है।

(ब) कृत्रिम गर्भधारण क्षेत्र की स्थापना:- पंचम पंचवर्षीय योजना में एक द्विचम गभधारण क्षेत्र तथा 6 उच्च क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में एक क्षेत्र स्थान कर्णप्रयाग में तथा 4 उच्च क्षेत्र स्थान आदिवप्री, तिमली, गौचर तखर नगरापुर में स्थापित किये गये हैं। दो उच्च क्षेत्र लंगसु व नौली में स्थापित किये जायेंगे।

(स) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र:- अनुमानतः जनपद में प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 520 क्विण्टल है, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 170-00 मिलीलीटर उपलब्ध होता है रैंड पर्याप्त मानक दृष्टि से न्यून है। पंचम योजनाकाल में लक्ष्य रखा गया है कि प्रति व्यक्ति को 210 मिलीलीटर दुग्ध प्रति दिन प्राप्त हो। इस हेतु एक जर्सी स्तरीय की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जो कि दुग्ध के साथ उन्नत नस्ल के बछड़े भी अभयारण्य कार्य हेतु देगा। इस प्रक्षेत्र पर 300 गाँवों रैंड 6 हीड रखे जायेंगे जिस पर 67-85 लाख रुपये व्यय होगा। कार्य स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक कार्य वर्ष 1974-75 में शुरु हो गया है और 1 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

2:- भैड़ रैंड ऊन विकास

जनपद में इस समय 1,27,000 भैड़े तथा 98,000 बकरियाँ हैं। जनपद में तेरह मेढा क्षेत्र उपलब्ध है, जिन पर 354 भैड़े फार्मरत हैं। स्थानीय भैड़ों की ऊन तथा घाँस भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रजनन हेतु विदेशी भैड़े, विदेशी क्राइप्रीड भैड़े तथा रामपुर मुसादर भैड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। जनपद में भैड़ बकरी विकास हेतु 3 भैड़ प्रक्षेत्र तथा एक बकरी प्रक्षेत्र कार्यरत है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1050 भैड़े रैंड बकरें उपलब्ध होते हैं। इस समय अनुमानतः प्रति भैड़ 600 ग्राम रूज पर्यन्त प्राप्त होते हैं। पंचम योजना में प्रयास किया जा रहा है कि ऊन की मात्रा प्रति भैड़ 1-00 किलो वार्षिक प्राप्त हो तथा घाँस के उत्पादन में वृद्धि हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न योजनाएँ अनुमोदित हैं:-

(अ) भैड़ रैंड ऊन प्रसार केन्द्रों का विस्तार रैंड नये केन्द्रों की स्थापना:- 4-665 लाख रुपये की लागत से वर्तमान मेढा क्षेत्रों की भैड़ रैंड ऊन प्रसार केन्द्रों में परिवर्तित किया जावेगा। वर्ष 1974-75 में एक केन्द्र का निर्माण को भैड़गाँवों पर पत्तों की व्यवस्था की गई तथा 40 विदेशी भैड़े जनपद में उपलब्ध कराये गये।

(ब) मांस इंसिडिंग:- भैड़ प्रजनन में मांस इंसिडिंग का विशेष महत्त्व है। पंचम योजना काल में भैड़ों में मांस इंसिडिंग हेतु 8-595 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। वर्ष 1974-75 में 42,000 भैड़ों में मांस इंसिडिंग करने हेतु 8-119 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसे शतप्रतिशत उपयोग कर लिया गया।

(स) शिशुान पर बकरा लाने का विस्तार:- पंचम योजना काल में बकरियों में शिशुान हेतु बकरी मातृकों के बीच शिशुान पर विस्तारित किये जायेंगे, जिस पर 0-120 लाख

स्मरण व्यय होगा। वर्ष 1974-75 में 28 टकरे बंटे गये, जिस पर 0-037 लाख रुपया व्यय हुआ।

द-छ- सघन भेड़ विकास योजना :- जनपद में भेड़ पालन व्यवसाय को उन्नत एवं प्रचुर करने हेतु एक सघन भेड़ फार्म की स्थापना यकू(उरवीगठ)में प्रस्तावित है जिस पर 33-212 लाख रुपया व्यय होगा। इस योजना पर वर्ष 1974-75 में 20 हजार रुपया व्यय करके भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

घ:- भेड़ परिजैतिक इकाई:- भेड़ एवं उन विकास योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वयन करने हेतु एक भेड़ परिसरगत इकाई की स्थापना की जावेगी, जिस पर 1-369 लाख रुपया व्यय होगा।

च:- भेड़ों की उत्कृष्ट करने की योजना:- भेड़ों की उत्कृष्ट करने हेतु 4 केंद्र स्थापित किये जायेंगे, जिस पर 1-631 लाख रुपया व्यय होगा।

ल:- भेड़ एवं उन प्रसार केंद्र:- 66-228 लाख रुपया की लागत से जनपद में 9 भेड़ एवं उन प्रसार केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

व:- जीप की व्यवस्था:- उक्त योजनाओं की भली भण्ति पर्यवेक्षण हेतु जीप की व्यवस्था का प्राविष्टान है, जिस पर 0-665 लाख रुपया व्यय होगा।

झ:- विदेशी भेड़ों की खरीद:- भेड़ फार्मों पर उन्नत नस्ल के भेड़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु योजना बाजार से विदेशों से भेड़े खरीदी जावेगी, जिस पर 2-575 लाख रुपया व्यय होगा।

3- कुकूट विकास :-

=====

कुकूट पालन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु अब तक जनपद में 5 कुकूट प्रसार केंद्र तथा एक कुकूट प्रदर्शन इकाई उपलब्ध है। कुकूट पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण तथा अनुदानित दर पर कुकूट का आहार उपलब्ध कराया गया तथा हरिजनों को चुने हुए करने एवं इनके लिये चुना बनाने हेतु आवास गृह व्यवस्था की गई। इस पर अनुदान:- अनुदानतः 10-5 लाख अंडों का वार्षिक उत्पादन है और कुकूट-रक्त पक्षियों की संख्या 15000 है। पंचम योजना काल में अण्डा उत्पादन का लक्ष्य 136-00 लाख रखा गया है जिससे प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक अण्डा उपलब्ध हो सके। इस हेतु पंचम योजना काल में कुकूट पक्षियों की संख्या 1700,000 प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त उद्देश्य को प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा निम्न योजनाएं अनुमोदित हैं:-

अ:- कुकूट पक्षियों का पुनर्गठन एवं नये पक्षियों का स्थापना:- योजना काल में कार्यरत 5 कुकूट प्रसार केंद्रों में कुकूट पक्षियों में पुनर्गठन किया जायेगा तथा स्थान योगेश्वर में उक्त कुकूट प्रसार स्थापित किया जायेगा जिस पर कुल 8-000 लाख रुपया व्यय किया जावेगा। इस योजना को सफल बनाने हेतु 200 पक्षियों को कय किया जावेगा तथा 70-470 चूकों के उत्पादन का लक्ष्य है।

वर्ष 1975-75 में इस परियोजना के अन्तर्गत 2-62 लाख रुपये-समकालिक निर्माण विभाग की गाँवों में कुकुट प्रक्षेत्र के निर्माण हेतु प्रविष्टित किया गया है।

क- पुष्पाहार कार्यक्रम :- योजना काल में 0-198 लाख रुपये पुष्पाहार कार्यक्रम का रकम पर व्यय किये जायेंगे। इसके लिये जनपद में 9 वि.कास क्षेत्र लिये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में यह कार्यक्रम थाली विकास रचना में प्रारम्भ किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत 180 व्यक्तियों को कुकुट प्रशिक्षण दिया जायेगा और 3600 बूँदें वितरित किये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में 20 व्यक्तियों प्रशिक्षित किये गये और 400 बूँदों का वितरण किया गया।

ख- कुकुट आहार परिवहन व्यय पर अनुदान :- योजना काल में 4700 क्वीटल कुकुट आहार वितरित किया जायेगा, जिससे 11,280 व्यक्तियों लाभान्वित होंगे। योजना पर 1-0600 लाख रुपये व्यय किया जायेगा। वर्ष 1974-75 में इस कार्यक्रम पर 1-04-0-15 रुपये व्यय करके 123 क्वीटल आहार वितरित किया गया।

*** ख 4 - चारा विकास ***

जिले में लगभग 25800 हेक्टेयर भूमि में खाई चारागाह उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 13943 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बंजर के अन्तर्गत है। चारा विकास के दृष्टिकोण से कृषि योग्य बंजर भूमि इस कार्य में ली जा सकती है, जिसपर उन्नतशील चारे चारे का बीज बोकर पशुधान के लिये उन्नतशील चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में चारा बीज वितरण, जिले आधिग के प्रदर्शन तथा चारा प्रदर्शनों द्वारा चारा उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किये गये हैं :-

अ- चारा बीजों का वितरण :- जनपद में 282 हेक्टेयर भूमि पर चारा-उत्पादन हेतु 0-338 लाख रुपये की लागत से चारा बीजों की वितरण किया जायेगा। वर्ष 1974-75 में 50 हेक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम सलाया गया जिस पर 0-060 लाख रुपये व्यय हुआ। वर्ष 1975-76 के लिये 58 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है।

ब- चारा प्रदर्शन :- योजना काल में 50 चारा प्रदर्शन किये जायेंगे जिससे पशुपालक लाभान्वित होंगे। प्रदर्शन हेतु कुल 0-010 लाख रुपये व्यय होगा। वर्ष 1974-75 में 10 प्रदर्शन किये गये जिस पर 0-002 लाख रुपये व्यय हुआ।

66

5:- रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा कार्य :-

विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का है। निम्नलिखित लक्ष्यों के अनुसार सभी विकास स्तरों में पशु चिकित्सा लय उपलब्ध है। परन्तु फिर भी कुछ स्थानों में पशु चिकित्सा लय एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना विषयक कार्य बराबर आ रही है। सम्बन्धित राज्यों एवं स्थानों की विधित्त को देखते हुये निम्न प्रस्ताव योजना में सम्मिलित है:-

अ:- पशु चिकित्सा लय का प्रांतीयकरण :- वर्णप्रभाग में पशु चिकित्सा लय जिला परिषद द्वारा संचालित है, जिसे प्रांतीयकरण हेतु योजना में 0-879 लाख खर्चा व्यय किये जाने का प्राविधान है।

ब:- संचल इकाई की स्थापना :- जनपद के बेहड़ क्षेत्रों जहां से पशु चिकित्सा लय की सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है रोग नियंत्रण हेतु 1-445 लाख खर्चे के व्यय से एक संचल पशु चिकित्सा लय की स्थापना की जावेगी। इस इकाई का मुख्यालय स्थान देवाल में होगा।

स:- अतिरिक्त दवाई तथा औजारों की व्यवस्था :- जनपद के 3 पशु चिकित्सा लयों पर अतिरिक्त दवाई तथा औजारों की व्यवस्था का प्राविधान है। इस हेतु 0-300 लाख खर्चा व्यय किया जावेगा। यह योजना पशु चिकित्सा लय चणोली, अगस्तदुनी एवं थराली में कार्यान्वित की जावेगी।

द:- पशु चिकित्सा लयों के भवनों का निर्माण :- 2-444 लाख खर्चे के व्यय से पशु चिकित्सा लय थराली के भवन का निर्माण किया जावेगा।

य:- पशु चिकित्सा लय के कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण - 0-056 लाख खर्चे के व्यय से एक निम्नलिखित लय अगस्तदुनी के कार्य किया जावेगा। रि.म. के तहत आवासीय भवनों का निर्माण किया जावेगा।

6:- छोटे तथा छोटे हीन कृषकों की सहायता :-

जनपद के 295 छोटे एवं 295 छोटे हीन कृषकों को क्रासब्रेड बच्चों की पालने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जावेगी जिस पर क्रमांक 3-960 व 3-960 लाख खर्चा व्यय होगा।

7- प्रदर्शनीयां एवं प्रचार

जनता में पशुपालन के प्रति जागरूकता लाने के लिये प्रदर्शनीयों का आयोजन

किया जावेगा।

अ- तहशील स्तर पर योजना काल में 5 पशु एवं कुकूट प्रदर्शनीयां आयोजित की जायेगी, जिस पर 0-015 लाख खर्चा व्यय होगा।

ब- इसी प्रकार जिला स्तर पर एक भेड़ एवं ऊँट प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। कुल 5 प्रतियोगिताएँ 0-05-0-015 लाख खर्चा व्यय से आयोजित होंगे।

8- स्वास्थ्यकीय प्रशिक्षण एवं प्रशासन :-

विभागीय कार्यकलापों के कार्यान्वयन, उपलब्ध एवं प्रगति विवरण के ररव ररवाव हेतु निम्न लिखित योजनाये प्रस्तावित की गई हैं :-

अ- लेखा अनुभाग का सुदृढीकरण :- जनपद में चल रहे पशुपालन कार्य कलापों पर होने वाले व्यय के लेखों के सुदृढीकरण हेतु एक इकाई की स्थापना की जायेगी जिस पर 0-068 लाख खर्चा व्यय होगा।

ब- नियोजन कक्ष की स्थापना :- पशुपालन कार्यक्रम के प्रगति विवरण के ररव ररवाव हेतु एक इकाई की स्थापना की जायेगी, जिस पर 0-142 लाख खर्चा व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्यकलापों के संचालन हेतु पाँचवी योजना का परिव्यय 212-24 लाख खर्चा वर्ष 1975-76 का परिव्यय 17-47 लाख खर्चा राज्य आयोजनागत श्रोत से निर्धारित किया गया है। वर्ष 1974-75 में 6-17 लाख खर्चे का परिव्यय ररवा गया था जिसके विपरीत 2-27 लाख खर्चा व्यय हुआ।

सहकारिता तथा निजी क्षेत्रों में पशुपालन योजनाओं का सम्पादन

किया जाना :-

उपरोक्त पंचवर्षीय योजना में बौध्दिक तर्कों की पूर्ति पशुपालन विभाग द्वारा की जानी है। कुकूट एवं पशुपालन योजनाओं के संचालन हेतु निम्न लिखित है, निजी एवं सहकारिता के आधार पर संचालन करने का प्रयास किया जायेगा।

अ- कुकूट इकाईयों की स्थापना :- निजी क्षेत्र में 6 कुकूट इकाईयों की स्थापना किया जायेगा जिस पर 1975-76 का खर्चा व्यय होगा।

ब- ऊँट क्रय केंद्र :- जनपद में 4 ऊँट क्रय केंद्र सहकारिता के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

सः- जनपद के 50 भेड़ पालकों को यो जना काल में 2-000 लाख रुपये का ऋण संध्यागत वित्त के माध्यम से वितरित किया जावेगा, जिससे भेड़ एवं उन विकास कार्य-क्रम में अधिक प्रगति होगी।

दः- जनपद के 250 पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु खरीद कर ऋण के रूप में वितरित किये जायेंगे। इस हिसाब 3-00 लाख रुपये के ऋण का प्राविधान व्यवसाय बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित है। इस प्रकार व्यवसाय बैंकों के माध्यम से 5-30 लाख रुपये ऋण की व्यवस्था की जावेगी जिससे निजी क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को संचालित किया जावेगा।

9:- कार्यचारियों की व्यवस्था :-

उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन होने पर कार्यालय के कार्य में वृद्धि होगी तथा अतिरिक्त कार्यचारियों की आवश्यकता पड़ेगी एवं प्रशिक्षित तकनीकी कार्यचारियों द्वारा ही योजनाएँ सफल हो सकेंगी। अतः निम्न अतिरिक्त कार्यचारियों का प्राविधान किया जाना आवश्यक है :-

तकनीकी :-

1:- प्रभारी अधिकारी	3
2:- भेड़ निरीक्षक	1
3:- डुबुट निरीक्षक	1
4:- चारा निरीक्षक	1
5:- पशु चिकित्सक	2
6:- पशुपाल	8
7:- प्रमुख दूरदर्श केंद्री के कार्यकारी	30
8:- प्रधान लिपिक	1
9:- सहायक लिपिक	1
10:- नेष्ट लिपिक	2
11:- क्लर्क लिपिक	1
12:- चपरासी	1
13:- चौकीदार	1
14:- जवाकर	1
15:- जीप चालक	1
16:- ट्रक चालक	1

10:- यो जना का संचालन हेतु संसाधनों की आवश्यकता, उनका जुटाया जाना तथा राशि उपलब्ध होना आदि बातों का ध्यान रखना :-

पशुधन संध्या की निरंतर वृद्धि हेतु चरानुसंधी की कमी होती जा रही है, जिससे पशुपालक, श्रेष्ठ नस्ल प्रदान कराया न जा सके के कारण पशुधन को बढ़ावा देने में बाधा पड़ती है। इसलिये जनपद में पशुधन विकास योजना

निम्नलिखित प्राकृतिक चरमाह - दुर्घटना तत्काल सुदृढीकरण करना अनिवार्य है। इस हेतु उसके उर्वरक एवं रेरबाड़ की व्यवस्था की जावे।

ब- जनपद में सतृप्त आहार के निर्माण का उपयोग न होने से पशुधन के लिये पोषिक आहार की अति आवश्यकता नहीं है अतः जनपद में पोषिक पशुधन आहार के निर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना की जावे।

स- विधानीय कार्यों की सुचारु रूप से कार्यनिष्ठा करने हेतु तकनीकी तथा प्राविधिक कर्मचारियों की कमी है। अतः नियंत्रण एवं संचालन के लिये विभिन्न विभागों की नियुक्तियाँ होनी आवश्यक हैं तथा विभिन्न प्रकार के उनका नियंत्रण भी उनके द्वारा ही होना आवश्यक है।

द- विधानीय कार्यों के पंचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जीप की कमी लगातार बनी ही है। अतः शासक एवं नियंत्रण कार्यों के लिये निम्न पशुधन अधिकारी के लिये जीप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

ख- राजकीय पशुधन की एक स्थान से अन्य स्थानों पर पहुँचाने हेतु विभाग के पास ट्रक की व्यवस्था नहीं है, जिस हेतु एक टन क्षमता के ट्रक के क्रय किया जाना आवश्यक है।

जनपद में उच्च कठिनाईयों निरंतर बनी हुई हैं जो कि समाधान हेतु राज्य सरकार के विचारणीय प्रसिद्ध हैं।

प्रमुख समस्याएँ

जनपद में दूध उत्पादन कार्यवाही के लिये पाँचवीं योजना में 80 हजार रुपये परिव्यय निर्धारित है।

(6) पत्तन

जनानुसार पत्तन पालन के लिए अभी तक कोई कोई कार्य शुरू नहीं चलाना गया है। यद्यपि इस जिले में 9 पार, मच्छीपट्टी, मच्छीपट्टी तथा रायगाँव नदियाँ मछलियों के लिए पैदा हैं। लगभग विभागों के जो मछली संरक्षण कार्य शुरू हो चुके हैं। इन नदियों के स्वच्छता कार्य मछलियों को बढ़ावा दे रहे हैं। जनसुधार में मछली पकड़ने की योजना है। इसके कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2- पत्तन योजना को अन्तर्गत पत्तन पालन कार्य को सुविधायित्व दान से चलाने हेतु 118 हजार रुपये का बजट तैयार किया गया है। वर्ष 1974-75 में 15 हजार रुपये का परिवर्धन निर्धारित किया गया जो कि अभी तक निर्धारित कार्य कुछ नहीं किया गया। वर्ष 1975-76 में लिये 20 हजार रुपये का बजट तैयार किया गया है। इस योजना में उपयुक्त जलधाराओं में निरन्तरकालीन ड्राउट दायित्व तथा मच्छीपट्टी जल को मछलियों के पालने का कार्य शुरू प्रस्तावित है। वर्ष 1975-76 में पत्तन पालन को प्रारम्भिक तैयारियाँ को आदेशों।

(7) - वन

जनपद का लगभग 54 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यटन क्षेत्रों के 50 भाग के 66 प्रतिशत में वनों का होना आवश्यक है। किन्तु कृषि एवं वाणिक्य के लिये वन क्षेत्रों के अतिक्रमण के कोई सुझाव नहीं है। अतः लेकर पड़ी हुई भूमि के निर्दिष्ट वनीकरण की आवश्यकता है।

इन जिले में वन विभाग के तीन वन प्रभागों का कार्य क्षेत्र है - जिनके अधीन वनों का क्षेत्रफल 3-27 लाख हेक्टर है।

पश्चिमी अखण्ड वन प्रभाग के क्षेत्र में भूमि संरक्षण वन प्रभाग का कार्य क्षेत्र भी प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त जनपद में विस्तृत एवं पंचायती वनों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :-

- 1- विस्तृत वन - 1-13 लाख हेक्टर
- 2- पंचायती वन - 0-36 लाख हेक्टर

योग :- 1-69 लाख हेक्टर

वन विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार विभागीय वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 3-70 लाख हेक्टर आँका गया है किन्तु जब तक जिले के सम्पूर्ण भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण नहीं होता है तब उन आँकड़ों में सुधार करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त एक में जौन, तुर्रांस, तिलिन्, पधा, पागार, दुर्ज, कैल, देवदार आदि वृक्षा पाये जाते हैं। उपरोक्त भाग -2 में जोड़, चुन, हल्दी, बेसल आदि वृक्षा मिलते हैं। वहाँ के वनों से भारी मात्रा में हारती ककड़ी का निर्यात होता है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1968-69 में 13-55 हजार क्विंटल वर्ष 1973-74 में 12-98 हजार क्विंटल और हारती ककड़ी उपलब्ध हुई। इसके अतिरिक्त उक्त वर्षों में क्रमशः 533 एवं 5088 क्विंटल हारती ककड़ी उपलब्ध हुई। वर्ष 1973-74 में 15628 क्विंटल लोहा का भी उत्पादन किया गया।

इसके अतिरिक्त कई वस्तुयुक्त जड़ी-बूटियाँ भी वनों से प्राप्त होती हैं जिनके ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानतया जौन उन वनभागों से कान्ने मात्रा में जड़ें वृक्षों निकाली जाते हैं। अन्य जड़ें-बूटियाँ हल्दी, कूबेरे, ताँठ, अतोस, हथनड़ी, वन ककड़ी, बालवर्षा आदि हैं। इनका भी वहाँ से पकड़ा जाता है। बाहरी ठेकेदार वन विभाग से ठेका लेकर इन जड़ें-बूटियों के संग्रह तथा निर्यात का कार्य करते हैं। इस पद्धति को दो हीनियाँ हैं - एक तो उपरोक्त जड़ें-बूटियों का अक्षांश पश्चिम एवं दिक्कत यथायोग्य ठीक रूप से ले उठाता है।

शासन को वर्तमान में वनों के अनुमान विस्तृत एवं पंचायती वनों का भी वन विभाग दूरदर्शी किया जाएगा। इस परिवर्तन के अन्तर्गत जनपद के सम्पूर्ण अलाकनन्दा जलधारा क्षेत्र में भूमि संरक्षण एवं लक्ष्य निर्यात योजना के अन्तर्गत वनीकरण तथा परामाह विकसित किया जाएगा। यह कार्य स्थानीय निवासियों को तहसील तथा परामाह

ने निष्ठा जावेगा । हम कार्पोरेशन के अंतर्गत चारा तथा ईंधन पर्याप्त नै कुछ जैसे म
 लक्ष्मी, सह नून, रेतनिर्माण आदि तथा इन्डियन चार्ज एंड रीपैरिंग की जायेगी जिन्से
 स्थानोय निवारणों की चारा तथा ईंधन सम्बन्धी समस्या का समाधान सम्भव हो सके ।

जनपद में वनों के विकास हेतु पिछले पांच वर्षों में योजनाओं में पर्याप्त परियोजना
 वन विभाग द्वारा चालू की गई तथा यह प्रस्ताव निम्न प्रकार है इन जनपद में वनों के
 विकास के लिये जो कार्य बहुत ही आवश्यक है उन्हें वन विभाग द्वारा चालू किया जाय
 पिछले पांचवर्षों में निम्न योजनाओं में निम्न कार्य किये जो 1973-74 तक को स्थिति निम्न प्रकार
 है :-

1-	अग्नि एवं औद्योगिक सहायक को प्रजातियों का वृक्षारोपण	-- 65 हजार हेक्
2-	यातायात वन संचार योजना अर्थात् सर्व सुर्ती का निर्माण -	
	(अ) - मोटर मार्ग निर्माण	- 95-00 कि०मी०
	(ब) - पैदल मार्ग निर्माण	- 289-00 कि०मी०
	(ग) - मार्ग सुधार	- 301-00 कि०मी०
	(द) - टेलीफोन लाइन का निर्माण	- 261-00 कि०मी०
3-	भवन निर्माण योजना	- 129 भवन
4-	नेल लोहा विदेकन	- 15,628 बिक टन
5-	सम्भारण योजना	गोश्वर में एक पर्यटन को अग्नि निर्माण सर्व 1500 मी० लंबाई ।

पिछले पांचवर्षों में स्थापना के लिये परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है
 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाईओं का समाधान सम्भव नहीं है फिर भी प्रत्येक
 वन्य को उपलब्ध है आगार सभी योजनाओं सम्बन्ध पूर्ण कर लो गई ।
 वनों के विकास तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बहुत कार्य कर चुके हुये दो
 सालों की प्रतीक्षा में निम्न प्रकार के कार्य पूर्ण करने को आवश्यकता है :-

परियोजना का नाम	इकाई	प्रतिशत की सम्पत्ता	कुल मूल्य अनुमानित आवृत्त वर्षों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1- औद्योगिक सहायक को परियोजनाओं का वृक्षारोपण	हजार हेक्टेयर	3-00	3240
2- वन संचार योजना अर्थात् सर्व सुर्ती का निर्माण			
अ- मोटर मार्ग निर्माण -	कि०मी०	92-00	7440
ब- मार्ग सुधार	कि०मी०	90-00	
3- भवन निर्माण	भवन	99	3125
4- नैल उगाने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण	हेक्टेयर	480	450
5- वन संचारण			954

(1)	(2)	(3)	(4)
6- अलावन्ना रसोई एवं वाहु जनक पंजीयना :-			
(1)- जलकान इत्र का सर्वेक्षण	लाइ हैक्टर	1-5	22500
(2)- चरगाघर विकास एवं वनोपकरण दोबारा तथा रिपेटो का काम	हैक्टर	0-21	
(3)- कृषि क्षति का आकलनकरण	,,	500	
(4)- फसल पर पीठ लगाना	,,	600	
(5)- चण्डाण	संख्या	2040	
(6)- स्पर	,,	60	
(7)- सिंच	,,	60	
7- प्र काष्ठ के अनाज लकूटे बनाना	हजार क्वार्टर	91-5	16446
8- अभिन पररक्षण योजना	कैचर्स	6 (काच टावर)	8500
9- वन जोय नाम का रेपेरडिंग कमरा का प्रयोग को स्थापना तथा सर्वेक्षण	संख्या	3 फार्	1800
10- सिविल वर्क एवं वीरिंग वर्क के वन्दोपकरण को संभालना			
1- सर्वेक्षण एवं डीजलिंग	हजार हैक्टर	45	15600
2- चरगाघर विकास	,, ,,	3-0	
3- वनोपकरण	,, ,,	1-0	
4- रोकथाम का निर्माण	,, ,,	0-105	

पंचायत संवर्धन योजना में प्रास्ताविक स्थानों को विकसित करने के लिये अतिरिक्त क्षेत्रों को व्यापकता पर होगा और अक्षयक है । पंचायत योजनाओं को लागू करने के लिये धन प्राप्त होने तक वसुधो कुतरो से धर्म इत्यादि कार्यवाही से टैण्डर आग्रित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्ये जायेगी । सभी कार्य पूर्ण होने पर वसुधो कुतरो जनपद के वनों को सर्वेक्षण एवं विकास एवं उनकी उपलब्धता वहापर सुव्यवस्था भी अन्तर्गत के अतिरिक्त व्यय करना है ।

पंचायत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में वन विभाग द्वारा 110 हैक्टर क्षेत्रफल में अतिरिक्त व्यय के लिये अनुदान प्राप्त हुआ और 3 हेक्टर 10 मीटर वर्ग का निर्माण किया गया । वन विभाग का समग्र क्षेत्र 2-27 लाख हैक्टर वर्ग स्थान के अन्तर्गत लिया जा चुका है । अतिरिक्त व्यय के अन्तर्गत यह कार्य पंचायतों के बीच योजना है । हजार हैक्टर तथा वर्ष 1975-76 में 150 हैक्टर निर्धारित किया गया है । पंचायतों के वनों के अन्तर्गत पैकलियु 10000 मीटर वर्ग का निर्माण भी प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त यह वृक्षारोपण तथा बेदारनाथ कस्तुरी का बिहार पंजीयनवले भी लागू करने को जायेगा ।

इस पथ वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोटर मार्गों के किनारे जल तथा छायादार वृक्ष लगाने जायेंगे जो आकर्षण के साथ-साथ पक्षियों के लिये आवासप्रद भी होंगे। प्रारम्भ में इस प्रकार के अन्वेषण या उनके विकास करने वाले मोटर मार्गों पर यह कार्य प्रारम्भ किया गया है और जैकरोन्डा, अलकतारा, कस्तुरी, कुलिच्छ, गवनों, रोठा तथा बयैन आदि के पौधे लगाये जा रहे हैं। जनपद के लगभग 96,900 हेक्टर क्षेत्र में कस्तुरी पत्र के संरक्षण करने के लिये एक वृक्ष विहार स्थापित है। पक्षियों योजना में इस पत्र विहार का सन्तोषजनक किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य पक्षियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये अधिक कार्यवाही कार्यरत होगी साथ ही वृक्ष विहार में आवासन को सुविधा देने हेतु दृग्गम स्थानों में पैदल मार्ग प्रमुख मार्गों, साथ टावर तथा लीग डेविन बनाने का भी प्रस्ताव है। इन ही कस्तुरी पत्र के प्रजनन के लिये एक प्रजनन कक्ष को भी योजना है।

वन विभाग के पक्षियों योजना के लिये वर्ष 1974-75 में 881 हजार रुपा निष्ठा परिव्याय के विधित 385 हजार रुपा व्यय किये गये और पक्षियों पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1975-76 में इसका 17,713 हजार तथा 545 हजार रुपा परिव्याय निष्ठा-यह सस्त धनराशि राज्य आयोजनागत क्षेत्र के वहन को जायेगी।

भूमि संरक्षण

जनपद में वन विभाग द्वारा भूमि संरक्षण कार्य अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग मोदीश्वर तथा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जनिशेट द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग का प्रजन 1974-75 में हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य जनपद में अलकनन्दा एवं उसकी सहायक नदियों के जलमय क्षेत्र में विविध प्रकार के भूमि संरक्षण कार्य करना है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग जनिशेट द्वारा रामगंगा घाटी में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1973-74 में 1890 हेक्टर क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य किया गया और वर्ष 1974-75 में इसको उपलब्धि 230 हेक्टर रही। भूमि संरक्षण कार्य का सर्वेक्षण योजना का क्षेत्र 7,400 हेक्टर तथा वर्ष 1975-76 का लक्ष्य 560 हेक्टर निर्धारित है।

जनपद में अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो को वर्ष 1974-75 को शीतल उपलब्धि पक्षियों योजना एवं वर्ष 1975-76 के लक्ष्य का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

परियोजना	इकाई	वर्ष 1974-75 को उपलब्धि	पक्षियों योजना का लक्ष्य	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1- सर्वेक्षण	हजार हेक्टर	5	60	10
2- दोषलवन्दो	हेक्टर	100	3600	500
3- सुरागह विकास एवं वनीकरण	हेक्टर	-	2600	140

1	2	3	4	5
4- रीफ़ेडिंग मैशीन	संख्या	-	400	50
5- स्पर मैशीन	११	-	40	10
6- स्लैब का उपकरण	११	-	20	5
7- फसदार कृषि का रोड	११	-	20,000	4,000
8- कृषि शक्ति का मातृकरण हेक्टर		-	50	-

समाप्तता वाले ऋण परियोजना कुल 11 लाख द्वारा पुरोनिर्धारित वित्तीय श्रोत से और अल्पमूलक श्रुति संरक्षण कार्य के लिए उपनिर्धारित श्रोत से व्यय किया जा रहा है। श्रुति संरक्षण कार्य हेतु वर्ष 1974-75 में निर्धारित 6.75 हजार रुपया परियोजना के विपरित 696 हजार रुपया व्यय किया गया। परियोजना के लिए वर्ष 1975-76 के लिए कुल 8430 हजार रुपया 1800 हजार रुपया परियोजना के विपरित है।

यह विवरण को उक्त परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के अन्तर्गत श्रुतियों को प्राथमिकता देने के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। श्रुतियों के आवेदन हेतु विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अन्तर्गत प्राप्त श्रुतियों का उपयोग किया जायेगा।

(9) कृषि का

क्षेत्रों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है किन्तु लगभग 95 प्रतिशत जोतें एक ही जगह पर ही हैं। इस कारण कृषि में इतनी श्रम नहीं हो पाती है कि भूमि सुधार, सिंचन, खाद बीज सस्ती-आवश्यकताओं की पूर्ति इन छोटी-जोतों की श्रम से कर पाने में कृषक सक्षम हों। अतः सस्ती-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे श्रम की आवश्यकता होती है। अभी तक केवल सस्ती-आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन श्रम प्रदान करने तथा कृषि विभाग द्वारा सस्ती-आवश्यकताओं की पूर्ति करने की गई है। चतुर्थ, पंच, तृतीय एवं द्वितीय काल में कृषि विभाग द्वारा 3.21 लाख रुपये की तकियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा 2.00 लाख रुपये का ऋण बस्तु के रूप में (अर्थात् 50 प्रतिशत) वितरित किया गया। पंचम, पंचतृतीय योजना में कृषि विभाग द्वारा तकियों उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसी उद्देश्य यह है कि सरकारी ऋण अथवा कृषक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों के ऋण से करें। अतः सरकारी योजनाओं अन्तर्गत में कृषकों को खाद बीज तथा अन्य छोटी-मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक करोड़ रुपये का अल्पकालीन श्रम तथा भूमि सुधार, छोटे-मोटे कृषि उपकरण, सिंचन, बीजों की बरीकद के लिए 11-48 करोड़ रुपये का मध्यकालीन श्रम वितरित किये जाने का प्रारम्भ प्राविधान है। वर्ष 1971-75 में यह श्रम प्रमाण 24-37 एवं 12-14 लाख रुपये वितरित किया जायेगा। अतः अल्पकालीन श्रम के लिए कृषि विभाग द्वारा अल्पकालीन श्रम का प्राविधान है। वर्ष 1975-75 में सहकारी बैंकों द्वारा 20 लाख रुपये अल्पकालीन और 3-30 लाख रुपये मध्यकालीन श्रम वितरण करने का बड़ा रसम किया है। इसके अतिरिक्त कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यावसायिक बैंकों द्वारा भी श्रम उपलब्ध कराये जाने की दिशा में किये जा रहे हैं। व्यावसायिक बैंकों का प्रारम्भ 1975-75 से प्रारम्भ हुआ है।

स्थापित है और छठी तथा सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद में सभी विकास सख्तों में कृषि की क्रम से क्रम एक-एक प्राप्ति स्थापित हो जायेगी । सहकारी ऋण व्यवस्था इन सख्तों के माध्यम से अधिक से अधिक सुविधा मुक्त हो जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बजटों के रूप में कार्य क्रम के अन्तर्गत काशी समितियों के द्वारा भी ऋण व्यवस्था सुलभ की जायेगी ।

(ख) - ऋण विकास एवं उपभोक्ता कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद में एक ऋण विकास उपधी संघ संगठित है तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित काशी समितियों द्वारा भी उपभोक्ता ऋण विकास के कार्य को व्यापक रूप से लिये जाने की योजना प्रस्तावित है। वर्तमान में कु 56 सहकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्य को लिया जा रहा है । पंचम पंचवर्षीय योजना में इस क्रम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का सुदृढीकरण एवं विभिन्न केंद्रों का खोला जाना तथा ऋण विकास समिति के ग्रामीण गेदाम घरों के निर्माण का भी दृष्टा प्रस्तावित है ताकि अज्ञानता व अभाव को निर्मूलित के कार्य को सुव्यवस्थित किया जा सके । इस कार्य क्रम का इस जनपद के लिये विशेष महत्व है ।

(स) - यह जनपद उन सख्तों में अन्तर्गत है इस कार्य क्रम के अन्तर्गत जूड़ी-बूड़ी मरुभूमि प्रशिक्षण तथा कृषि के कार्य को पूर्ववत् चालू रखा जायेगा और अधिक विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद के 3 विकास सख्तों में अधिकाधिक विकास प्रसार की योजना प्रस्तावित की गई है ताकि जनता अभाव के वस प्राकृतिक क्षेत्रों में विशेष महत्व देकर जायेगी । एक

4- सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य क्रमों की तत् पश्चात् तीर्थारणिक के प्रदेश में छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी रखे जाने की संस्तुति की जाती है । इन कार्य क्रमों की सकारण तथा अधिक व्यापकता एवं अथवा सातवीं योजना में की जायेगी तब में सभी कार्य क्रम इस जनपद के लिये महत्वपूर्ण और निराला अत्यन्त हैं । सातवीं योजना के पश्चात् अनेक तरह अथवा प्रकृतिक क्षेत्रों के उपयोग सहकारिता के अन्तर्गत चालू विकास के कर्तव्य सख्तों में शिक्षा का प्रकृतिक अर्थात् उच्चतर सख्तारित शिक्षा का अनुमान निम्नानुसार है :-

(स्रोत हजार में)

विवरण	1975-74 का 1974	पंचवर्षीय योजनाओं		
		पंचवर्षीय योजना	छठी योजना	सातवीं योजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1- सरकारी स्तर पर	49	48	49	52
2- अर्ध-सरकारी	1240	1360	1420	1500
3- अज्ञान	212	512	1000	1200
4- अज्ञानकारी ऋण	1303	2200	2400	2600
5- अज्ञानकारी ऋण	450	1130	1200	1250
6- तीर्थारणिक ऋण	-	-	-	-

1	2	3	4	5
7- उपभोक्ता वाणिज्य कार्य	1 323	9200	9500	3000
8- जनसौख्य के अन्तर्गत क्षेत्र (हिलार में)	25-5	95	30	35
3- कुल लड़की-बूटी का संग्रहण (निकुण पूरा)	116	720	725	730

पंचायत योजना के उपरान्त कुछ विशिष्ट कार्य क्रमों को जनपद में सहकारी विभाग के अन्तर्गत चालू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जनपद में फल एवं अन्न आलू विकास की सम्भावित प्रगति को आँकते हुये उनके अर्थात् हेतु जनपद में सातवीं तथा आठवीं योजनाओं में एक-एक शीत अण्डार का निर्माण प्रस्तावित किया जाता है। फलों के उपज के साथ ही लठी योजना में एक फल प्रकृषात्मक इकाई तथा एक अन्न प्रकृषात्मक इकाई की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। लठी योजना के अन्तर्गत एक लीसा समिति, एक गृह निर्माण समिति के संगठन का भी लक्ष्य प्रस्तावित है। लीसा प्रकृषात्मक इकाई की स्थापना सातवीं योजना में प्रस्तावित की गई है। जनपद में दुधार पशुओं के विकास होने के फलस्वरूप जनपद के पुराने पर एक दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना सम्भव हो सकती है। अतः उसके संगठन का लक्ष्य लठी योजना में प्रस्तावित है। जनपद में पहले अग्रणी पात्रा में चारा बागान् थे उनका पुनर्स्थापन करने हेतु सातवीं एवं आठवीं योजनाओं में एक-एक चारा कृषि समिति संगठित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। गातागत के वर्तमान सहकारी संस्था के सुदृढीकरण के उपरान्त सातवीं योजना में जनपद में एक गातागत सहकारी संस्था संगठित करने की भी सम्भावना है। इन सम्भावनाओं की परिकल्पना पूर्ण स्थिति एवं जनपद में विकास कर्षी क्रमों की रक्ति को ध्यान में रखकर की गई है।

5- पाँचवीं योजना के अन्तर्गत शैतिक लक्ष्यों का सियारण, वर्तमान की वास्तविकताओं एवं विकास कार्य क्रमों की सम्भावित पूर्ति और उनकी पूर्णताओं को दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। लक्ष्यों की क्रमिक वृद्धि तथा अन्तत प्रति सदस्य अंशपूर्ति, आनन्द तथा अत्याकालीन व अष्टकालीन अन्न वितरण भी तदनुसार प्रस्तावित किया गया है। शैतिक लक्ष्यों की वार्षिक वृद्धि और जनता अथवा संस्था के परिष्कारों की सँग अथवा मिली-सम साधनों की उपलब्धता पर भी योजना के सर्वांगीणों का निश्चितिकरण और भविष्य के कार्य क्रमों का समन्वय किया गया है।

6- पाँचवीं पंचकालीन योजना में सहकारी अन्न तथा अधिकोषण कार्य क्रम को सुदृढ करने के लिये प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्थायी बनाया जायेगा। इन प्राथमिक स्थायी इकाईयों में 6,000 नये सदस्यों की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इन स्थायी समितियों में पुराने एवं नये दोनों प्रकार के सदस्यों में 120 हजार स्थायी अंशपूर्ति का भी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। प्रारम्भिक अन्न समितियों द्वारा अपने सदस्यों को पाँचवीं पंच वर्षीय योजना काल में 2200 हजार रुपये अत्याकालीन तथा 1130 हजार रुपये अष्टकालीन अन्न वितरण का लक्ष्य भी प्रस्तावित है। निर्बल वर्गों के समुदाय को सहकारी समितियों के सदस्य बनने हेतु अष्टकालीन अन्न भी अंशपूर्ति क्रम हेतु दिया जाना प्रस्तावित है जो कि पाँचवीं योजना काल के लिये 120 हजार

स्मर्ये हैं। जिला सहकारी बैंक में सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 41 हजार 8 अंगरूजों के निवेशित एवं 6 लाख रुपया निधि संघ का भी लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1974-75 में प्रारम्भिक रूप से समितियों द्वारा 26.12 हजार रुपया अल्पकालीन तथा 12.14 हजार रुपया मध्यकालीन रूप से वितरण किया गया। इन समितियों को सदस्यता 2 हजार की वृद्धि के साथ सदस्य संख्या 42 हजार हो गयी है। इस वर्ष अंगरूजों 162 हजार की वृद्धि हुई जो पत्तियों योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है। प्रारम्भिक रूप से समितियों को जमा धन में वृद्धि 102 हजार रुपया हुई। इसके समितियों को जमा धनरशि 314 हजार रुपया हो गई है।

वर्ष 1975-76 में सदस्यता, अंगरूजों तथा जमा धनरशि में वृद्धि का लक्ष्य 2-5 हजार, 50 लाख 300 हजार रुपये निर्धारित है। इस वर्ष जिला सहकारी बैंक एक शाखा को खोलो जाने प्रस्तावित है। एवं समितियों द्वारा इस वर्ष कुल 2000 930 हजार रुपया अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रूप से वितरण करने का लक्ष्य है।

उपभोक्ता मार्गें इस के अन्तर्गत पत्तियों योजना में नये भण्डार संयोजित नहीं होंगे। केवल दो उपभोक्ता भण्डारों के सुदृढीकरण तथा एक कुटार विक्री केन्द्र के खोले जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इस विक्रय मार्गें इस में वर्तमान को संयोजित रूप से विक्री निर्धारित का मार्ग व्यापक किया जायेगा एवं जनपद के 9 विकास क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तु छात्राणों के निवेशित तथा अनियोजित वस्तु का भाग को सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु 22 ग्रामोण मोदार संरक्षण का प्रस्ताव है। पत्तियों पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद 2 ग्राम विद्या सहकारी समितियों और संयोजित को जानों प्रस्तावित की गई है। पुरमे सहकारी समितियों को अधिक सुदृढ मार्ग जोत बनाया जायेगा। इस हेतु उनमें राजस्व पाठेदारों लैव मार्गें जोत लुंजी हेतु एवं तथा अनुदान को भी सहूलियों को दिया जान प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 1974-75 में एक ग्राम विद्या संयोजित को जमा हुआ है। इस वर्ष इस विक्री तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के लक्ष्य 285 लाख 1134 हजार रुपये के मूल्य को वस्तुओं का विक्रय किया।

शेज विकास योजना के अन्तर्गत पत्तियों योजना के अन्तर्गत 85 हेक्टर भूमि पर शेष सुधारण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जनपद के नौ विकास क्षेत्रों में इस लक्ष्य के अधीन व्यापक व संयोजित बनाये हेतु 9 छोटी इकाईयां तथा एक शेज विकास संघ संयोजित किया जायेगा। इस संघ द्वारा एक शोधक संरक्षण निर्माण का भी लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 80 हजार रुपये मूल्य का जड़ो-सूतों के उत्पादन और 640 हजार रुपया के मूल्य को क्षेत्रों का बर्तों के संयोजित करने का लक्ष्य पत्तियों पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पत्तियों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्व से चले आ रहे उक्त मार्गों को पूर्ववत् चालू रखे रखा जायेगा।

पत्तियों पंचवर्षीय योजना में उक्त मार्गों के संयोजित हेतु एवं तथा अधिलेखन योजना के अन्तर्गत 580 हजार रुपये, उपभोक्ता मार्गें हेतु 700 हजार रुपये, विक्रय विक्रय मार्गें के लिये 188-7 हजार रुपये, ग्राम विद्या योजना के अन्तर्गत 38 हजार रुपये एवं शेष

विकास योजना के लिये 363-4 हजार रुपये का राज्य आयोजनागत श्रोत से परिकल्पित प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त औषधीय योजना के अन्तर्गत 3330 हजार रुपये संस्थागत और 720 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से, अन्य विक्रय योजना के अन्तर्गत 205-9 हजार रुपये केन्द्रीय सचिव से तथा शेष जन विकास योजनाओं के लिये 720 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से वित्त पोषण किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सभी श्रोतों से पाँचवीं योजना का कुल परिव्यय 6146 हजार रुपये निर्धारित है।

वर्ष 1974-75 में 181-6 हजार रुपये राज्य आयोजनागत, 2550 हजार रुपये संस्थागत तथा 345 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से निर्धारित परिव्यय के विपरीत 5348 हजार रुपये संस्थागत तथा 489 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से व्यय किया गया। राज्य आयोजनागत श्रोत से इस वर्ष व्यय शून्य रहा।

वर्ष 1975-76 में राज्य आयोजनागत, संस्थागत तथा जनपोषित श्रोत से क्रमशः 61, 2930 और 485 हजार रुपये का वित्त पोषण किये जाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष का कुल परिव्यय 3476 हजार रुपये निर्धारित है।

योजना में विकास कार्य क्रमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर ही प्रथम रूपेण कृषि तथा औषधीय योजना पुनः स्वयं विक्रय एवं उपशोका और श्रम संचिदा तथा वनोष्पि विकास कार्य क्रमों को रखा गया है। जहाँ तक परिव्यय का प्रश्न है, शासन से धन की कम अपेक्षा की गई है केवल उन्हीं विज्ञान तथा तकनीकी सहायताओं की माँग की गई है जो नितान्त आवश्यक है। संस्थागत परिव्यय अतिरिक्त एवं तत्पश्चात् जनपोषित परिव्यय का प्रस्ताव स्थापित किया गया है। जनसाधारण कमजोर और पिछड़े वर्ग के समुदाय की प्रयत्न व उनकी सुविधाएँ सुदृढ करने का भी सुसूचित ध्यान रखा गया है।

7- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न संगठित सहकारी संस्थाओं के विस्तार तथा नव संगठनों के लिये विभिन्न प्रकार के कारोबारों तथा तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न स्तर पर आवश्यकता होगी। अन्य विक्रय समिति एवं स्वाश्रयी सहकारी समितियों, उपशोका श्रमिकों, श्रम संचिदाओं तथा वनोष्पि विकास योजना के अन्तर्गत नव संगठित शेष जन विकास विध और शेष जन इकाईयों आदि के लिये सचिवों, लेखा लिपिकों, साखा व्यवस्थापकों और शेष जन इकाईयों में तकनीकी सहायकों की आवश्यकता की अनुभूति हुई है। इस प्रकार मानव शक्ति के कुशल और अकुशल श्रम की उपयोगिता को योजना के सफल कार्यान्वयन में संयोजित किया गया है, ऐसे कर्मचारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रवेश स्तर पर विभाग द्वारा पूर्वतः की जायेगी। सहकारी विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य क्रमों में इस योजना में लगभग 400 व्यक्तियों को पूर्ण कालिक आय का व्यवसाय तथा श्रम संचिदाओं एवं शेष जन संग्रहण आदि के द्वारा लगभग 8000 हजार व्यक्तियों को अंशकालिक आय का व्यवसाय मिलने की संभावना है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा निजी भवन, गोदाम, घर आदि के निर्माण भी किये जावेंगे। इस प्रकार इन सभी प्रकार के व्ययों

के निर्माण में निम्नानुसार सा सामग्री की आवश्यकता का अनुमान है :-

1- सीमेंट	21-888 टन
2- लोहे की चादर	14.4 टन
3- लोहा (सिरेया हेतु)	14.4 टन

8- जनपद में शोचिष्ठा जाति के सुदुदाय के विकास तथा सुविधाओं के लिये सहकारिता के क्षेत्र में संगठित दो सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसायिक रूप तथा आप आर्थिक सुविधाओं का प्रश्न राज्य स्तर से विचारणीय है। जनपद में प्राचीन क्षेत्रों में जनजाति तथा हारेजनों के लिये उनके पूर्व प्रचलित शिल्पकला व तत्सम्बन्धी उपकरणों के लिये भी राज्य स्तर से सहकारिता के क्षेत्र में विशेष सुविधाओं की भी उपलब्ध कराया जाना श्रेयस्कर होगा क्योंकि हारेजन तथा जनजाति के लोग जो कि सहकारी समितियों के सदस्य हैं और कृषक भी हैं को राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि कार्यों हेतु फसली अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण की सुव्यवस्था उपलब्ध है किन्तु सहकारी समितियों द्वारा उन हारेजनों तथा जनजाति के लोगों के लिये जो कृषि करने के साथ साथ अन्य व्यवसाय यथा लोहार गिरी व बढई गिरी, राज गिरी आदि अन्य सहायक व्यवसाय भी करते आ रहे हैं, हेतु नानरेगिफ्लवरेल लोन की भी सुविधा उनके इन्हीं सहकारी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध हो जाये तो इन कृषकों के लिये जो शिल्पकार भी हैं, लाभ स्तर पर आर्थिक सुविधा प्रद हो सकेगा। यह प्रश्न भी विचारणीय है।

इस प्रकार कम भूमि वाले सदस्यों जैसे साच्छा आदि जनजाति वालों का प्रश्न भी इस दृष्टिकोण से सुविधाओं से जुड़ा है। क्योंकि कि इन्हें पहले फसली कार्यों के लिये सहकारी समितियों द्वारा ऋण उनकी कम अथवा असम्पूर्ण संपत्ति के आधार पर दिया जाता था, पर अब आर्थिक नीति निर्धारण अनुसार उन्हें भूमि कम अथवा नहीं होने से फसली यथा सुविधा अति न्यून और प्रयाप्त नहीं मिल पाती है। अतः पर्यतीय क्षेत्रों में पूर्ववत् पूर्ण संपत्ति के आधार पर ही ऋण दिया जाना वाञ्छनीय है। उनके तिब्बत से व्यापार बन्द हो जाने से ये व्यवसाय हीन हो गये हैं ये लोग शेरु, बकरी, घोड़े आदि पालकर अपनी अस्तित्व की सुरक्षा कर सकते हैं। अतः ऐसे सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को भी यदि उनके व्यवसायिक उद्देश्यों के लिये भी ऋण राज्य द्वारा उनकी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही मिल पाये तो इनकी जन शक्ति का राष्ट्र के हित में अच्छा उपयोग सिद्ध हो गा।

अतः ऐसे सदस्य ऋण को प्राप्त करवा देने के लिये विभिन्न विभागों से कक्षा व तीडज पत्र लिख कर पोरबंदर आदि संस्थाओं से जनता में वितरित किये जा रहे हैं वे सभी उनकी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित किये जाय जिससे ऋण वितरण एवं वसूली होने में सुविधा न होगी और ऋण मिलने का एक ही श्रोत हो जाने से जनता को विशेष आशंकाओं तक पहुँचने में जो जन शक्ति नष्ट करनी पड़ती है वह भी राष्ट्र के अन्य उपयोगी कार्यों में व्यय होगी।

(2) वर्तमान में जनपद में कृषकों को बागवानी, फलउपयोग, उद्यान, पशुधन आदि हेतु विकास के विभिन्न प्रकार के पशासकीय विभागों द्वारा भी शासन से अत्यन्त अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण लिये जा रहे हैं और उन्हें कृषकों को कोषों सहकारी बैंक द्वारा भी समान उद्देश्यों के लिये अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन ऋण भी वितरित किया जा रहा है। यदि ये सरस्त ऋण सकारिता द्वारा ही दिया जाय तो अधिक सुविधाएँ प्रदान हो सकेंगी और कृषकों को वास्तविक भूमि और प्रतिदान कारता के अन्तर्गत ही ऋण सुविधा दी जा सकेगी और कुंआक भी अनावश्यक शर्तों से नहीं दबने पायेंगे एवं ऋण का भी सहयोग ही सकेगा। यह अधिक व्यापक भी रहेगा। अतः इस हेतु सरस्त ऋणों को सकारिता संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहनीय है। इस प्रकार राजस्व से ही कार्यवाही की सकती है।

(10) पंचायत राज

जनपद में इस समय 508 ग्राम सभाएँ और 54 न्याय पंचायतें गठित हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 280365 है। जिले में 1639 ग्राम हैं। इनमें से 146 ग्राम गैर आबाद हैं। जनपद में पंचायतों की औसत वार्षिक आय 805100 रु के बीच है जिसमें वे अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा आय के स्रोत जैसे भूमि चारागाह भूले काट आदि की उपलब्ध नहीं है। ग्राम सभाओं के ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तरों पर विकास सम्बन्धी कार्य सँपे गये हैं। जो विकास खण्डों के स्तर पर सँपाये जाते हैं।

2- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल तक 8 ग्राम सभाओं को 24,100 रु उत्पादक परि-सम्पद के विकास हेतु संपूर्ण वितरित किया जा चुका है। 13 पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण जिस पर 2500 रु व्यय हुआ है, दिया गया है। 19-20 लाख रुपये की लागत से 30 किलोमीटर जन सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 108 फ्रीड पाठशालायें चालू की गईं जिन पर 6 माह तक पाठशालायें चलाकर 5400 रु व्यय हुआ है और 3000 फ्रीडों को सँभर दिया गया है।

3- 10 ग्राम सभाओं को उनके द्वारा अच्छे कार्य करने पर शासन द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 5700 रु पुरस्कार स्वस्थ दिया गया है। 3 ग्राम सभाओं को 2 पंचायत शरों के निर्माण हेतु शासन द्वारा 10,000 रु अनुदान दिया गया एवं गाँव सभाओं ने स्वयं अपने सञ्चन से तथा दान आदि से पंचायत शर निर्माण किये हैं। वर्तमान समय में जनपद में 174 पंचायत शर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

4-5 पंचायतों के सुदृढ़ विकास के लिये जो भी आवश्यकताएँ हैं सीमित साधनों को देखते हुए उनकी पूर्ति पंचायतों को करना चालू नहीं की जा सकती है अतः पाँचवी योजना के उपरान्त दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत 34 पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण जिस पर 50 हजार रु व्यय का अनुमान है प्रस्तावित किया गया है। 10 न्याय पंचायतों केन्द्रों पर पंचायत शरों का निर्माण किया जायेगा जिस पर 50 हजार रु व्यय होने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु 10 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 20 हजार रु व्यय का अनुमान है। पंचायतों उद्योगों के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर सहाय एवं तकनीकी सहायकों की नियुक्ति किये जाने हेतु 50,000 रु व्यय का अनुमान है। अच्छे कार्य करने वाली ग्राम सभाओं को शासन द्वारा पुरस्कार दिये जाने की भी परियोजना प्रस्तावित है जिस पर लगभग 50,000 रु व्यय का अनुमान है। पंचायत पदाधिकारियों में लचीलापन करने का एवं कार्य में स्फूर्ति लाने के निमित्त प्रशिक्षण योजना का भी रखा गया है। इस प्रशिक्षण योजना पर 41 हजार रुपये व्यय का अनुमान है। पंचायतों के पुस्तकालय तक पहुँचाने एवं उनके कार्य का सिद्धान्तलोकन करने एवं पदाधिकारियों के मिलन हेतु छात्र स्तर, जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन किये जाने की योजना है। इन सम्मेलनों पर 9 हजार रु व्यय का अनुमान है।

5- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास पंचायतों के आय के साधन बढ़ाने पंचायतों के पदाधिकारियों में सहयोग की भावना जागृत करने, विकास कार्यों के सम्पादन में अभिरुचि पैदा करने हेतु पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना पंचायत उद्योगों के संचालन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति, पंच सम्मेलनों का आयोजन, पंचायत घरों का निर्माण पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना आदि परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई है।

6- पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में उपरोक्त परियोजनाओं पर 1,53,400 रु का परिबन्ध निर्धारित किया गया है। वर्ष 74-75 में 4900 के परिबन्ध के विपरीत 4400 रु पुरस्कार योजना के अन्तर्गत अच्छे कार्य करने वाली गाँव सभाओं को पुरस्कार वितरण किया गया है वर्ष 75-76 में 19,600 रु का परिबन्ध निर्धारित है। जिसमें जिला स्तर पर निम्न परियोजनाएँ कार्यान्वित की जावेगी:-

1-5-1 पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण - इस वर्ष एक पंचायत सेवक को प्रशिक्षित किया जावेगा- इस परियोजना का कार्यान्वयन सामुदायिक विकास विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा किया जावेगा। 1 जुलाई 75 से प्रारम्भ हो चुका है।

2- पंचायत सँस्थाओं के प्रोत्साहन - वर्ष 75-76 में पंचायत सँस्थाओं के प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ 3 गाँव सभाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किया जावेगा।

3- पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण - पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 75-76 में इस जनपद के 33 सरपंचों एवं 33 सहायक सरपंचों को तहसील स्तर पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा।

7- जैसे जैसे साधन सुलभ होंगे पाँचवीं योजना काल में निम्न परियोजनाएँ कार्यान्वित की जावेगी:-

1- पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण - जिले के 5 अप्रशिक्षित पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण में उन्हें पंचायतों के सम्बन्ध में व्यवहारिक ज्ञान कराया जावेगा।

2- पंचायत सँस्थाओं के प्रोत्साहन - जनपद में अच्छे कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ गाँव सभाओं को पुरस्कार वितरित किया जावेगा।

3- पंचायत उद्योगों का प्रशिक्षण - पंचायत उद्योगों के सफल संचालन हेतु उद्योगों के प्रबन्धकों का प्रशिक्षण दिया जावेगा।

4- पंचायत सेवकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण - सेवारत पंचायत सेवकों की क्षमता स्तर को समुन्नत करने तथा उन्हें उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से उन्हें सँस्थागत अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

5- पर्यावरण स्वच्छता - गाँवों की सर्वांगीण स्वच्छता तथा गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये पर्यावरण स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित परियोजना के अर्धीन गन्दी पानी के गद्दों को पाटने छड़ने लगाने पुलियों और नाले बनवाने का काम किया जावेगा। खाद के गद्दों के साथ तरकारी फूल पौधे, वास, ईंधन लकड़ी

तथा फल के बूझों का रोपण किया जावेगा ।

6- पंचायत कार्यालय भवन :- न्याय पंचायत स्तर पर । पंचायत स्तर निर्माण की नितान्त आवश्यकता है इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पंचायत घरों के निर्माण की परियोजना रखी गई है ।

7- पुस्तकालय एवं पुस्तक केंद्र :- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक तथा अर्थ आर्थिक असमानताओं, बेकारी व जनश्रमता की समस्याओं को प्रथम ही दृष्टि से सुलझाने के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण जनसमुदाय को समार व सुशिक्षित बनाया जाय और उनका वैदिक स्तर उठाया जावे । इस उद्देश्य की पूर्ति ग्रामीणों को शैक्षिक तथा पठनीय सामग्री प्रदान में ही सुलभ करा कर की जा सकती है । अतएव इस परियोजना के अधीन ग्रामीणों में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

8- पंचायत पंचायतियों का प्रशिक्षण :- न्याय पंचायतों के सरपंचों एवं सहस्रपंचों को गाँव सभाओं के प्रशासन एवं उप प्रशासकों की प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्रशिक्षण की योजना रखी गई है ।

9- पशु पालने तथा पशुचिकित्सालय के लिये गाँव पंचायतों के आर्थिक अनुदान :- ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नत, भूमि के कटाव को रोकने, पशुओं का चारा उपलब्ध कराने तथा देखभाल आदि के उपलब्ध करने के लिये यह परियोजना तैयार की गई है ।

10- पंचायत सभालय :- विभागीय कर्मियों की गतिविधि ज्ञात करने पंचायतों के सभालय स्थापन तथा पशुचिकित्सालय के लिये सभालय एवं अण्डल स्तर पर पंचायत सभालयों के स्थापन की परियोजना रखी गई है ।

11- पंचायत उद्योग तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति :- पंचायत उद्योग के संचालन एवं निहित वैयक्तिक व्यक्तियों को रोजगार देने के निमित्त यह योजना रखी गई है ।

12- पशु पालने तथा पशुचिकित्सालय के लिये गाँव पंचायतों के आर्थिक अनुदान :- पशु पालने के उपयोग एवं पशुचिकित्सालय के लिये गाँव पंचायतों को रोजगार देने हेतु यह योजना रखी गई है ।

13- पंचायत उद्योगों के समस्त संचालन हेतु निला स्तर पर बैठक :-

अब तक निला स्तर पर उद्योगों के संचालन हेतु स्वयं नियुक्त नहीं था इस परियोजना के अन्तर्गत । पंचायत निरीक्षण उद्योग । संचालन की नियुक्ति की योजना रखी गई है ।

पंचायतों के कर्मियों के वेतन रिकॉर्ड के लिये ग्राम स्तर पर पंचायत वेतन अण्डल स्तर पर संचालित (10) नियुक्त है इस पंचायत जनपद में पंचायत वेतन का कार्य क्षेत्र विस्तृत है । पंचायत वेतन के 10 से 15 तक गाँव समायें स्थितित है । कहीं कहीं पंच एक गाँव से दोसरे गाँव की दूरी 10 से 15 कीलोमीटर तक पैदल से है । जिससे क्षेत्र में भ्रमण करने की आवश्यकता है । जिले में 90 ग्राम वेतन के नई कार्य की प्रतिष्ठा के अनुसार यह उचित होगा कि पंचायत वेतन एवं ग्राम वेतन का क्षेत्र एक ही हो इससे जनता शासन को भी योजनाओं की जानकारी होगी ।

पंचायत पदाधिकारियों के बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा होगी कर्मचारी वर्ग भी क्षेत्र में प्राप्त मात्रा में भ्रक्षण कर सकेंगे ।

अतः नयाय पंचायतों की संख्या 54 से बढ़कर 90 की जाने की शासन से यांग की जाती है ।

=====

(11) सामुदायिक विकास प्रयोजना

सामुदायिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को सम्बन्धित विभिन्न विकास विभागों के निकटतम सहयोग से सम्पादित किया जाता है। सामान्यतः ऐसे कार्यक्रम जिनमें जन सहयोग अंग्रेजित है। सामुदायिक विकास विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। पंचय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास प्रयोजना के अन्तर्गत जनपद में जो कार्य कार्य प्रस्तावित किये गये हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-

(1) कृषि प्रसार :- विकास खण्ड के प्रसार स्वयं द्वारा कृषकों को उन्नतशील खेती के तरीकों जैसे उन्नत बीज, रसायनिक उर्वरक तथा पौध सुरक्षा हेतु रसायनिक दवाओं के उपयोग से अवगत कराया जाता है। इसके लिये प्रदर्शक कार्य क्रम के द्वारा लाभदायक भूमिका अदा की जाती है। सामुदायिक सिंचाइ के लिये पक्की नालियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।

(2) सामाजिक शिक्षा :- ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय तथा पुचना केन्द्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी देकर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस मद के अन्तर्गत पुस्तकालय एवं पुचना केन्द्रों को चल देने के लिये धन का प्राविधान किया जाता है।

(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य :- विकास खण्डों में अग्रदान द्वारा छोटटे मोटे निर्माण कार्य कराने तथा भविष्य के गाँवों की प्रतियोगिता में पुरस्कार देने के लिये कुछ अनराशि का प्राविधान क्षेत्र समितियों के निस्तारण पर किया जाता है।

2- जिले में राज्य आयोजनागत क्षेत्र से पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1974-75 तथा 1975-76 का कार्यक्रमवार परिव्यय एवं 74-75 के व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

कार्यक्रम	पंचवर्षीय योजना परिव्यय	वार्षिक योजना		
		1974-75	व्यय	परिव्यय
1- कृषि प्रसार	19.5	2.8	2.6	7.7
25- सामाजिक शिक्षा	22.5	2.8	2.4	6.0
3- सार्वजनिक स्वास्थ्य	45.0	3.8	3.8	18.9
योग	87.0	9.4	8.8	32.6

हजार रुपय में

(III) प्रादेशिक विकास दल

अक्टूबर 1971 में अखिल भारतीय रक्षक दल का नाम बदल कर प्रादेशिक विकास दल कर दिया है। इस निर्णय के फलस्वरूप प्रादेशिक विकास दल को ग्रामों की सर्वोत्तम उन्नति के लिए सामुदायिक विकास कार्य में लगाया गया है। दल के गठन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :-

- 1- प्राचीन स्तर पर प्रा(वि) दल (अर्थात् रक्षक दल) का गठन जो सामुदायिक विकास कार्य के संयोजन सम्पादन हेतु अग्रगामी दल के रूप में कार्य करेंगे।
- 2- प्राचीन युवकों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सामुदायिक कार्य रूप में युवकों के योगदान हेतु प्राचीन स्तर पर युवक में गल दलों एवं बाल मंगल दलों का गठन।
- 3- युवकों में कार्य करते हुए सीखना और सीखते हुए ^{कमान के} आधारित सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न आर्थिक योजनाओं एवं कार्य कलाओं द्वारा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विकास कार्य कला की नवीनतम प्रादेशिक जानकारी तथा व्यवहारिक दक्षता का विकास।
- 4- प्राचीन स्तर पर भारतीय व्यायामशाला प्रीडा केन्द्र, खेलकूद प्रतियोगिताएँ एवं अन्य शारीरिक सम्बर्धन तथा पशुधन द्वारा युवकों की शारीरिक उन्नति।
- 5- परिव्यय राज स्वयंसेवक के अंतर्गत प्राचीन सुरक्षा का कार्य।

चतुर्थ वन शीघ्र योजना के अन्तर्गत निम्न प्रगति रही :-

1-	युवक मंगल दलों की संख्या -	105
2-	युवक मंगल दल के सदस्यों की संख्या	1050
3-	क्लब क्लब हाउस	9
4-	हल्का सरदार	54
5-	दलगत	508
6-	टीली नायक	1568
7-	रक्षक	15660

वर्ष 1973-74 में 8 श्रमदान शिबिर आयोजित किये गये, जिसमें 350 अवैतनिक सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 210 श्रमियों ने श्रमदान करके योगदान दिया। उपरोक्त कार्यों के सम्पादन करने में निम्न के जन श्रम शक्ति के अतिरिक्त तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु विकास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना पड़ा गत वर्षों में प्रादेशिक (प्रा) वि) दल के कार्यकर्ताओं के अभाव में निम्नलिखित कठिनाइयाँ अनुभव की गई :-

- 1- प्रादेशिक विकास दल के अवैतनिक सदस्यों के मान देय बर्षी आदि सुविधायें न मिलने के कारण जनशक्ति रक्षक करने में कठिनाई रही।
- 2- जिले में प्रीडा के मैदानों एवं उत्तक राज लजह व रक्षक वर अभाव बना रहा।
- 3- युवक मंगल दलों की आर्थिक सहायता न मिलने के कारण दलों का गठन करने में कठिनाई रही युवकों के व्ययार्ण के लिये कुछ आर्थिक सहायता दिया जाना नितांत आवश्यक है।

4- जिला स्तर पर स्टेडियम की व्यवस्था न होने के खेलकूद के आयोजन में बड़ी कठिनाई होती है। इसी प्रकार क्लबघर, क्लबहालाओं का और उनकी राज सजा का भी प्राविधान जिले के युवा नग के स्वस्थिकवर्दन के लिये किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अगली योजना में इसकी पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक होगा। जिले में खेल के मैदानों की बहुत कमी है। बहाड़ी क्षेत्र होने के कारण खेल के मैदान सुसज्जित की पुगयता से नहीं तैयार किये जा सकते हैं। अतः शासन को प्रत्येक प्राईमरी और जूनियर हाई स्कूल के साथ साथ खेल कूद के मैदान की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा।

पाँचवी योजना में आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं :-

1- स्वयं सेवक दलघाटक - प्रत्येक विकास खण्ड में एक क्लब कर्मांडर, प्रत्येक न्याय विभागत क्षेत्र में एक हल्का सरदार, प्रत्येक ग्राम तथा स्तर पर एक दलपति एवं प्रत्येक ग्राम सभा में 500 की जनसंख्या पर एक स्त्री अध्यक्ष तथा एक रक्षकों की एक टोली तथा अधिक की ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक 3 टोलियों का गठन किया गया है। वर्ष 1974-75 में इन स्वयं सेवकों को 9 सेट वर्क वितरित की गई। वर्ष 1975-76 में 7 तथा पाँचवी योजना में 153 सेट वर्क वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- समाज सेवा कार्य- प्राथमिक स्तर पर स्वच्छता अभियान, ग्रामों में रतोई वाटिका अंशुपू तथा विचारण, आजीव सड़को व वास्तु, जालेवन्दी की मरुममत एवं समाज सेवा और सामुदायिक विकास के अन्य कार्यक्रम जो कि आवश्यक समझे जावेंगे क्रिया जवेगए। इससे अतिरिक्त देता ड्यूटी एवं रात्रा लाइन ड्यूटी की योजना रखी गई है।

3- युवक संगल वती के प्रति सहानुभूति :- इस योजना के अन्तर्गत युवक संगल वती के लिये रतोई, वाटिका, कुँकुट पालन, बछड़ा पालन, फसलों पर दवा छिड़कन, एवं आजीव लक्ष्म उद्योग चन्ने जैसे टैकरी बुनना (रिगाल का कार्य), मधु-यक्षी पालन, कुँकुट पालन आदि का कार्य रखा गया है।

4- युवक सेमिनार :- पाँचवी योजना में जम्बूद स्तर पर 5 सेमिनार आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5- विकास खण्ड स्तर पर खेलकूद प्रतिस्पर्धायें :- युवकों के शाररिक सम् वर्दन, अनुशासन वनदी एवं वर अंशु नागरिक के रभा में देस की सेवा और सामुदायिक विकास कर्तों की सेवा प्रति सहानुभूति के लिये ये खेलकूद खण्ड स्तर पर खेल कूद प्रति स्पर्धायें आयोजित करने का प्राविधान है। वर्ष 1974-75 में 9 प्रतिस्पर्धायें आयोजित की गईं जिसमें 450 प्रतिस्पर्धायें के भाग लिया। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक अर्थात् कुल 9 क्रीडा केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 1975-76 में 9 प्रतिस्पर्धायें आयोजित करके 900 प्रतिस्पर्धायों के सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पाँचवी योजना में 45 प्रतिस्पर्धायें आयोजित की जावेंगी जिनमें 2250 प्रतिस्पर्धायों को सम्मिलित करने का लक्ष्य है।

6- अन्तः जनसंघित कार्य :- वर्ष 1974-75 में स्वयं सेवकों द्वारा दुष्कारोपण हेतु 1132 गद्दे छोदे गये और 590 ब्रह्म लगाये गये। वर्ष 1975-76 में नौ कीलोमीटर प्राथमिक

संयोजक मार्ग की मरम्मत, पाँच कीलोमीटर मूल का निर्माण, 9 कीलोमीटर मूल की मरम्मत तथा 4 500 गड़बड़े सँवकर 45 00 इंच लगाने का लक्ष्य है। प्रादेशिक विकास दल के विभिन्न कार्य इन्हीं के लिये। पौखली योजना एवं वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 में क्रमशः 38 और 3 हजार रु० राज्य आवंटनगत स्रोत से परिकल्प्य प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 1974-75 में नियोजित 2 हजार रुपया परिकल्प्य के विपरित 2 हजार रु० व्यय किया गया था। प्रादेशिक विकास दल के कई कार्य क्रम जनसंकेतों द्वारा संपन्न किये जाते हैं। जनसंकेत पुरवाईकरण करने इन्हीं वर्षों 1974-75 में लगभग 2 रु० प्रति गड़बड़ और 200 कीमती रेंडू रुक रुपयों की दर से 2 हजार रुपया जनसंकेतित स्रोत से व्यय किया गया। वर्ष 1975-76 में प्रस्तावित लक्ष्य का प्यून में रखते हुए लगभग 10 हजार रु० प्रति कीलोमीटर की दर से मिक मार्ग निर्माण, एक हजार रु० प्रति कीलोमीटर की दर से मूल निर्माण तथा 500 रु० प्रति कीलोमीटर की दर से मूल मरम्मत आदि कार्य करने के लिये 2108 हजार रुपया जनसंकेतित स्रोत से परिकल्प्य प्रस्तावित किया गया है। इन्हीं प्रकार के जनसंकेतित कार्य कर्मों के आगामी वर्षों में भी चलते रहने की प्रत्याशा में पंचम वीत वसंतिय योजना में पाँच लाख रु० परिकल्प्य प्रस्तावित किया गया है।

शासन के निचरपीय सुझाव:-

- 1- प्रादेशिक विकास दल के विभिन्नों के माध्यम से निर्माण कार्य कराने में प्रायः प्रादेशिक सहायता को भी आवश्यकता होती है। इसके लिये कम से कम जिला स्तर पर दो सहस्राब्द निजामत अतिरिक्त, प्रादेशिक अधिकारी जो कि अवर अभियंता की शैक्षिक एवं प्रादेशिक दक्षता रखते हों, जिन्हें निम्न की नियुक्ति की जाती चाहिये।
- 2- इन विभाग के पास अनुदानों के सम्यक् की व्यवस्था न होने के कारण श्रम शक्ति का उपयोग करने में अड़िचाल होती है। यदि विभाग के पास एक टुक की व्यवस्था हो तथा तब श्रमजनों को निर्माण तंत्रों को टुक में बाँटकर आसानी मिले तो कार्य स्थल पर और बहुत कर अधिक समय तक श्रम शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।
- 3- अनुदान के अन्तर्गत तैयारी के वर्ष 1975-76 में सुरक्षा सेवा हेतु विभिन्न स्थानों पर पुलिस के अधिकारी नियुक्त किया गया। इन्हें केवल 6 रु० प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया गया। इन्हें अतिरिक्त इष्टुट्य स्थल पर आने जाने का वेतन किराया नहीं दिया गया। इससे इन्हें रोक्ने में अतिरिक्त व्यय होता है। भविष्य में इस प्रकार की सेवाएँ ली जाने पर इष्टुट्य स्थल तक आने जाने का किराया देय होना चाहिये।
- 4- अब जूलि जिला संगठन तर्ता प्रा०वि०द० के जन शक्ति का संयोजक नियुक्त किया गया है। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर कुछ आठार जैसे मैती, कपडुवा, तख्त, केला आदि उपलब्ध कराये जायें ?

XXXXXXXXXXXXXX

(11) बाढ़ नियंत्रण योजनाएँ ।

इस जनपद का समस्त क्षेत्र पर्वतीय है । नदी व नालों में अत्यधिक ढाल होने के कारण उनके किनारों पर बड़ी हुई आबादी तथा कृषि योग्य भूमि का कहीं भी कहीं कटाव हो जाता है । अतः इस क्षेत्र में नदी तथा नालों से गाँवों के कटाव को रोकने की समस्या मुख्य है । इस जनपद में जलोत्सर्जन की समस्या नहीं है केवल जोशीबाघ वर्षाकाल एवं थराली में आबादी के बीच से बहने वाले नालों का छिन्नक (ब्राम सेक्शन) ठीक न होने के कारण अतः पास के इलाकों में पानी भर जाता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक केदारनाथ, बन्नीनाथ, कुलतारी, चन्नापुरी एवं गौरासी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का कार्य सम्पन्नित किया गया है । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में बाढ़ सुरक्षा कार्य पर 52 हजार रुपया निर्धारित परिसर के विधरित 90 हजार रुपया व्यय किया गया है . अन्त वर्षों में पिलहाल कोई कार्य प्रारंभ प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

=====

हैं। वर्ष 1974-75 में 250 कि०वाट क्षमता का एक संयंत्र चालू हो गया है। स्थिति कार्य के लेखदारों को करने के कारण इस कार्य में बहुत क्लेश हुआ। इस परियोजना के अन्तर्गत भोपाल पाण्डुरीगर लाइन का निर्माण पूर्ण हो चुका है लेकिन बलि क्षेत्र के लिये उपयुक्त लाइन का जो के कारण पाण्डुरीगर, त्रिनाथ लाइन का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका अतएव उपलब्ध बिजली पाण्डुरी द्वारा ही लाइन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में सृष्टि के हेतु 250 कि०वाट के सिंगरे संयंत्र को बंद करा अथवा नहीं हो पाये है। एमए इन्फो एक धारतीय कार्य बिस्नेस अन्य दो संयंत्र उपलब्ध किये हैं वे सफलता में वेरो नहीं होंगे और पंच-वर्षीय योजना काल में ही शक्ति सृष्टि पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करने लग जायेंगे।

2 :- ग्रामीण विद्युत्तारण योजना

इसके अन्तर्गत 207 ग्रामों का विद्युत्तारण होना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों का विद्युत्तारण होना है। इस प्रकार वर्तमान योजना काल में 148 ग्रामों का विद्युत्तारण होना बाकी है। इस योजना के अनुसार पूरे 207 ग्रामों का विद्युत्तारण 3 वर्षों के भीतर पूर्ण होना चाहिये पर एमए, लोहा पोन्ट एवं अन्य आवश्यकता निर्माण पाण्डुरी को अत्यान्त लम्बे के कारण कार्य आकस्मिक रूप से नहीं चल पा रहा है।

इस जिले में अलकनन्दा एवं इन्फो : इन्फो नदियों में बिना जल विद्युत्त क्षमता विद्यमान है इसके अनुसंधान हेतु यहाँ सिंगरे विभाग का एक अनुसंधान एवं नियोजन बाडू कार्यरत है। उसने जिले में विष्णु अन्ना, लोका, काला, नन्दप्रयाग अदि अनेक विकास जल विद्युत्त योजनाओं का अनुसंधान किया है। इस योजना के कार्यान्वयन होने पर इस जिले में विद्युत्त मात्रा में विद्युत्त उत्पादन ही प्रयोग जिसका उपयोग न केवल इस जिले में बल्कि प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में भी हो सकेगा। एमए इन योजनाओं को कार्यान्वित होने में बहुत समय लगने को आशंका है।

यह जिला अभी तक राज्य को मुख्य शक्ति से सम्बन्ध नहीं हो सका है। अतएव पंच-वर्षीय योजना काल में लखीम, कर्णप्रयाग, शोनागर, नजीबाबाद के बीच में एक एक 132 कि०वाट लाइन बनानी का प्रस्ताव है। कर्णप्रयाग में एक शक्ति उपस्थान बना कर जिले को राज्य को मुख्य शक्ति से विद्युत्त शक्ति उपलब्ध कराये जायेगी। जिले में बड़ो-बड़ो उपयुक्त जल विद्युत्त योजनाओं का जाने के बाद इस 132 कि०वाट लाइन का उपयोग यहाँ पर विद्युत्त शक्ति अथवा धारतीय जिलों में पहुँचाने हेतु किया जायेगा।

विद्युत्तारण का उपयोग किस प्रकार के हेतु किया जाना है :-

- 1- घरेलू कार्य हेतु अर्थात् अर्थात् प्रयोग के यंत्रों को सुविधा हेतु।
- 2- पर्यटन उद्योग के विकास हेतु।
- 3- टुरिज्म उद्योग हेतु।
- 4- वनसम्पदा के उद्योग हेतु।
- 5- पेयजल योजनाओं हेतु।
- 6- विद्युत्त कार्य हेतु।

पाँचों पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 43 ग्रामों तथा 20 हरिजन कक्ष वसतिगृहों का विद्युत्तारण किया गया है। इस वर्ष 6 औद्योगिक कक्षों का देना मंजूर है और 28 बैटरी लाइनों, 11 बैटरी लाइन एवं 51 बैटरी लाइन का निर्माण किया गया है। वर्ष 1975-76 में 23 ग्रामों का विद्युत्तारण, 22 हरिजन वसतिगृहों का विद्युत्तारण तथा 40 बैटरी लाइनों का निर्माण का लक्ष्य है। राय विद्युत्त परिषद् के पाँचों योजना के पूर्ण लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुये है।

ग्रामीण विद्युत्तारण हेतु 1974-75 में निर्धारित 629 हजार रुपये परिव्यय के विधित 1191 हजार रुपये व्यय किया गया है। वर्ष 1975-76 में 1911 हजार रुपये परिव्यय निर्धारित है। पाँचों योजना के लिये निर्धारित परिव्यय को संचना अभी तक प्राप्त नहीं हो पाये है। ताइको हाइड्रिल स्पेस पाण्डुलेटर 250 कि०वाट के निर्माण पर वर्ष 1974-75 में 592 हजार रुपये व्यय किया गया और वर्ष 1975-76 में 250 कि०वाट ताइको हाइड्रिल परियोजना पाण्डुलेटर हेतु 500 हजार रुपये परिव्यय निर्धारित है।

न्यूनतम आवश्यकता काई इकाई को ग्रामीण विद्युत्तारण निगम द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। निगम के निर्देशानुसार यह कार्य कुल संकेत रज विद्युत्त क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाये जहाँ निगम द्वारा स्वीकृत अन्तःसंचालन योजना लागू नहीं है। इसके अन्तर्गत जेले ब्रिड का लक्ष्य 70 ग्रामों का है परन्तु अन्तःसंचालन में निगम को साधारण योजना लागू है, वहीं देवना होना कि क्या औद्योगिक क्षेत्रों में ही 70 ग्रामों का विद्युत्तारण ही योजना के अन्तर्गत हो (लेना 2 औद्योगिक क्षेत्रों के ग्रामों में केवल प्रो. रज स्वीकृत नहीं हो आयाकी होती है। जो त. रज. में नहीं के निर्माण विद्युत्त क्षेत्रों में कले जाये हैं इस कारण जनसंख्या पुस्तिका में इन ग्रामों को आयाकी कुछ क्षेत्रों में दर्शाये गये हैं। अतएव यह सम्भव है कि इन योजना के अन्तर्गत विद्युत्तारण किये जाने वाली ग्रामों के लक्ष्य में कुछ कमो करनी पड़े।

जिले के अन्तर्गत सर्वो निर्माण कार्यों को करने हेतु इस वर्ष यहाँ एक विद्युत्त कण्ड कार्यालय है। परन्तु यहाँ अभी तक कार्यालयों स्वीकृत अन्तःसंचालन नहीं हो पाये हैं। योजना का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये इसको पूर्ण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों और संचालन को संचालन भी आवश्यक होगी। इसके लिये कुछ कार्यालयों को नियुक्त विद्युत्त परिषद् दफ्तरा करने सम्भव होगी। साधारण पाण्डुलेटर के संचालन के लिये का पूर्ण संचालन कार्यों में कार्य हो सके।

पाँचों पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 में पूर्ण किये जाने वाले कार्यों के लिये साक्षात्कोष को अनुमानित पाँचों का विवरण इस प्रकार है :-

पाँचों पंचवर्षीय योजना काल में साक्षात्कोष को आवश्यकता के अनुमान			
साक्षात्कोष का नाम	वर्ष	1975-76	पाँचों पंचवर्षीय योजना
(1)	(2)	(3)	(4)
1- 11 बैटरी लाइनें	रुपया	720	4800
2- 11 बैटरी लाइनें	,,	1450	9600

(1)	(2)	(3)	(4)
3- 11 बैटरी डिस्चार्जिंग	संख्या	1450	9600
4- 11 बैटरी चार्जिंग इन्वर्टर	संख्या	1450	9600
5- 11 बैटरी चार्जिंग के लिए	११	1450	9600
6- एल्यूमीनियम चार्जिंग	बैटरी	5-50	35-00
7- एल्यूमीनियम चार्जिंग	११	5-20	35-20
8- लीड अम्ल बैटरी	११	2-10	14-10
9- 11 बैटरी टोपिंग एल्यूमीनियम	संख्या	60	398
10- फ्लूइड बैटरी चार्जिंग	संख्या	60	398
11- टर्मिनल			
11/0-416 बैटरी, 2 5 बैटरी	संख्या	30	185
11/0-416 बैटरी, 15 बैटरी	११	15	140
11/0-416 बैटरी, 5 बैटरी	११	15	73
12- एल्यूमीनियम चार्जिंग	संख्या	1800	12000
13- एल्यूमीनियम चार्जिंग इन्वर्टर	११	7200	48000
14- लीड अम्ल बैटरी के लिए	११	10800	72000
15- इलेक्ट्रोलाइट	११	3000	20000
16- चार्जिंग	बैटरी	30-00	200-00
17- इलेक्ट्रोलाइट	११	34-00	224-00
18- एल्यूमीनियम चार्जिंग इन्वर्टर, 11 बैटरी के लिए	बैटरी	200	1375
19- लीड अम्ल बैटरी चार्जिंग इन्वर्टर एल्यूमीनियम के लिए	बैटरी	300	2100
20- चार्जिंग	बैटरी	74-00	488-00

वैदुतिकरण को उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्त आवश्यक व्ययों को भी रोजवार प्राप्त होगा। वर्ष 1975-76 में लगभग 30,000 और 78-79 में 50 हजार तक व्यय का रोजवार प्राप्त होने का अनुमान है।

===== 0 0 0 =====

13-आधीन एवं तद् उद्योगः-

11-औद्योगिक दृष्टिकोण से यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। इस जिले में कौतुपय आरा मशीन तथा आटा चक्कियों के अतिरिक्त उद्योग नही नगण्य है। इस औद्योगिक पिछड़ेपन के लिये यहां की भौगोलिक स्थिति मुख्य रूप से बाधक है। क्यों कि पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहां पर यातायात की सुविधाये प्रयाप्त नहीं है और जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार तथा खोधादेश यहां से 200 कीलोमीटर की दूरी से अधिक है। यहां के निवासियों की जीविका का मुख्य साधन खेती है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहां खेती के लिये उपजाऊ भूमि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और इस प्रकार यहां के निवासी कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी वर्ष में केवल केवल तीन या चार फास की आवश्यकता के लिये ही अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। जिले में 5.5% क्षेत्रफल पर सिंचन प्रकार के बने हैं जिनमें अनेक प्रकार की औद्योगिक उपयोग की लक्ष्मी उपलब्ध है किन्तु अभी तक इस सम्पदा का पूर्ण उपयोग जिले के औद्योगिककरण के लिये नहीं हो पाया है। प्रति वर्ष हजारों मन तीसा तथा हजारों मन उम्पस्त्रिक इट लक्ष्मी इस जिले से वैदानी क्षेत्रों के कारखानों में कच्चे माल के रूप में बाहर भेजी जाती है। लेकिन इस कच्चे माल का उपयोग यहां के औद्योगिककरण के लिये नहीं हो पा रहा है।

यह जिला वर्ष 1960 से बना प्रदेश का उद्योग विभाग जिले के सृजन से सेयहां पर औद्योगिककरण के लिये प्रयास करता रहा और वर्तमान समय में यहां पर 12 इकाईयों का उत्पादन किया जा रहा है। इन इकाईयों पर विभिन्न कलाओं में प्रोत्साहन दिया जाता रहा है जिससे कि जनपद में औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा सके। विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था श्री विभाग द्वारा की जाती थी और अक्टूबर वर्ष 1973-74 तक 85 और 1974-75 में 15 कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थापना सम्भव हो पाई है। वर्ष 1975-76 में 15 इकाईयों स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिनमें से दिसम्बर 1975 तक 6 इकाईयों की स्थापना हो चुकी है, इन 106 इकाईयों में से 37 इकाईयां व-उद्योग विभाग द्वारा से कच्चा माल अनुभाग द्वारा पंजीकृत हैं।

28- चतुर्था पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्नांकित योजनाये जिले में कार्यरत रहती थी।

13- आयोजित योजनाये:-

14- कार्टिंग प्लांट जल चरवाहा योजना जिसके अन्तर्गत उन विकास योजना भी सम्मिलित है।

इस योजना के अन्तर्गत एक कार्टिंग प्लांट तथा 6 जलचरवाहे जिले के विभिन्न स्थानों पर चालू हैं। कार्टिंग प्लांट पर विभागीय उन परिष्कृत करने के अतिरिक्त स्थानीय वारीयों की उन भी परिष्कृत की जाती है और जलचरवाहे पर पानी की सप्ली का उपयोग कर इस पर सप्लीमेंट ग्रैव चला कर लाभ उत्पादन किया जाता है।

वह योजना स्थानीय कारीगरों के लिये बहुत लाभप्रद है और इससे उत्तरी वस्त्रों की उत्पादन क्षमता व विस्तार में प्रयाप्त सुधार हुआ है।

2१- उन उपयोगी केन्द्र :-

इस योजना का एकमात्र केन्द्र नन्दप्रयाग में स्थापित है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्थानीय कारीगरों को रुख बिनाई तथा रंगाई आदि की सार्वजनिक सुविधा प्रदान करना तथा नई बिधियों का प्रसार करना है।

3१- विभिन्न रंग एवं सचल रंगाई केन्द्र २० जिले में 2 प्रिन्सिपल रंग एवं सचल रंगाई केन्द्र स्थापित हैं। उन उपयोगी केन्द्र की शक्ति इस केन्द्र द्वारा स्थानीय कारीगरों को रंगाई आदि में सुविधा देने प्रदान की जाती है और रंगाई की नई बिधियों का प्रसार किया जाता है।

4१- व्यापार संगठन योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत जिले में 3, वही केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें विभागीय केन्द्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन किया जाता है। ये केन्द्र जिले के प्रमुख स्थानों में स्थित हैं जैसे मोशीमठ / श्रीमन्तल्ला, चण्डीली - बदीनाथ।

5१- कढ़ाई बुनाई एवं माल गरीबा बुनाई योजना :- इस योजना के अन्तर्गत साल, गलीचा तथा कढ़ाई बुनाई के 3 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर विभागीय कार्य के साथ साथ उक्त वस्तुओं में वर्ष 1973-74 तक प्रशिक्षण भी दिया जाता था।

6१- डीजरी एवं जूट-दगीमरी योजना :- इस योजना के अन्तर्गत दो उत्पादन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

7१- नमदा निर्माण केन्द्र :- इस केन्द्र के अन्तर्गत नमदा निर्माण विभाग में वर्ष 1973-74 तक प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन कार्य भी किया जाता है। वर्तमान समय में इसमें कार्य उत्पादन ही रहा है।

8१- बहुई गिरी एवं पापड़ी वस्तु निर्माण योजना :- इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण विभागों को "कूच वस्तु" एवं "पापड़ी" की वस्तुओं के निर्माण में वर्ष 73-74 तक प्रशिक्षण दिया जाता था तथा वर्तमान समय में केवल उत्पादन कार्य किया जाता है।

9१- कृषि उपकरण व शातुकला केन्द्र :- इस योजना में लोहे की वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण वर्ष 1973-74 तक किया जाता था तथा वर्तमान समय में कृषि उत्पादन का कार्य किया जाता है।

10१- चर्म उद्योग :- इस केन्द्र पर चर्म सीधुन एवं जूता निर्माण प्रशिक्षण दिया जाता था तथा अब उत्पादन किया जाता है।

11१- रिंगल उपयोगी केन्द्र :- इस केन्द्र पर रिंगल की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वर्ष 1973-74 तक प्रशिक्षण भी दिया जाता था।

चतुर्थ योजना के पूर्व वर्ष 1968-69 तथा योजना के अन्तिम वर्ष 73-74 में कार्यरत 12 उत्पादन-केन्द्रों के उत्पादन लक्ष्य व पूर्ति का तुलनात्मक विवरण तथा वर्ष 74-75 की उपलब्धि निम्न प्रकार है-

	1968-69		1973-74		1974-75
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति
19- कर्तबगुम साइट ज लघुसहा योजना व उन विकास योजना-केन्द्रों में	5000	5338	6950	6470	760
20- कम्प्लेक्स एवं पायटो योजना	₹ 13000	11762	20000	564820 56630	48820
30- कड़ाई विनाई शाल गलीचा	₹ 14000	13741	20000	19179	15726
40- कृषि उपकरण व सातुकला	₹ 15000	15380	50000	28146	14568
50- सचस रियाई योजना	₹ 1600	3812	12000	13687	14134
60- उन उपयुक्त योजना	₹ 600	272	5500	2592	1455
70- लघु निर्माण योजना	₹ 2000	3096	2600	2633	3300
80- कच्चा माल तथा अन्य विपणन डिपो	20000	33963	35000	17300	18670
90- व्यापार संगठन योजना	₹ 35000	39863	45000	83873	90528
100- रिगल उपकरणों योजना	₹ 7500	1554	500	676	1288
110- चर्मोद्योग व मुता निर्माण	₹ 3000	5230	5000	2375	1606
120- कर्मचारी व होमरी योजना	₹ 6000	6136	8000	7000	6024

उपरोक्त योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति के अनुसार कम्प्लेक्स परियोजना, कृषि उपकरण व सातुकला परियोजना, कर्तबगुम साइट, उन विकास योजना, व्यापार संगठन योजनाओं की उपलब्धि विशेष रूप से उत्साह बढ़ाईक रही। उनके अतिरिक्त अन्य केन्द्रों की उपलब्धि भी सन्तोषजनक रही। कृषि उपकरण व सातुकला योजना के उत्पादन के लक्ष्य पूर्ति, टिन सीट न मिलने के कारण न हो सकी।

जनपद में औद्योगिक विकास का पर्याप्त क्षेत्र होते हुये भी अवस्थापना सम्बन्धि सुविधाओं की उपलब्धि का पर्याप्त न होने के कारण निम्न उद्योग पाँचवीं योजना में नहीं प्रस्तावित किये जा सकते हैं। अतः पाँचवीं योजना की अवधि में याता यात विद्युतीकरण आदि के विकास के उपरान्त छदी व सातवीं योजना में निम्न क्षेत्रों में ऐसे बृहत उद्योग पथी चलाने जा सकेंगे:-

- (1) स्टीन प्रोसेसिंग इकाई (2) अद्युक्तिक औद्योगिकालय निर्माण (3) ओटोमोबाइल कार्यशाला
- (4) याता यात उद्योग (5) स्टीलफर्निचर (6) औरिज मील आयल (7) पर्निचर व कृषि उपकरण ।

प्रदेशीय विद्युत् विभागों के माध्यम से लक्षित 6-10 लाख रुपये की वार्षिक है इन उद्योगों को विद्युत् वितरण का अनुदान का वितरण कर सहायता मिलेगी। ये उद्योगों को सहायता मिलेगी तक आगे पूरा लगता से कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। वर्तमान समय के विद्युत् के ताकत अर्थव्यवस्था के वातावरण पूर्ण रूप से विद्युत् विकसित नहीं हो पाया है विद्युत् के क्षेत्र स्थानीय उद्योगों में बड़े उद्योगों में घुनी लगाने के जोखिम उठाने का तैयार नहीं है। अतः लघु व सूक्ष्म उद्योग उद्योगों को लगाने का भी प्रस्ताव योजनाकाल में किया गया है।

आगामी योजनाओं में उद्योगों की सुगम बनाने के कारखाने, कागज मल्ला निर्माण इकाइयों, प्रसारण उद्योगों, इकाइयों, हाई वोल्ट निर्माण इकाई और सीधु नार्मी के क्षेत्रों से विद्युत् तैयार करने को इकाइयों लगाने का उद्योग है। ये इकाइयों बृहत् उद्योग इकाई के रूप में चलाने जा सकेंगे तथा इन उद्योगों के लिए पैसे का माल विद्युत् के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकेगा। इन उद्योगों को आरम्भ करने के लिये विद्युत् उत्पादन के लिये पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होगी अतः यह है कि पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन का क्षेत्र को विद्युत् उत्पादन पर्याप्त विचार प्राप्त हो सकेगी और इन उद्योगों के विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी।

पंचम पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल - पंचम पंच वर्षीय योजनाकाल में विद्युत् विद्युत् परियोजनाएँ कार्य में स्थित विद्युत् क्षेत्र का प्रस्ताव है -

- 18- विभागीय योजना -
 - लघु क्षेत्रीय उद्योग
 - (18) अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग - योजनाकाल में विभाग का कार्य क्षेत्र व उत्तर दाहत्व बढायेगा। इसके लिये जिला उद्योग कार्यालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी। जिले के अन्तर्गत योजना का कार्यालय के निर्मित निम्न लिखित अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी -
 - 19- औद्योगिक निरीक्षक
 - 20- अधीक्षक ऋण अनुदान
 - 21- प्रकाश लिपिक
 - 22- कैलकुलेशन
 - 23- आशु लिपिक
- उद्योगों के कर्मचारी विभागीय संस्थागत ऋण अनुदान की वसूली तथा निजी क्षेत्र में निजी उद्योग पतियों को सहायता को मार्ग दर्शित करेंगे। अन्य तीन कर्मचारी कार्यालय के कार्य संवर्धन में सहायक होंगे। इन कर्मचारियों को वर्ग 75-76 में विद्युत् क्षेत्र जाने का प्रस्ताव है और उक्त वर्ग में इन पर 40 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

24- अ- विद्युत् राज सहायता -
इस योजना के अन्तर्गत निजी उद्योग पतियों को विद्युत् की खपत -

पर सहायता प्रदान की जावेगी जिसके लिये योजना काल में 1-00 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है। तथा वर्ष 75-76 में 10 हजार रु० विद्युत सहायता हेतु परिव्यय निर्धारित है।

(ब) जनरेटिंग सेट लगाने हेतु समिती:-

जो निजी उद्योगपति अपनी इकाइयों के संचालन के लिये जनरेटिंग सेट लगा कर विद्युत उत्पादन करेंगे उनके सहायता के रूप में समितीडी वितरित की जावेगी। योजनाकाल में इस कार्य के लिये 5-00 लाख तथा क्षेत्र योजना के वर्ष 75-76 में 10 हजार रु० निर्धारित किये गये है।

3- औद्योगिक सहकारिता अवस्तीय:-

चतुर्थ योजना काल में जिले के अन्तर्गत सहकारी समितियों का गठन सम्बन्धित कार्यालयों के अभाव में न ही हाँ पाया है। वर्तमान योजना में सहकारी समितियों के गठन हेतु निम्न कार्यालयों की आवश्यकता होगी जो कि समितियों के पुनर्गठन उनके लेखों की जाँच आदि करेंगे। योजना में इनके लिये 1-00 लाख रु० का प्रावधान है। तथा योजना के द्वितीय वर्ष 75-76 में 15 हजार रु० का प्रावधान इस कार्य के लिये किया गया है।

1- प्राथमिक सहायक (2) सहकारिता निरीक्षक (3) चपरासी (4) चौकीदार।

4- प्रदर्शनी व गैलरी:-

जनपद में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिये प्रचार सामग्री की आवश्यकता होगी जिसके लिये योजना के द्वितीय वर्ष 75-76 के लिये 10 हजार रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

5- गुणबिन्हाकन योजना (कमलिटी प्रदर्शन प्रीम):-

जनपद में जर्जर का बहुतायत होने के कारण यहाँ पर कच्छला उद्योग का कच्चा माल प्राप्त मात्रा में कुलभ है। इस उद्योग के विस्तार की प्रयाप्त सम्भावना को दृष्टिगत करके जिले में एक गुण बिन्हाकन योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिससे कच्छला निर्मित वस्तुओं के गुणों में सुधार किया जा सके।

6- उद्योगियों द्वारा अध्ययन दौरा:-

इस जनपद के उद्योगियों को अन्य जनपदों व उद्योग कक्ष प्रान्तों/जनपदों में क्षेत्र के पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है। जिले के उद्योगी अन्य जिलों में जाकर उद्योग के विषय में नई जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके आने जाने में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

7- लघु उद्योग पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने हेतु अनुदान:-

निजी उद्योगपति अपने उद्योग के सम्बन्ध में देश के सम्बन्धित उद्योग में विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायेगे। इस कार्य में जो वित्तीय व्यय होगा उद्योगपतियों को अनुदान के रूप में धानराशि भुगतान की जावेगी।

81- राष्ट्रीय उत्पादकता परिवर्धन कार्यक्रम द्वारा उद्योगिकता परामर्श योजना-

जिले के उद्योग पतियों को अपने उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये परामर्श आदि लेने हेतु जो व्यय होगा उसके लिये विभाग कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में उद्योगों को पैसा देगा-

9- प्रशिक्षण आदर्श विद्यालय योजना-

(अ) इंदौर जिले - संयोजित योजना में इंदौर में 3 लाख 50 हजार रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

10- राष्ट्रीय जिले के लिये राष्ट्रीय परामर्श योजना काल में उद्योगपतियों के उद्योगों की स्थापना व उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये 5 लाख 50 हजार रुपये के ऋण वितरण का प्रस्ताव है। जिले 75-76 में 14 हजार 50 व्यय करने का प्रस्ताव है।

11- संयोजित योजना में उद्योग-

जिले में उद्योगों की संख्या कम है बताने में वर्तमान समय में शिथिलता है। उसके ऊपर कार्य में उद्योगों के प्रवेश कम है बताने पर कुछ कर्मचारियों व अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी। योजना काल में इस कार्य के लिये 1 लाख 50 हजार का प्रस्ताव है।

12- आवासीय / कार्यालय भवन निर्माण-

जिले में आवासीय व कार्यालय भवन तथा कर्मचारियों की आवासीय भवन निर्मित नहीं है। इसके लिये योजना काल में 3 लाख 50 का प्रस्ताव है।

13- हस्त शिल्प-

1- हस्त शिल्प सहकारी समितियों का विकास तथा वित्तीय सहायता-

जिले में वर्तमान समय में हस्त शिल्प सहकारी समितियों का गठन नगण्य है। इसके विकास व उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये योजना में प्रस्ताव है।

2- अभिलेखित आवासीय व कार्यालय भवन निर्माण-

प्रदेश स्तर पर वर्तमान समय पर हस्त शिल्प की वस्तुओं के प्रचार हेतु साप्ताहिक कार्यक्रम चले जाते हैं। इस हस्त शिल्प सहकारियों में भाग लेने के लिये हस्त शिल्पियों को वित्तीय परामर्शियों को अपनी उत्पादित वस्तुओं सहित निर्धारित स्थानों पर जाकर-सुचना है। इस कार्य के लिये जो अनराशि खर्च होगी उसके पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

रियासत लक्ष्मी के विशाल प्रचार की दृष्टि से जलो हेतु जलो जिले में प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना

जनपद जलो में रियासत काफी मात्रा में उपलब्ध है इसके उपयोग के लिये योजना काल में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। योजना काल में इस केन्द्र की स्थापना हेतु 5 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1975-76 में 65 हजार 50 व्यय करने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प इकाइयों की तथा कारीगरों का सर्वेक्षण -

हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिये जनपद के पुस्तैनी हस्तशिल्पियों का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है इस कार्यक्रम को योजना में प्रस्तावित किया गया है । उक्त विभागीय कार्यक्रम के लिये पाँचवी योजना में 24.05 लाख , वर्ष 1974-75 में 19.5 अर्थात् वर्ष 1975-76 में 15.5 लाख रुपया का विभागीय परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

प्रस्तावित योजनाएँ :-

(अ) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास विभाग द्वारा प्रदत्त कर यशिन उत्पन्न कराये जाने पर व्यय का स्तर :-

जनपद के उद्योगपतियों के लिए का प्रयत्न वृद्धि के अन्तर्गत लघु उद्योग विभाग द्वारा अणु वितरण किया जायेगा । इस अणु पर जो व्यय उद्योगी को वहन करना पड़ेगा उस पर विभाग द्वारा सहायता की जायेगी जिसे मिलके लिये योजना काल में 10 हजार रु का प्रस्ताव है । वर्ष 1975-76 के लिये एक हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित है ।

(क) विद्युत का प्रदत्त पर यशिन :-

विद्युत का प्रदत्त के अन्तर्गत उद्योगपतियों को यशिन करके पूर्ति की जायेगी जिसके मूल्य की अद्यतनी किस्तों में करना होगा । इस परियोजना के लिये वर्ष 1975-76 में 8 हजार रु का परिव्यय निर्धारित है ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विभाग द्वारा सहायता की विनियोजनाएँ :-

इस योजना के अन्तर्गत विभाग उद्योगियों के उद्योग में अपनी अंश पूजी सहायता दे करी में सहायता और उद्योग में होने वाली लागत का भाग भी लेगा । इस कार्य के लिये योजनाकाल में 1 लाख रु का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा सहायता :-

उद्योगपतियों को विद्युत सहायता के लिये निगम अणु वितरित करेगा इस हेतु पाँचवी योजना काल में 5 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 25 हजार रु का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इन संस्थागत योजनाओं के लिये पाँचवी योजना काल में 68.10 लाख , 1974-75 में 33.70 लाख तथा 1975-76 में 34.40 लाख रु का परिव्यय निर्धारित है । जनपद में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अणु तथा विभागीय अणु के अतिरिक्त उद्योगपति को भी जाने सहायता से कुछ पूजी सहायता होगी- जो अनुमानतः 40 प्रतिशत होगी । इस प्रकार पाँचवी योजना में 4 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 16 हजार रु जनपोषित स्त्रोत से व्यय करने का प्रस्ताव है ।

खादी एवं ग्रामीणोद्योग बोर्ड :-

जिले में औद्योगीकरण हेतु खादी एवं ग्रामीणोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान करने के लिये पाँचवी पाँचवी योजना में 11.07 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 1.75 हजार रु परिव्यय निर्धारित किया गया है ; वर्ष 1974-75

में 224 हजार ₹ का परिव्यय निर्धारित किया गया था ।

परियोजनावार परिव्यय का वितरण इस प्रकार है:-

परियोजना	1975-76 का परिव्यय (हजार ₹)	पाचवी योजना का परिव्यय (हजार ₹ में)
1- काँठ कला	15	82
2- कुपीर दिवास्ताई	-	18
3- बुम्हासी उद्योग	-	82
4- मैन पालन	2	8
5- रेशा उद्योग	-	17
6- हूना उद्योग	-	32
7- बनौषीय उद्योग	3	49
8- बीस, बैत उद्योग	-	8
9- पक्कीय ऊन योजना	155	768
10- साइर उद्योग	-	43
=====		=====
योग		योग
175		1107

दूधगाय स्टेट डेरी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा योगदान:-

कारपोरेशन ने जिले में स्तन वर्मिडायन में पैकिंग केसेज बनाने हेतु एक कारखाने की स्थापना की है । इस कारखाने में 1974-75 में 278 हजार ₹ व्यय किया जा चुका है और आशा है कि वर्ष 1975-76 में उत्पादन प्रारम्भ हो जावेगा इस कारण से के संयोजन हेतु कारपोरेशन ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना में 1040 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 310 हजार ₹ अतिरिक्त निर्धारित किया है । पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में 12860 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 10360 लाख ₹ मूल्य के पैकिंग केसेज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

हथकरघा- रेशम एवं ट्यूबल धीन नायें

जनसह चर्पाही की उपयुक्त जलवायु, निवासियों की आर्थिक स्थिति एवं अन्य कुटीर उद्योगों की अत्यन्त कमी से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 में रेशम कीट पालन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । प्रारम्भ में किसानों द्वारा रेशम कीट पालन एवं सहतुत बृष्णारोपण सम्बन्धी कार्य किये गये, जैसे कीट पालन हेतु जलवायु का उपयुक्त होना, वर्ष के कौन कौन से माह व ऋतुओं कीट पालन हेतु अनुकूल है, प्रत्येक फसल में कौन कौन सी उन्नत जातियाँ के कीट व्यावसायिक रूप में सफलता से पाले जा सकते हैं । एवं उन्नत जाति के सहतुत बृष्णों की वृद्धि हेतु अनुकूल पौधों का चुनाव इत्यादि ।

1969-70 तक प्रयोगात्मक कार्यक्रम पूर्ण एखलना से सम्पन्न किये गये एवं यह सिद्ध हुआ कि जनपद में रेशम योजना के द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है तथा प्रदेश में रेशम उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में जनपद के अनेक भागों में योजना के प्रसार एवं विस्तार हेतु सहतुत फार्म स्थापित किये गये जिनके द्वारा प्राथमिक अवस्था में जापानी जाति के उन्नत प्रकार के कीटों को पाल कर स्थानीय कीटपालकों को बाँटे जाते हैं जिनका आगामी दो-तीन साल तक तकनीकी विधि अनुसार रेशम कोष तैयार किया जाता है। अर्थात् ग्रामीणों में वृक्षारोपण हेतु ग्रामवासियों को निम्न उन्नत जाति के सहतुत वृक्ष दिये जाते हैं। ग्रामवासियों को प्रोत्साहन देने की योजना भी लागू की गई है। इन समस्त कार्यों के फलस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक जो उपलब्धियाँ हुईं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्य	इकाई	उपलब्धि
शुद्धि क्रम	हेक्टेयर	59-65
सहतुत पौधा वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में	शिपमेंट	106254
कोषा उत्पादन	कीटपालकों में	2814
प्रशिक्षण	सीधे	49

वर्ष 1974-75 में 1270 कीटपालकों कोषा उत्पादन किया गया और 5 हजार सूत के बूझ सम्पन्न गये।

कीटपालकों द्वारा उत्पादित कोषों का क्रय बिक्रय विभाग के माध्यम से किया जाता है।

इन सब कार्यों का द्वारा योजना का प्रसार इस जनपद में तेरह गति से हुआ है। किन्तु कोषा उत्पादन के लिये सम्यक् बड़ी कठिनाई सहतुत वृक्षों की कमी अनुभाव की गई है जो कि इस जनपद में पुराने समय से लगाने गये कोई सहतुत के वृक्ष नहीं है। अब विशेष प्रयास इस ओर किया जा रहा है जो कि योजना का विस्तार केवल सहतुत वृक्षों की उपलब्धि पर ही निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुये पंचम पंचवर्षीय योजना में सहतुत वृक्षारोपण हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इस योजना में एक बड़ा सहतुत पौधातय स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया है।

जैसे जैसे जनपद के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सहतुत वृक्ष तैयार होंगे एवं ग्रामोद्योग वृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसी अनुसार कोषा उत्पादन में भी वृद्धि होगी तथा कीटपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। यह निश्चित है कि आगामी 10-20 वर्षों में यह जनपद रेशम कोषा उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का एक क्षेत्र बन जायेगा जिसके निवासी इस उद्योग से बहुत लाभ उठा सकेंगे तथा उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जायेगा।

जैसे जैसे वृक्षारोपण होगा उसी पर आधारित कीटपालन केंद्र तथा फार्म भी स्थापित किये जायेंगे जिनके द्वारा उन्नत प्रकार के कीट ग्रामीणों में वितरित किये जायेंगे।

तथा विभागीय कर्मचारियों की देखरेख में तकनीकी विधि-अनुसार द्वारा कीटपालन करा कर कोया उत्पादन कराया जायेगा। पंचवर्षीय-योजनाकाल में 6 हजार कीटों का प्रायः वर्ष 1975-76 में स्थान एक हजार कीटों का कोया उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राथमिक कीटपालकों को प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम रखा गया है ताकि आने वाले वर्षों में वे तकनीकी विधि द्वारा कीटपालन कर सकें।

जिसे में रेशम योजना की कार्यान्वित करने के लिये पंचवर्षीय योजनाकाल में 1-95 लाख और वर्ष 1975-76 में 63-9 हजार रुपये का परिष्वय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1974-75 में 83-9 हजार रुपये परिष्वय के विपरित 52-8 हजार रुपये का व्यय किया गया।

उत्तर प्रदेश विकास योजना

उत्तर प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में 7 हजार से 7 हजार फीट की ऊँचाई तक बीज के जमाव का कार्य सम्पन्न हो चुका है। जलोत्पी जनपद में भी बीज के पर्याप्त वन उपलब्ध हैं। इस समय बीज का उपयोग मुख्य रूप से जमाव के लिये अथवा जलाने की तकनीक के लिये किया जाता है। चीन ने बीज पर उत्तर के बड़े पैमाने पर अपने निर्यात को बहुत अधिक बढ़ाया है और इस प्रकार के बीज की माँग विदेशों में बहुत अधिक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969-70 से उत्तर कीट पालन का कार्य भारत में भी फलरूप दिया गया और इसमें हमें आशावादीता प्रकट हो गयी है। परिश्रमों से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसी जमाव को जलवायु व इस क्षेत्र में पायी जाने वाली बीज की परिस्थिति उत्तर पालन के लिये उपयुक्त है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक 27,257 बीजों का उत्पादन किया गया और 50 करोड़ रुपये की प्रशिक्षण किया गया। वर्ष 1974-75 में 59-19 कोया उत्पादन किया गया। पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 में प्रकृत 1-50 तथा 0-225 लाख कोया उत्पादन का लक्ष्य है। उत्तर योजना के लिये पंचवर्षीय योजना में 3-29 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और वर्ष 1975-76 के लिये 17-8 हजार रुपये परिष्वय निर्धारित है। वर्ष 1974-75 में 50-2 हजार रुपये परिष्वय के विपरित 8-3 हजार रुपये व्यय किया गया।

उपर्युक्त सब प्रयत्नों से पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सका और लगभग इतने ही व्यक्तियों को अल्पकालिक काम भी मिल सकेगा। इन प्रयत्नों से जिले की प्राथमिक जनता की आय में बृद्धि होने के अवसर प्राप्त होंगे।

(14) - खनिज विकास

जनपद में विभिन्न खनिज पदार्थ पाये जाते हैं किन्तु उनको पत्रा ले बारे में कोई निश्चित धारणा अभी तक नहीं बन पायी है । खनिज पदार्थों के विषय में जिन अनुचित जानकारी भ्रूक्षी शास्त्रों में से द्वारा उपलब्ध किये जाने के बाद हो हो गयेगी । पंचम पंच वर्षीय योजना में भ्रूक्षी शास्त्रों द्वारा जनपद में मैनेसइट , सोफस्टोन और तथा धातुओं के अनदेखण का कार्य हुआ बनाया गया है इस हेतु पंचम पंचवर्षीय योजना में 5 लाख और वार्षिक योजना 1975-76 में 10 हजार स्वयं परिवर्ण निश्चित है । वर्ष 1974-75 में उक्त अनदेखण हेतु 25 हजार स्वयं परिवर्ण निश्चित किया गया था जिसे विपरित 10 हजार स्वयं व रण किया गया ।

=====

(15) - बिहार का स्थिति

=====

जनपद चौली व्यापक दृष्टि से राज्य का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किन्तु भौगोलिक एवं रक्षात्मक दृष्टि से इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। शासन भी इस बात को ही ध्यान में रखता है कि विभिन्न भागों क्षेत्रों में रेल संसार शुरू होने के कारण मोटर मार्ग निर्माण का प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

2- इस जिले का प्रदेश के अन्य भागों से रेल मोटर मार्गों से सम्पर्क है। यहाँ इस समय 641 कि०मी० मोटर मार्ग उपलब्ध हैं। जनपद में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। जिले के प्रमुख मोटर मार्ग निम्न लिखित हैं।

- (1) - हरिद्वार - बदीनाथ मोटर मार्ग जिले द्वारा देहरो मद्रास, पौड़ो और देहरादून जनपदों से सम्पर्क होता है।
- (2) - लक्ष्मणपुर - रामोखेत व
- (3) - लक्ष्मणपुर - गधालदय (अलीगढ़) मोटर मार्ग जो जनपद को अलीगढ़ व नैनोताल और पिथौरागढ़ से जोड़ती है। जनपद के दार्जौली उप-प्रभाग इन्हीं मुख्य मार्गों के पैदानो एवं रेल मार्गों से जो कि लखीमपुर, देहरादून, रामपुर, लोटद्वार और काठगोदाय में स्थित है, जुड़े हैं। इन्हीं मार्गों के द्वारा प्रदेश को राजधानी लखनऊ का सम्पर्क भी जनपद से स्थापित होता है।
- (4) - लक्ष्मणपुर - उज्जैन - चौली मोटर मार्ग उक्त मार्गों से जिले के समस्त तहसील मुख्यालय एवं अति विकास बौद्ध मुख्यालय जुड़े हुए हैं।

3- जिले के क्षेत्र के आधार पर यहाँ का घनत्व पैदानो भागों को तुलना में ही कम है जो, उत्तराखण्ड के अन्य जिलों को तुलना में भी सबसे कम है, जैसा कि निम्न तालिका में विदित होता है :-

जनपद	मोटर मार्ग प्रति हजार जनसंख्या (कि०मी०)	मोटर मार्ग प्रति 100 वर्ग कि०मी० (कि०मी०)
1- चौली	2-10	7-02
2- उत्तरखण्ड	5-29	10-57
3- पिथौरागढ़	2-48 2-89	13-21

शासन को जितने क्षेत्रीय असाधनता को दूर करने को है। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि जिले को विभिन्न जिलों के आधार में असाधनता दूर करने के लिये चौली जिले में पड़क निर्माण को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन दिया जाये।

4- प्रति हजार जनसंख्या और प्रति किलोमीटर वर्ग कि०मी० पर 1968 में क्रमशः 2-17 तथा 6-13 कि०मी० मोटर मार्ग उपलब्ध थे जिसको बीसो योजना के अन्त में प्रति क्रमशः 2-10 तथा 7-02 कि०मी० हो गई। जनसंख्या तथा क्षेत्र से ही आधार पर मोटर मार्ग के प्रक्षेप को संघी

लान है ।

इस समय तक निर्मित रोटर मार्गों से जनपद को केवल 135 ग्राम सभाओं को जोड़ा जा सका है, जब 373 ग्राम सभाओं को भी यह सुविधा प्रदान की जानी है । जनपद में 537=500=37=373 ग्रामों से अधिक आबादी वाले कुल ग्रामों की संख्या 79 है । इस समय तक 36 ऐसे ग्रामों को रोटर मार्गों से सम्बद्ध किया गया है ।

जिले का क्षेत्र रू बहुत अधिक है । और गाँव छिछोटे से बने हैं इस कारण सभी गाँवों को रोटर मार्गों से सम्बद्ध कर वापस तो बर्बाद कइयो भी सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि 500 तक की आबादी वाले ग्रामों को रोटर मार्ग से जोना निरन्तर आवश्यक है । जिससे सभी औद्योगिक एवं विपणन केन्द्र तथा उद्योगक्षेत्र रोटर मार्ग से सम्बद्ध हो पाएँ । अग्रे भी बहुत से ऐसे ग्राम हैं जहाँ पहुँचने के लिये 25 कि०मी० तक पैदल चलना मजबूत पड़ता है ।

जिसो भी क्षेत्र से विकास के लिये संशोधन व्यय रू का निष्कास होना परम आवश्यक है उसी के समानांतर ही सड़कों से उपलब्ध होने से जिसो भी क्षेत्र से उत्पादक एवं औद्योगिक निर्माण को बसूरे आठे समार तक पहुँचाना सम्भव हो सकता है । जिले को पाँचों पंच-वर्षीय योजनाओं इसो उद्देश्य से बनाई गई है कि आवागमन तथा विद्युत् का एकत्रणी सुविधाएं मनीष्यजनक रूप से उपलब्ध हो सकें, पर्यटन को दृष्टि से जिले का महत्व बढ़े और अखिल से अधिक अस्त प्रदेशों में जोड़े का लगे लगे क्लों को विकासो सस्ते दरों पर सम्भव हो सकें ।

5- पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 132 कि०मी० नये रोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । प्राथमिकता के आधार पर कृत्ति देते हुये निम्नलिखित मार्गों को चुने बनाई गई थी । अग्रे मार्ग शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों व जिला परामर्श दायि निर्मित द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के आधार पर लिये गये थे और इन मार्गों के प्रस्ताव पर अधिभूष अभियन्ता सर्वेक्षण निदेश वेधा, 38वीं कुल को भी महति प्राप्त कर ली गई थी । इन योजनाओं में जिन मार्गों को स्वीकृत नहीं कि जिल पायेगी उन हैं अग्रे को योजना में मयिल किया जावेगा :-

- 1- सुन्दोलो - वीरग - 25 कि०मी०
- 2- सोपेखर - उरुग - 60 कि०मी०
- 3- मेलचौरो - बहुवाबाण - 23 कि०मी०
- 4- घाट - रामगो - 30 कि०मी०
- 5- भलो पैण - पैरौण 40 कि०मी०
(चाली जनपद का मार्ग)
- 6- वर्णप्रभा - नौतो 35 कि०मी०
- 7- सोपेखरघाट - धंधेरिया 25 कि०मी०
- 8- सुप्तकाणो - बालोठ-नौडार- 30 कि०मी०

कु संख्या 7 व 8 पर अखिल मार्ग पर्यटन को दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों की समुह

स्वीकृत के विपरित प्रस्तावित किये गये हों।

6- जनपद में सड़कों के निर्माण हेतु पंचम पंचवर्षीय योजना में 92, 587 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 8, 390 हजार रुपया परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 1974-75 में 10, 605 हजार रुपया परिव्यय के विपरित 11, 286 हजार रुपया व्यय किया गया।

7- चतुर्थ योजना का शेष कार्य :- गत छह योजनाओं में स्वीकृत कार्य जो अधो तक पूर्ण नहीं हो पाये थे उन्हें पाँचवीं योजना में पूर्ण करने का संकल्प है।

8- निर्माण प्रयागो :- पंचम पंचवर्षीय योजना तथा 1975-76 में निर्माण कार्य को सम्पन्न करने हेतु अनुमानतः निम्नलिखित प्रयागो की आवश्यकता होगी :-

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये महत्वपूर्ण प्रयागो को अनुमानित प्राँ

क्र. सं.	वर्ग	कुल योग मीटर	वर्ष 1975-76
1-	डोमन्ट	23, 000	3400
2-	लोहा	1, 670	250
3-	श्रीकृत	129	18
4-	वेक फल	500	75

9- रोजगार :- प्रस्तावित योजना में श्रम का अनुमान निकाला गया है तदनुसार तत्कालीन आवश्यकता प्राप्त 105 अभियन्ता व अवर अभियन्ता, 100 लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी कार्यचारी तथा 1, 000 वर्य कृषिकों एवं श्रमिकों को औद्योगिक आधार पर निरन्तर रोजगार उपलब्ध होगा। यदि श्रमिकों को पूर्ण जिले से न हो पड़े तो कार्य समाप्त के लिये उन्हें अन्यत्र बाहर से बुलाना होगा।

10- जनपद में टोल :- वर्ष 1975-76 में टोल समाप्त कर दिया गया है।

अल्पानन्द में पुल का निर्माण कार्य प्रयाग पर हो लिया जा रहा है। सड़कों पर परिवहन का भार निरन्तर बढ़ रहा है। यद्यपि चलने वाली गाड़ियों को सड़क के किनारे कोई खड़ेवानों का आलू उभलव्य नहीं है तथा तेल मार्ग पर आने वाले भार को सज्जा अक्षय को गई है, जो 5 वर्ष पहले औसत 40 टन प्रति दिन था आज बढ़कर 56 टन हो गया है और आने वाले पाँच वर्षों में 200 टन प्रति दिन हो जाने का अनुमान है।

11- जनपद में वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को चार बसें तथा 381 निजी बसें चल रही थी। वर्ष 1974-75 में इनकी संख्या क्रमशः चार और 452 थी। यह बसें पीछे, उत्तर भागों तथा देहरो जिलों में भी चलती हैं। अतः इनकी मार्गों का जिला वार विभाजन सम्भव नहीं है। जिले में निजी बसें तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें के लिये मार्ग विभाजित नहीं हैं।

प्रक्षेप

उत्तराखण्ड के जिला चणौली में वोटर मार्गों को विभिन्न समय पर सम्भावित क्षति प्रति एक हजार जनसंख्या के आधार पर :-

वर्ष	सम्भावित जनसंख्या 1971 के आधार पर (1,000)	वोटर मार्ग कि०मी०	वोटर मार्ग कि०मी० प्रति हजार जन- संख्या	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
1-	1968	2, 58	560	2-17
2-	1972	2, 97	641	2-16
3-	1973	3, 01	641	2-15
4-	1974	3, 05	641	2-10
5-	1979	3, 28	773	2-36

चार्ज योजना के अन्त पर तैयारी विद्यमान जनपदों को क्षति लगभग निम्न प्रकार में है :-

चणौली	3, 05	641	2-10
उस्तामनगढ़ी	1, 56	826	5-29
भियौरगढ़	3, 31	957	2-89

इस प्रकार प्रति हजार जनसंख्या पर उपलब्ध वोटर मार्ग को देखते हुये भी चणौली जिला सबसे पिछड़ा हुआ है ।

प्रक्षेप

उत्तराखण्ड के जिला चणौली में वोटर मार्गों को विभिन्न समय पर सम्भावित क्षति क्षेत्रफल के अनुपात में :-

वर्ष	वोटर मार्ग कि०मी०	क्षेत्रफल का प्रतिशत	वोटर मार्ग कि०मी० प्रति 100 वर्ग कि०मी०	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
1-	1968	560	6-13	
2-	1972	641	7-02	
3-	1973	642	7-02	
4-	1974	641	9128 वर्ग कि०मी०	7-02
5-	1979	773		8-45

विमान्त जनपदों को सतुर्ग योजना के अन्तर्गत तुलनात्मक विवरण :-

1	2	3	4	5	6
	क्षेत्रफल	641	9128	7-02	
	उत्पन्नकृषि	826	7816	10-57	
	पिपौरासद	957	7243	13-21	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सड़की के घनत्व अर्थात् प्रति 100 कि०मी० क्षेत्रफल पर सड़क की उपलब्धता को देखते हुए 8 गो जनपद क्षेत्रीय उत्तराखण्ड के अन्य जिलों के मुकाबले में फे पिछड़ा हुआ है और उसी उन्नति के लिये सड़क निर्माण को प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य होगा ।

दरों का लगभग विवरण

अ- मोटर मार्ग के नए निर्माण के लिये दरों का विवरण

1-	8 फीट की अदृश्यरहित सड़क प्रतिमीटर	रु०	10,000 प्रति कि०मी०
2-	घड़ाड़ो की तरफ सड़क $222 \times 1000 \times 60 \times 100 = 39,000$ क्यू०मी० दर स्वयं 400/= क्यू०मी०	रु०	1,20,000 प्रति कि०मी०
3-	दिवाल, खबर, बावड़े व नालो का निर्माण	रु०	30,000 प्रति ,,
4-	15 से०मी० मोटा गोलियाँ लकड़े हिस्सों में लगभग $1/3$ कि०मी० प्रति कि०मी० दर 30,000/= प्रति कि०मी०		10,000 ,, ,,
5-	वैरापेट हो 10 मोटर पत्थर इतयदि	रु०	17,000 ,, ,,
6-	लघु खेती का निर्माण	रु०	30,000 ,, ,,
7-	मार्ग निर्माण के समय में सड़क का रखरखाव व गोलियाँ लकड़े	रु०	15,000 ,, ,,
8-	मार्ग स्थल पर अज्ञात एवं भावनों का निर्माण	रु०	5,000 ,, ,,
9-	सड़कीनरो व टोकरण्ड को लगभग 5%	रु०	13,000 ,, ,,

योग :- रु० 2,50,000 प्रति कि०मी०

===== 0 0 0 =====

जनपद की धार्मिक सूर्य प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिय स्थलों की दृष्टि से अद्वितीय महत्ता है। यहाँ बड़ीनाथ-देवदारनाथ जैसे धार्मिक महत्व के स्थान हैं जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ फूलों की घाटी, हैमकुण्ड आदि सूर्य प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिय स्थल भी विद्यमान हैं। श्री बड़ीनाथ-देवदारनाथ के सुपरिचित धर्मों के अतिरिक्त जनपद के कुछ प्रमुख दृष्टिय स्थलों का विवरण इस प्रकार है :-

१) गोविन्दघाट :- जोशीमठ से लगभग ७ मील की दूरी पर बड़ीनाथ मोड़मणी से शक्तिमठ नदी की घाटी की ओर पैदल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर सिक्की का गुरुद्वारा है और यहीं से होकर फूलों की घाटी होते हुये हैमकुण्ड साहब को जाते हैं। हैमकुण्ड साहब सिक्की का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि वहाँ गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज ने तपस्या की थी। इस स्थल की उँचाई समुद्रतल से ४,००० मीटर है।

२) फूलों की घाटी :- गोविन्द घाट से लगभग १० मील की दूरी पर स्थित है जहाँ शरद ऋतु में नाना प्रकार के असंख्य पुष्प खिल जाते हैं। सम्पूर्ण घाटी फूलों से ढकी जाती है। समुद्रतल से उँचाई ३३५० मीटर है।

३) कुधारा :- यह एक जल प्रपात है जो बड़ीनाथ से माणा घाटी की ओर ३ मील की दूरी पर है। पानी के काफी उँचाई से गिरने के कारण स्थान दृष्टिय बन गया है। समुद्रतल से उँचाई १००० मीटर है।

४) अविष्य बड़ी :- यह जोशीमठ से लगभग ११ मील की दूरी पर स्थित है। यह पर बड़ीनाथ जी की लघुआकार वाली मूर्ति है। ४ मील पैदल मार्ग है।

५) - अनुसूया देवी :- यह जोशीमठ के मुख्यालय गोपेश्वर से ६ मील दूर है। केवल पैदल ३ मील चलना पड़ता है, शेष मोटर मार्ग है। धार्मिक दृष्टि से यह मन्दिर बड़े महत्व का है। यहाँ पर अनुसूया देवी की मूर्ति है। विश्वदन्ति है कि देवी के दर्शन करने पर मनो कामार्थ पूर्ण होती है। अधिकतर जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते हैं वे वर माँगने के लिये मन्दिर में उपवास करती हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है।

६) रजनाथ:- जिले के मुख्यालय से १४ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान रजनाथ की अनोखी ढंग की मूर्ति विराजमान है। मार्ग चढ़ाई एवं फाड़ण्डों का है। समुद्रतल से इस स्थान की उँचाई ५,००० मीटर है।

७) तुंगनाथ:- जिले के मुख्यालय से ११ मील की दूरी पर भगवान शिव का मन्दिर है जो अपने ढंग का महत्वपूर्ण है। पैदलमार्ग केवल ३ कि०मी० है। समुद्रतल से उँचाई ४,१४६ मीटर है।

चौदपुर गढ़ी:- यह स्थान कर्णप्रयाग से रानीखेत मोटरमार्ग पर १० मील दूरी पर है जो सड़क से करीब १ फलिंग की चढ़ाई पर एक खण्डहर (किले) के रूप में स्थित है कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा राज्य करता था।

क्षेत्रीताल:- यह कर्णप्रयाग, आदवडी मोटरमार्ग से लगभग ३ मील की चढ़ाई लेकर स्थित है। ताल की लम्बाई चौड़ाई लगभग आधा मील है और आस-पास पैदली भूमि और जंगल हैं और दृश्यिय है।

१०) कोटी:- यह कर्णप्रयाग से थराली मोटर मार्ग पर स्थान कौली गढ़ी से लगभग ३ मील की चढ़ाई लेकर स्थित है। वहाँ पर नन्दादेवी का एक विशाल मन्दिर है। कहा जाता है कि जब जब वर्षा का अभाव होता है तब-तब लोग इस मन्दिर में पानी के लिये नन्दा जी की आराधना करते हैं और पानी बरसने लगता है।

११) चोपता चरनी:- यह स्थान थराली मोटरमार्ग के स्थान नारायणबाड़ से लगभग ५ मील चढ़ाई लेकर पैदल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी का एक प्राचीन मन्दिर है। देवी की मूर्ति के साथ-साथ उनके अन्य गणों की भी मूर्ति विराजमान है जो कि अपने ढंग की कौली है। समुद्रतल से उँचाई १५०० मीटर है।

१२) तरवाड़ी:- थराली से लगभग ६ मील दूरी पर एक रमणीय स्थल है। समुद्रतल से इस स्थल की उँचाई २००० मीटर है।

१३) वेदनी दुग्गल:- यह स्थान थराली से लगभग २४ मील पैदल मार्ग पर है और बहुत रमणीय तथा दृश्यिय है। समुद्रतल से उँचाई २००० मीटर है।

१४) रू पुरुण्ड:- वेदनी दुग्गल से आगे लगभग १६-१९ मील की चढ़ाई पर है जहाँ नन्दा देवी की जात लगती है जिसमें जिले के निवासी बड़ी संख्या में जात के समय पाग लेंते हैं और वहाँ जाते हैं। जात के समय स्थान काँसुवा में पहले एक चार सिंगी वाला

मेडा (वेहार) उत्पन्न होता है जो कि मन्दा केने की भेंट में हफ्लुण्ड तक छोड़ा जाता है। जात का मेडा हर बारह वर्षी बाद पाइ भावी में लगता है। समुद्रतल से उर्चाई ६००० मीटर है।

१५) मन्दाकेसर :- स्थान गुप्तकारी से ३ मील उत्तर पूरु वीसम्बा शिखर (७००६ मी०) की दूरी पर पैदल मार्ग के नीचे स्थित है जहाँ पर मन्दाकेसर का प्राचीन मन्दिर है व फरुही की दक्षिण वीस पर है। यह पाँच केवारी में आता है।

१६) कालीमठ :- स्थान गुप्तकारी से ३ मील की दूरी पर स्थित एक विशाल काली देवी का मन्दिर है। नवरात्रि के अवसर पर कारवात्रि के पर्य पर काफी संख्या में जन समुदाय दशैं एवं काली माई की पूजा के लिये आते हैं तथा मूर्ति कुत होभयकर है।

१७) वासुकीदारु :- केदारनाथ की के मन्दिर से लगभग ढाई मील की चढ़ाई लेकर है जो कि लगभग दो मील की पश्चिम पर है व दक्षिण है। वहाँ पर केवल ग्रीष्म ऋतु में ही आया जाता है।

१८) कोटेदार महादेव :- यह स्थान राहुप्राग से २ मील पैदल मार्ग पर स्थित है वहाँ पर कोई मन्दिर नहीं है बल्कि एक गुफा के अन्दर गुफा है जहाँ पर शिव की साधारण मूर्ति अपने आप उत्पन्न है। अमन्दा नहीं इस स्थान से कुछ ही मज दूरी पर वही है। वहाँ पर हर कारवात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। स्थान दक्षिण है तथा शिवलिंग के ऊपर जगमारा स्तंभ बहती है।

पर्यटन विकास के लिये तीन प्रमुख आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रथम आवास की व्यवस्था, दूसरी सुगम एवं सस्ते यातायात की व्यवस्था तीसरी स्वच्छ और रसिक के अनुकूल भोजन की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ आभोद-मनोद के साधन आदि भी पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने पर्यटन विकास में पर्यटन की सम्भावनाओं पर गहन अध्ययन करने उपरान्त उक्त सुविधाओं को अधिकाधिक तत्पलव्य कर पड़े जाये की संस्तुति की है।

जिले में तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जिसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :-

स्थान	पार्टी, तीर्थ यात्रियों की संख्या (०००)					
	६८	६९	७०	७१	७२	७३
१- वद्वीनाथ	१४८	१५१	६६	१६०	२००	२५०
२- केदारनाथ	५१	७०	५७	७१	८०	१००

यात्रा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान जोशीमठ में इस समय लगभग २१२ व्यक्तियों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध है। कृष्णिकेण से प्रातः प्रस्थान करने वाली प्रायः सभी गाड़ियाँ जोशीमठ में रात में ठहरती हैं। यहीं से यात्री वद्वीनाथ फुलों की घाटी, कुधारा तथा हैमकुण्ड सहैव को प्रस्थान करते हैं। अतएव जोशीमठ में २०० फेसों के अतिरिक्त आवास की सुविधा का सृजन किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार सोनप्रयाग जहाँ से केदारनाथ की यात्रा के लिये पैदल प्रस्थान करना पड़ता है, में वद्वीनाथ में बहुत ही निम्नस्तर की आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अतः इस स्थान पर न्यूनतम २०० व्यक्तियों के ठहरने के लिये अस्थायी निमणियाँ तुरन्त करायी जाने की आवश्यकता है क्योंकि सोनप्रयाग-जोशीमठ मोटरमार्ग का जाने के बाद इस स्थान का महत्व नहीं रह जायेगा। इसके अतिरिक्त वद्वीनाथ-केदारनाथ में भी यात्रियों के ठहरने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। वद्वीनाथ-केदारनाथ यात्रा पर आने वाले व्यक्तियों में से लगभग ६० प्रतिशत यात्री कर्जून में आते हैं और अनुमानतः ३,००० यात्री प्रतिदिन वद्वीनाथ घाम में पहुँचते हैं। यह मानते हुये कुछ यात्रियों तीन रात और कुछ दो रात ठहरते हैं लगभग ७५०० यात्रियों के लिये प्रतिदिन आवास की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स ने यात्रियों में ८५० रु प्रतिवर्षी वृद्धि की मानकर वर्षी ६७८-७६ तक यात्रियों की यह संख्या लगभग १२००० हो जाने का अनुमान लगाया है इस प्रकार अभी काफी समय तक इन स्थानों पर आवास की समस्या बनी रहेगी जिसे ही भित्त गांधी जी देखते हुये शीघ्र दूर किया जाना सम्भव नहीं है।

यातायात के लिये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा निजी चालकों जैसे टिहरी गढ़वाल मोटर्स और सी यू नियन, गढ़वाल मोटर और सी यू नियन

कुमारों मोटर औनर्स यूनियन द्वारा चलाने जाने वाली कोर्स एवं निजी चालकों की टैक्सी उपलब्ध है। निजी चालकों को कोर्स काफ़ी पुराने एवं असुविधाजनक तथा इनकी संख्या भी आवश्यकता को देखते हुये कम है। पर्यटन विकास के लिये अधिक संख्या में साधारण और ही-क्वॉलिटी कारों तथा टैक्सी आदि की आवश्यकता है।

पर्यटन उद्योग की सम्माननार्थी के विकास हेतु विभिन्न स्तर के पर्यटकों की सुविधा के लिये होटल विकास के साथ-साथ होटल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्राविधान किया जाना है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय व्यवस्थितों में इस कार्यक्रम को अपनाने की योग्यता एवं क्षमता नहीं है। अतएव आरम्भ में होटल व्यवस्था हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये और बाद में इसका अनुपालन स्थानीय स्तर पर होसकेगा।

पर्यटन योजनाओं का कार्यक्रम: - पर्यटन योजना में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में १२९६४ हजार ₹७० और वर्षी १९७५-७६ में २२२७ हजार ₹७० व्यय किया जा सके जाने का अनुमान है। इसके आवासीय सुविधायी प्रदान करने के साथ-साथ प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर प्रकाशित करिये जाने और स्वागत केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। फुल्लों की पाट्टी और हेमकुण्ड लोम्पाठ के उपर एक फिल्म तैयार कराने हेतु ६-७० लाख ₹७० का प्राविधान किया गया है। यह फिल्म भारत और विदेशों में दिखायी जायेगी। वर्षी १९७५-७६ में जनपद में ६२० हजार ₹७० पर्यटन विकास के लिये व्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त राजप्रताप में यानी विश्राम गुड्ड का निर्माण होरहा है इसका चमोली जिले के लिये विशेष महत्व है, क्योंकि की चारनाथ व बद्रीनाथ धामों के लिए मार्ग यहीं से आरंभ होते हैं और आगे-जाते यात्रियों को राजप्रताप में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है।

सड़क परिवहन, संचार साधन, आवास की सुविधायी तथा अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि के साथ-साथ पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की सम्भावनाएँ हैं जिसे कि जिले के स्थानीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय अस्मानतार्थी हुए होंगे। पर्यटन विकास से स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध होसकेगा।

इस अपद में पर्यटन विकास के लिये सबसे बड़ी बाधा किसी पेट्रोल पम्प का न होना है। वर्षी १९७५-७६ में एक पेट्रोल पम्प जिला मुख्यालय, गोपिझर में स्थापित होगया है।

इस अपद के लिये पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना काई गई है उसमें मुख्यतः वक्रीनाथ-केदारनाथ जाने वाली यात्रियों को आवासीय सुविधा देने का ही उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी महत्ता फूलों की घाटी व लोफपाल-हमपुण्ड को दी गई है। इस अपद में रूफुण्ड व मड नई खर में प्रतिवर्षी काफी पैगाली पर्यटक आते हैं जिसका उद्देश्य टूरिज्म होता है। उपरोक्त स्थानों के रास्तों में लागू हट्स काई जानी चाहिये। रूफुण्ड जाने हेतु निम्न स्थानों में लागू हट्स की आवश्यकता है।

- १- देवालय
- २- मन्दीर
- ३- देवालय
- ४- विदिनी-वग्यल
- ५- वज्जु वासेरा।

मध्यमेश्वर हेतु निम्न स्थानों में लागू हट्स की सुविधा चाहिये :-

- १- कुलीफु
- २- गौडपुर
- ३- मध्यमेश्वर।

इस अपद में निम्न सुन्दर-आकषीक ताल (Lakes) हैं जहाँ लागू हट्स की आवश्यकता है :-

- | | |
|----------------|------------------------|
| १- भीरु ताल | (विकास खण्ड, थराली) |
| २- देवरिया ताल | (विकास खण्ड, ठासीपठ) |
| ३- ब्रह्म ताल | (विकास खण्ड, थराली) |
| ४- मालताल | (विकास खण्ड, दशोली) |

इस वर्षी में अपद का एक बड़ा भाग विदेशी पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है। यह आशा है कि विदेशी पर्यटक पर्यटनोद्दोषण एवं टूरिज्म हेतु आयेंगे, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि विभिन्न भागों में लागू हट्स व आवास, होटल्स एवं रेस्टोरैण्ट की सुविधा प्रदान की जाय। इस हेतु एक सर्वोद्देश्यपूर्ण तुरन्त करना आवश्यक होगा। यहाँ पर यह बतलाना उपयुक्त होगा कि

कलीम्प का मन्दिर धार्मिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्यमेश्वर मन्दिरों में से है। साथ ही कुक्कवासी में गुप्तकाली-कलीम्प न-सीगौडार मोटर मार्ग बनने की सम्भावना है जिसे यह आशा है कि पर्यटकों को मँया देगी। इस क्षेत्र में सुन्दर वन तथा फलों से आच्छादित पहाड़ियाँ भी हैं।

राङ्गाथ-गोपेश्वर से ६४ मील की दूरी पर स्थित है जहाँ सार्वजनिक निमण्डल विभाग द्वारा यात्रियों के लिये पैदल राहती बनाया जा रहा है। राङ्गाथ इस समय भी यात्री आते हैं और यह अत्यन्त सुसज्ज है। यहाँ पर भी लगभग हट्टस की अति शक्ति है। इसी प्रकार कुंआथ में भी एक लगभग हट्टस की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में बहुत प्राकृतिक सम्पदा है तथा अन्य जीवन में यह क्षेत्र धनी है। अन्य जन्तु व पक्षी वृक्ष, महती पशुना, ट्रेनिंग आदि की सुविधा हेतु इस क्षेत्र में ही भी प्राविधान नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि पर्यटन विभाग द्वारा एक पूरक योजना बनाई जाये।

ब्रिटिश काल में ओली-कुंग्याल में अंग्रेज आइस-स्पोर्ट्स के लिये आते थे। ओली कुंग्याल व ओली (जोशीमठ) इन्फैन्ट्री व आइस-स्पोर्ट्स के लिये उपयुक्त है।

गोपेश्वर - चमोली के बीच तथा उमीप व हेलंग के बीच रोडवेज (रज्जुमार्ग) होना चाहिये।

(17) सामान्य शिक्षा

जिला चणौली उत्तराखण्ड का एक क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जिला पूर्णतः पर्वतीय है जिसकारण विकास हेतु इसको विशेष सावधानी है। इसका क्षेत्र 9,128 वर्ग किलोमीटर तथा 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,92,571 है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 32 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 60 प्रतिशत वस्ति 200 से कम आबादी वाली तथा छोटी हैं। साक्षरता की अनुसूचित अनुविधा तथा पिछड़ेपन व निर्धनता से व्यक्तिगत विद्यालयों को चलाने में जनता को सहायता के कारण यहाँ की शैक्षिक प्रगति स्थिर रही है। इस पर भी यह जनपद साक्षरता की दृष्टि से राज्य में ऊँचा स्थान रखता है। 1971 में यहाँ पुरुषों में 48-9 प्रतिशत एवं महिलाओं में 9-6 % साक्षर थे। राज्य के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 31-5 व 10-5 प्रतिशत था। नवीन विद्यालयों को खोलने में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद से नियमित मानदण्ड इस विहड़ भौगोलिक परिस्थिति वाले पर्वतीय जिले के लिये पूर्णतः ब्यवहार्य नहीं है। अतः विद्युत् संचालन जनता को यहाँ एवं भौगोलिक परिस्थितियों का प्रयोजन करूँ, मिडिल, हायर सेन्ट्री विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।

वर्तमान शैक्षिक प्रगति का तुल्यकन

सन् 1960 में जनपद के निर्माण के समय से वर्तमान समय तक 1974-75 तक विभिन्न स्तर को जिला में जो प्रगति हुई है व निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

क्र. सं. विद्यालय का प्रकार	1960-61	1971-72	1973-74	1974-75
1- आधरिण विद्यालय	400	528	542	567
2- पूर्व माध्यमिक विद्यालय	22	63	67	72
3- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	7	24	35	38
4- डिग्री कालेज	-	1	1	2
5- प्रविजन विद्यालय (इकाई विहित)	1	2	2	2
6- प्रौढ शिक्षा केन्द्र	-	14	16	-

विद्यालयों के खुलने के साथ-साथ छात्र संख्या में भी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :-

क्र. सं. विद्यालय का प्रकार	1960-61	1971-72	1973-74	1974-75
1- आधरिण विद्यालय	18,219	32,325	36,120	39,704
2- पूर्व माध्यमिक विद्यालय	1,556	6,267	7,525	8,435
3- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1,453	3,667	4,118	4,185

उत्तर संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अध्यापकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका में स्पष्ट हो जाती है :-

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	1969-71	1971-72	1973-74	1974-75
1-	आधारिक विद्यालय	690	979	1172	1290
2-	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	110	252	291	304
3-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	104	408	556	600

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जयपुर के अधिकांश शिक्षित वर्ग की संख्या परिलक्षित करने में भी सुविधा रही है। जहाँ तक विद्यालय अधीन का प्रश्न है वर्ष 1973-74 तक 542 प्राइमरी स्कूलों में से 520 में भवन हैं। 67 जूनियर हाई स्कूलों में 31 में भवन हैं। अधिकांश भवन नवीन शैली के हैं जो कि जयपुर में ही जिनका सुंदर चित्र प्राप्त अपेक्षित है। भवनों का विवरण निम्न तालिका में स्पष्ट हो जाता है :-

उप-प्रश्नांक - 1

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्राथमिक विद्यालयों का भवन		जूनियर हाई स्कूलों का भवन		उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भवन		कुल	
		भवन	रहित	भवन	रहित	भवन	रहित	भवन	रहित
1-	जयपुरी स्कूल	60	2	3	5	2	-	-	-
2-	राधा कृष्ण	74	9	2	3	5	-	1	-
3-	श्री गुरुदेव	61	-	2	1	3	-	-	-
4-	राधा कृष्ण	48	1	5	3	5	-	-	-
कुल :-		243	12	13	14	15	-	1	-

उप-प्रश्नांक - 2

1-	जयपुरी स्कूल	46	2	2	6	3	-	-	-
2-	राधा कृष्ण	52	2	2	5	2	-	-	-
3-	श्री गुरुदेव	48	4	1	5	2	-	-	-
4-	जयपुरी	63	2	3	4	5	-	-	-
5-	राधा कृष्ण	68	-	5	2	6	-	-	-
कुल :-		277	10	13	22	20	-	-	-
कुल :-		520	22	31	36	35	-	1	-

इस प्रकार 22 प्राइमरी विद्यालयों में भवन नहीं हैं किन्तु प्रायः सभी में प्राइमरी स्कूल चलाने की व्यवस्था है। जूनियर हाई स्कूलों में 36 विद्यालयों में भवन नहीं हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भवनों की व्यवस्था है परन्तु अधिकांश अनाई टिन होर्डो अर्थात् लकड़ी की बने हुए हैं। परिसर में प्राइमरी विद्यालयों की व्यवस्था हेतु प्रारम्भ में

अनुदान िला है और कार्य चल रहा है । राजकीय विद्यालय धर्मों भवन निर्माण में ग्राम पंचायतें 50% अदान देती हैं जो राजकीय अनुदान में उहालक हैं तथापि यह अदान भी नगन है । पिछले तीन वर्षों में कुछ धन ग्राम पंचायतों ने अदान आदि से बने हैं जो अर्थात् अनुपुक्त हैं । जनता के इस शूलों में उपकरण, पुस्तकें, राज राजा, बीमहर के भोजन, निःशुल्क वाट्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्र वर्कियों के लिये कोई व्यवस्था अदा प्रयास नहीं किया गया है । इस प्रकार विद्यालय शाकीय अनुदान पर हो निर्भर हैं ।

जनपद को विकास के दृष्टिकोण से दो उप-प्रभागों में बाँटा गया है । प्रभाग अक्षा में चार विकास क्षेत्र और द्वितीय अक्षा में 5 विकास क्षेत्र समितित किये गये हैं । पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण दोनों उप-प्रभागों में प्रत्येक प्रकार को शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान र्थ से उपलब्ध हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रविर्ण हेतु जनपद में एक राजकीय दोहा विद्यालय गौहर में है तथा महिलाओं के लिये एक प्रविर्ण युनिट बालिका इण्डर कलेज गौहर के । एक अन्तर्गत है । बालिका युनिट गौहर को यदि पूर्ण प्रविर्ण विद्यालय बना दिया जावे तो शिक्षा विभागों के प्रविर्ण के लिये उक्त दोनों संस्मों समाप्त हो जायेंगे ।

जिले के कुछ ऐसे भी अक्षा हैं जिनमें विद्यालयों में स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में समस्याएँ आती हैं तथा उनका निराकरण प्राइमरी स्तर पर अपना पाठशाला देने के तथा जूनियर स्तर पर शासन द्वारा नवीन जूनियर हाई स्कूल खोलने पर किया जाता है । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ छोटी एकाईयों के खोलने के विद्यालयों के निर्माण से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है । भारत सरकार द्वारा जो द्वितीय शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था उनमें नवीन विद्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में निर्धारित मानक इस जनपद को विशेष शैक्षणिक परिस्थितियों के कारण तथा छोटे आबादी वाले ग्रामों के कारण पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है । क्यों कि यदि वस्तु 30 को जनसंख्या वाली है और वह समोसा ग्रामों के 3 मील के दूर है तो वहाँ विद्यालय दिया जाना वांछित है जब कि सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ विद्यालय नहीं दिया जा सकता है । इस कारण जनपद में 100 से अधिक शाखा विद्यालय चल रहे हैं । जनता को यदि पर शाखा पाठशालाओं को संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जनपद पिछड़ा है जो बालिकाओं के विद्यालयों से हो रहा है । इस जनपद में 38 लम्बा प्राइमरी पाठशालाएँ 6 लम्बा जूनियर हाई स्कूल हैं । अर्थात् एक सामाजिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश अधिशासक बालिकाओं को पढ़ाना पान्द नहीं करते हैं । जनपद में प्रविर्ण महिला अध्यापिकाएँ पर्याप्त हैं । अनुपुचित जाति तथा अनुपुचित जन जाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा को शक्ति समीपजक नहीं है । ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, मुक्तकालीन पुस्तकीय सहायता देने को व्यवस्था है किन्तु अल्पसंख्यक बच्चों के कारण अनुपुचित जाति को अधिकांश अधिशासक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते हैं । इस वर्ग के छात्र छात्राओं को/शैक्षणिक को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थान बीबीठ में एक आश्रमपुर्णित विद्यालय संयोजित किया गया है जो लक्ष्मी 6 से 8 तक को शिक्षा देता है । इसके अतिरिक्त निरपेक्ष में अनुपुचित जाति के छात्रों के लिये

एक आधारभूत विद्यालय और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जनजाति भाषा वास की स्थापना की गई है।

जनपद में वर्ष 1973-74 तक 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त, अथवा स्वतंत्र प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों में स्थापित हैं। 25 विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा दी जाती है परंतु विज्ञान सामग्री एवं विद्यार्थियों की कमी है जिससे छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य में कठिनाई होती है। अब 'यूनिफ़ॉर्म' की शर्त से विज्ञान किट उपलब्ध कराये जाने से शिक्षकों को नए पाठ्य क्रम के अनुसार प्री इन्टर दिया जा रहा है जिससे विज्ञान उपकरणों की कमी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। उपर्युक्त क्षेत्रों के विकास क्षेत्रों व अग्रस्त युनि में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकारी में एक मात्र हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के साथ साथ क्रीडा की शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न प्रकार की शैक्षिक स्थितियों तथा प्रशिक्षण विद्यालय बच्चों को केवल कृते शिक्षा दे रहे हैं और ये बच्चे सामान्यतया प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अध्यापक, लिपिक तथा सेना में भी भर्ती होते हैं। न्यूनतम सीखने में प्राथमिक शिक्षा हेतु मैदानों में जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है जिससे जिले के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

दीर्घकालीन कार्यक्रम

=====

जनपद की विशिष्ट शैक्षिक परिस्थितियों एवं जनता की मांग के अनुसार बढ़ती हुई छात्र संख्या को पूर्ण रूप से शैक्षिक व्यवस्था में पांचवी योजना के अन्ततक तक भी नहीं उपलब्ध हो पायेगी। प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 50% एवं इसी प्रकार हायर सेकण्डरी स्तर पर 35% शिक्षा स्तर को प्राप्त करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 80 प्राथमिक विद्यालय, 30 जूनियर हाई स्कूल एवं 25 हायर सेकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे। सामान्य शिक्षा में दुर्दिन के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जावेगी। अतः यह आवश्यक है कि जनपद में व्यावसायिक शिक्षा की अधिक से अधिक व्यवस्था की जावे। आम जनता की वैश्विक विकास हेतु प्रत्येक तहसील में एक एक पुस्तकालय स्थापित करने होंगे। जनपद में विद्यालयों के पास खेल के मैदानों की दिव्यता कमी है। खेल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर स्टी डायमंड की व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

पंचम पंचवर्षीय योजना की परिप्रेक्षा

=====

शैक्षिक आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1973-74 तक प्राइमरी स्तर पर 68%, मिडिल स्तर पर 28% एवं हायर सेकण्डरी स्तर पर 15% छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं। पंचम योजनाकाल में वर्ष 1974-75 में 25 आधुनिक विद्यालय, 5 मिडिल स्कूल तथा 3 हायर सेकण्डरी स्कूलों की स्थापना की गई है। पांचवी योजना में 13 आधुनिक विद्यालय, 14 मिडिल स्कूल और 10 हायर सेकण्डरी स्कूल खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1975-76 में 10 आधुनिक विद्यालय, 6 मिडिल स्कूल और 9 हायर सेकण्डरी स्कूल स्थापित किये जाने थे - का प्रस्ताव है। इस प्रकार पांचवी योजना के अन्ततक आधुनिक विद्यालयों में 85%, मिडिल स्तर पर 49% त-

तथा हायर सेकेंडरी स्तर पर 33% तक शिक्षा की व्यवस्था हो जाने का अनुमान है। प्राथमिक स्तरों में पठ्यक्रमिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अनेक /इसकाओं में प्रमुखों को भी नई आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकें। वैश्विक सुविधा प्रदान करने हेतु 15 अंक हलीन सहायता केन्द्र वर्ष 1975-76 में केंद्रीय जारिनों सामाजिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रथम वर्ष तक शिक्षा में प्रवेश को साक्षर करने के उद्देश्य से वर्ष 1975-76 में 15 प्रतिशत शिक्षा देकर दो लेन की जो सुविधा प्राप्त हुई है। निचले स्तरों की शिक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु विद्यार्थी योजना में एक सेकी को स्थापित करने का प्रस्ताव है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जनपद स्तर पर काफी पिछड़ा हुआ है। बालिकाओं की शिक्षा हेतु जूनियर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षित शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

परिचयी योजना के अंत में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक राजकीय डिग्री कॉलेज विकास क्षेत्र अमरसमूनि में वर्ष 1974-75 में स्थापित किया गया है। हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर पर पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मत, विधान शिक्षा के सुदृष्टीकरण एवं विद्यालयों में स्थापित राजकीय पुस्तकालयों के सुधार की भी आवश्यकता है।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1974-75 में निर्धारित 112 हजार रुपया परिचय के विपरीत 137 हजार रुपया देय किया गया। पंचवी योजना की अवधि शुरू वर्ष 1974-76 के लिये काशी 2233 और 301 हजार रुपया का परिचय राज्य आयोजना अंत में निर्धारित है।

संसाधनों का जुटाना - पिछड़े पन एवं निर्जनता के कारण शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये क्षेत्रों में कोई अधिकारी नहीं है। वर्ष 1971-72 में इस जनपद में 16 जूनियर हाई स्कूलों की संख्या में संघात के निमित्त के लिये के लिये वर्ष 1973-74 में केवल 5 रह गई है और इन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। संघात विद्यालयों को पूर्ण-पूर्ण राजकीय अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्रत्येक प्रत्येक स्तर के विद्यालयों का कार्य और शासन को ही सहन करना होगा।

शासन के विचारणीय प्रश्न - नैतिक उल्लेख किया जा चुका है कि जनपद की विद्यार्थी भौतिक परिस्थितियों के कारण जनपद में 100 से अधिक शाखा आधुनिक विद्यालय बंद हो जा रहे हैं। लगभग 60 शाखाओं में जनता ने सतत निर्यात का कार्य भी पूरा कर दिया है और अब तक संबंधित जनता उन विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय का दर्जा देने के लिये पत्र व्यवहार कर रही है। शासन शाखाओं की शीघ्रता विशेष परिस्थितियों में इस जनपद के लिये प्रति वर्ष रु केवल 1000 से अधिक विद्यालयों की शीघ्रता विचार पर जनहित में दी गई है। अतः ऐसे शाखा विद्यालय जिनके पास भूमि भवन उपलब्ध है, पूर्ण विद्यालय बनाये जाय ता कि जनता के रोगदान के लक्ष्य के लिये शाखाओं के स्तर को उच्च उन्नत कर सकें।

=====

(1.8) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

=====

जनपद गंगोली का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ का कोई भाग किसी विशेष प्रकार की बीमारी से प्रभावित नहीं है। वर्ष 1973-74 में जनपद की 3-05 लाख जन संख्या को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने हेतु विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सालयों की संख्या निम्न प्रकार है:-

1- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	} नगरीय चिकित्सालयों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
2- स्त्रीरोग चिकित्सालय	22	
3- आयुर्वेदिक चिकित्सालय	39	} चिकित्सालय की सुविधा प्राप्त है जबकि वर्ष 1971-72 में प्रदेशों आगत 30000 जन संख्या पर 1 चिकित्सालय था।
4- होम्योपैथिक चिकित्सालय	1	
5- नेत्र चिकित्सालय (अनुदान पर)	1	} इसी प्रकार 1000 वर्ग की 8 मी० पर 8 चिकित्सालय उपलब्ध है। इन प्रसंगों के अतिरिक्त विशेष प्रकार के रोगियों की चिकित्सा के लिये एक टोडकी, स्त्रीरोग, एक टोडकी स्त्रीरोग, तथा एक आई टोडकी भी स्थापित है।
6- स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्र	36	
7- ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र	9	} लक्ष्य 4444 जनसंख्या के लिए एक केन्द्र के स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्रों उपलब्ध है।
8- नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र	1	
9- परिवार नियोजन सम केन्द्र	45	

दिल्ली में भारत सरकारों की संख्या

1- स्त्रीरोग चिकित्सालय	48	} लगभग 4840 जनसंख्या की देख रेख के लिये एक डॉक्टर की सेवाएँ उपलब्ध है।
2- आयुर्वेदिक चिकित्सालय	13	
3- होम्योपैथिक चिकित्सालय	1	} 53 स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टर उपलब्ध हो जाने पर चिकित्सा सुविधा में सुधार सम्भव हो सकेगा।
4- नेत्र चिकित्सालय	1	

चिकित्सालयों में शैफरों की संख्या इस प्रकार है :-

1- नगरीय स्त्रीरोग चिकित्सालय	116	} 471	} लगभग 647 जनसंख्या पर एक शैफर उपलब्ध है।
2- ग्रामीण स्त्रीरोग चिकित्सालय	75		
3- आयुर्वेदिक चिकित्सालय	156		
4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	83		
5- नेत्र चिकित्सालय	40		
6- होम्योपैथिक चिकित्सालय	4		

जनपद का मुख्यालय गोंदश्वर विकासोन्मुख नगर है। यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जिला अस्पताल में शैरवाओं की वृद्धि, प्रत्येक महिला अस्पताल की स्थापना, चिकित्सक एवं नर्सों विशेषज्ञों की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना तथा चिकित्सालय को विभिन्न तान एवं तंत्र तथा उपकरणों से सुसज्जित कराना आवश्यक है।

पर्यटकीय क्षेत्र होने के कारण जनपद की जलवायु स्वास्थ्य प्रद है। सुबूह क्षेत्रों में यहाँ के किसी भी उपस्थान में किसी संक्रामक रोग की बढनाये होती नहीं देखी गई है।

ज्वारीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुवन्धी सेवाओं अधिक उपलब्ध है सुदूर क्षेत्रों में यातायात के अभाव में औषधि आदि के पहुँचने में बाधनाई होती है। निजी चिकित्सालयों की उपलब्धि नगण्य ही है। औषधि आदि के ले जाने में यही बाधनाई है निजी औषधि दुकानों की भी है।

जनपद के निवासी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और चिकित्सा सुवन्धी सुविधाओं के लिये पूर्णतः प्रशासनिक व्ययों पर ही निर्भर है। और निकट भविष्य में भी रहेंगे।

केवल चिकित्सालयों (एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक) में चिकित्सा अधिकारी नहीं रहते हैं। गिनके न रहने के मुख्य कारण है- (1) चिकित्सकों की आयतन पर कमी, (2) देहाती और पर्यटकीय क्षेत्र में चिकित्सकों की अल्पता, (3) आवास सुविधा का अभाव, (4) पुत्र सुविधा काट नीति का अभाव। कस्बर पदार्थों के अति रक्षक यातायात की व्यवस्था का न होना एवं निजी चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा का न होना। कालान्तर में सेवा एवं यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाने पर भी यह आवश्यक होगा कि इन स्थानों पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाय और सुविधा जनक स्थानों पर कार्य करने के विभिन्न विधियाँ स्थापित किया जाना।

राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में जनपद में एक प्राथमिक एलोपैथिक तथा एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की गई है। इनमें 8 शैरवाओं का प्राविशान किया गया है। वर्ष 1975-76 में ज्वारीय तालाब में 10 शैरवाओं की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित है। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत एक प्राथमिक एलोपैथिक दो आयुर्वेदिक तथा एक होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

वर्ष 1984 तथा 1989 में जिले की जनसंख्या क्रमशः 3-55 तथा 3-71 लाख हो जाने का अनुमान है। यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और गीव छुटाछुट बने हुये हैं। यातायात की सुविधाएँ भी इतनी अच्छे नहीं हैं कि सरलता से जिला केन्द्र तक पहुँचा जा सके। इलाके में प्रत्येक विभाग हण्ड में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सम्बन्धित चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक 25 शैरवाओं को ले चाहिये तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वतन्त्र प्लाज्म, डाइग्नोसि, इन्फरिड, अल्ट्रावायलेट, रेडियालमी, पैथोलॉजी आदि सुविधाएँ उपलब्ध हों। वर्तमान समय में जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। जिला मुख्यालय की बढ़ती हुई आबादी का देखते हुये एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की प्राविशान किया जाना है।

चिकित्सा, रैव जनस्वास्थ्य सर्वस्वी सुविधाओं हेतु वर्ष 1974-75 में निर्धारित 1400 हजार स्वया परिचर्य के विपरीत 883 हजार स्वया र्वय किया गया। वर्ष 75-76 में 1311 हजार तथा पञ्जीय योजन में 9527 हजार स्वया परिचर्य निर्धारित है। इन में से क्रमशः 426 और 883 हजार तथा 2570 और 6957 हजार स्वया र्वय आयोगनायक और केन्द्र द्वारा पुरोनिध तानित श्रीती से बहन किया जायेगा।

शासन के विचरिणीय प्रश्न - इस जनपद में अधिकतर चिकित्सालय/औषधालय तथा मातृ शिशु केन्द्र रैव परिवार नियोजन केन्द्र /रूप केन्द्र किराये के भवनों पर चल रहे हैं जि नों पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता । साथ ही इस जनपद में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। अतः प्रत्येक चिकित्सालय/औषधालय तथा केन्द्रों रैव उप केन्द्रों हेतु भवन निर्माण आवश्यक है तनि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक एक महिला चिकित्सक की आवश्यकता है।

परिवार नियोजन

वर्तमान समय में जनपद में परिवार नियोजन सुविधा हेतु 9 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र , एक नवीरीय केन्द्र, 45 उप केन्द्र तथा 36 मातृ रैव शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1973-74 तक जनपद में 7116 पुरुषों तथा 15 महिलाओं का वन्यकरण आपरेकृत तथा 935 महिलाओं को लुप निवेशन किया गया। वर्ष 1974-75 में 33 पुरुषों और 6 महिलाओं का आपरेकृत किया गया और 387 महिलाओं को लुप लगाये गये। पञ्जीय योजनाकाल में वन्यकरण रैव लुप निवेशन का लक्ष्य क्रमशः 6066 तथा 5197 और वर्ष 1975-76 में 985 रैव 1641 निर्धारित है।

जनपद में जनसंख्या का वन्यकरण कम है। यह प्रदेश में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कीसो गीसक के मुकामले में जनपद में 32 है। जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर भी प्रदेश केवले के औसत के मुकामले में कम रहती है। इसका कारण वही के वयस्क पुरुषों का अधिकतम वयस और अन्य व्ययसतों में जिले के बाहर रहना है। दूर दूर छितरी वास्तवों में इस कार्यक्रम का प्रसार उस सीमा तक नहीं हुआ है कि लोग अंतः इस कार्य हेतु उन्मुख हों। उनमें रैसा वातावरण भी नहीं मिल पाता कि वे परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को अपना सकें। इसके अतिरिक्त मी हलानों में लुप निवेशन में जड़बर्त भी अधिक है। रैके तो महिला चिकित्सकों की कमी है, दुर्बरे महिलाओं को वांछित उठाने का कार्य करने के कारण लुप असफल हो जाता है।

जिले में रैव सरकारी चिकित्सकों की बहुत कमी है इस कारण उनके द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में योगदान नसक्य है।

=====

जनता को पोषिक आहार उपलब्ध कराये जाने की समस्या प्रदेश व्यापी है किन्तु क पहाड़ी क्षेत्र जहाँ का आर्थिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है में यह समस्या और भी गम्भीर है न्यून पोषण को दूर करने के लिये गर्भवती महिलाओं, शिशु माताओं तथा पिछड़े समुदाय के प्राथमरी स्कूल के छात्रों को पोषिक आहार उपलब्ध कराये जाने की परम आवश्यकता है । शासन ने इस जनपद में वर्ष 1972-73 से दो प्रकार की योजनाये लागू किया :-

1- आधा रक विद्यालयों में आलाहार योजना ।

2- सामुदायिक विकास विभाग में विशेष पोषिक आहार योजना ।

आलाहार योजना वर्ष 1972-73 में 124 आधारिक विद्यालयों में चलाई गई जिसके अन्तर्गत छात्र छात्राओं के लिये मध्याह्न आहार की प्राविधान है । वर्ष 1973-74 में यह योजना 124 आधारिक विद्यालयों से बढ़ा कर 140 में लागू की गई । दोनो वर्षों में क्रमशः 5962 तथा 6730 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है । चतुर्थ वर्ष योजना में आलाहार योजना के अन्तर्गत लगभग 3-4 लाख पीण्ड सीधा 45 किलोग्राम प्राप्त हुआ और 1-89 लाख रुपये व्यय हुये । इस योजना के अन्तर्गत छात्र छात्राओं के लिये मध्याह्न आहार तैयार करने वाले रसोइये को 15 रु० और लेखा रखने वाले प्रधानाध्यापक को 10 रु० मासिक मान देय दिया जाता है ।

सामुदायिक विकास विभाग में विशेष पोषिक आहार योजना पूर्व पाठशाला के बच्चों (0-6 वर्ष) गर्भवती महिलाओं तथा शिशु माताओं को पोषिक आहार उपलब्ध कराये एवं प्राथमिक जनता को पोषिक आहार का ज्ञान कराने के उद्देश्य से इस जनपद में विकास खण्ड दशौली में कार्यान्वित की गई । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विकास खण्ड में नियुक्त कार्यकारी के अतिरिक्त एक सह मदक विकास अधिकारी (महिला) पांच ग्रामसेविका तथा एक जीव चालक की स्वीकृति है । इसके अलावा विकास खण्ड के अन्तर्गत अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे प्राध्यापक, केन्द्र के चिकित्सक, पशु चिकित्सक, प्रसार अध्यापक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं निरीक्षिका, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, एवं कुछ आधारिक विद्यालय की सेवार्थे भी ली जा ती है ।

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड दशौली में पांच ग्राम सेविका केन्द्र क्रमशः गडौरा बेरागना, गेठाण, गण्डाचू एवं भूट स्थापित किये गये है । प्रथम वर्ष 1972-73 में 20 ग्राम व द्वितीय वर्ष में अन्य 30 ग्राम छूटे गये एवं तृतीय वर्ष में विकास खण्ड के समस्त ग्रामों में योजना कार्यान्वित करने का प्राविधान है ।

चतुर्थ योजना कात के अन्तर्गत दो वर्षों में वित्तीय स्वीकृति एवं सम्पादित कार्य कार्य इस प्रकार रहे :-

क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय उप योग
1-	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना रु०	37,000	37,000
2-	कुछ विकास कार्य	12,000	12,000
3-	सहयोगी संस्थाओं को सहायता रु०	7,000	7,000
4-	छात्र बस्ती (सरकारी एवं सरकारी कर्मियों वा प्रतिभवा व्यवस्था)	20,100	7,400

उपरोक्त मदों में से छात्र वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग महिला कार्यकर्तियों के अभाव में महिला मण्डलों का गठन और उनका प्रशिक्षण न होने के कारण नहीं हो सका। वर्ष 1973-74 में अंत में केवल दो ग्राम सेविकाओं की ही नियुक्ति हो पाई थी। इस के साथ अधिकांश जी.एस.टी. स्टाफ कर्मचारियों के प्रशिक्षण न लेने के कारण इस पद में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया।

इन दो वर्षों में उक्त धनराशि के उपयोग के पक्षस्वरूप निम्न प्रकार भौतिक उपलब्धियाँ हुईं:-

क्र.सं.	मद	इकाई	दो वर्षों का लक्ष्य (1972-74)	दो वर्षों की उपलब्धियाँ (1972-74)	विशेष
1-	योजना के लिये छूटे गये ग्राह्य	सं०	50	50	
2-	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना	सं०	11	11	
3-	स्कूल वाटिकाओं का क्षेत्रफल	हे०	2-20	2-62 2A2	
4-	ग्रह वाटिकाओं की स्थापना	सं०	400	712	
5-	ग्रह वाटिकाओं का क्षेत्रफल	हे०	16-00	19-67	
6-	सब्सिडी वीलों का वितरण				
	1- सूनीसिफ द्वारा दिये गये प्लॉट सं०		-	278	
	2- उत्पादन केन्द्रों द्वारा	कि०मी०	-	78-10	
7-	दो दात वाली फसलों की बुवाई	हे०	-	5-75	
8-	स्कूल वाटिकाओं की सीमा निर्देश रूबर				
	सं०	सं०	4	4	
9-	दुकानें बनाने की स्थापना				
	1. प्राथमिक दुकानें	सं०	3	2	
	2. अतिरिक्त दुकानें	सं०	110	129	
3.	सुविधों का वितरण	सं०	775	299	सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई
4.	बुकलेट संतुलित आहार का	सं०	-	3-90	
10-	महिला सामूहिक/सहकारी संस्थाओं की स्थापना जिन्हें राजस्व अथवा अनुदान दिये गये	सं०	-	-	राजस्व अथवा अनुदान की मदद से स्थापना नहीं हो सका।
11-	कर्मियों की सं० जिन्हें पौष्टिक आहार प्रशिक्षण दिया गया	सं०	360	246	

पान्चवी योजना के कार्यक्रम:-

पान्चवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी उक्त दोनों योजनाएँ जनपद में कार्यरत रखी जायेंगी। पालोडर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 अतिरिक्त आचारिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए लगभग 13,000 छात्र छात्राओं के लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

साधुदायिक विकास विभाग की व्यवहारिक पोषक आहार योजना विकास खण्ड व दशौली में पाँचवी योजना के प्रथम तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 1976-77 तक कार्य रत रहेगी। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड थराली में यह कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुखात् ती न सौ कैलोरिज तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक आहार 20 पैसे की दर से प्रति शिशु/महिला प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। पाँचम पाँचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यवहारिक व पुष्पहार कार्यक्रम की वर्ष 1974-75 की प्रगति तथा वर्ष 1975-76 और पाँचवी योजना काल के प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	गद	ईकाई	पाचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धता	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
15-	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना तथा रख रखाव	सं०	42	4	12
2-	सहयोगी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाली :-				
	(क) संस्थागत कु ईकाई	सं०	14	2	4
	(ख) व्यक्तिगत सदस्यों की कु कुट ई०	सं०	602	43	172
3-	सहयोगी संगठनों जिनको सज सजा देना है -	सं०	35	5	10
4-	सर्व पालन के तालाबों का पुधार हेक्टर -			-	-
5-	सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों की पुष्टिकर्त में प्रशिक्षण	संख्या	700	29	200

साधुदायिक विकास विभाग की व्यवहारिक पोषक आहार योजना के कार्यान्वयन में पाँचवी पाँच वर्षीय योजना की अवधि में लगभग 10-46 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 0-66 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1974-75 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0-73 लाख रुपया परिव्यय निर्धारित था जो शत प्रतिशत उपयोग कर लिया गया था। पोषक आहार योजना हेतु वित्तीय संसाधन राज्य आयोजनागत, संस्थागत (यूनिकेफ), केन्द्र द्वारा प्रोत्साहित एवं केन्द्रिय सैक्य स्रोतों द्वारा जुटाये जायेंगे जिसका विस्तृत उल्लेख रूप पत्र एक में किया गया है।

जनपद चकौली आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और सामान्य जनता को पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि अनुमानित दश प्रतिशत व्यक्ति क्षय रोग के शिकार हो रहे हैं यह बात शासन की जानकारी में भी लायी जा चुकी है। उक्त दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि पोषक आहार योजना जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में लागू की जावे और शिक्षा विभाग के माध्यम से जिले के प्रत्येक आचारिक विद्यालय को इस योजना से लाभान्वित किया जावे।

(20) - जल सप्लाय

जनपद चणोली में 1639 ग्राम हैं। जिनमें से केवल 1493 ग्राम आषाढो वाले हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार उपरोक्त ग्रामों की जनसंख्या 2,80,365 है। इसके अतिरिक्त जनपद के अन्तर्गत 3 नगरपालिकाओं की जनसंख्या 12,276 है। इस प्रकार चणोली जनपद की कुल जनसंख्या 2,82,641 है। जनपद में स्वच्छ पेयजल का अभाव है और पूरे जिले में साफ़सा लगभग स्थान है। किन्तु कुछ ग्राम ऐसे हैं जहाँ एक किमी. से भी अधिक दूर से पानी का पानी लाना पड़ता है। ऐसे ग्रामों की प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना बनाई गई है। इस जिले की पेयजल समस्या को के दूर करने के लिये निम्नलिखित विभागों द्वारा कार्य किया गया है :-

अ- स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग :- वसुंधरा पंचायतीय योजना के अन्तर्गत स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल 191 ग्रामों जिनकी जनसंख्या 48,694 है, को पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। जिनकी विकास खण्डवार सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त जनपद के नगरपालिकाओं जिनकी कुल जनसंख्या 12,276 है, को भी पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार लगभग 17-4 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पेयजल सुविधा से लाभान्वित हो जा चुकी है।

ब- सिंचाई विभाग :- सिंचाई विभाग द्वारा जनपद चणोली में 50 ग्रामों में पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। शासन के आदेशानुसार यह पर्यस्त योजनाओं स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को सौंप रखी है। इन पर्यस्त योजनाओं को पर्यस्त कुनसूच कुर्व पुनर्गठन तथा विस्तार कर करना आवश्यक है।

क- विकास खण्ड :- विकास खण्डों द्वारा इस जिले में 460 ग्रामों में पेयजल समस्या का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं की वसुधितिकता का मूल्यांकन कराया गया था तथा यह पाया गया कि इनमें अधिकांश ग्रामों की योजनाओं कार्य नहीं कर रहे हैं तथा जोर्न-शोर्न अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त शेष योजनाओं से तो हैं जिनमें पूर्ण ग्राम की जनता लाभान्वित नहीं हो पा रही है तथा जनता को आसानी से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अभी तक पेयजल योजनाओं के कार्य में अजिब रुकने से हो प्रकृत हो गई है।

पिछली योजना में पेयजल सम्पूर्ति का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया है। वर्ष 1974-75 में इस विभाग द्वारा 64 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे 18 हजार जनसंख्या लाभान्वित हुई है। इस प्रकार लगभग 25-6 % जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इस जिले में पेयजल के लिये अधिकतर नदी, घाटोरे एवं कस्बे श्रोत उपलब्ध हैं। प्रायः इन सभी श्रोतों का जल कैटेरीरियालाजिललो अदुरक्षित है। पेयजल के श्रोत कस्बे एवं कस्बे होने के कारण योजनाओं बनाने से पूर्व ग्रीष्म ऋतु में जल नमूने कार्य कराने आवश्यक होता है। जहाँ पर श्रोतों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वहाँ पर योजना 70 स्क्वीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन को दर से बनायी जायेगी। तथा जिन श्रोतों में पानी की

योजना पर्याप्त नहीं है, वहाँ की योजना 50 सेकेंड लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन को ढर में बनाई जायेगी।

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में 125 ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान करके 81 हजार जनसंख्या को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1975-76 में 35 ग्रामों को 21 हजार जनसंख्या को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने को का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरिजनों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु हरिजन शिविरों में अतिरिक्त जल सार्वभूमि दिये जाने का प्रावधान है।

योजनाओं का संचय स्वयंसेवक समान अधीक्षण विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। समुचित स्वरूप हेतु छोटे-छोटे योजनाओं में एक अंगुली फीट लम्बा ब्रह्मो योजनाओं एवं उन योजनाओं के लिये जिनके द्वारा ग्राम गृहों को पेयजल सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, में एक पूर्ण कालीन फीट लम्बा बनाया जायेगा तथा पानी को शुद्ध करने हेतु उचित आवश्यकतानुसार क्लोरिनेशन पाउडर मिलाया जायेगा।

जनसंख्या में जल आपूर्ति कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में निर्धारित 3,509 हजार स्थायी परिव्यय से विधित 5,121 हजार स्थायी राजस्व आयोजनाएत श्रोत से व्यय किया गया। पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 के लिये अनुमान: 58,174 हजार और 6,813 हजार स्थायी परिव्यय निर्धारित है जिसका श्रोत वार भाजन इस प्रकार है :-

श्रेणी	पंचवर्षीय योजना	वर्षिक योजना 1975-76
(1)	(2)	(3)
1- राज्य आयोजनाएत	47,049	3750
2 - संसदीय	11,125	3063
योग :-	58,174	6,813

वर्ष 1974-75 में सार्वजनिक विभाग विभाग द्वारा 20 हजार रुपये का प्रावधान पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु किया गया था जिसने उपयोग से 2 हरिजन शिविरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1975-76 में भी इस कार्य के अन्तर्गत 30 हजार स्थायी परिव्यय निर्धारित किया गया है।

पंचम पंचवर्षीय योजना तथा वर्षिक योजना 1975-76 में आशुपत्र पत्राग्री का विवरण इस प्रकार है :-

आशुपत्र	पंचवर्षीय योजना	वर्षिक योजना 1975-76
1- सोरेंट (10 टन)	8,658	1,710
2- स्टोल (10)	305	76
3- पाइप (10)	8,658	1,710
4- सॉल्ट (10)	435	85
5- सॉल्ट (10)	216	42
6- क्लोरिनेटर (10)	750	150
7- फीट लीटर (10)	2,175	230

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचयत विधा प्रदान किये गये ग्रामों को विकास खण्डवार सूची ।

क्र.सं.	विकास खण्ड	ग्राम	क्र.सं.	विकास खण्ड	ग्राम
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1-	ऊखीमठ	1- ऊखीमठ			31- जौला
		2- मण्डी			31- कालिन
		3- चुनो			32- जाँ
		4- धरवाड़ी	2- जीशोमठ		1- पाण्डुशेर
		5- मोटरे			2- तपोवन
		6- घतारा			3- टंगो
		7- परखण्डो			4- टंगोपल्ली
		8- सेरघो			5- लासो
		9- नाला			6- दाल
		10- रुद्रपुर			7- हुण्डो
		11- लोडापा			8- लाम्बगड
		12- गजन			9- परना
		13- न्याल			10- बाम्पा
		14- शीप्रयाग			11- पाखो
		15- बाल मल्ला			12- सेलंग
		16- मुण्ड			13- जलवाड़
		17- मुन्नालो			14- राजा
		18- रामपुर			15- सतारो
		19- फल	३ दशौलो		1- गंडासू
		20- त्रिमुनीनाशायण			2- छिनला
		21- गौरो मुण्ड			3- पिपलौ
		22- रामबाड़ा			4- बौला
		23- देदारनाथ			5- विजार
		24- मोटया			6- विजराहीट
		25- मलमुफा			7- देहरगाँव
		26- घकिमाना			8- तुटौला
		27- कालीमठ			9- पिलंग
		28- तन			10- मठ
		29- मन			11- बाला

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		12- डुग्री			19- देवराड़ा
		13- सेना			20- सुगेश्वर
		14- नारो			21- गोपाटा
		15- नावा			22- छाल
		16- एण्ड	5-नामनाम पोखरो-		1- देवगान
		17- हरानो			2- छाल
		18- लखारो			3- भडोला
		19- बुधातगाँव			4- राना
		20- यलिया			5- छोड़ो
		21- बालभिला			6- तोलो
		22- भिमतला			7- रोठली
		23- हाट			8- डंगार
		24- दिगोलो			9- पोखरो
		25- लडाइ			10- भानो
		26- नन्दप्रयाग			11- मुनिगला
		27- पोखलपोटो	6- कर्णप्रयाग		12- रोठगो
4- परालो -		1- सेवाड़			1- कर्णप्रयाग
		2- हाट			2- एण्ड
		3- ललाणो			3- रानरा
		4- काग			4- डिमार
		5- देरुड			5- कणारा
		6- काताराकण्डो			6- हिण्डौलो
		7- बुधरो			7- नौलो मल्लो
		8- सेना			8- नौलो
		9- विजयपुर			9- दोरो नागला
		10- ललवाटो			10- नौलो
		11- गुरगानि			11- यवाड़
		12- बुरभल			12- देवलो बगड़
		13- गुनाक	7- अण्डगुनो -		1- काणपोट
		14- यवाड़लगा			2- यवाण्टो
		15- गुन्दोलो			3- विजपुरो
		16- लोट			4- सोरागाँव
		17- दाता			5- बोरा
		18- शिलपोटो			6- धनेया

(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)
		7- बेलगाँव		8- नारायणबगड	1- बेरा
		8- रामगढ़			2- श्रुतिगाला
		9- कपूरी			3- चिरो
		10- चौधरी			4- बाली
		11- तिलवाड़ा			5- जालपुर
		12- नालोट			6- कुनेम
		13- अमरगुनो			7- लखारा
		14- हनुमाल		9- गैरसैण :-	1- गेहलचौरी
		15- लखनगर			2- गाला
		16- रामपुर			3- गैर
		17- बीरा			4- लंका
		18- ताजपला			5- पञ्जियाना
		19- सागना			6- टावर
		20- डामो			7- धुगड
		21- बांडो			8- नगलो
		22- काण्डा			9- हरगाँव
		23- लौल			10- पण्डवालो
		24- जवेनो			11- जेण
		25- नैलना			12- गायलो
		26- नगरो			13- सेलकोट
		27- डोधा			14- नालपो
		28- खान्दर			15- धारगड
		29- दोषदा			16- म्वाड
		30- सतियागड			17- हरगड
		31- जहलौर			18- धारापानो
		32- वार			19- शिगलो
		33- शीमल			20- गैरसैण
		34- सौरा			21- डडागज्जाडो
		35- कुनोधर			22- जालपुर
		36- लणलोतो			23- अलो
		37- जगोठ			24- गज्जाडो
		38- धानपुर			25- बजियाँरो
					26- गडेडा

कुल गाँव की संख्या - 191

(21) - आवास एवं नगरीय विकास

=====

बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगिकरण एवं रोजगार को साधनाओं के कारण गाँवों में अड़कों में आवास ने नगर क्षेत्रों को आवासीय समस्या को अधिक विषय बना दिया है। जनपद के दो नगर चणोली तथा गोबेण्डर तथा जीओणठ में से प्रथम में आवास को समस्या अधिक अटोल है। इसका कारण जिला मुख्यालय तथा सभी कार्यालयों का मुख्यालय इसी नगर में स्थापित होना है। इस कारण को कुछ हद तक शासकीय आवास गृह बनाकर दूर करने का प्रयास किया गया है। किन्तु अनेक अधिकारियों जनसंख्या को रोकना आवास वातावरण को प्रारम्भिक सुविधाओं को उपलब्ध नहीं हैं। नेटि-अइड स्तरों को आवास प्राप्त है इसलिए अभी तक आवास गृह निर्माण को और न कोई रुकावट उठाया गया है और न केवल निम्न श्रेणी के लिये इसको कोई योजना हो बनाई गई है। निम्नो क्षेत्र में भी कोई योजना, बंधन कार्य तथा नहीं बनना गया है और अब तक भी भी योजना बने हैं वे बीवना नगरपालिका आवासकार्यों की ध्यान में रखे हुए मालिकों को अपनी इच्छानुसार को बनाने गये हैं। चणोली गोबेण्डर नगर को बढ़ती हुई जनसंख्या के मुकाबले में आवास गृहों को बनाने को देखते हुये यह आवश्यक है कि यहाँ आधुनिक सुविधा युक्त भावनों के निर्माण के साथ-साथ ऐसी एक कस्तुरी विभाजन को जहाँ जिनमें आधुनिक आवास सुविधाओं जैसे पेयजल जलविद्युत, नालियाँ, सड़क, बिजली आदि को सुविधा उपलब्ध हो। कुछ लोग तथा इस कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य के परिषदों पर तर्कीय योजना को अर्द्ध में उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा चणोली गोबेण्डर नगर में ₹ 5-1.75 लाख रुपये को लागत से 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके 4 एकड़ भूमि का 23 भागों का निर्माण कराया जावेगा। इनमें दो शक्ति मध्य आय वर्ग, 3 अल्प आय वर्ग और 18 दुर्बल वर्ग के लिये निर्मित लिये जायेंगे। जनपद में यह कार्य वर्ष 1975-76 के बाद प्रारम्भ किया जा सकेगा। परिषद् ने इस कार्य को अन्तर्गत उन लोगों के लिये जो अपना भवन स्वयं बनाना चाहेंगे। के लिये अनुषंगी का प्रविधान किया जायेगा और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग को आवास समस्या को हल करने के लिये इसी गृहों पर भवन बनाकर उन्हें आवास किराये पर उपलब्ध कराया जावेगा।

* (22) पिछड़े समुदाय का कल्याण *

पिछड़े हुए समुदाय में प्रायः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का ही जन्म जाता है। प्रदेश के अन्य भागों की भाँति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों का आर्थिक जीवन पिछड़ा हुआ है। कहीं-कहीं यह स्थिति अधिक दैयनीय है। पर्वतीय प्रदेशों की नारी भी उपेक्षित रही है। अतः उसे भी पिछड़े समुदाय में सम्मिलित करना न्याय संगत है।

सन् 1971 की जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला समाज के सदस्यों की संख्या क्रमशः 49 हजार, 8 हजार तथा 1-51 लाख पाई गई है जो जनपद की कुल जनसंख्या का क्रमशः 16-0, 2-98 एवं 51-5 % होती है। गत दशक में जहाँ जनपद की सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर 15-6 % रही है वहाँ अनुसूचित जातियों एवं महिलाओं में इस वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 13-9 तथा 15-7 पाया गया है। अनुसूचित जन जाति की स्थिति के सन्दर्भ में कोई टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्योंकि 1961 की जनगणना के समय इनकी प्रथाक से गणना नहीं हुई थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की इस वृद्धि दर और पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जन जातियों के प्रतिशत को देखते हुये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जन संख्या का कुछ वर्षों का प्रक्षेपण इस प्रकार है :-

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का प्रक्षेपण :-

अनुसूचित जाति

वर्ष	जनसंख्या (000)	कुल परिवार संख्या (अनुमानित)
1971	49-0	9790
1973	51-0	10200
1979	54-4	10860
1981	53-8	11150
1989	62-0	12400

- अनुसूचित जन जाति :-

वर्ष	जनसंख्या (000)	कुल परिवार संख्या (अनुमानित)
1971	8-2	1630
1973	8-5	1710
1979	8-2	1640
1984	9-9	1990
1989	10-4	2080

पाँचवीं पाँच वर्षीय योजना के अंतर्गत जो तो पूरी जनसंख्या के लिये पेय जल शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी हैं किन्तु पिछड़े हुये इन 57000 लोगों के लिये उक्त के अलावा आवासीय सुविधा भी प्राथमिकता के आधार पर जुटाई जानी है। ये जादातर भूमिहीन हैं तथा इनके पास जी. विकासाजर्जन के कोई विशेष साधन नहीं है। अतः इनकी सामाजिक एवं आर्थिक ज़रूरतों को तीव्र गति से उठाना ही है तभी जनपद व प्रदेश का चौथी विकास सम्भव है।

अ- अनुसूचित जाति का कल्याण :-

चौथी पाँचवर्षीय योजना में संचालित परियोजनाएँ एवं अनुभव की गई कठिनाईयाँ :-

चौथी पाँच वर्षीय योजना के अंत तक अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यतया शिक्षा, आवास एवं पेशे के विकासार्थ हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इससे ग्रामीण कठिनायियाँ यह रही हैं कि अनुदान की घनराशि कम व दूरी काफी पुरानी है। आज की महंगाई में इन दूरों पर खिंच रह कर अनुदान ग्रहिताओं को समुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भवन निर्माण हेतु एक परिवार को 1500 रुपये तक अनुदान दिया जाता है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों में 27 फीट लम्बे, 21 फीट चौड़े तथा 10 फीट ऊँचे भवन के निर्माण में कम से कम 5000 रुपये की लागत आती है। इसलिये जो परिवार आवास की दीनहीन स्थिति में है तथा जो वास्तव में अनुदान पाने के पात्र हैं वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

दूसरे अनुदान की घनराशि कम प्राप्त होती है जिससे सामाजिक स्थिति के अलावा देवी प्रदोषी से प्रभावित परिवारों को तुरन्त लाभ नहीं दिया जा सकता। पहाड़ी क्षेत्र का शिल्कार अपेक्षाकृत अधिक गरीब है तथा वर्षा ऋतु में भूस्खलन एवं टूटफूट होती रहती है जिससे इनके कच्चे आवास स्थलों तथा पेटक कारोबार को हानि पहुँचती है। इसलिये पहाड़ी प्रदेश के विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अनुदान की वर्तमान दरों में वृद्धि करनी हा होगी तथा मैदानी क्षेत्रों की प. अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परियोजना में अधिक घनराशि का प्राविधान करना होगा तभी विकास तीव्र गति पर लाया जा सकता है।

गत योजनाओं में संचालित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त :-

अब तक संचालित परियोजनाओं के अतिरिक्त पाँचवीं पाँच वर्षीय योजना में कृषि विकास अनुदान और एक राजकीय औद्योगिक आश्रम पट्टादि विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। सभी संचालित की जाने वाली योजनाओं की स्थ. रेखा निम्न प्रकार है-

1.- पूर्वदशक शिक्षाओं की जा. त्रुटि एवं अनावर्तीय सहायता :-

चौथी पाँच वर्षीय योजना के अंत तक इस मद में 5-28 लाख रुपये व्यय किये गये जिससे 11300 छात्र लाभान्वित हुये वर्ष 1974-75 में 70 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी गई जिससे 507 छात्र लाभान्वित हुये वर्ष 1975-76 में 63 छात्रों की छात्रवृत्ति से

17-18 मार्च 1976 को 1975-76 के लिए 141 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

लाभान्वित करने हेतु 12 लाख परिवारों का पर्याय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

22- अनाज की आवश्यकताओं में बढ़ने वाले वर्षों में 7 करोड़ 10 लाख छत्रों के कुल की प्रतिपूर्ति -

इस वर्ष इस मद में चौथा पंचवर्षीय योजना के अंत तक 43,000 हजार रुपये व्यय हुआ है

जिसमें 5840 छत्र लाभान्वित हुए। इसमें वर्ष 7 से 19 तक के छत्र प्रतिवर्ष 1974-75

में 32 लाख की कुल की प्रतिपूर्ति हेतु 3-00 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

52- दशमोत्तर वर्षों की मात्रा -

चौथा पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना में 76-70 हजार रुपये व्यय हुए जिससे अनुसूचित जाति के 222 छत्रों को छत्रवृत्ति प्रदान की गई वर्ष 1974-75 में 52 छत्रों को 26-8 हजार रुपये की छत्रवृत्ति दी गई है और 1975-76 में 60 छत्रों तथा पांचवी योजना में 322 छत्रों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

1- अनाज की आवश्यकताओं के व्ययों का भौतिक स्तर अभी काफी गिरा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं है अतः इनकी शिक्षा की आर्थिक स्तर पर लाने के लिये उक्त तीनों परियोजनाओं में आगामी क्रम-ब-छत्रों व तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखना होगा।

48- गैडवस्तु, इन्जिनयोरिंग तथा तकनीकी छात्रों को अनाज की सहायता -

इस मद की उक्त प्रकार की कोई भी प्रति बंधित सेवा नहीं है इसलिये इस परियोजना में अभी तक कोई भी व्यय नहीं हुआ है चालू योजना का 1975-76 में 1-00 लाख की स्थापना का प्रस्ताव है। इसी योजना के बाद ही तकनीकी छात्रों को सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

53- विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं, छात्रावासों, पुस्तकालयों का विस्तार -

वर्तमान समय में उक्त प्रकार की किसी भी संस्था को विभागीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। वर्ष 1975-76 में दो संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 1-30 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

64- कुटी विकास अनुदान -

वर्ष 1965-66 तक इस परियोजना में 3-80 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे 36 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। हरिजनों में लगभग 20% कुटी कार्य करते हैं। इनकी 13-9 प्रतिशत वृद्धि दर को देखते हुए आगामी 15 वर्ष में इनकी जनसंख्या लगभग 62 हजार हो जाने का अनुमान है जिस पर 12400 परिवार होंगे। इन कुटी परिवारों में से 2480 कुटी परिवार होने का अनुमान है। वर्ष 1965-66 तक कुटी अनुदान किया गया है वह औसतन 100 रुपये प्रति परिवार किया है जिसमें कोई विशेष बहाल नहीं था। अतः सभी 2480 परिवारों को लाभान्वित किया जाना होगा। वर्ष 1974-75 में 5 हजार रुपये का अनुदान वितरित करके 5 परिवारों को लाभान्वित किया गया और वर्ष 1975-76

के लिये 6000 रूपया प्रस्तावित है जिससे 12 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।।

71- कुटीर उद्योग सहायता :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना के अन्तर्गत 2-17 लाख रु रुपये व्यय किये गये जिससे 770 परिवार लाभान्वित हुये ! हरिजनों में 70 % परिवार आने पैत्रिक ढंग से अपनी आजीवनिका चलाते है । ऐसे परिवारों की कुल संख्या आगामी 15 वर्षों में 8680 होगी । वर्ष 1973-74 तक 770 परिवारों को लाभान्वित किये जाने के उपरान्त 7910 परिवारों को आगामी वर्षों में यह सहायता दी जानी है । पाँचवीं योजना के वर्ष 1974-75 में एक औद्योगिक सहकारी समिति का गठन स्थान मण्डलमें करके 5 हजारे-हस्त हजार रूपया अनुदान के रूप में प्रदान किये गये । इस समिति में लगभग 20 परिवार सदस्य के रूप में शामिल हुये है ।

81- गृह निर्माण योजना :-

अनुपूचित जाति के 80 % परिवार उपर्युक्त आवास रहित है , यह 80 % परिवार आत पूरा की लक्ष्यी योजनाओं से तर्की गयी व वर्तमान का मौसमी वीन हालत में दिताते है । अतः इन्हे प्राथमिकता के आधार पर आवास सुविधा उत्त उपलब्ध कराई जानी है । चौथी पंचवर्षीय योजना तक 337 परिवारों को भवन अनुदान दिया गया है जिस पर 4 लाख रूपया व्यय हुये है । इन 337 परिवारों जिन्हे आवास सुविधा दी जा चुकी है की खटा कर 9583 परिवारों को आगामी 15 वर्षों के अन्तर्गत यह सुविधा दी जानी है । पाँचवीं योजना काल वर्ष 1974-75 में 12 हजार रूपये की सहायता से 12 परिवारों को गृह निर्माण सहायता प्रदान की गई है ! वर्ष 1975-76 में 13 परिवारों के लिये 13 हजार रूपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है ।

91- आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना :-

इस जनपद के अनुपूचित जाति के लोगों की विगत 4 वर्षों से यह मांग रही है कि स्थान थिरवाक में एक औद्योगिक प्रकार का आश्रम पद्धति विद्यालय शासन द्वारा स्थापित किया जाय जिसमें शिक्षा के अलावा औद्योगिक कारखाने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो । इन लोगों की वैयक्तिक स्थिति को देखते हुये यह मांग व्यापक संगत हुई है । इस प्रकार के विद्यालय में उम्र 6 से 10 तक की शिक्षा के साथ ही साथ भिन्न प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण, तथा भोजन क्षेत्र एवं आवास की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाय , इसकी संयता कम से कम 200 छात्रों की होनी चाहिये । इस मांग पर विचार करते हुये भारत न के वर्ष 1974-75 में स्थान थिरवाक में पिताहाल एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना कर दी है । जिसमें वर्ग 1 से 5 तक के छात्रों को सामान्य शिक्षा , आवास , भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा आदि निःशुल्क प्रदान किये जाने की व्यवस्था है । वर्ष 1974-75 में इस विद्यालय का पर 1-25 लाख रूपया व्यय हुये है और वर्ष 1975-76 के लिये 9-15

लारव रनादे का परिचय निर्धारित किया गया है ।

कम अनुसूचित जन जाति वर्गों का :-

इस जनपद में बाछों एवं लो लोला नाय की जन जाति निवास करती है जिसे सामूहिक रूप में भीटिया की जाति दी गई है । 1971 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 8-0 हजार अंकी गई है जो जनपद की कुल जनसंख्या का 2-8% है, 1961 की जनगणना के अनुसार जाय भीटियों की गणना अलग से नहीं की गई थी, इसलिये इनकी संख्या की दृष्टि दरिया रही इस पर टिप्पणी देना सम्भव नहीं है । इसलिये इनकी जनसंख्या में 2-8% के आधार पर, अंकी गई है ।

भीटिया लोगों का कारखाना मुख्यतया भूख दफ्तरी पालन लिखत कृषक व्यापार एवं औद्योगिक रूप से कृषि रहा है । 1960 के दशक में भारत के अन्तर्गत विगड़ने के कारण लिखत व्यापार रुक ही गया तथा इनकी आजीविका को गहरी टैस पहुँची । भूख दफ्तरी के कारणों से अवकाश भी अब कम हो गये है जिससे उनके पालन पोषण में भी अड़तीका हो रही है उनकी आवास व्यवस्था भी पंढिते ले ही ठीक नहीं रही है । वर्ष 1967 में भीटिया जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया तथा इनके लिए आवास विकास के लिये आवश्यक सहायता का प्रविधान किया गया ।

चौथी पाँच वर्षीय योजना काल में संघालित परिवर्तनों एवं अनुभव की गई परिस्थितियाँ :-

चौथी पाँच वर्षीय योजना के अंत तक मुख्यतया शिक्षा, आवास, कुटीर उद्योग, कृषि विकास, योग्यता सुविधा एवं सहकारी समितियों के गठन हेतु सुविधाएँ दी गई है । इसमें मुख्य कठिनाई अनुदान की गई कि अनुदान की दर काफी पुरानी है जिससे अर्थ की योग्यता को देखते हुये अनुदान लिखत को उचित लाभ नहीं मिल सकता है । दूसरे जन जाति के लोगों की आवश्यकता को देखते-ही-देखते हुये नि तनी भाग रही उतनी धनराशि भी जनपद में प्राप्त नहीं हुई, तीसरे भीटिया लोगों को हरिजनो की भाति भवन निर्माण हेतु अण भी नहीं दिया जाता है । अतः अनुदान की धनराशि की दरें बढ़ाई जाय वहाड़ी क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये धनराशि का अधिक प्राणिकरण किया जाय तथा भीटियों लोगों को भवन निर्माण हेतु अण की भी व्यवस्था हो ।

यस योजनाओं के संघालित परिवर्तनों की प्रगत समीक्षा एवं दीर्घकालीन परिस्थितियों संघालित :-

1. पूर्ववर्ती वर्षों की छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता :-

चौथी पाँच वर्षीय योजना के अंत तक तथा एक से तथा 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिये इस परिवर्तनों में 2-53तारव स्वयं कृत किया गया जिससे 5580 छात्रों को लाभान्वित किया गया । पाँचवीं योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 38 हजार रुपये की छात्रवृत्ति 302 छात्रों को वितरित की गई ।

वर्ष 1975-76 में 20 छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान करने हेतु 3 हजार रुपये का परिचयित निधि परियोजना निर्धारित किया गया है।

(2) कक्षा 9 से 10 में अध्ययन करने वाले अशासकीय विद्यालयों के छात्रों के शुल्क की क्षतिपूर्ति :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना के अन्तर्गत 3-60 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे 62 छात्रों का लाभान्वित किया गया। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 1-5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति से 22 छात्रों को सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 1975-76 में 20 छात्रों की सहायता के लिये 2 हजार रुपये का परिचयित निर्धारित किया गया है।

3:- दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :- इस परियोजना में चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक 90-200-90-20 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे 5980 छात्रों को इसका लाभ मिला। पांचवीं पंच वर्षीय योजना काल में वर्ष 1974-75 में 95 छात्रों को 40-49-5 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई और वर्ष 1975-76 में 100 छात्रों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शैक्षिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर अभी काफी गिरा हुआ है और इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है। अतः इनकी शिक्षा को सामान्य स्तर पर लाने के निमित्त उक्त तीनों परियोजनायें आगामी छठी एवं सातवीं पंच वर्षीय योजना में भी चालू रखनी होंगी।

4:- वैडिकल इंजिनियरिंग तथा तकनीकी छात्रों को अनावर्तीय सहायता :-

जनपद में इस प्रकार की कोई प्राविधिक शिक्षा संस्था नहीं है इसलिए इसमें अभी तक कोई व्यय होने का भी प्रश्न नहीं उठा रहा है। जनपद में आईटीआई × की स्थापना हो जाने के बाद ही प्राविधिक शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जा सकेगी।

5:- विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं, छात्रावासों एवं पुस्तकालयों का प्रसार :-

इस जनपद में विभाग की ओर से जनजाति छात्रों के लिये उक्त प्रकार का कोई छात्रावास एवं पुस्तकालय आदि संचालित नहीं है।

6:- कृषि विकास अनुदान :- चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन मद में 94 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया जिससे 47-0 हजार रुपये व्यय हुये हैं। भौटिया लोगो में लगभग 25% परिवार कृषि का कार्य करते हैं जनपद की सम्मति सामान्य जनसंख्या में जनजाति जनजाति के प्रतिशत में भौटिया लोगो की वर्ष 1973-74 में 8540 हो जाने का अनुमान है जिसके 25% के हिसाब से 427 कृषि परिवार होंगे जनसंख्या की यदि यही वृद्धि दर रहेगी तो वर्ष 1989 इनके कुल परिवार 519 तक हो जाने की सम्भावना है अब तक 94 परिवारों को यह सुविधा दी जा चुकी है। अतः शेष 425 परिवारों को अभी और लाभान्वित किया जाना होगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, 11 परिवारों को 1000 रुपये

पंचवर्षीय परिवार नियोजना में वर्ष 1974-75 में 11 परिवारों को 1000-1000 की दर से 11000-9999 रुपये की सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1975-76 में 39 परिवारों को सुविधा दे लिये। 5 हजार रुपये की परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 384 परिवारों को सहायता प्रदान करना शेष रह जावेगा।

(7) कुटोब उद्योग:- इस परियोजना के अंतर्गत चौथे पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत 123 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है जिससे 389 परिवार लाभान्वित हुये हैं। भोईया लोगों में 79% परिवार अपने पैतृक कारोबार में जैसे मैड बनरो पालन कटाई बुनाई सिलाई बट्टींगरी एवं लोहारों में आदि कारोबार करते हैं। इन 79% परिवारों में 19% परिवारों की वे अपने स्वयं से पैतृक कारोबार की व्यवस्था है, अतः 60 प्रतिशत परिवारों को इस परियोजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है। इनकी जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुये आगामे 15 वर्षों में 60 प्रतिशत के हिसाब से 1245 परिवार होने का अनुमान है। इनमें 389 परिवारों जिन्हें वर्ष 1973-74 में लाभान्वित किया जा चुका है, को छोटा कर 386.5 परिवारों को कुटोब उद्योग में अनुदान दिया जाना है। पांचवें पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1974-75 में इस मद में कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकी है किन्तु वर्ष 1975-76 में पिछला 12 हजार रुपये का प्राविधान किया जा चुका है।

(8) गृह निर्माण अनुदान:- चौथे पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत भोईया लोगों को 250 परिवारों को भवन निर्माण अनुदान दिया गया है। इस निष्ठा कार्य में 32 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वर्तमान समय में अनुमानतः इनमें 170 परिवार होने। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर आगामे 15 वर्षों में इन परिवारों की संख्या 2080 हो जाने की सम्भावना है। भोईया लोगों से 50 प्रतिशत परिवार घास पूस की झोपड़ियों में निवास करते हैं। 250 परिवारों परिवारों जिन्हें भवन सुविधा दी जा चुकी है को छोटा कर 790 परिवारों को आगामे 15 वर्षों को अर्थात् यह सुविधा दी जाना है। पांचवें पंच वर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 26 हजार रुपये की सहायता से 14 परिवारों को लाभ प्रदान किया गया और वर्ष 1975-76 में 10 परिवारों को सहायता हेतु 16 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(9) पुनर्वास योजना:- भोईया लोगों के ऐसे परिवारों को जिनके पास शरणदान, मूदान या अर्ध श्रौती से प्राप्त 5 एकड़ तक जमीन हो उन्हें इस प्राप्त जमीन पर पुनर्वासित करने लिये 5000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से अनुदान देने का प्राविधान है। इस जनपद में अभी तक किसी भूमिहीन परिवार को इस प्रकार की भूमि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस परियोजना पर अभी चौथे पंच वर्षीय योजना के लिये 12 हजार रुपये व्यय नहीं हुआ है। वर्ष 1974-75 में प्रति 55 हजार रुपये के 11 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु पर्यावही चल रही है। वर्ष 1975-76 में 4 परिवारों को सुविधा प्रदान करने हेतु 29 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

10- अश्व पद्धति विद्यालय को स्थापना:- इस जनपद में चौथे पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत

कमिश्नरिठ में एक अश्रम पद्धति विद्यालय जनजातियों के लिए 6 से 8 तक के बच्चों के लिये स्थापित किया गया है। जिसमें निशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास को सुनिश्चित व्यवस्था है। इस विद्यालय को पढ़ता 105 छात्रों को है। जो समय में शिक्षा के प्रति जीवित होने के लिये इस प्रकार के बालिका अश्रम पद्धति विद्यालय को भी आवश्यकता है।

11:- जनजाति छात्रावास की स्थापना :- मिला मुख्यतः मोहर में वर्ष 1974-75 में एक जनजाति छात्रावास की स्थापना की गई है। इसे जनजाति के छात्रों को आवास तथा भोजन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की है।

12:- शोर्टिया जाति का सर्वांगीण विकास :- पश्चिम पूर्व वर्गीय योजना के अंतर्गत शोर्टिया जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु अन्तर्गत गार्म, लिंग गार्म तथा सिंघाई योजनाओं के निर्माण विद्युत्करण तथा दुधारू पशुओं के विवरण का कार्यक्रम किया गया है। इस हेतु वर्ष 1974-75 में 2-25 लाख रुपये व्यय किया गया और वर्ष 1975-76 के लिये 3-17 लाख रुपये का परिचय निर्धारित किया गया है।

अ(2) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति :-

शासन ने अन्य पिछड़ी जातियों जैसे नाई, स्वामी, गिरी (गोपाली) आदि के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है। इस प्रकार अन्य के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग के छात्र को जिसके अभिभावक को आय 250 रुपये प्रतिमाह से कम हो, वे भी छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इन परियोजनाओं का स्थापित विवरण निम्न प्रकार है :-

1:- पिछड़ी जाति के पूर्ववर्ग वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा आवासीय सहायता :-

इस मद में साथ पूर्व वर्गीय योजना के अंतर्गत 20 छात्रों को सम्पादित किया गया है। जिन पर 7-50 हजार रुपये व्यय हुआ है। पश्चिम योजना ताल में वर्ष 1974-75 में 1 हजार रुपये की सहायता 6 विद्यार्थियों को दी गई है और 1975-76 में 9-00 हजार रुपये से 60 छात्रों को सम्पादित लिये जाने का प्रस्ताव है।

2:- पिछड़ी जाति के अन्य के आधार पर अध्ययन करने वाले दशोत्तर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा आवासीय सहायता :-

वर्ष 1973-74 तक इस परियोजना के अंतर्गत 3-00 हजार रुपये व्यय हो चुके हैं जिससे 7 छात्र सम्पादित हुये हैं। वर्ष 1974-75 में 11-7 हजार रुपये से 22 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई यह सुविधा वर्ष 1975-76 में भी जारी रहेगी जिसके लिये 16 हजार रुपये का प्रावधान किया जा चुका है।

3:- उक्त के अतिरिक्त 1974-75 में गैरिजिस्ट्रार जाति के दशोत्तर वर्ग के 4 छात्रों को 982 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष 1975-76 के लिये 500 रुपये का अवयव प्रदान हुआ है।

(23) - समाज कल्याण

=====

ए। समाज कल्याण की परियोजनाएँ :- समाज कल्याण में जनपद की निराश्रित महिलाओं का उद्धार तथा अर्थात् एवं वहीरे लोगों के कल्याण का कार्य सम्पन्न है। जहाँ तक इस योजनाओं में जनपद की महिला समाज की स्थिति का प्रश्न है वह बहुत ही कमजोर है। सुगौदम के लेकर रात के अंधेरे तक यहाँ की महिलाएँ अपने कृषि, पशुपालन एवं अनेक धरेलू कार्यों में कठिन परिश्रम के साथ व्यस्त रहती हैं। यहाँ का पढ़ा लिखा युवक अक्सर शासकीय सेवाओं में रहता है। इसलिये जनपद की जनशक्ति पूर्ण तया स्त्री समाज पर निर्भर करती है। यहाँ के पुरुष ने स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज के विकास शील युग में भी यहाँ का समाजिक रूप ठीका समानता पर आधारित नहीं है। यह कारण है कि जनपद के 500 प्रधानों में से एक भी महिला प्रधान नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि स्त्रियों के उत्थान हेतु यहाँ के पुरुषों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। स्त्रियों का कारोबार हल्का करने के लिये पकिंगमैच में पानी को सुविधा हो, कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रसार हो। युवक और युवतियों को शिक्षा में सन्तुलन हो। इच्छुल पढ़ी लिखी युवतियों एवं निराश्रित विधवा महिलाओं के लिये प्रत्येक प्र. विकास कार्यक्रम पर एक-एक बिल्ली प्रशिक्षण केन्द्र हो। जहाँ एक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक से एक 50 महिलाओं के लिये भिलाई, इडाई, गुनाई आदि कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण एक वर्ष का हो जिसमें प्रत्येक महिला को कम से कम 60-80 रूपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाए। स्त्री शिक्षा तथा 8 तक अनिवार्य कर दी जाए। स्त्री-विशेष-संरक्षण-संस्थानों में जनपद की स्त्री शिक्षा समाज का उत्थान सम्भव है।

इसी प्रकार दीर्घ प्रयोगों के ओहोन अर्थात् ही जाने काले व्यक्तियों को राहत देने का कार्य स्त्री-विशेष-संरक्षण और समाज का है। उन्हें उद्योग की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये।

समाज कल्याण से सम्बन्धित जो परियोजनाएँ इस विभाग द्वारा संकलित की जा रही है उनका सविस्तर विवरण आगे दिया जा रहा है :-

गत योजनाओं में संकलित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा पाँचवीं पंच वीर योजना को रूप रेखा

1. निराश्रित एवं विधवा महिलाओं की जिम्माउत्तजिन को सुविधा (भिलाई उपकरण के रूप में)

इस परियोजना के अन्तर्गत बीसों पंच वीर योजना के अन्त तक 65-50 हजार रूपये व्यय किये गये हैं जिसमें से 330 महिलाओं को भिलाई यन्त्रों अनुदान के रूप में दी गई हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सहायता के लिये 59 हजार रूपया और वर्ष 1975-76 में 5 हजार रूपया का परिवर्धन निर्धारित किया गया है। वर्ष 1975-76 में निर्धारित 5 हजार रूपया परिवर्धन के विपरित 1-5 हजार रूपया व्यय किया गया था। जिसमें 3 महिलाओं को भिलाई यन्त्रों और प्रत्येक को 150 रूपया का बड़ा उपलब्ध कराया गया।

2: निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सहायता अनुदान (पेंशन के रूप में)

=====
 यह परियोजना वित्त 2 वर्ष से चालू की गयी है । इसमें एक महिला को 30=00 रुपया प्रतिमास तथा प्रत्येक बच्चे के लिए 10=00 रुपया अतिरिक्त धनराशि के रूप में स्वीकृत किया जाता है । इसमें अधिकतम धनराशि एक महिला को 60=00 रुपया प्रतिमास है । इस परियोजना के अन्तर्गत 1973-74 तक 21-70 हजार रुपये व्यय किये गये हैं जिसमें जनपद को 37 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है । पश्चिमी पंच शील योजना में वर्ष 1974-75 में 27-70 हजार रुपया व्यय करके 28 महिलाओं को पेंशन की सहायता प्रदान की गई । योजना के आगामी वर्षों में भी यह पुर्विष्टा जारी रखने का प्रस्ताव है ।

3: बहरे तथा अर्धंग लोगों को सहायता :- (कृतिग अंगों के रूप में)

=====
 चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस परियोजना में 1-86 हजार रुपये व्यय किये गये हैं जिसमें जनपद के 6 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 400=00 रुपये की सहायता एक व्यक्ति को प्रवण मंत्र कारोदने हेतु दी गई । पश्चिमी योजना के शेष वर्षों में भी इस प्रकार की सहायता प्रदान किये जाने की सम्भावनाएँ हैं ।

=====
 0 0 0
 =====

(25) आर्थिक सेवाएँ

जिला सहायक कारो कार्यालय को कार्यक्षमता में प्रवृद्धि लाने के लिये पंचायत पंच कर्षण योजनावधि में गणक पत्र इन्फ्लेक्टर तथा टेलोपेन का सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर नियोजन सम्बन्धी कार्यों में प्रगति लाने के लिये एक नियोजन शिष्ट को स्थापना किये जाने का प्रावधान है। जिससे एक अर्थशास्त्री और उसको सहायता के लिये कुछ अन्य सदस्यों को नियुक्ति हो जावेगी। इस शिष्ट का कार्य जिला स्तर पर योजना बनाने में स्थानीय अधिकारियों को मदद करना तथा समय समय पर योजना सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को वेश रक्षण करना होगा। पंचायत पंच कर्षण योजना में उक्त उद्देश्य को पूर्ति के लिये निम्नलिखित दो परियोजनाओं को स्वीकृत की गई है:-

- 1.- साक्षरता:- जिला साक्षरता कार्यालयों को उनकी क्षमता में प्रवृद्धि लाने हेतु सजा की सम्पूर्ति। इसके अंतर्गत पंचायत योजना तथा वर्ष 1975-76 का परिव्यय क्रमशः 4-0 तथा 3-6 हजार रुपये है।
- 2.- नियोजन पत्र:- जिला योजनाओं के निष्पन्न में प्रगति लाना। यह परियोजना इस जनपद के लिये 24-3 हजार रुपये के प्रावधान के साथ वर्ष 1974-75 में स्वीकृत की गई थी किंतु प्रशासन में गिरक्यता के कारण इस पर व्यय नहीं किया गया। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायत योजना तथा वर्ष 1975-76 में क्रमशः 129.5 और 31-3 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2.- प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975-76 में भी इन दोनों परियोजनाओं पर व्यय करने की अनिर्णीत शासन से नहीं प्राप्त हुई है।

6- कितीय दृष्टिकोण एवं रण संघाओ का योगदान

=====

साधनों की उपलब्धता प्रगति शक्ति देशों के लिए किताब के युग में एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश जैसे गरीब और कम विकसित प्रदेश में यह समस्या बहुत और गंभीर हो जाती है। जब साधनों की पूर्ति मुश्किल होती है तो जुटाने और पूरा करनी पड़ती है। इस समस्या के निराकरण में कितीय संघाओ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इनका मुख्य कार्य पूजा को बाह्य यंत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में जुटाना है। इस कार्य हेतु अधीर ध्यान दिए बिना ही प्रतिक्रिया पर विचार करना है। कितीय संघाओ वस्तु की मात्रा, आयु का अनुपात बढ़ाने में भी अर्थ व्यवस्था को उत्पादक बंधन बढ़ाकर सहाय्य सिद्ध होती है। व्यवस्था के अभाव में उच्च दायर वस्तु को प्रोत्साहन देने में भी सहाय्य सिद्ध होती है। व्यवस्था के अभाव में रहने वाले जीवन वीर्य कमिनी, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा प्रमुख कितीय संघाओ ने देश की अर्थ व्यवस्था में अपना एक उच्च स्थान बना लिया है। राष्ट्रीय रण के उपरान्त व्यवस्था के अभाव में भी सुदृढ़ हुई है। प्रदेश में जुलाई 1969 से पूर्व 11.6 हजार के जनसंख्या पर अक्षरता के अभाव में यथा जहाँ देश का अक्षरता 365 जनसंख्या था जून 1972 के अंत में स्थिति का अभाव सुधरो और प्रदेश में 65 हजार के जनसंख्या पर एक के अभाव में अक्षरता हो गया जहाँ देश का यह अक्षरता 40 हजार के जनसंख्या तक पहुँच गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अक्षरता में भी सुधार आया है फिर भी यह देश के अक्षरता से भी अभी तक पीछे है।

चर्खे की जनपद प्रदेश का एक पहाड़ी और बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ संसाधन संसाधनों का अभाव बहुत ही कम हुआ है। अभी तक संसाधन जुटाने में अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत रहने के द्वारा प्रमुख योगदान रहा है। जनपद के दोनो उप संसाधनों में कृषि को रण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक सहायता के चर्खे में स्थित है जिसकी तीन शाखाएँ अर्थ व्यवस्था और जोशोष्ठ में कार्य कर रही हैं। यद्यपि स्टेट बैंक आफ इंडिया की जनपद का नृत्य के अभाव में बनाया गया है। परन्तु इसकी द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक स्वयं आगामी संसाधन संसाधन श्रोतों के उपयोग के क्षेत्रों में धार्य बने रहे रहती है वर्ष 1973-74 तक स्टेट बैंक की शाखाएँ, चर्खे की अर्थ व्यवस्था एवं जोशोष्ठ में कार्यरत दो इनके अंतर्गत जोशोष्ठ में देखा नेशनल बैंक की एक शाखा है। इस समय स्टेट बैंक की उत्तर शाखाओं के अंतर्गत गोपे इतर धारकों तथा अर्थ व्यवस्था में भी इनकी शाखाएँ स्थापित हो गई हैं। रण वितरण कार्यक्रम हेतु अभी इन राष्ट्रीय बैंकों के प्रयत्न नगण्य हैं।

जनपद के अर्थ आर्थिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण के अभाव में राष्ट्रीय तथ्यांक पर आधारित अनेक आर्थिक आँकड़ों के अनुमान ही कहे जा सकते हैं। वर्ष 1971 की

जनगणना की रविवर अनुमानों के आधार पर जनसंख्या का 37-2 प्रतिशत कृषि एवं सम्बन्धीय कार्यों में 10-4 प्रतिशत विनिर्माण और परिवहन संसार एवं अन्य सेवाओं में तथा केवल 2-4 प्रतिशत उद्योग विनिर्माण और कार्यों में लगे हुए थे। कृषि प्रमुख उद्योग होने पर भी जनपद में वास्तविकता का अभाव रहता है। क्षेत्र आय के हाथने की इस पृष्ठभूमि में जनपद की अर्थी स्थिति एवं श्रमोत्पादक शक्तों को न सहज हो किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनिर्माण, परिवहन संसार और में जो लोग लगे हैं उनमें से अधिकांश जनपद के बाहर के लोग हैं जिन्होंने असाई निवास के लिये उपार्जन की वृद्धि से जनपद में रहता है।

यहाँ का स्थानीय पूँजीपति जीवन छानने में ही निश्चित है। और अपने लक्ष्य श्रमोत्पादक अर्थी धन को किसी जीवम से उठाना नहीं चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के कृषि की अधिकांश आवश्यकता को पूर्ण उच्च व्यय पर गैर जमानती ऋण के राहूतों द्वारा भी जाती है। इस बात का अनुमान लगाना फलित है कि जितने कृषि श्रमोत्पादक राहूतों से ऋण प्राप्त करते हैं। कृषि श्रमोत्पादक के प्रकार से राहूतों को वहरता कम होती जा रही है। राहूतों को द्वारा कृषि को कृषि करने, क्षेत्रों के छोटे आकार कृषि करने तथा कृषि सुधार एवं लक्ष्य शिक्षा योजनाओं के लिये मध्यम से न ऋण दिया जाता है। दोष फलित ऋण को कोई व्यवस्था नहीं है। यद्यपि जनपद में कृषि कृषि को भी कोई शाखा चार्ज नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राहूतों द्वारा ऋण पूर्ण मुख्यतः उपभोग कार्यों हेतु की जाती है। परन्तु यही राहूत अन्य क्षेत्रों में पूँजी विनियोग हेतु जीवम के कारण स्वीकृत करते हैं। इन्होंने स्वयं के लिये स्वयं कृषि भांडारण, यातायात एवं संसार और व्यक्तियों में बाहर की लगे अपना पैसा जनोचित के आधार पर पिछले कुछ समय से इस ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय उद्योगों की विकसित करने के लिये भी कुछ मजदूरी उपलब्ध में वायदा होने के कारण कोई उजबल भी देख नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकांशतया यहाँ के सम्भावित उद्योग वनाधारित हैं। वन विभाग अभी यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि इस प्रकार के वनाधारित उद्योगों के लिये किस मात्रा में किस कीटपत्तों और योग्य सामग्री प्रदान करने में सम्मर्थ हो सकेगा। अतः वनाधारित उद्योगों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन की आशाओं भी धीरे धीरे एवं संदेहों में प्रतीत होती है।

उपरोक्त कारणों से ही जलत योजना के तहत शरान द्वारा ही जनपद के निरक्षर अर्थी स्वयं को ध्यान में रखते हुये विभिन्न विभागीय कार्यों के लिये व्यय भार वहन करने की चेष्टा की गई थी।

राहूतों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऊँच पढ़न की वृद्धि हेतु वर्ष 1973-74 से 19-06 लाख रुपये तक के लिये 4-50 लाख रुपये मध्यम से न ऋण वितरित किया गया।

पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत तृतीय स्थापन जुटाने के लिये में राहूतों के अतिरिक्त नेतृत्व के (स्टेट कै आफ इण्डिया) राष्ट्रीय मूत्र के तहत कृषि पुनरुत्थ

निम्नलिखित अर्थ संस्थाओं के लगभग 177-42 लाख रुपये के योगदान की अपेक्षा की गई है।

इसके अतिरिक्त जनपद के श्रौतिक ऋणों में ऋण धाने की वृद्धि वैभव प्रणाली उपलब्ध है। ऋणारो रणितियों एवं ऋणारो ऋणों में अमानत के रूप में बहुत कम धन जमा होता है। आय की न्यूनता के कारण वृद्धि कम होती है। इन्होंने अधिकांश भाग गहनो के वरदाने ऋणानिर्माण अर्थात् भूमि अधिग्रहण करने पर लगान दिया जाता है। ऋण धर वृद्धि के लिए अधिकांश धन जमा करने के लिये ऋण सहाय पर अभियान को चलाये जाते हैं जिन्होंने पौरजाम किसी रीति में उत्साह दर्शाते रहे हैं।

जनपद में मुख्यतया उन शही स्थानों पर जहाँ से आलू धान निर्यात होता है वैभव सुविधा के प्रकार की आवश्यकता है। मुख्य विपणन क्षेत्रों पर शही वैभव सुविधाये अर्पित है। यह सुविधा नेतृत्व के (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) राष्ट्रीय कृत वृद्धि, ऋणारो वृद्धि एवं भूमि विकास को की शायदे क्षेत्र प्रदान की जाती जा सकती है।

अधिक वृद्धि को पछड़े हुए क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाओं के प्रकार रक के आयन्विधन रक वृद्धि ठोस योजनाये नेतृत्व के वैभव द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रवृद्धि की जा सकती है।

किसी योजना को कुशलता एवं प्रितव्यता से चलाने के लिये पूजीयत संसाधनों का समानुसार उपलब्ध होते रहना अत्यन्त आवश्यक है। यह आवश्यकता चोली जैसे पहाड़ी और आर्थिक दृष्टी से पिछड़े हुए जनपद में ज़रूर और भी तीव्र हो जाती है। जनपद में केवल वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के वित्तीय संशोधन शून्य से ही हैं।

संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण एक कठिन कार्य है। सम्पूर्ण आवश्यकताओं का पहले से ही सही अनुमान लगाने के लिये बहुत विस्तृत और वास्तविकता पर आधारित योजना बनाने की आवश्यकता होती है। निरसिद्ध आवश्यकता के अनुमान पहला बदल जाते हैं। और समय समय पर पूरक अनुमान बनाने पड़ते हैं। फिर भी यदि पहले से वास्तविकता पर आधारिक अनुमान बना लिये जाय तो काफी हद तक परिवर्तनों को कम किया जा सकता है।

आर्थिक उन्नति के लिये संतुलित योजना हेतु आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न प्रकार का कच्चा और अन्य सामान जो उत्पादन प्रक्रिया के काम आते हैं समानुसार आवश्यक मात्रा एवं अच्छे प्रकार का उपलब्ध हो सके ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले कारखानों व संस्थाओं की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

हालांकि उन मदों की सूची जिनकी आवश्यकता का अनुमान लगाना आवश्यक है काफी लम्बी है। यहाँ केवल मुख्य मदों जैसे कृषि सामग्री, रसायनिक छाद सहित और मुख्य मुख्य निर्माण सामग्री जैसे लोहा और स्टील, सिमेंट आदि का ही विवेचन नीचे किया जा रहा है।

1) कृषि पदार्थः- कृषि सामग्री की आवश्यकता इन पदार्थों की भाँग के अनुसार आँकी जा सकती है। और उत्पादन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यक निर्देशों का जुटाया जाना आवश्यक है।

जनपद की आभासी पंचवर्षीय योजना में कुछ मुख्य मुख्य मदों की आवश्यकता के मोटे अनुमान निम्न प्रकार हैं :-

कृषि पदार्थों की भाँग वर्ष 1975-76 तथा पाँचवी योजना के अनुमान

पदार्थ	इकाई	कृषि उत्पादन			
		1973-74	74-75	75-76	78-79
1- खादसान (000) मेटन		74	78	79	83
2- दालें					

उपरोक्त वर्णित पदार्थों की भाँग का ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन के लिये किसी सीमा तक उभरे रहे किये हैं। ताकि उक्त वस्तुओं का कुछ अधिक रटाक उपलब्ध हो सके और उसका प्रयोग अभाव के वर्षों में किया जा सके। यह इसी लिये भी आवश्यक है ताकि खादसानों के मूल्य को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित रखा जा सके। उपरोक्त बातों के ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की कुछ मुख्य वस्तुओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है।

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1975-76 तथा 78-79 में कृषि पदार्थों का प्रक्षिप्त उत्पादन है (हजार मेटन)

वर्ष 1975

2) प्रक्षिप्त उत्पादन

	75-76 80-89	78-79 89-06
1- खाद्यान्न		
2- दालें	1321-32	1-65
योग	82-27	90-71

2) रासायनिक खाद:-

उपरोक्त वर्णित खाद्यान्नों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये रासायनिक खादों का समयानुसार आवश्यक मात्रा में उपलब्धता अनिवार्य है। सघन एवं द्रिक्सली कृषि भी उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक है। सिंचाई साधनों के अतिरिक्त, रासायनिक खाद ही ऐसा निदेश (input) है जिसके संतुलित प्रयोग से कृषि उत्पादन को एक अच्छे स्तर तक बढ़ाना संभव हो सकता है। जनपद में रासायनिक खाद के प्रयोग की कुछ वर्षों की प्रगति इस प्रकार रही है:-

जनपद में वर्षवार रासायनिक खाद के प्रयोग की प्रगति

वर्ष	नाइट्रोजन खादें	फास्फोरिक खादें	पोटेशिक खादें
1970-71	61	44	23
1971-72	52	38	17
1972-73	71	48	22
1973-74	86	78	15
1974-75	87	47	13

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1975-76 तथा 78-79 में रासायनिक खादों के उपयोग के प्रक्षिप्त अनुमान - (मेटन)

वर्ष	नाइट्रोजन खादें	फास्फोरिक खादें	पोटेशिक खादें
1975-76	286	220	140
1978-79	294	220	147

हृद्य निर्माण साधनों और उनकी आवश्यकता:-

आर्थिक और सामाजिक उन्नति से ही इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश, प्रदेश अथवा जनपद की प्रगति की क्या सीमा है। इसके लिये निर्माण कार्यों का समयानुसार कार्यक्रम के अन्तर्भूत पूरा किया जाना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिये निर्माण साधनों जैसे सीमेंट और स्पात, सीमेंट और कोयला आदि की लगातार आवश्यक मात्रा में उपलब्धता, प्रा-थमिक आवश्यकता हैं। इसके लिये जन हृद्य निर्माण साधनों पदार्थों का पहले

से समुचित अनुभव लगाना आवश्यक है। ताकि बाद में इन वस्तुओं की लगातार मांग के अनुरूप पूर्ति में कोई बाधा न पड़े। मशीनों में मरिचि सामग्री जैसे लेहा सेमैन्ट आदि की आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन है। क्योंकि इसके कोई निरूपण नहीं है। उपलब्ध नहीं है। सरकारी क्षेत्र में किये गये जाने वाले मरिचि कार्यों हेतु सामग्री की आवश्यकता विभागीय योजनाओं के सहायित रूप से वर्तन की गई है। फिर भी कुछ प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता का विभागीय विवरण इस प्रकार है :-

विभाग	सेमैन्ट (मै. टन)	लेहा एवं स्यात (मै. टन)	स्टील (मै. टन)	वायर (मै. टन)
1- सिंचन व्यवस्था	23,000	1670	120	-
2- पेयजल सप्लाई पूर्ण	8,658	385	-	-
3- सिंचन	6,000	55	-	-
4- विद्युत	488	84	-	424
5- सहकारित (इनो एवं गोदामों के मरिचि हेतु)	22	14	14	-

प्रत्येक विभाग के निरन्तर लक्ष रूप पत्र। एवं तैयार लक्ष रूप पत्र 2 में विस्तार पूर्वक भेजा गया है।

जनपद में मरिचि कार्यक्रमों के निम्न कृषि श्रमिकों की आवश्यकता होगी जो कि जनपद के श्रमिक समिति क्षेत्र के कार्य में अधिक दक्ष नहीं हो पाये हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के निम्न ठेकेदार निर्माताओं के सम्पादन हेतु कृषि श्रमिक जनपद के बाहर से लाते हैं। उनके कर्म सहाय्य करने पर भी यहाँ के श्रमिक प्रियुक्त हो सके। वैसा ही प्रसार के क्षेत्र सप्लाई कृषि श्रमिकों के बढ़ने की सम्भावना है। प्रादेशिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार से प्रियुक्त श्रमिकों की संख्या में अज्ञान वृद्धि हो सकेगी।

यों तो प्रत्येक विभाग में कार्य क्रमों के प्रसार एवं संचालन हेतु सहायकों के अभाव पर अपनी रणनीति का निर्धारण कर लिया है। और इसका उल्लेख प्रदेश के विभाग के योजना के अन्तर्गत में किया गया है। हाँ इससे यह अपेक्षा की जाती है कि कार्य क्रमों के सम्पादन एवं संचालन हेतु कर्म कठिनियों का सम्पूर्ण समूह शासकीय मितियों में परिवर्तन कर लिया जाये। उदाहरण के लिये जड़ी वृद्धियों की वनों से निपटारा हेतु केवल प्रशिक्षित श्रमिकों को ही, अक्षर दिया जाये, तकि अक्षर जड़ी वृद्धियों समूल नष्ट न हों पावे और आय का यह श्रोत सतत चलता रहे।

पंचम पर्यवेक्षण योजना में आधुनिक सूक्ष्म विधायी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम एवं उपलब्ध सहायकों के अभाव अर्थन रहेगा। अतः, निरन्तर एवं कृषि श्रमिकों का पूरा उपयोग किया जाय जिससे अधिक निरक्षर में सदाचार उपलब्ध हो सके और प्रति व्यक्ति अधिक आय में अक्षर से अक्षर वृद्धि हो सके।

(8)- सेवा योजना कार्य क्रम

=====

1961 में जनसंख्या को जनसंख्या का 65-3 प्रतिशत भारीत था जो 1971 में घटकर 53-2 प्रतिशत हो गया । 1961 में जहाँ 60-8 प्रतिशत पुरुष तथा 69% महिलाएँ भारीत थी वहाँ यही प्रतिशत 1971 में घटकर 54-5 और 61 हो गये । 1971 में राज्य को 32-26 प्रतिशत और भारत को 33-54 प्रतिशत जनसंख्या भारीत पाई गई तथा उसमें पुरुषों का प्रतिशत 52-30 एवं 52-53 और महिलाओं का योगदान 3-3 प्रतिशत व 13-3 प्रतिशत रहा । इन आँकों से प्रकट होता है कि जिले में भारीत जनसंख्या राज्य और राष्ट्र के सम्बन्ध औरतों के अधिक है तथा जहाँ यह भारीत पुरुषों का प्रतिशत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है, वहाँ महिलाओं के सम्बन्ध में वह राज्य के औरतों से 7 गुने एवं राष्ट्र के औसत से 4 गुने से भी अधिक है ।

2- 1961 में भारीत जनसंख्या का 83-8 प्रतिशत बोली में लया हुआ था । 1971 में यह प्रतिशत घटकर 86-9 हो गया । भारीत पुरुषों में से जहाँ 80-4 प्रतिशत 1961 में बृद्धि करके भी वहाँ 1971 में उनको पंजाब घटकर 74-3 प्रतिशत रह गई । इसके विपरीत महिलाओं को संख्या जो 1961 में 95-4 प्रतिशत थी, 1971 में बढ़कर 97-4 प्रतिशत हो गई । 1971 में उत्तर-प्रदेश में क्षेत्रों में लगे हुए पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 59-10 तथा 34-30 एवं भारत में लगे 46-35 तथा 27-93 थाया गया ।

3- काम करने की आयु प्रायः 15 से 59 वर्षों के बीच को कही जाती है । 1961 में इस आयु वर्ग में जिले की जनसंख्या में 5% लोग आते थे । उनमें भी पुरुष 46% तथा महिलाएँ 54% थी । 1971 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 52, 47 तथा 53 हो गये ।

4- उपर्युक्त विवेचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि जिले में राज्य और राष्ट्र को तुलना में लड़ों अधिक अनुपात में महिलाएँ भारीत हैं और काम करने आती स्त्रियों को संख्या पुरुषों से अधिक है तथा क्षेत्रों के स्तरों में महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं से हो निकल रहा है । यह भी अनुभव में आया है कि यहाँ के बृद्धि कार्य में सिवाय हल तथा देने तथा क्षेत्रों को जुड़ाई कर देने के अतिरिक्त पुरुष अन्य कोई भूमि का नहीं निभाता । इस प्रकार जनगणना के अवसर पर जिन पुरुषों ने अपना मुख्य उद्योग क्षेत्रों लिखा था वो होगा वे इसी वोटों के अंश कालेक भारीत व्यक्त रहे होंगे ।

5- 1961 की जनगणना के अवसर पर जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार जिले में वेपदे-लिपे एवं विना लिपि में लिखे गये जिले के लोग वगैरहों को संख्या 19 था जो नगण्य है । ऐसा लगता है कि इस बात का कोई विचार नहीं किया गया कि बृद्धि लिखाने वाले पुरुष अधिकतर पिठले लड़े रहते हैं ।

6- वेते जिले में प्रति बृद्धि परिवारों का औसत आकार एक हैक्टर के लगभग आता है और इतनी भूमि है में भरपूर क्षेत्रों को अधिदाने के बाद 5 वगैरहों को बृद्धि को जो विना लगे से चल सकता है परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

अधिकांश लोग अपना धनो न बचके पारके रूप या डेढ क ल हो लेते हैं । लगभग सारे पुरुष कृषक बेरोजगारों को श्रेणी में आ जाते हैं । 1971 को जनगणना के अनुसार देश के व्यक्तियों की संख्या 58,154 है । इनमें अतिरिक्त 393 पुरुष एवं 249 स्त्री भोज. हर राजपूरी की धो नहीं छोड़ा जाऊँ सकता । इस प्रकार यदि पूर्ण रूप से बेरोजगार न धो नहीं परन्तु वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या 58,702 अति है जो सौधो योजना के अन्त में बढ़कर 61,637 हो जाने का अनुमान है । धेतो के धन्धो में लगे हुदू महिलाओं को बेरोजगार नहीं कहाँ जा सकता क्यो के वे तो इ. मध्य धो इतना परिश्रम कर रही है के उन्हें और कियो काम के लिये फुरसा हो नहीं मिल पातो ।

7- धेतो की अल्प आधुनिक ढाँचे से सचन धेतो धन्धे करके उच्च बेरोजगार अनुदान अधनो कृति धिनता को धिति को धूर कर सकता है परन्तु अनुभव में यह आता है के धेतो के प्रति यहाँ के पुरुष समाज में रुचो नहीं है । यह उधयो अलाभकारी धन्धा मानता है । आसक्तिता यह है के विधणन को पुदिधियों के अधा में वह मानता है के अधिकांशकाल पैदा करके वह का तो अधिकांश पैसा परन्तु उतने हाथ में वह ध्रुव नहीं आ पायेगा जिसके धी ध्वारा वह जीवन को अन्य आनन्दधताओं को पूर्ति करना चाहता है । अतएव वह कष्ट नन्ध परिश्रमिक को अधिकांश धरता है । यह परिश्रमिक उधे राजपूरी के रूप में मिल सकता है परन्तु धर से धूर का कर का न करने को प्रकृतित एवं कायिक पर आका अदि को पुदिधियों के अधा में वह राजपूरी धो अपने गणियों के निष्कट हो करना चाहता है । धिहास को प्रति विद्र होने के को निष्कट मार्ग धीमें उनधे धो गणियों में रहने वाले लौहारी, राजपूरी और लहारी तथा अनुभल धिधियों को जोधिया के अतिरिक्त आधन उपलब्ध हो एधियों ।

8- 1961 को जनगणना पुस्तिका में लिखित बेरोजगारों की संख्या 67 हो हुई है । 1971-72 में धेका योजना मण्डलिय में धंधोनूत ऐसे व्यक्तियों की संख्या 639 थी जो 1973-74 में 967 हो गई । 1973-74 में स्थलिय रोजगार मण्डलिय जादातर इस धीधो के 190 और 1974-75 में 220 लोगों को काम देलवा का । धिया प्रकार के हाथ धी लिये बेरोजगारों की संख्या निःसन्देह बढ़ेगी परन्तु उधका आकार इतना धोधण नहीं होगा जितना पैदानो क्षेत्रों में देखने को मिलता है । इधका कारण यह है के विछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ किला को प्रति अपेक्षानूत जोड़ रहे धिया पैदानो धान को तुलना में यहाँ बेरोजगार के अकार अधिकांश संख्या में धृजित होंगे । धिनित करने धालो बात यह है के जनसंख्या के धन्धे के नून होने तथा धिधियों के धूर-धूर धूर्म धियाँ धर विधारा होने के कारण यहाँ पड़े लिये लोगों को विजलो, धानो, विधणन, धंधे, उधधिया को कसुओं के धृम धिधिया, परिधहन, धंधार अदि अ ध्याधना पैदाओं के विधान के धध्याधिया उधयो आता न हो धंधे धिधियों के के उनधे मिललिले में उधन्न होने धाले रोजगार धधों को आंन आधेति हो धी ।

9- धधै-1973-74 में 4,113 अत्र-अधारे उधतर मण्डलिय कलाओं में धिया धा रही धो । यह धानो हुये के 48 प्रतिधता कधित का तो उधध धिया ध्राप्त करेधे या

सहलायें गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे तो लगभग 2,470 स्त्री-पुरुष रोजगार को जलाए लेंगे। इसी दर पर पाँचों योजना के अन्तर्गत यह संख्या लगभग 8,600 पहुँच जायेगी। इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारों का संख्या में घटनार सुनिश्चित होतो रहेगा।

10- जहाँ तक बेरोजगारी का प्रश्न है जिले के दोनों उप-प्रभागों में स्थिति लगभग एक ही है।

11- जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी बाधा स्थानीय दुर्लभ कारीगरों को लगी है। अतः बेरोजगार भ्रमशक्ति को औद्योगिक प्रविणता देने हेतु जिले में

औद्योगिक प्रविणता केन्द्र खोले जाने को निश्चिन्त आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये शासन ने जनपद में एक औद्योगिक प्रविणता संस्थान को स्थापना करने का निर्णय किया है। इस हेतु वर्ष 1975-76 में 2-50 लाख रुपये परिसंयुक्त विधित्त किया गया है।

=====

9 न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

पंचम पंच वर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों के बढ़ने पर भी निम्न वर्ग इस योग्य नहीं हो सकेगा कि वह अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ एवं सेवाएँ ब्रह्म करके जीवन का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। इस कमी को कुछ अनुसूचक कार्य क्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, पीने के पानी की सुविधा, भ्रमण, आवागमन के साधन, वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता एवं विद्युत्करण द्वारा दूर कर न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा। इनहीं आधारित सुविधाओं को न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने जिला स्तर पर पंचम पंच वर्षीय योजना में निम्न कार्यक्रमों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है।

- 1- समस्त बच्चों को आधारिक शिक्षा एवं 60 प्रतिशत बच्चों को आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान किया जाना।
 - 2- सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को पेयजल की सुविधा प्रदान किया जाना।
 - 3- ग्रामीण क्षेत्रों में 80 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर साज सज्जित प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपलब्ध कराया जाना तथा प्रत्येक 8,000 से 10,000 की जनसंख्या पर एक उप-केन्द्र की स्थापना।
 - 4- 1500 या उससे अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम को पूर्णकालिक सड़कों से जुड़ाया जाना।
 - 5- कम से कम 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को विद्युत् की सुविधा प्राप्त किया जाना।
 - 6- नगरीय क्षेत्रों में गन्दी वस्तीयों का हटाना।
 - 7- कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं, घातु माताओं एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार की सुविधा का प्रदान कराया जाना।
 - 8- भूमिहीन श्रमिकों को एकान्तीय भूमि का आवंटन।
- जनपद बोर्डों में उपरोक्त कार्यक्रमों की सीखित में निम्न प्रकार सदीक्षा की गई है।

1- आधारिक शिक्षा :- यह अब सर्वमान्य है कि आर्थिक बाजार में उत्पादकता की दृष्टि से सीधा सम्बन्ध लोगों की शिक्षा प्राप्त से है। इसी कारण प्रत्येक नागरिक की शिक्षा का एक न्यूनतम निर्धारित स्तर प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। आधारिक शिक्षा को प्राप्त कराना दुनिया की आवश्यकता है। योजना आयोग के शिक्षा अनुभाग ने निम्न परिषदों को प्रथम स्तर पर न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किये जाने की संज्ञा दी है :-

- 1- बालिकाओं के लिये कमी से पांच तक पूरे समय के प्राथमिक स्कूलों की स्थापना।

- 2- छटी कक्षा से आठवी कक्षा तक पूरे समय के स्कूलों का होना ।
 - 3- प्राइमरी स्कूलों के साथ छटी कक्षा से आठवी कक्षा तक की क्रमोत्तर कक्षाएँ ।
 - 4- 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के 10 प्रतिशत बच्चों के लिये अत्यकालिक (Part-time) शिक्षा का प्रवन्ध ।
 - 5- प्राइमरी स्टाफ विहित कक्षाओं की 25 प्रतिशत अतिरिक्त बालिकाओं को धूनी फार्म एवं उपरिष्ठत श्रुति देकर शिक्षा उपार्जन हेतु प्रोत्साहित करना । प्राइमरी कक्षाओं की 50 प्रतिशत अतिरिक्त बालिकाओं का उच्च पुस्तकों की सुविधाओं का दिया जाना, तथा मिडिल कक्षाओं के 50 प्रतिशत अतिरिक्त बच्चों (बालक एवं बालिका) को भी यही सुविधा प्रदान किया जाना, और प्राइमरी कक्षाओं के बालकों को दोपहर के भोजन का प्रवन्ध कराया जाना ।
- जनपद में पंचम पंचवर्षिय योजना काल (1974-79) में बालक एवं बालिकाओं के लिये प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता निम्न प्रकार से दर्शायी गई है ।

(हजारों में)

वर्ष 73-74 के 6-11 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या	कक्षा 1 से 5 के वर्ष 73-74 में शर्ति	कक्षा 1-5 के वर्ष 78-79 में अनुमानित शर्ति	अतिरिक्त बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में शर्ति होंगे	प्राइमरी स्कूलों का पंचम योजना का लक्ष्य
26	23	24	1	13
बालिकाएँ 26	13	24	11	5

पंचम पंचवर्षिय योजना की अवधि में 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के 85 प्रतिशत बच्चों को आधा शैक्षिक शिक्षा सुलभ हो सकेगी ।

2- ग्रामीण पेयजल पूर्ति :-

अब तक की प्रगति को देखते हुए यह स्पष्ट विदित होता है कि जनपद में ग्रामीण पेयजल योजना में आशिक सफलता मिली है । 1971 के जनगणना के अनुसार जनपद में 1639 ग्राम हैं । इनमें से 146 गैरआबाद हैं । शेष 1493 ग्रामों में से वर्ष 1973-74 के अंत तक, स्वायत्त शासन अधि यंत्रण विभाग द्वारा 191 ग्रामों में यह सुविधा प्रदान करायी गई है । सिंचाई विभाग एवं विकास खण्डों द्वारा 510 ग्रामों में पेयजल योजनाएं बनायी गई थी जो जीर्णोन्नीर्ण अवस्था में हैं । उनका पुनर्गठन एवं विस्तार किया जाना है ।

जनपद के अधिकांश ग्रामीणों में पाईप द्वारा पानी उपलब्ध होने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है । जनपद में पेयजल साधनों के उपलब्ध कराये जाने की सम्भावनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है ।

ग्रामों को अभावग्रस्त ग्रामों में संख्या को संख्या 31 मार्च 1974 तक 1974 तक 1979 तक

1493	693	191	316	581-74
------	-----	-----	-----	--------

इसकाडी क्षेत्र में अधिकांश ग्रामों में पानी की सुविधा घरों के निकट नहीं है। कहीं कहीं तो एक गोल से अधिक की दूरी से पानी लाया जाता है जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पंचायत योजना में इसी कठिनाई एवं समस्या को दूर करने का प्रावधान है। पंचायत वर्ष की योजना के तहत साप्ताहिक पूर्ण विद्ये जाने के उपरान्त मिलने में 47.8 अभावग्रस्त ग्राम रह गये। जिसे प्राथमिकता के आधार पर एक जल सुविधा प्रदान करना होगा।

31- स्वस्थ 1- नूतन आवृत्ता के राष्ट्रीय कार्यक्रम में निर्धारित पंचायत वर्ष की योजना में 80-00 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वस्थ केंद्र और 2-10 ओके। एच 10 हजार की जनसंख्या के सेवार्थ नूतन पाना रखवा गया है। परन्तु उपरोक्त मात्र केवल पैदावार में ही हो सकेगा। चूंकि जैसे पहाड़ी जनसंख्या में जिसकी अभाव मुख्यतया स्थित है। उद्योग विद्ये नये होंगे। अतः इसे 35 हजार- 50 हजार जनसंख्या पर आधारित किया गया है।

जनसंख्या के वर्गीकरण के आधार पर इसकाय विशेषज्ञ विचारणा, समन्वित, दन्त विचारणा, बच्चों तथा बच्चों की संरक्षण की सुविधा उद्भव की है। अतः प्राथमिक विद्ये क्षेत्रों की वर्तमान सामंजस्य से सुसजित करना आवश्यक है। जिन प्राथमिक विद्ये क्षेत्रों के अने भवन नहीं है, उन्हें भवन की सुविधा का प्रावधान करना तथा रहने के आधारों की सुविधा का प्रावधान करना निश्चित है।

वर्तमान समय में किसी भी उद्योग का अभाव भवन नहीं है, उनमें विद्ये एवं ~~व्यवस्था~~ नये स्थानों में वाते जा रहे हैं। जिन निवास की प्राथमिकता को जानने चाहिए।

जनसंख्या के वर्तमान एवं पंचायत योजना के तहत विद्ये निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

	विद्ये क्षेत्रों की उपलब्धि 1973-74 में पूर्णको योजना के अंत में		पंचायत योजना के तहत एवं विद्ये क्षेत्रों की स्थिति (अब तक के)
1- प्राथमिक विद्ये क्षेत्र	9	9	93-27
2- एकीकृत विद्ये क्षेत्र	22	23	
3- आधुनिक विद्ये क्षेत्र	39	41	
4- द्वितीयक विद्ये क्षेत्र	1	2	

6.1- पोषिक आहार:- राष्ट्रीय योजना है कि प्रारम्भ से ही युन पोषण को दूर किया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को कीमती भोजन मिले। महिलाओं, स्तनधर माताओं और गर्भवती स्त्रियों को विद्यार्थियों को पोषिक आहार उपलब्ध कराया जाये। यत वर्ग में इस हेतु दो प्रकार की योजनाएँ योजनाएँ चलाई गईं। शिक्षा विभाग के अखिल बालाहार योजना और साहुदाई विकास विभाग के अंतर्गत विशेष पोषिक आहार योजना। बालाहार योजना के अंतर्गत अब तक 140 अधारित विद्यालयों को सम्मिलित किया जा चुका है। और इसमें 6730 छात्र छात्राएँ सम्मिलित हुई हैं। साहुदाई विकास विभाग के विशेष पोषिक आहार योजना के अंतर्गत एक विकास स्तण्ड दशो में चालू की गई है। इस योजना के बालाहार योजना के अंतर्गत 25 अतिरिक्त विद्यालय प्रतिष्ठा सम्मिलित करते हुये लगभग 3 हजार छात्र छात्राओं को सम्मिलित करने का अनुमान है। वर्ष 1974-75 में साहुदाई विकास विभाग को अखिल पोषिक आहार योजना विकास स्तण्ड यथागत में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः 390 तेलंगाना तथा 12 ग्राम प्रायोजन युक्त पुराने आहार 29 क्षेत्रों को दूर से प्रति शिक्षा/महिला प्रति दिन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। निम्नोक्त अखिल पोषिक आहार योजना हेतु पत्नी योजना में 17-46 लाख रखा परियोजना निर्धारित है।

7.1- भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान करने हेतु भूमि का आवंटन :-

केंद्रीय सरकार ने इस योजना को *central sector scheme* के अंतर्गत अन्वेषण है और इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जात है। परिवार को परिभाषा में किया, उसके पत्नी और आश्रित माता पिता एवं बच्चों को सम्मिलित किया गया है। ऐसी प्रकार के लिये 150 वर्ग मी भूमि का आवंटन करने का अनुमान है। केंद्रीय सरकार को योजना भी प्रदान परिवार ने इतने से भूमि विद्ये अनेक-क-के है। वर्ष 1974-75 में बंगलौर वर्ग के 2406 परिवारों को 407 हेक्टर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इस वर्ग के श्रमिकों को आवंटन करने हेतु 655-6 हेक्टर भूमि उपलब्ध है आः 10 भूमि के आवंटन हेतु श्रेष्ठ वास्तविकता को जा रहा है।

विद्यार्थियों को अध्ययन कराने उनको शूल को प्रतिभूति को लिये जाने का प्राविधान है ।
 गैडोक्ला, इन्जिनियरिंग तथा कानोले छात्रों को अनातर्थीय सहायता देने के लिये भी इस
 योजना को प्राविधान किया गया है किन्तु इसका लाभ छात्र जनपद को प्राविधान शिक्षा
 संस्था स्थापित हो जाने के बाद हो पा सकेगा । तथा 1973 से उपर का शिक्षा के लिये शत
 प्रतिशत छात्रों को छात्र प्रति प्रदान लिये जाने का प्रस्ताव है ।

2- शुद्धि विकास अमुदान:- जिन परिवारों के पास थोड़ा दहत जमीन है उनके शुद्धि विकास
 अमुदान प्रदान किया जाएगा ।

3- छोटे उद्योग सहायता:- छोटे उद्योग क्षेत्रों से गोविन्दोपार्जन हेतु सहायता हरिजन
 तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान लिये जाने का प्रस्ताव है ।

4- शुद्ध निर्माण अमुदान:- आवास हेतु शुद्ध निर्माण के लिये भी अमुदान दिये जाने का
 प्राविधान है ।

4 अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जातियों को तरह जनजातियों को भी उचित प्रकार को सभी सुविधाएँ प्रदान
 लिये जाने का प्राविधान है अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के लिये 2 वह
 क्षेत्रों सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिन्हें हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग
 द्वारा वर्ष 1974-75 तक 4650000 अमुदान तथा ऋण दिया जा चुका है ।

5- अन्य पिछड़े जातियों एवं ऐसे क्षेत्रों जिनके अविभाज्यों को मासिक आय 250 रु० से
 कम हो तो भी छात्र प्रति दिये जाने का प्राविधान है

6- निरश्रित एवं दिवंगत महिलाओं को गोविन्दोपार्जन को सुविधा (सिलाई उपकरण
 के रूप में) तथा सहायक अमुदान (पैन्सन के रूप में) दिये जाने को योजना में प्रस्तावित है ।

7- उच्चत सुविधाओं के अतिरिक्त हरिजन वस्तियों में प्रमुखतः स्थान, विद्यार्थिताकरण
 प्राप्ति के आधार पर किया जाएगा । वर्ष 1973-74 तक 39 हरिजन एवं जनजाति
 वस्तियों का विद्यार्थिताकरण किया जा चुका है । वर्ष 1974-75 में 20 हरिजन वस्तियों
 को विद्यार्थिताकरण को सुविधा प्रदान की गई और योजना के आगामी वर्षों में विद्यार्थिताकरण
 लिये जाने वाले ग्रामों से संवद्ध हरिजन तथा जन जाति वस्तियों का विद्यार्थिताकरण साथ
 साथ लिये जाने को निम्न निश्चित की गई है । हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा
 पदवत सुविधाओं के अतिरिक्त सामाजिक विकास विभाग द्वारा वर्ष 1973-74 में
 50 ग्राम हरिजनों के आवास हेतु निर्मित लिये गये और दो ग्रामों में प्रमुखतः योजना

का निर्माण किया गया। वर्ष 1975-76 के बजट में बजट के 20 परिसरों के लिये स्थलों का विनाश करने प्रथम निर्माण हेतु मूल्य प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 30 हजार रुपये का प्रावधान है।

8:- उद्योग विभाग द्वारा हवेली उद्योगों के स्थापना के लिये वर्ष 1973-74 के अनुसूचित जाति के सदस्यों को 37-8 हजार रु. 10 हजारों हेतु और जनजाति के सदस्यों को 4-79 हजार रु. 280 हजारों स्थापित करने हेतु न्य. वितरित किया गया।

वर्ष 1974-75 में 5 हजार रु. अनुसूचित जाति के उद्योग पति को एक हजार स्थापित करने हेतु न्य. प्रदान किया गया। उद्योग विभाग द्वारा न्य. वितरित करने के लिये पिछले वर्ष के आवेदन पत्रों को बरीयता को माते है। प्रसादो शोधोद्योग बोर्ड द्वारा एक हजार के स्थापना के लिये 500 रु. जनजाति वर्ग को वर्ष 1975-76 में न्य. देने का प्रस्ताव है।

9:- अनुसूचित जाति जन जाति तथा बजट में वर्ष के 2406 परिसरों को वर्ष 1975-76 में 407 हेक्टरों का अकटन किया जा चुका है। इस वर्ष के वर्षों लिये आर्किटेक्ट करने हेतु 655-26 हेक्टर मूल्य उपलब्ध है। अतः शेष मूल्य के अभाव में शोध कार्यवाही को आरंभ है।

10:- अनुसूचित जाति तथा जनजाति को प्रतिवर्षी के प्रथम मूल्य प्रदान किये जाने का यो प्रावधान है। सायल शोध अभियंत्रण विभाग द्वारा जिन शोधों के प्रथम योजना का निर्माण किया जायेगा उनसे संबंध बजट में जो इन वस्तुओं में आये प्रथम सुविधाये उपलब्ध कराये जायेंगे।

11:- शासन के वर्तमान निर्णय के अनुसार बजट में न्य. प्रस्त. व्ययों को पूरने ल्यों और तथापि उन्हें लो प्रथा से पूरित मिल जायेंगे।

अध्यक्ष: मैं बजट में उद्योग विभाग के अंतर्गत उद्योग पति को एक हजार स्थापित करने हेतु न्य. प्रदान किया गया है। उद्योग विभाग द्वारा न्य. वितरित करने के लिये पिछले वर्ष के आवेदन पत्रों को बरीयता को माते है। प्रसादो शोधोद्योग बोर्ड द्वारा एक हजार के स्थापना के लिये 500 रु. जनजाति वर्ग को वर्ष 1975-76 में न्य. देने का प्रस्ताव है।

जनजाति विकास (Tribal Development)

इस क्षेत्रगत जनपद में क्षेत्रीय जनजाति विकास करती रूप है, जू 1967 में भारत सरकार ने इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। इस जनजाति की जनपद में कुल जन जनसंख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर 8-0 हजार दर्ज हुई है। यह जनजाति जनपद की दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। इनके मूल मेधासो नीति व भात एपी में है। ये लोग गर्भियों में विकास विकास एकद रवड क्षेत्र के अंतर्गत अपने मूल ग्रामों में निवास करते हैं तथा सर्दियों में विकास रवड देसी रथं कर्मयोग के अंतर्गत अलकनन्दा के दोनों ओर अपने क्षेत्र पहाड़ों में रहते हैं। रन्धेश इनका प्रमुख पेश सेवक करी पालन, कताई बुनाई तथा तिसत से व्यापार रहा है। नीति व भात एपी में अपने मूल ग्रामों में अधिक रूप से कृषि भी करते हैं। आयें है।

सन 1960 से पूर्व इनका तिव्यत से व्यापार चलाता रहा है तथा इनकी आयी वला संचालन रूप से चलती रही, लेकिन 1960 के बाद भारत कोन एज के प्रस्ताव इनका तिव्यत व्यापार ठप हो गया तथा इनकी आयी वला को काफी क्षति पहुंची। इनमें जो हरिजन आदिवासी थे उनकी स्थिति और भी खराब हुई। भीड़ बल्लेश सारागह के क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। 1970 की अलकनन्दा की बाढ़र बाड से इनके बावास स्थली को बहुत क्षति पहुंची है। इसलिये इन लोगों केही स्थिति और भी दयनीय हो गई है।

वैसे तजा पिछड़ी हुई जिल्लों के लक्षण अध्याय में भी दिया जनजाति के विकास के संचालित परियोजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया तथा प्राचनो प्राचनोय योजना में आवश्यक चरनीस प्रकृति का प्रस्ताव है, फिर भी इनके जीवन स्तर को जनपद के सामान्य जीवन स्तर पर लाने के लिये चाल योजनाओं के अलावा कुछ अन्य विशेष प्रकार को परियोजनाओं में प्राथमिकता करनी आवश्यक होगी जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1 :- विशेष देखभाल को होना ;

अ- लोहार पिन्स

बुन बुनई करी -

उमी उद्घोष ।

द- सिलाई कार्य आवी ।।

2 :- शिक्षण मागों का निपटारा - जो-जो-अधि त्तरक्या खोरेर मागों से नहीं मिल पाये हैं, वही शिक्षण मागों का निपटारा किया जाना चाहिये ।

3:- धीकरणा सुविधा :- प्राप्त नही, एवं सुगडटोटा, यदि ये क्षेत्र सामलप्राप्तित
 होगा त वरने को आवश्यकता है ।

4:- आधारित विद्यालयों को स्थापना :- प्राप्त कर देया, रिकवर्स(आ कोशपुर)
 एवं रेन्डुरा में एक एक आधारित विद्यालय स्थापना को मति को । इनको शारका विद्यालय
 संरक्षित ही मने हैं ।

5:- शीघ्र बरारी प्रय हेतु एक को व्यवस्था :- जिन शीघ्रता परिवारों के प्राण
 धो: बरारी नहीं हैं और वे इस बरारीकार को बरना चाहते हैं । जो कोशिकों में उन्हें
 इसी व्यवस्था को कर है । शीघ्र बरारी प्रय हेतु एक को व्यवस्था मने ली है ।

6:- एक से पुकेत :- शीघ्रता जनजाति के कुछ हरिजन शीघ्रता परिवार को
 हैं जो सुविधों से सर्व से लदे हुए हैं । इनका शासन के स्तर से सर्व से लदे जाने तथा
 सर्व से पुकेत दिलाने को आवश्यकता थी। शासन को वर्तमान नीति से उन्हें बहुत को
 राहत मिल जायेगी ।

7:- शीघ्रता लोको का पुनर्वास एवं श्रुति व्यवस्था :- लोकोओं को वे कुछ प्राण
 को श्रुति वैशेष अधिकार से ले ली गई है। अतः श्रुतिहीन परिवारों को तराई क्षेत्र में
 बसाया जाय । कुछ शीघ्रता परिवार जिनका पैतृक क्षेत्र मणि बरारी को नहीं कहा लेकिन
 अब वे वृषि बरना चाहते हैं । उन्हें शीघ्रता तराई क्षेत्र में श्रुति को साथ साथ पुनर्वास से
 पुनर्वासित किया जाय ।

8:- शासकीय सेवाओं में आरक्षण:- जनजाति के युक्तों के लिये शासकीय सेवाओं में
 2 प्रतिशत आरक्षण है इनको देशनीय शिष्ट को देरवले हुने को प्रतिशत से श्यान पर
 10 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया जाय ।

9:- अधिकांश एवं कार्यकारिणों के अभाव व्यवस्था :- जनजाति क्षेत्र में कार्यरत
 अधिकारों एवं कार्यकारिणों को शासन को ओर से आवाह सुविधा उपलब्ध तराई काय तकि
 वे लोक पूर्ण लक्ष्य से कार्य कर लें ।

10:- जनजाति क्षेत्र में विद्युत्तरण :- शीघ्रता वंश वर्धित योजना में जनजाति
 जनजाति क्षेत्रों में वे गांवों में प्राप्ति का वे आधार पर विद्युत्तरण किया जाय ।

11:- शीघ्रता सुविधाओं का विस्तार :- विद्यालय विभाग द्वारा शीघ्रता सुविधाओं के
 लिये राजकीय सहायता को जारी है। इनको वृषि योग्य श्रुति में प्राप्ति का वे आधार पर
 शीघ्रता के राशियों को व्यवस्था होनी चाहिए ।

उक्त प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जनजाति सुदाय का विस्तृत
 विचार आवश्यक हो लगेगा ।

(12) - पर्वतीय क्षेत्र का विकास

=====

विकास के विभिन्न कार्यक्रमों तथा आवश्यकता सम्बन्धी सुविधाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र का राज्य के अन्य भागों को अपेक्षा करके पिछड़ा हुआ है। जनपद चमोली को अन्य पर्वतीय जिलों की तुलना में भी काफी पिछे है। राज्य सरकार की नीति अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा जिले के अन्तर्गत सम्भागीय विस्तारों दूर करने की है। यद्यपि इस उद्देश्य को पूर्णतः सिधित साधनों एवं अन्य कठिनाईयों के कारण केवल पंचवर्षीय योजना में कर पाना सम्भव नहीं है, तथापि इन्हीं उद्देश्यों एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र को विशा चमोली के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये हैं उन्हें शीघ्र तौर पर वे भागों में बाँटा जा सकता है।

1- उत्पादक कार्य क्रम (Productive Programme)

2- कल्याणकारी कार्य क्रम (Amenities Programme)

उत्पादक कार्य क्रम में कृषि, उद्योग, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन को लिया गया है। आगामी 5 वर्षों में जनपद क्षेत्र से कम छादयों के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करके इसे ध्यान में रखकर कृषि की योजना बनाई गई है। इसके लिये अधिक उपज देने वाली बीजों से आर्सेनिक, रासायनिक उर्वरकों का समुचित प्रयोग, आर्द्र, सोयाबीन, हुनहन तथा अन्य नवदी फसलों के लिये विकास की योजना बनाई गई है। इस समय जनपद में कुल क्षेत्रफल भौतिक क्षेत्रफल के लगभग 3-1 1/2 भाग में खेती की जाती है जिसका लगभग 3-6 % सिंचित है। आगामी 5 वर्षों में 112 लाख रुपये की लागत से राजकीय साधनों द्वारा 620 हेक्टर और अन्य सहायक साधनों द्वारा 847 हेक्टर सिंचन क्षेत्र का स्थापना सुनिश्चित किये जाने का प्रस्ताव है। पूरे सिंचित क्षेत्रफल में स्थान कृषि पद्धति अपना कर खाददानों का उत्पादन बढ़ाया जावेगा। सोयाबीन का 1973-74 का क्षेत्रफल लगभग 189 हेक्टर है जिससे पंचम योजना में बढ़ाकर 1500 हे० करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार आर्द्र, जो इस जनपद के उपलब्ध एक की मुख्य नवदी फसल के रूप में उगाया जाता है। 1973-74 के 2807 हे० क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3086 हे० करने का लक्ष्य है।

उद्योगों के अन्तर्गत 46000 हे० क्षेत्रफल को आगामी 5 वर्षों में बढ़ाकर 7100 हे० स्थित किया जायेगा। यह भूमि अधिकांश कृषि भूमि से ली जायेगी। वे उद्योग जो इस पंचवर्षीय योजना में लयाये जायेंगे फल देने की स्थिति में तो इस अवधि में नहीं आयेगे किन्तु जो पहले के उद्योग लयाये गये हैं उनके फल देने की स्थिति (fruit bearing) में आ जाने के कारण फलों का 1973-74 उत्पादन 5000 मेटन है वर्षवर्ष योजना के अन्त तक बढ़कर 13000 मेटन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 1440 हे० में कच्ची उत्पादन का कार्य भी सम्भव बनाया गया है।

पशु पशुपालन के क्षेत्र में आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अल्पतम 5 लाख 50 हजार केन्द्रों का सुकुटा प्रयोगों में पुनर्र्गठन तथा एक नया सुकुटा क्षेत्र खोले जाने का सम्बन्धि प्राविधान है। इस योजना में जनपद में एक नयी नर्सरी की स्थापना की जायेगी।

जिले में 380 गांवों व 6 गांव रखे जावेंगे। इसी प्रकार जिले में उन उत्पादन वृद्धि के लिये 4-665 लाख रुपये की लागत से वर्तमान 13 पैदा होने वाली शेंद एवं उन प्रकार केन्द्रों के रूप में परिकल्पित किया जाएगा और 33-212 लाख रुपये की लागत से एक सड़क भी बनाई जायेगी।

जिले लघु उद्योगों की इस समय छोटी वड़ी 85 इकाईयाँ जिले में कार्यरत हैं जिनमें बड़ाकर 100 इकाईयाँ करने का कार्य शुरू बनाया गया है। औद्योगिक विकास हेतु बनाये गये कार्य क्रम में लगभग 200 कुशल कारीगरों तथा 500 अकुशल कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा।

जिले में रेशम - टावर विकास को भी योजना बनाई गई है। योजना की अवधि में रेशम योजना के अन्तर्गत 6 हजार सिंक्राफ्ट बूझ लीया और टावर योजना के अन्तर्गत 1-50 लाख लीया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है दोनों प्रकार की योजनाओं में 100 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

उद्योग और पशुपालन को जो विकास योजनाएँ बनाई गई हैं वे अधिकांश रूप में बनों पर ही आधारित रखे रहेगी वही कि चरणगाह तथा चारा के अतिरिक्त उद्योगों के लिये अच्छा पाल बनों से ही प्राप्त होगा। इस समय जनपद में कुल क्षेत्रफल का लगभग 54 % भाग बनों से आच्छादित है जिनमें बौड़, बैल, देवदार, सुरई, बाँज, रिंगाल, अंगू, अमरोट, जलज आदि के वन हैं। इनके अतिरिक्त उपायधाय -1 में ऊँचाई में निम्नवत् क्षेत्रों में बहुतायत बनीयधियों तथा विशाल कुसाल हैं।

उद्योग और पशुपालन क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाय है और इसी दृष्टि से का सम्बन्ध एवं उन पर आधारित उद्योगों को स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

पर्यटन विकास का जिले में औद्योगिक विकास के विद्यमान प्रयत्न है। जिनसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अच्छी संसार व्यवस्था, एक सुन्दरे आवासीय एवं संधी स्तर में होटलों को व्यवस्था, आवासीय सुविधा आदि का होना आवश्यक है। पर्यटकों को पर्यटन विकास पर 127-94 लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया है। पर्यटकों को संख्या में वृद्धि के साथ स्थानीय औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित सामान, फल, दूध आदि को विक्री करेगी जिससे स्थानीय जनता को रोजगार का अवसर मिलेगा।

वस्त्राज कारो कारी क्रम

=====

सर्वप्रथम आवश्यकता पैयजल को अनुमान लो लो गई है जिसके लिये आगो संवर्धित योजनाकाल में जिले में 683 अभावग्रस्त ग्रामों में से 125 ग्रामों जिनको जनसंख्या 81000 है में स्वयंसेवा शासन अधिकांश विभाग द्वारा पैयजल योजना बनाकर पैयजल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्य क्रम पर 581-74 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

विश्विक्ता एवं जन स्वास्थ्य के लिये जिले में 72 विद्वित्मालय उपलब्ध है और पाँचवीं योजना की अवधि में 4 विद्वित्मालय और स्थापित किये जायेंगे । 36 मात्र एवं हिन्दु स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित है । सभी विद्वित्मालयों की आधुनिक भाषा सज्जा के सुव्यवस्थापन को का प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिये योजना यह बनाई गई है कि 6-11 वर्ष की आयु के 85% बालक बालिकाओं को लिये शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था हो जायें ।

इस हेतु जनसंख्या में स्थापित 542 विद्वित्मालयों के अतिरिक्त 13 विद्वित्मालय पाँचवीं योजना में स्थापित किये जायेंगे । शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से 14 यू.ओ.ओ. और 10 उच्चतर माध्यमिक विद्वित्मालय पाँचवीं योजना में प्रस्तावित किये जायेंगे हैं ।

साक्षात्कार एवं संसार व स्वास्थ्य के सुधार हेतु योजनाएँ बनाई गई हैं । इनसे अन्तर्गत में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक से अधिक औद्योगिक एवं विद्युत् केन्द्रों का उद्घाटन प्रयोग को मोटर यंत्रों में व्यवस्था किया जायें । पाँचवीं योजना में 132 कि.मी. लंबी मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है । संसार का स्थापित 925-87 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है ।

उद्योगों का विकास विद्युत्-सर्वे विद्युत् संचालन के अन्तर्गत है । इनके अतिरिक्त इनके लिये लोकोटि के मोशन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये आवश्यक है कि सभी गाँवों को बिजली से जोड़ें और तारों के रेंज दिया जाय । पाँचवीं योजना में 750 कि.मी. लंबी लोकोटि स्तर पर स्थापित स्तंभों का काम हो जायेंगे । इनके अन्तर्गत जनसंख्या को विद्युत् की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा । पाँचवीं योजना के प्रस्तावित योजनाओं में 66 ग्रामों का विद्युत् संचालन पूर्ण हो जाने की आशा है ।

पिछड़े गाँवों के विकास के लिये उनको अभाव व्यवस्था जिविकोपार्जन के लिये कृषि विकास अनुदान, मोटर उद्योग अनुदान आदि का प्राविधान किया गया है । शिक्षा प्रसार के लिये आधुनिक यंत्रों का स्तंभों का भी प्रस्ताव है । इस प्रकार पिछड़े समुदायों के उत्थान हेतु इस योजना में 31-97 लाख रूपयों का प्राविधान हरिजन तथा समाज कल्याण की ओर से किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा समान किये जाने वाले कार्य में इस कार्य के कल्याणकारी कार्य इस प्रस्तावित किये गये हैं जिनका विस्तृत उल्लेख अद्यावत् दस्तावेज में किया जा चुका है ।

धूम्र-उपयोग के वर्गीकृत क्षेत्रों में सभी प्रकार के परिवर्तन का कार्य इस वर्ष में ही । राष्ट्रीय जन शिक्षा के अनुसार कृषि या उद्योगों में लगे हुए धूम्र नहीं ली जायेंगे । उद्योगों को क्षेत्रफल को लक्ष्य कृषि के अन्तर्गत अनुपयोगी धूम्र के लिए ली जायेंगी ।

विबरण पत्र

जिला - चण्डीगढ़

पंचायती राज योजना परिवर्तन

(हजार रुपये में)

क्र. सं.	कार्य का	पंचायती		योजना		परिवर्तन		योग
		राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- कृषि								
क-	कृषि विभाग	3568	350	-	2960	-	-	6878
ख-	बागवानी तथा फलों- पयोग	11648	-	-	2432	381	-	14461
ग-	भांडारण एवं विपणन (भांडारण पर निर्धारित)	-	-	-	-	-	-	-
2- लघु विद्युत								
(1)-	निजी	1210	-	-	-	-	-	1210
(2)-	राजकीय	11200	-	-	-	-	-	11200
3-	भूमि एवं जल संरक्षण	1228	-	-	1875	-	-	3103
4-	पशुपालन	21224	530	-	-	-	-	21754
5-	दुग्ध विकास	80	-	-	-	-	-	80
6-	पर्यटन	118	-	-	-	-	-	118
7- वन								
(1)-	वैज्ञानिक	17713	-	-	-	-	-	17713
(2)-	भूमि संरक्षण	7400	-	-	-	1030	-	8430
8- प्राथमिक विद्यालय धार्मिक कार्य								
क-	पंचायत राज	153	-	-	18	-	-	171
ख-	प्राथमिक विद्यालय धार्मिक कार्य	87	-	-	-	-	-	87
ग-	प्राथमिक विद्यालय दल	38	-	-	500	-	-	538
घ-	राजकीय अभियंत्रण विभाग	-	-	-	-	-	-	-
योग कृषि एवं लघु विद्युत								
कार्य का	-	75667	880	-	7875	1351	-	85773

		वर्ष 1974-75													
		परिमल						व्यय							
		राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	राज्य	
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1-	क-	335	-	-	340	-	-	675	35	-	-	340	-	-	375
	ख-	331	-	-	421	52	-	804	522	-	-	421	34	-	977
	ग-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	(1)-	390	-	-	-	-	-	390	341	-	-	-	-	-	341
	(2)-	920	-	-	-	-	-	920	202	-	-	-	-	-	202
3-	3-	381	-	-	375	-	-	756	567	-	-	375	-	-	942
	4-	617	-	-	-	-	-	617	227	-	-	-	-	-	227
	5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
7-	(1)-	881	-	-	-	-	-	881	885	-	-	-	-	-	885
	(2)-	475	-	-	-	200	-	675	472	-	-	-	224	-	696
8-	क-	5	-	-	-	5	-	5	4	-	-	-	-	-	4
	ख-	9	-	-	-	9	-	9	10	-	-	-	-	-	10
	ग-	2	-	-	2	-	-	4	2	-	-	2	-	-	4
	घ-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग		4361	-	-	1138	852	-	5751	3267	-	-	1138	253	-	4663

1975-76 का परिचय							
क्र. सं.	राज्य अर्थविभाग	परिचय	राज्य निर्माण प्रणालि द्वारा प्रयुक्त	जबो-बिग	लेन्ड द्वारा प्रयुक्त	लेन्ड द्वारा प्रयुक्त	योग
1	24	25	26	27	28	29	30
1-							
क-	203	70	-	2 622	-	-	2975
ख-	3 75	-	-	535	50	-	1460
ग-	"	"	-	-	-	-	-
2-							
(1)-	209	-	-	-	-	-	209
(2)-	1140	"	-	-	-	-	1140
3-	242	-	-	375	-	-	617
4-	1747	-	-	-	-	-	1747
5-	-	-	-	-	-	-	-
6-	20	-	-	-	-	-	20
7-							
(1)-	545	-	-	-	-	-	545
(2)-	1000	"	-	-	200	-	1200
8 -							
क-	20	"	-	6	-	-	26
ख-	33	-	-	-	-	-	33
ग-	3	-	-	108	-	-	111
घ-	-	-	-	-	-	-	-
योग :-	6198	70	-	3646	250	-	10074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9-	गृहपरिष्कार	1170	3330	-	1440	206	-	6146
10-	विद्युत्	-	-	-	-	-	-	-
11-	वाह्य नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-
12-	(क) - विद्युत्	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) - ग्रामीण विद्युत् योजना	-	-	-	-	-	-	-
	योग जल एवं विद्युत् विकास	-	-	-	-	-	-	-
13-	बृहत् उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
14-	मिनरल एवं धातु उद्योग	500	-	-	-	-	-	500
15-	ग्रामीण एवं तमू उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
	(1) - लघु उद्योग	3915	740	300	400	-	-	4455
	(2) - छोटी एवं ग्रामीण उद्योग	-	-	-	-	-	-	-
	जोई	-	1107	-	-	-	-	1107
	(3) - हस्तकरणा	524	-	-	-	-	-	524
	योग उद्योग एवं धातु उद्योग	4039	1847	300	400	-	-	6586
16-	सड़क एवं जेतु	92587	-	-	-	-	-	92587
17-	सड़क एवं सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-
18-	पर्यटन	12794	-	-	-	-	-	12794
	योग यातायात संसार	105381	-	-	-	-	-	105381
19-	शिक्षा	2233	-	-	-	-	-	2233
20-	व्यावसायिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
21-	वैज्ञानिक विद्यार्थी एवं शोध	-	-	-	-	-	-	-
22-	बिजनेस	-	-	-	-	-	-	-
23-	जन स्वास्थ्य	2570	-	-	-	6957	-	9527
24-	(क) - जल आपूर्ति	47049	11125	-	-	-	-	58174
	(ख) - पेय जल (ग्रामीण विकास)	-	-	-	-	-	-	-
25-	आवास	-	-	-	-	-	-	-
	भवन निर्माण	-	518	-	-	-	-	518
	अन्य	-	-	-	-	-	-	-
26-	शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-
27-	सुवना एवं प्रसार	-	-	-	-	-	-	-

	24	25	26	27	28	29	30
9-	61	2930	-	485	-	-	3476
10-	-	-	-	-	-	-	-
11-	-	-	-	-	-	-	-
12-(अ)	500	-	-	-	-	-	500
(ब)	1911	-	-	-	-	-	1911
योग	2411	-	-	-	-	-	2411
13-	-	-	-	-	-	-	-
14-	10	-	-	-	-	-	10
15-							
(1)-	155	378	22	16	-	-	571
(2)-	-	175	-	-	-	-	175
(3)-	81	-	-	-	-	-	81
योग	246	553	22	16	-	-	837
16-	8890	-	-	-	-	-	8890
17-	-	-	-	-	-	-	-
18-	2287	-	-	-	-	-	2287
योग	11177	-	-	-	-	-	11177
19-	301	-	-	-	-	-	301
20-	-	-	-	-	-	-	-
21-	-	-	-	-	-	-	-
22-)	428	-	-	-	383	-	1311
23-)							
24-							
अ-	3750	3063	-	-	-	-	6813
ब-	30	-	-	-	-	-	30
25-							
अ-	-	-	-	-	-	-	-
ब-	-	-	-	-	-	-	-
26-	-	-	-	-	-	-	-
27-	-	-	-	-	-	-	-

179

(हजार रुपये)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28-	(क) प्रशासन एवं सेवा योजना	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) -श्रम कल्याण	20	-	-	-	-	-	20
29-	पिछड़े जातियों जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1128	-	-	-	1830	-	3008
30-	समाज कल्याण	189	-	-	-	-	-	189
31-	पौष्टिक आहार	766	42	-	-	238	-	1046
32-	अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-
	योग, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	53955	11685	-	-	9075	-	74715
33-	अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं (अन्य एवं सेवाएं प्रशासन)	134	9	-	-	-	-	134
34-	विकास अनुसंधान एवं उद्योग प्रशासन	87	-	-	-	-	-	87
	योग	221	-	-	-	-	-	221
महसूल		240433	17742	300	9675	10632	-	273782

===== 0 0 =====

(हजार रु० में)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28-(क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-	27	-	-	-	१७	-	37	421	-	-	-	-	-	421
30-	5	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	2
31-	-	13	-	-	60	0-4	73-4	-	13	-	-	60	१-4	73-4
32-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	4022	13	-	-	1121	0-4	5156-4	-	13	-	-	733	0-4	6639-4
							5893							
33-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
34-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
महायोग	20925	2787			1373		23381		278		991			
		278		1483	0-4	26846-4		5861		1627	0-4	32038-4		

====0 0 0====

1	24	25	26	27	28	29	30
28-(क)	257	-	-	-	-	-	250
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
29-	633	-	-	-	412	-	1045
30-	5	-	-	-	-	-	5
31-	-	6	-	-	60	-	66
32-	-	-	-	-	-	-	-
योग	5397	3069	-	-	1355	-	9821
33-	35	-	-	-	-	-	35
34-	17	-	-	-	-	-	17
योग	52	-	-	-	-	-	52
प्रहास्य	25452	6622	22	4147	1605	-	37848

===== 0 0 0 =====

जिला चणौली पंचायती योजना का कार्य क्रम - भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष	31-3-69 तक स्थिति	31-5-74 तक स्थिति	पंचायती कार्य-योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-							
(1)-	भौतिक केन्द्रमूल हजार है०	११	912-8	912-8	912-8	912-8	912-8
(2)-	सुदस बोया गया क्षेत्र	११	55-8	55-8	53-7	55-8	55-6
(3)-	सुदस क्षेत्र में सुधिया बोया गया क्षेत्र	११	27-7	35-3	44-1	37-1	39-3
(4)-	सुदस बोया गया क्षेत्र	११	83-5	91-1	97-8	92-9	84-9
(5)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	496-0	496-0	496-0	496-0	496-0
(6)-	क्षेत्र योग्य क्षेत्र	११	13-9	13-1	12-7	12-9	12-7
(7)-	उत्तर आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	309-0	309-0	309-0	309-0	309-0
(8)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत उपयोग्य क्षेत्र	११	8-5	8-5	8-5	8-5	8-5
(9)-	अन्य उपयोग्य क्षेत्रों का क्षेत्र	११	3-8	4-6	5-1	4-8	5-2
(10)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	25-8	25-8	25-8	25-8	25-8
(11)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	-	-	-	-	-
(12)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	-	-	-	-	-
(13)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	54-3	54-5	53-2	54-5	54-2
(14)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	29-2	36-6	44-6	38-4	40-7
(15)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	-	0-01	0-02	0-02	0-01
(16)-	क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्र	११	6-1	6-1	5-9	6-1	6-1

1	2	3	4	5	6	7	8
(17)	खरोक के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र	हजार है०	1-65	2-04	3-00	2-06	2-08
(18)	रबो के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र	,,	1-53	2-04	2-80	2-04	2-04
(19)	जायस के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र	,,	-	0-01	0-02	0-01	0-01
(20)	गकल विद्युत क्षेत्र	,,	3-28	4-09	5-82	4-11	4-13
(21)	शुद्ध विद्युत क्षेत्र	,,	1-65	2-04	3-00	2-06	2-08
(22)	बिचार्ई लो सघनता प्रतिशत						
	1- शुद्ध विद्युत क्षेत्र शुद्धी के क्षेत्र के %	%	2-9	3-6	5-6	3-7	3-7
	2- कुल विद्युत क्षेत्र कुल क्षेत्र के प्रतिशत में	%	3-8	4-5	6-7	4-4	4-4
(23)	वृद्धि योग्य क्षमता कुल औद्योगिक क्षेत्रफल प्रतिशत		7-5	7-4	7-2	7-4	7-4
(24)	शुद्ध क्षेत्र कुल क्षेत्र के प्रतिशत	प्रतिशत	6-1	6-1	5-9	6-1	6-1
(25)	विभिन्न श्रोतों के द्वारा शुद्ध विद्युत क्षेत्र हजार हैक्टर						
	1- नहरों	,, (राज)	0-30	0-34	1-00	0-36	0-38
	2- कृषि के आन्वेषण नलक्षों	,, ,,	-	-	-	-	-
	3- निजी नलक्षों	,,	-	-	-	-	-
	4- अन्य (बल, होज, व सह परियोजनाएँ)	,,	1-35	1-70	2-00	1-70	1-70
(26)	अधिक उन्नत शक्ति के बोरों का वितरण :-						
	1- सज्जित किलों कुल		100	218	700	316	202
	2- समानोत किलों	,,	65	459	25	37	75
(27)	अधिक उत्पादन वाली किलों के अन्तर्गत क्षेत्र हजार है०						
(28)	सज्जित किलों						

1	2	3	4	5	6	7	8
(1) खाद	हजार है०	0-46	1-67	2-10	1-56	1-95	
(2) मकड़ा	"	0-14	0-06	0-30	0-13	0-25	
(3) लजरा	"	-	"	"	-	-	
(4) मेहें	"	0-90	2-17	4-95	2-46	4-39	
(ग) - स्थानोपयोगी	हजार है०						
(1) खाद	"	2-15	2-64	5-00	2-62	2-78	
(2) मकड़ा	"	0-09	0-18	0-95	0-15	0-31	
(3) लजरा	"	-	-	-	-	-	
(4) मेहें	"	2-33	2-40	5-00	2-75	3-62	
(5) लजरा	"	-	-	-	-	-	
(28) - मकड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार है०						
(क) - खाद	हजार है०						
(1) खाद	हजार है०	18-0	21-1	25-0	24-0	24-7	
(2) मकड़ा	"	8-6	8-5	7-0	8-0	7-3	
(3) लजरा	"	19-7	17-1	11-7	14-0	13-5	
(4) मकड़ा	"	0-7	0-7	0-9	0-7	0-7	
(5) मेहें	"	19-0	25-6	31-3	26-6	27-7	
(6) लौ	"	7-3	7-3	7-0	7-3	7-3	
योग	"	73-3	80-3	82-9	80-6	81-2	
(ख) - खाद	हजार है०						
(1) उद	"	0-16	0-17	0-18	0-17	0-17	
(2) लौ	"	-	-	-	-	-	
(3) लजरा	"	-	-	0-05	0-04	0-04	
(4) मकड़ा	"	-	-	0-16	0-11	0-13	
(5) लजरा	"	-	-	-	-	-	
(6) अन्य (मकड़ा, मकड़ा)	"	2-14	2-14	2-61	2-18	2-31	
योग	हजार है०	2-30	2-51	3-00	2-50	2-65	

1	2	3	4	5	6	7	8
(म)- वाणिज्यिक बससे							
(1)-	हजार में		-	-	-	-	-
(2)-	गाड़ी/सड़कों	११	-	0-23	0-80	0-3 4	0-67
(3)-	सुरक्षा	११	-	0-02	0-60	0-04	0-60
(4)-	मोबाइल	११	-	0-19	1-50	0-52	1-00
(5)-	इतर वि. लक्ष्य	११	1-86	1-61	0-90	1-57	0-77
(6)-	समाप्त	११	-	-	-	-	-
(7)-	समाप्त	११	2-42	2-81	3-38	2-37	2-93
(8)-	समाप्त	44	0-26	0-26	0-26	0-26	0-26
(9)-	समाप्त (समाप्त समाप्त)	११	2-57	2-37	2-35	2-37	2-36
	योग	११	7-11	7-49	9-49 9-49	7-75	8-59

(29)- मुख्य बससे का उत्पादन

(क)- वाहन

(1)-	वाहन	हजार में	19-0	21-1	29-5	25-0	26-6
(2)-	इतर	११	5-2	5-2	4-9	4-9	4-7
(3)-	मजदूर	११	15-8	10-2	8-2	8-7	8-7
(4)-	समाप्त	47	0-4	0-4	0-7	0-5	0-5
(5)-	वेह	११	13-0	30-7	39-1	32-5	34-2
(6)-	जो	११	4-0	4-4	4-9	4-7	4-7
	योग	११	59-4	72-0	87-3	76-3	79-4

(ख)- वाहन

(1)-	उत्प	११	0-08	0-08	0-09	0-08	0-08
(2)-	समाप्त	११	-	-	-	-	-
(3)-	समाप्त	११	-	-	0-03	0-02	0-02

1	2	3	4	5	6	7	8
(4)- गहर	हजार में 0 टन	-	-	0-08	0-05	0-06	
(5)- अरहर	"	-	-	-	-	-	
(6)- अन्य	"	1-06	1-07	1-45	1-12	1-22	
योग	"	1-14	1-15	1-65	1-27	1-58	
(ग)- कृषि पशु ज्योत फसलें							
(1)- गेहूँ/जलो	"	-	-	-	-	-	
(2)- लहसुन/सरसों	"	-	0-06	0-29	0-08	0-17	
(3)- सुरजमुषी	"	-	0-006	0-180	0-012	0-180	
(4)- सोया बीज	"	-	0-09	0-75	0-15	0-50	
(5)- अन्य किल्लान	"	0-26	0-20	0-15	0-19	0-11	
(6)- बन्ना	"	-	-	-	-	-	
(7)- डालू	"	19-38	22-50	29-93	24-40	25-70	
(8)- तील फलू	"	0-08	0-08	0-08	0-08	0-08	
(9)- अन्य	"	1-00	0-95	1-01	0-97	0-99	
(30)- कुल कृषि पशु ज्योत उत्पादन		61-54	74-19	90-71	78-69	82-27	82-27
(30)- पशु सुरक्षा के उत्पन्न क्षेत्र	हजार में 0	15-00	30-10	40-00	18-30	40-00	
(31)- शूरीय संरक्षण							
(1)- शूरीय शूरीय के (राज्य)	"	-	1-040	1-500	0-304	0-300	
(2)- रेवाडन्स के	"	-	-	-	-	-	
(32)- जलकन्दो	"	-	-	-	-	-	
(33)- रासायनिक उत्पादन के किल्लान	में 0 टन (राज्य)						
(1)- नम्रजन (N)							
क कृषि विभाग	"	45	86	294	87	286	

1	2	3	4	5	6	7	8
ख- सहकारिता विभाग	टो टन	-	-	-	-	-	-
ग- रेलो	(राज्य)	-	-	-	-	-	-
घ- अन्ना सहकारी	११	-	-	-	-	-	-
ङ- प्राइवेट एजेन्सोज	११	-	-	-	-	-	-
(2)- फास्फेट (P_2O_5)	११	-	-	-	-	-	-
क- कृषि विभाग	११	27	78	220	47	220	
ख- सहकारिता विभाग	११	-	-	-	-	-	-
ग- रेलो	११	-	-	-	-	-	-
घ- अन्ना सहकारी	११	-	-	-	-	-	-
ङ- प्राइवेट एजेन्सोज	११	-	-	-	-	-	-
(3)- पोटास (K_2O ग्रॅ)	११	-	-	-	-	-	-
क- कृषि विभाग	११	18	15	147	13	140	134
ख- सहकारिता विभाग	११	-	-	-	-	-	-
ग- रेलो	११	-	-	-	-	-	-
घ- अन्ना सहकारी	११	-	-	-	-	-	-
ङ- प्राइवेट एजेन्सोज	११	-	-	-	-	-	-
(4)- फास्फेट खाद का	हजार टो	600	625	621	302	587	
उत्पादन	टन						
(5)- इरो खाद के अन्त	हेक्टर	-	-	300	66	250	
34)- निर्यात बंधन	प्रॉजेंट (राज्य)	-	-	-	-	-	-
35)- उर्वरक का संयोजन	हजार टो टन (राज्य)						
क- उर्वरक							
(1)- कृषि विभाग	११	0-26	0-26	0-40	0-26	0-26	
(2)- सहकारिता विभाग	११	-	-	-	-	-	-
(3)- अन्ना (वेयर हाउसिंग)	११	-	-	-	-	-	-
योग :-	११	0-26	0-26	0-40	0-26	0-26	

1	2	3	4	5	6	7	8
(ब) - भाषादान							
(1)	सहकारिता विभाग हजार मैटन (राज्य)	हजार	0-5	1-14	1-04	1-04	1-04
(2)	खाद्य निगम	,,	-	-	-	-	-
(3)	अन्य (पूर्व विभाग)	,,	2-6	4-6 2	4-6 2	4-6 2	4-6 2
	योग :-	,,	3-1	5-6 6	5-6 6	5-6 6	5-6 6
(36) - कृषि औद्योगिक निगम के विभाग से उद्धार की का विवरण - योजना (रक)							
(1)	पथ पैद	,,	-	-	-	-	-
(2)	शक्ति यन्त्रित टिलर्स	,,	-	-	-	-	-
(3)	रेक्टर	,,	-	-	-	-	-
(4)	अन्य (विवरण दिए गये)	,,	-	-	-	-	-
(37) - कृषि सेवा केंद्रों को संख्या							
(1)	कृषि उद्धार निगम	,,	-	-	-	-	-
(2)	सहकारिता	,,	-	-	-	-	-
(3)	कृषि विभाग आदि	,,	-	-	1	-	-
(4)	अन्य	,,	-	-	-	-	-

2- वस्त्राद्य क्षेत्र, पौध पुराना के अन्तर्गत क्षेत्र

(1)	फल	हजार है।	3-107	4-6 00	2-5 00	0-2 04	0-4 50
(2)	साम धातु	,,	1-2 13	1-2 40	0-2 10	0-0 90	0-0 35
(3)	लोहापु रोगरोग	,,	0-4 55	10-3 28	5-5 50	0-4 74	1-0 00
(4)	फल उत्पादन	हजार मी० टन					
	क- सेब, नाशपाती, आदि, अमरौट आदि	,,	1-8 75	2-8 00	13-3 00	4-5 00	9-3 00
	ख- जामु, गारुड, नारंगी आदि	,,	1-6 25	2-2 00			

ग- अन्य

(फलों के नाम दोजिए)

1	2	3	4	5	6	7	8
3- पशुपालन							
(1)- वृत्रिम गर्भाधान सेन्ट्र (राज्य)							
(2)- वृत्रिम गर्भाधानो को (राज्य)						1	
(3)- वृत्रिम गर्भाधान उप-सेन्ट्र							
(4)- स्टाफ मीन सेन्टर (पशु सेवा सेन्टर)					6	4	
(5)- राजकीय दुग्ध पार्क		47	47				
(6)- सहकारी दुग्ध पार्क					1		
(7)- पशु विज्ञानशाला / कोषधालय							
(8)- डोह एवं जन क्लिनिक सेन्टर		10	10				
(9)- सामन पशु क्लिनिक					9		
(10)- नारे को फालो से अन्तर्गत सेन							
(11)- पशुओं को सेवा सेन को सेवा सेन							
	हजार है 0	0-330	0-050	0-232	0-050	0-058	
	कंका						
1-सबसेसब							
2- डोक्यू		4, 434	24339			31106	
3- रिपडर पीट		2, 582	32499			10800	
		2, 997	51367			36553	
4- मत्स्य							
(1)- नारों का प्रयोगोकरण							
(2)- प्रयोग यंत्रों का कारो विज्ञान							
(3)- अंगुलिओं का विज्ञान							
(4)- मत्स्य बोध फार्म							
(5)- मत्स्य उत्पादन							

1	2	3	4	5	6	7	8
5- वन							
(1)- वन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष अन्तर्गत कुल क्षेत्र - हजार है।			327	327	327	327	327
(2)- वर्क प्लान क्षेत्र (राज्य)			327	327	327	327	327
(3)- अधिभूत गहते के वृक्षों का क्षेत्र		११	20	65	1-0	0-11	0-15
(4)- जलोपार्जित वृक्षों का क्षेत्र		११	-	-	-	-	-
(5)- ईंधन वृक्षों का क्षेत्र		११	4-7	71-9	-	-	-
(6)- शहरी परिसरों के अन्त- र्गत क्षेत्र		११	0-97	1-39	7-4	0-23	0-56
(7)- जलोपार्जित वृक्षों की लम्बाई कि.मी०							
1- सरपेड		११	-	-	-	-	-
2- अनसरपेड		११	35	95	45	3	-
(8)- रेवाइन रिक्लेमेशन हजार है। (राज्य)			-	-	-	-	-
(9)- वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र		११	-	-	-	-	-
6- सिंचाई							
(1)- लघु सिंचाई							
क- निजी लघु सिंचाई							(11)
1- प्रकृत कुएँ	संख्या		-	-	-	-	-
2- कुएँ	११		-	-	-	-	-
3- रकट	११		-	-	-	-	-
4- नलकूप	११		-	-	-	-	-
5- पम्प सेट	११		-	7	30	1	8
6- बाँधी	हेक्टेयर		-	-	-	-	-
7- पहाड़ी क्षेत्रों में नलियाँ कि.मी० (राज्य)		220		304	165	6	25
8- पहाड़ी क्षेत्रों में हीज नलियाँ	संख्या (राज्य)	534		745	690	43	160
9- सिंचन क्षमता का पूजन हजार है।			1-5	1-58	0-847	0-138	0-195

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ख- राजकीय लघु सिंचाई

(1)- नलकूप	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-	-
(2)- कुल निर्माण (पर्यटन नहरें)	कि.मी. (राज्य)	92	98	35-50	1-25	11-75	
(3)- अन्न (डाल सिंचाई योजना)	संख्या (राज्य)	-	-	2	-	-	
(4)- पर्यटन नहरों का आधुनिकीकरण	कि.मी. (राज्य)	5	-	29-6	-	-	
(5)- सिंचन क्षमता का वृद्धि	हजार है. (राज्य)	1-49	1-58	0-62	0-28	0-06	

ग- मौजूदा सिंचन क्षमता में ह्रास

(1)- निजी लघु सिंचाई	हजार है. (राज्य)	-	-	0-12	0-10	0-10	
(2)- राजकीय लघु सिंचाई	''	-	-	0-10	0-08	0-08	
योग :-	''	-	-	0-22	0-18	0-18	

घ- कुल उपलब्ध शुद्ध क्षमता

(1)- निजी लघु सिंचाई	''	1-50	1-98	2-50	1-92	2-01	
(2)- राजकीय लघु सिंचाई	''	1-49	1-58	1-94	1-58	1-56	
योग :-	''	2-99	3-56	4-44	3-50	3-57	

2 - बृहत एवं मध्यम सिंचाई

(1)- सिंचन क्षमता का वृद्धि	हजार है. (राज्य)	-	-	-	-	-	
(2)- नहर निर्माण	कि.मी. (राज्य)	-	-	-	-	-	

(3)-

3 - सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग

(1)- निजी लघु सिंचाई	हजार है. (राज्य)	1-35	1-70	2-00	1-70	1-70	
(2)- राजकीय लघु सिंचाई	''	0-30	0-34	1-00	0-36	0-38	
(3)- बृहत एवं मध्यम सिंचाई	''	-	-	-	-	-	
योग :-	''	1-65	2-04	3-00	2-06	2-08	

1	2	3	4	5	6	7	8
7- उद्योग							
(1)- औद्योगिक इकाइयों की संख्या							
क-	संगठित						
	(1) - पैदाईश के अन्तर्गत	11	-	-	-	-	-
	(2) - अन्य	11	16	85	75	15	15
ख-	असंगठित	11	300	350	150	15	15
(2)- रोजगार में लगे व्यक्ति की संख्या							
क-	संगठित क्षेत्रों में -						
	(1) - पैदाईश के अन्तर्गत	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) - अन्य	संख्या	50	275	300	60	60
ख-	असंगठित क्षेत्रों	11	750	875	375	35	40
(3)- उत्पादित वस्तुओं का मूल्य							
क-	संगठित क्षेत्र	हजार रुपये	150	550	750	225	230
ख-	असंगठित क्षेत्र	11	150	200	375	75	75
4- औद्योगिक अर्थात् -							
(1)-	संख्या	राज्य	-	-	-	-	-
(2)-	वैद्युत की संख्या	11	-	-	-	-	-
(3)-	कारखानों की संख्या	11	-	-	-	-	-
5- हस्तशिल्प उद्योग							
क-	हस्तशिल्पियों की संख्या	राज्य	-	-	-	-	-
ख-	हस्तशिल्प क्षेत्रों में हस्तशिल्पियों की संख्या	11	-	-	-	-	-
ग-	संख्या की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
घ-	हस्तशिल्प क्षेत्रों का उत्पादन लाखों में	-	-	-	-	10	-
6- शिल्प उद्योग							
क-	वस्तु का उत्पादन	क	3-2	2-8	6-0	1-27	1-0

1	2	3	4	5	6	7	8
7 - ऊन उद्योग							
क-	इस्पातरवीं को संख्या	संख्या	1000	1250	50	5	5
ख-	पहकारों क्षेत्र में इस्पातरवीं को संख्या	,,	-	-	5	5	5
ग-	तुम्कारों को पहकारों में तैयारियों का मठन	,,	-	-	5	1	1
घ-	ऊनी मस्तर का उत्पादन	मॉन्टन	6-0	7-5	1-5	0-3	0-3
8 - बृहत शक्ति में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ							
क- चीनी मिल							
(1)-	संख्या	संख्या (राज्य)	5	-	-	-	-
(2)-	उत्पादन	टन हजार में (राज्य)	-	-	-	-	-
(3)-	रेजिस्टर में लगे व्यक्ति	संख्या हजार (राज्य)	-	-	-	-	-
ख- बल मिल							
(1)-	संख्या	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
(2)-	उत्पादन	लाख मॉन्टर (राज्य)	-	-	-	-	-
(3)-	कार्यरत व सक्रिय	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
8 - पहकारिता :-							
(1) - बैंक							
क- जिला सहकारी बैंक :-							
(1)-	बैंकों को संख्या	संख्या (राज्य)	1	1	-	-	-
(2)-	शाखाओं को संख्या	,, (राज्य)	1	3	1	-	1
(3)-	अंशधरों	हजार हजार (राज्य)	325	557	40	50	10
(4)-	बाजु धूजी	,,	14, 44	41, 92	-	576	-
(5)-	जमा धनराशि	,,	251	342	600	57	300
(6)-	जमा वितरण	,,	-	-	-	-	-
क-	अस्पिताली न	,,	435	2160	2200	2 6 1 4	2000
ख-	पहकाराली न	,,	207	319	1130	346	930
ग-	नृति विभाग बैंक	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	शाखा की संख्या	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
(2)	दीर्घकालीन ऋण वितरण	हजार रु (राज्य)	-	-	-	-	-
2-	प्रारंभिक ऋण समितियाँ						
(1)	समितियों की संख्या	संख्या (राज्य)	140	135	-	-	-
(2)	सदस्यता	हजार रु	34	40	6	2	2-5
(3)	निजी पूँजी	हजार रु (राज्य)	711	1240	120	162	50
(4)	घातु पूँजी	,,	1321	4811	-	795	-
(5)	जमा धनराशि	,,	140	212	600	102	300
(6)	अल्पकालीन ऋण वितरण	,,					
क-	नकद	,,	498	1301	2200	2497	2000
ख-	वस्तु ले रख ले	,,	5	105	-	115	-
(7)	दीर्घकालीन ऋण वितरण	,,	244	450	1130	1214	930
3-	ग्रह विक्रय समितियाँ						
(1)	समितियों की संख्या	संख्या	1	1	1	-	-
(2)	सदस्यता	संख्या हजार	0-1	0-1	0-10	-	-
(3)	निजी पूँजी	हजार रु	74	134	-	3	-
(4)	वैपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	-	-	-	-	-
क-	उत्तरक	,,	-	-	-	-	-
ख-	बोज	,,	-	-	-	-	-
ग-	आयुक्त	,,	295	556	-	388	5
घ-	अन्य	,,	-	-	-	-	-
4-	सहकारी विकास समितियाँ						
(1)	समितियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
(2)	सदस्यता	,, हजारों	-	-	-	-	-
(3)	निजी पूँजी	हजार रु	-	-	-	-	-
(4)	वैपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	-	-	-	-	-

(5)-

1	2	3	4	5	6	7	8
5- उद्योगिकीय सहकारो समितियाँ							
(1)- समितियों की संख्या	संख्या		8	12	-	-	-
(2)- सदस्यता	हजार में		2	2	-	-	-
(3)- निजी पूँजी	हजार रुपये		22	61	-	-	-
(4)- विकास को सही वस्तुओं का मूल्य	,"		170	1373	-	1134	-
6- सहकारो युग्म समितियाँ							
(1)- समितियों की संख्या	संख्या		-	-	-	-	-
(2)- सदस्यता	,"		-	-	-	-	-
(3)- निजी पूँजी	हजार रुपये		-	-	-	-	-
(4)- विकास को सही दृष्ट को मात्रा	," लीटर में		-	-	-	-	-
7- अन्य समितियाँ :-							
(1)- समितियों की संख्या	संख्या		3	5	2	1	-
(2)- सदस्यता	हजार में		0-3	0-4	0-04	0-02	-
8- ग्रामा समितियाँ :-							
(1)- समितियों की संख्या	संख्या		-	-	-	-	-
(2)- सदस्यता	हजार में		-	-	-	-	-
(3)- निजी पूँजी	हजार रुपये		-	-	-	-	-
(4)- वस्तु मूल्य	,"		-	-	-	-	-
(5)- जमा धनराशि			-	-	-	-	-
9- व्यावहारिक बैंक :-							
(1)- अनुसूचित व्यावहारिक बैंकों की संख्या	संख्या		1	4	अप्राप्त	2	अप्राप्त
(2)- प्रति बैंक का निवेश समस्या	हजार में		284	75	,"	52	,"
(3)- अनुसूचित व्यावहारिक बैंक में जमा धनराशि	लाख रुप		7	35	,"	अप्राप्त	अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
(4)- अनुसूचित जाति शिक्षण केन्द्रों द्वारा वितरित ग्रन्थ	लाभ रुपये	5	2	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
(5)- प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	रुपये	2-50	11-60	११	११	११	
(6)- प्रति व्यक्ति तदिया गया रकम	११	-	0-67	११	११	११	
9- विद्युत्							
=====							
1- विद्युत् का उपयोग							
	कि०वाट घण्टे (राज्य)	अप्राप्त	7, 62, 487	-	7, 33, 363	-	
2- शिक्षण केन्द्रों में विद्युत् का उपयोग							
(1)- धरेलु एवं वा. विजल	११	११	6, 61, 532	-	6, 22, 583	-	
(2)- औद्योगिक	११	११	1, 00, 955	-	1, 60, 775	-	
(3)- अन्य विद्युत् द्वारा की संशोधित करते हुये	११	११	-	-	-	-	
(4)- अन्य	११	११	-	-	-	-	
3- उपरोक्त मदों (1-4) में प्रति व्यक्ति उपभोग							
	११	११	2-5	-	2-5	-	
4- वितरण लाइनों की लम्बाई:-							
(1)- हाइ टैन्शन लाइन्स:-							
11 कैबलों	कि०मी० (राज्य)	११	262	-	28	40	
33 कैबलों	११	११	-	-	-	-	
अन्य	११	११	-	-	-	-	
(2)- लो टैन्शन लाइन्स	११	११	153	-	51	-	
5- विद्युत् तन्त्र ग्रन्थ :-							
(1)- संख्या							
	संख्या	११	22	११९	-	43	23
(2)- प्रतिशत							
	प्रतिशत	११	1-4	7-6	-	10-8	12-3
6- हरिजन बस्तियों का विद्युत् वितरण							
	संख्या	११	अप्राप्त	39	-	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8
7- औद्योगिक कर्मचारी							
(1)- प्राचीन	संख्या (राज्य)	अप्राप्त	30	-	5	-	-
(2)- नए शहरी	,, ,,	,, ,,	8	-	1	-	-
8- विद्युत्-निर्गत ट्यूबवेल/ पम्प सेटों की संख्या							
(1)- राजकीय	,, ,,	,, ,,	-	-	-	-	-
(2)- निजी	,, ,,	,, ,,	-	-	-	-	-
(3)- अन्य	,, ,,	,, ,,	-	-	-	-	-
9- सड़कें							
(1)- रेलवे लाइनों की लम्बाई	कि० मी० (राज्य)	-	-	-	-	-	-
(2)- सड़कों की लम्बाई:-							
1- राष्ट्रीय राज मार्ग	कि० मी० (राज्य)-	-	-	-	-	-	-
2- प्रदेशीय राज मार्ग	,, ,,	299	209	-	-	-	-
3- मुख्य जिला सड़कें							
4- अन्य जिला सड़कें	,, ,,	432	432	132	-	22	
5- प्राचीन सड़कें							
(3)- सड़कें समुदायों की संख्या	,, ,,	214	214	-	214	-	-
(4)- सड़कों की संख्या							
जो सड़कें समुदायों की सड़कों की संख्या में शामिल हैं							
संख्या	459	459	-	459	-	-	-
(5)- सड़कों की लम्बाई							
जिस पर बस चलती है							
1- निजी	कि० मी० (राज्य)	531	530	-	530	-	-
2- राज्य की सड़कें	,, ,,	-	131	-	131	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

(6)- प्रकीर्णत वर्षों :-

(1)- निजी वर्षों	क्रिया(राज्य)	343	381	100	452	-
(2)-राज्य की रोड वज. वर्षों	,, ,,	-	4	-	4	-

11- विद्या :-

1- विद्यालयों की संख्या

क- नगरीय

(1)-बैथिक स्कूल	संख्या(राज्य)	11	12	-	3	-
(2)-सो निगर बैथिक स्कूल	,,	3	3	-	-	-
(3)-हायर सेन्ट्रल स्कूल	,,	2	3	5	-	9
(4)-डिग्री कॉलेज	,,	1	1	1	-	-
(5)-विश्व विद्यालय	,,	-	-	-	-	-

ख- ग्रामीण :-

(1)- बैथिक स्कूल	संख्या(राज्य)	507	530	13	22	10
(2)-सो निगर बैथिक स्कूल	,,	49	64	14	5	6
(3)-हायर सेन्ट्रल स्कूल	,,	19	32	5	3	-
(4)-डिग्री कॉलेज	,,	-	-	-	1	-
(5)-विश्व विद्यालय	,,	-	-	-	-	-

2- छात्रों

क- नगरीय

(1)-बैथिक स्कूल	हजार में (राज्य)	2-1	36-1	43-5	39-7	40-0
आयु वर्ग का प्रतिशत %		63	68	85	72	73
(2)-सो निगर बैथिक स्कूल	हजारों (राज्य)	5-7	7-5	14-0	8-4	9-4
आयु वर्ग का प्रतिशत %		2-8	3-1	4-9	3-2	3-4
(3)-हायर सेन्ट्रल स्कूल	हजारों (राज्य)	2-7	4-1	14-0	4-2	4-3
आयु वर्ग का प्रतिशत %		11	15	33	15-2	15-6
(4)-डिग्री कॉलेज	हजारों	0-1	0-2	0-5	0-3	0-4

1	2	3	4	5	6	7	8
2-(ख)- बालिकाएँ							
(1)	बैंचक स्कूल हजार में (राज्य)	5-5	12-9	24-2	14-1	14-9	
(2)	गोविन्द बैंचक स्कूल ,,	0-5	1-5	6-0	1-1	1-2	
(3)	हायर सैलेण्डरो स्कूल ,,	0-2	0-4	4-0	0-3	0-4	
(4)	डिग्री कालेज ,,	-	0-05	0-1	0-1	0-04	
(5)	बैंक विद्यालय ,,	-	-	-	-	-	
(ग)-अनुसूचित जाति/जनजाति							
(1)	बैंचक स्कूल हजार में (राज्य)	4-2	5-9	8-0	6-2	6-3	
(2)	गोविन्द बैंचक स्कूल हजार में (राज्य)	0-6	1-0	1-5	1-1	1-2	
(3)	हायर सैलेण्डरो स्कूल ,,	0-2	0-4	0-3	0-5	0-5	
(4)	डिग्री कालेज ,,	0-01	0-02	0-2	0-03	0-05	
(5)	बैंक विद्यालय ,,	-	-	-	-	-	
3-बैंचक क्षेत्र अनुपात							
(1)	बैंचक स्कूल अनुपात (राज्य)	1: 25	1: 30	1: 40	1: 31	1: 32	
(2)	गोविन्द बैंचक स्कूल ,,	1: 15	1: 15	1: 30	1: 15	1: 15	
(3)	हायर सैलेण्डरो स्कूल ,,	1: 10	1: 12	1: 25	1: 12	1: 12	
12- प्रादेशिक शिक्षा							
1-							
(1)	इन्-जोनियरिंग/प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
(2)	डिप्लोमा स्तर की संख्या	संख्या ,,	-	-	-	-	-
(3)	मास्ट्रीफिट स्तर की संख्या	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
2- शर्ती							
(1)	डिग्री	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
(2)	डिप्लोमा	,,	-	-	-	-	-
(3)	मास्ट्रीफिट	,,	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1-जनस्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन							
1- शैक्षिक अस्पताल/ओम्हालस की संख्या							
क- राजकीय							
(*) (1)-नगरीय	संख्या (राज्य)	2	7	-	-	-	-
(2)-ग्रामीण	,, ,,	12	16	1	1	-	-
ख-अन्य							
(1)-नगरीय (नेत्र)	,, ,,	1	1	-	-	-	-
(2)-ग्रामीण	,, ,,	-	-	-	-	-	-
2- आधुनिक एवं मूलानु अस्पताल/ओम्हालस की संख्या							
क- राजकीय							
(1)-नगरीय	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-	-
(2)-ग्रामीण	,, ,,	24	39	2	1	-	-
ख- अन्य							
(1)-नगरीय	,, ,,	-	-	-	-	-	-
(2)-ग्रामीण	,, ,,	-	-	-	-	-	-
3-शैक्षिक अस्पताल एवं ओम्हालस की संख्या							
क- राजकीय							
(1)-नगरीय	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-	-
(2)-ग्रामीण	,, ,,	-	1	1	-	-	-
4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या							
	,,	9	9	-	-	-	-

(*) इस मद की सूचना में मद 6(1) '6(3) पर अंकित विवेकसमय तथा एक जोड़ो कमीनीय इस सभ्य 5 की सूचना में प्रकृत है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
5- शैयाओं की संख्या							
क- नगरीय							

(*) (1)- रेलोपेथिक	संख्या (राज्य)	96	156	10	-	10	
(2)-आयुर्वेदिक/युनानो	,,	-	-	-	-	-	
(3)-होमोपेथिक	,,	-	-	-	-	-	
ख- ग्रामीण							

(x) (1)-रेलोपेथिक	,,	112	155	-	4	-	
(2)- आयुर्वेदिक/युनानो	,,	96	156	8	4	-	
(3)-होमोपेथिक	,,	-	4	-	-	-	
6-विभिन्न बिमारियों के							
अस्पतालों में अस्पतालों की संख्या							
(1)- टोन्बो (क्लोनीक)	संख्या	-	-	-	-	-	
समा अस्पताल	,,	1	2	-	-	-	
(2)- पाइलेरिया	,,	-	-	-	-	-	
(3)- छूत की बिमारो	संख्या	-	1	-	-	-	
(आईडोस लोफ)	,,	-	-	-	-	-	
(4)- दुग्ध रोग (समाईन)	संख्या	-	-	-	-	-	
टोन्बो ड्र)	,,	-	5	-	-	-	
7- परिवार नियोजन केन्द्रों	संख्या	10	10	-	-	-	
की संख्या	,,	-	-	-	-	-	
8- मात्र एवं शिशुलक्षण	संख्या	51	36	-	-	-	
केन्द्रों की संख्या	,,	-	-	-	-	-	
9- एन एनएनएन उप केन्द्रों	संख्या	45	45	-	-	-	
की संख्या	,,	-	-	-	-	-	
10- रेडिअल कालेजों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-	
11- प्रवेश क्षमता	संख्या	-	-	-	-	-	
12- सरकारी अस्पताल/ औपचारिकों के डाक्टरों	संख्या	38	63	-	1	-	
की संख्या	,,	-	-	-	-	-	

(*) स्तम्भ 4 व 5 में नेत्र चिकित्सालय की 40 शैयाओं परिगणित हैं ।

(x) स्तम्भ 4 व 5 में 30 शैयाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की परिगणित हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8
परिवार नियोजन							
1- वन्द्याकरण							
(1)- पुरुष		संख्या (राज्य)	4,932	7416		307	
(2)- न स्त्री		"	-	15	6066	16	985
2- आईएमओ प्रोजेक्ट		"	132	935	5197	387	1641
14- आवास							
(1)- मध्यम आस वर्ग आवासें हो		संख्या (राज्य)	-	-	2	-	-
(2)- अल्पआयु वर्ग		"	-	-	3	-	-
(3)- दुर्गम आस वर्ग		"	-	-	16	-	-
15- पिछड़ी जातियों का कल्याण							
(1)- पीछे रह चुके उच्च-वृत्तियां							
क- सामान्य वर्ग							
(1)- अनुसूचित जातियां		संख्या (राज्य)	19	222	322	52	60
(2)- अनुसूचित जनजातियां		"	18	5930	590	95	100
ख- प्राथमिक एवं द्वितीयक वर्ग							
(1)- अनुसूचित जातियां		"	-	-	-	-	-
(2)- अनुसूचित जनजातियां		"	-	-	-	-	-
16- संरक्षणित क्षेत्र							
1- स्वोद्योग वर्ग		रजार रु० में	-	-	अप्राप्त	-	अप्राप्त
2- वितरित वर्ग							
(1)- स्त्री		"	-	-	"	-	"
(2)- उच्च वर्ग		"	-	-	"	-	"
क- प्रकृत		"	-	-	"	-	"
ख- प्रकृत		"	-	-	"	-	"
ग- लघु		"	-	-	"	-	"
(3)- अन्य		"	-	-	"	-	"

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

17- जल आपूर्ति

क- नगरीय जल आपूर्ति

(1)- नगरीय जल आपूर्ति संख्या(राज्य)	3	-	-	-	-	-	-
(2)- जनसंख्या लाभान्वित हजार, , 12206							

ख- ग्रामीण जल आपूर्ति

घाटव्य द्वारा

(1)- घाट संख्या(राज्य)	71	191	125	64	35
(2)- जनसंख्या लाभान्वित हजार (राज्य)	13-3	43-7	31	18	21

ग- शैल्युत्पत्त जल संचयन

(सामुदायिक विद्यालय विद्यालय)

(1)- घाट संख्या(राज्य)	-	-	-	-	-
(2)-जनसंख्या लाभान्वित हजार (राज्य)	-	-	-	-	-

घ- नगरीय जल निस्तारण

(1)-जल निस्तारण संख्या(राज्य)	-	1	-	-	-
(2)-जन संख्या लाभान्वित हजार (राज्य)	-	5-0	-	-	-

विवरण-१

जि. १००० का आंकड़ा

जिल्हा - चवली

कुल क्षेत्र :-	इकाई	वर्ष	१९७३-७४	श्रोत
	(१००० हे०)	१९७२-७३	१९७२-७३	
भौगोलिक क्षेत्र		६१२-८	६१२-८	सांख्यिकीय तालिका
वन क्षेत्र अन्तर्गत क्षेत्र	,,	४९६-०	४९६-०	उपजर्ण्यपाल
फलोपार्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	३-८	४-६	जिला उद्यान नियंत्रण
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	,,	५५-८	५५-८	जिला कृषि अधिकारी
परती भूमि (कुल)	,,	-	-	
(१) वर्तमान परती	,,	-	-	
(२) अन्य परती	,,	-	-	
कृषि योग्य बैज भूमि	,,	१३-९	१३-९	जिला कृषि अधिकारी
भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है (कुल)	,,	३९७-५	३९७-५	,,
(१) बैज भूमि जो कृषि योग्य नहीं है	,,	३०६-०	३०६-०	,,
(२) भूमि जो कृषि से भिन्न उद्योगों के लिये काम में लाई जा रही है	,,	९-५	९-५	,,
स्थायी चरगाहें तथा अन्य चरगाहें	,,	२५-८	२५-८	उपजर्ण्यपाल
जमीनों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र :-	संख्या क्षेत्रफल	संख्या क्षेत्रफल		
१ हेक्टर तक	६०४९ ३६७४०	६०४९ ३६७४०		जिला कृषि अधिकारी
१ हे० से ३ हे० के बीच	१०८०३ १६५०१	१०८०३ १६५०१		,,
३ हे० से ५ हे० के बीच	५०६ ६६२	५०६ ६६२		,,
५ हे० से अधिक	२८ ६६७	२८ ६६७		,,
कुल जमीनें-	७ ६८६ ५५००	७ ६८६ ५५००		,,

जसख्या वषी (००० म)	१९७३		१९७४		१९७५	
	नगर	ग्रामिण	नगर	ग्रामिण	नगर	ग्रामिण
पुराणा	७-६२४	१३४-३३८	१४१-६६२	६-५	१३७-७००	१४६-५००
स्त्री -	४-५८२	१४६-७२७	१५०-६०६	५-७	१४६-७०	१५४-७
योग -	१२-२०६	२८०-३६५	२९२-७५१	११-२	२८३-७७०	३०१-२

ग्रामिणी सख्या	(वषी १९६९)	(वषी १९७९)
पुराणा	७३-२०४	७८-४३
स्त्री	६२-३४	६१-२५४
योग	१३५-२३८	१३९-७४७

पिढे समुदाया की जसख्या (०००)	अनुसचित जाति		अनुसचित जाति	
	१९७१	१९७३	१९७१	१९७३
पुराणा	२४-३४	२४-५	४-५३	४-२
स्त्री	२४-६८४	२६-५	४-१०२	४-३
योग -	४८-७८	५१-७	८-१५५	८-५
	१९७१		१९७३	
घात्व प्रविगा क्रोमीय	३२		३३	

सत्त प्रवाशील नदियां :-	नाम	लम्बाई
	१- अल नन्दा	अप्राप्य
	२- घाली	११
	३- बिही	११
	४- नन्दाकिनि	११
	५- पिण्डा	११
	६- मन्दाकिनि	११
	७- रमिंगा	११
	८- केल	११
मोसमी नदियां :-	१- सरस्वती	११
	२- काकडा गाड	११
	३- कृजाड	११
	४- सारंगाड	११
	५- सारग गंधा	११

६- आटा गाड़	अप्राप्त
७- झीलतीर गाड़	”
८- निर्गले गाड़	”
९- प्राणामती	”
१०- नींग गयेरा	”
११- गरगाड़ गंगा	”
१२- बाल खिला	”
१३- माखल गंगा	”

मिट्टी के मुख्य किस्में:- (अन्तर्गत क्षेत्र) (हेक्टेयर) -

(क) दोमत	क्षेत्र अप्राप्त
(ख) मख्यार दोमत	”
(ग) ब्रवी दोमत	”

मासिक औसत वर्षा (किली मी) १५५ मि०मी०
 चक्रवर्द्धी क्षेत्र - (००० हे०) - क्षेत्र अप्राप्त
 साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (००० हे०) -

	१९६८-६९	७३-७४	श्री
१- नहर			
लिफ्ट (उत्थापक) पम्प	०-३०	०-३४	सिंचाई विभाग
तालाब	-	-	”
भण्डारा	”	”	”
निजी गूल व हाज	”	”	”
सिंचित क्षेत्रफल	१-३५	२-००	”
(१) शुद्ध	”	”	”
(२) सकल	१-६५	२-७५	”
महत्वपूर्ण फसलों के नाम	३-२०	४-७५	”
क- गेहूँ	”	”	”
ख- ज्वार	१९-७०	२५-६६	जिला कृषि अधिकारी
ग- मक्का	१-००	२-०९	”
घ- मूहुवा	”	”	”
ङ- आलू	८-६६	८-६६	”
	२-५२	२-५२	”

बौध्द उद्योग प्राप्त हैकेयर (कि० गु०)	जिला	राज्य
क- गौरी	१२००	१२६६
ख- धान	११००	७६८
ग- मंगौरा	६००	४२०
घ- मण्डुता	६००	५२६
च- बालू	८०००	६५८६

नोट- राज्य के औद्योगिक उद्योगों के विवरण के अनुसार है।

महत्वपूर्ण फलों के नाम	क्षेत्रफल (हैकेयर)	जिला उद्योग अधिकारी
(क) सेवनाशपाती	१०५०	१७५०
(ख) लाल, ग्लोब अमरौट	७५०	१७६३
(ग) नींबू प्रजाति	७८०	१७८०
(घ) अन्य	४२७	६७७

महत्वपूर्ण वन उद्योग के नाम क्षेत्रफल (००० हैक्टा० में)	उत्पाद
(१) चीड़	४०-०० उपाय उपपार
(२) रूपा	२-५०
(३) फर	१२-५०
(४) सुरई	१-२०
(५) लुपाइन	१-४०
(६) देवदार	०-२०

व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम - सूचना अपाय है।
(क- राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है)

महत्वपूर्ण स्थानिय औद्योगिक उत्पादन के नाम :-

- (क) उतन व उतनी वस्त्र
- (ख) लकड़ी का सामान
- (ग) गाल का सामान

जिला उद्योग अधिकारी

रुले लाइनों के लम्बाई - जिले में कोई रुले लाइन नहीं है।

सड़कों की लम्बाई (मीटर)

(क) सामान्य	६४६	६५१
(ख) अतिमत्त सड़कें	६६०	६६०

विजली की लाइनों की लम्बाई (मीटर)

(१) एच.टी. लाइनें	अप्राप्त	२६२	अधिसूची अधिन्याय विद्युत विभाग
(२) एल.टी. लाइनें	११	१५८	

पशु संख्या

	६६८६	६६९३७४	
(१) दुग्ध पशु	४८०००	६००००	जिला पशुधन अधिसूची
(२) अदुग्ध पशु	२२१०००	२४५०००	११
(३) भेड़ वकरियाँ	२२६४०७	२३२८८२	११
(४) अन्य	२६७४	२७६६	११

योग-

५३५२५४ ५५०४४८

कुक्कुट संख्या

१५००० २४५००

तहसीलों की संख्या

४ ४

सड़कों की संख्या

६ ६

ग्रामों की संख्या

१६३६ १६३६

६७१ अगापनगरियाँ

जनसंख्या सहित नगरों । शहरों की संख्या :-

१०,००० तक-	२	२
१०,००० से २०,०००	-	-
२०,००० से ५०,०००	-	-
५०,००० से १,००,०००	-	-
१,००,००० से ऊपर	-	-

नगरों की संख्या :-

(क) जिनमें विकसित लक्षण है	३	३	अधिसूची अधिन्याय विद्युत
----------------------------	---	---	-----------------------------

(ख) जिनमें पशुधन द्वारा जल
पूर्ति होवेगी -

३ अधिसूची अधिन्याय
विद्युत विभाग

गणित की संख्या :-

(क) जिनमें विज्ञान शामिल है	२२	१३६	अविशाली अभियन्ता विद्युत
(ख) जिनमें साहज द्वारा अधुपति होती है।	७१	३६९	अविशाली अभियन्ता स्वा. शा. अ. वि.

विद्यालयों की संख्या :-

(क) प्राथमिक	५३५	५४२	जिला विद्यालय मिर्जापुर
(ख) ऊपर (जुनियर)	५२	६७	
(ग) मिडिल (मध्यवर्ती)	-	-	
(घ) उच्च			
(ङ) उच्चतर माध्यमिक	२१	३५	
(च) महाविद्यालय। कलेजों की संख्या उत्तरी	१	१	

प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान

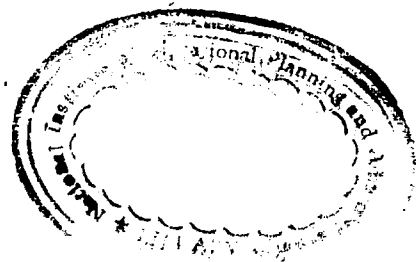
अनुसूचित वर्गों की शाखाओं की संख्या	१	४	सहायक निबंधक समित
नगर क्षेत्रों में	१	०	
ग्रामीण क्षेत्रों में	-	२	

प्राथमिक। कृषि। साज्जा सहकारी
समितियों की संख्या

कृषि सहकारी समितियों की संख्या	-	-	
सहकारी युनिवर्सों की संख्या	३	६६	
कृ-अ. सहकारी समितियों की संख्या	१	१	
जिला सहकारी बैंक	१	१	
सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या	१	३	११
विनियमित बाजारों की संख्या	-	-	

गोडाम	संख्या	संग्रहण क्षमता (मेट्रिक)	संख्या	संग्रहण क्षमता (मेट्रिक)
सरकारी	१२	२६,६२	१५	४६,४७
सहकारी	२५	५०७	५२	१०,४०
अन्य	-	-	-	-

Sub. Director Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Safdarjung Marg, New Delhi-110028
DCC No.....
Date.....



लवैरक डिपी

कृषि विभाग	१०	२६०	१३	२५०
सहकारी विभाग	-	-	-	-
अन्य -	-	-	-	-
राजकीय दीज फार्म :-				
संस्था	१		१	जिला कृषि अधिकारी
दोत्रफाल (हैजेयर)	८		८	
पशु चिकित्सालय । औषधालयों की संख्या-	१७		१७	जिला प्रमुख अधिकारी
कृत्रिम गनीयन केन्द्रों की संख्या	-		-	
पशुमालन केन्द्रों की संख्या	४७		४७	
चिकित्सालयों । औषधालयों की संख्या				
(१) शहरी	३		५	महानिरीक्षण अधिकारी
(२) ग्रामीण	३६		५८	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	६		६	
चिकित्सालय । औषधालयों में क्षमणों की संख्या :-				
(१) शहरी	६६		१५६	
(२) ग्रामीण	२७८		३१५	